वार्षिक रिपोर्ट
1984-85

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

वार्षिक रिपोर्ट

(1984-85)

वार्षिक रिपोर्ट

(1984-85)

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
17-बी, श्री अरबिंद मार्ग, नई दिल्ली-16

LIBRARY & DO
National Institute
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D-9365
Date 5-12-96

रूपेन्द्र प्रसाद सक्सेना, कुल सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान द्वारा प्रकाशित तथा हरीकृष्ण प्रिंटर्स द्वारा हिन्दुस्तान प्रेस बाबरपुर रोड शिवाजी पार्क शाहदरा दिल्ली-1100032 में मुद्रित ।

आभार प्रदर्शन

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों में सहयोग करने तथा दिलचस्पी लेने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान निम्नांकित संस्थाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है : शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, योजना आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली; राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान, हैदराबाद; भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली; व्यावहारिक मानवशक्ति अनुसंधान संस्थान, दिल्ली; केंद्रीय विद्यालय संगठन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली, वायु सेना का शिक्षा अनुभाग, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, राज्य अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राज्य शिक्षा संस्थान, दिल्ली, ए एन सिन्हा समाज विज्ञान संस्थान, पटना; पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना; भारतीय शिक्षा संस्थान पुणे, पश्चिम बंगाल सरकार, मध्यप्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर की सरकारें, तथा अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें।

संस्थान प्रशिक्षण के लिए आए विभिन्न विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों और जिला शिक्षा अधिकारियों की उनके क्षेत्र दौरों के दौरान स्वागत करने के लिए विभिन्न विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के प्रति भी आभार प्रदर्शित करता है।

विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन में अतिथि वक्ता अथवा संसाधन व्यक्तियों के रूप में जिन विशेषज्ञों ने भाग लिया है, संस्थान उनका आभारी है।

संस्थान के कुछ कार्यक्रमों के संचालन में निम्नांकित संस्थाओं से सहयोग मिला है। संस्थान उनका आभार स्वीकार करता है। ये संस्थाएं हैं : यू एन डी पी, शैक्षिक योजना का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, पेरिस, यूनेस्को सांख्यिकी कार्यालय, पेरिस; एशिया तथा ओसियानिया के लिए यूनेस्को का क्षेत्रीय कार्यालय बैंकाक; यूनाइटिड नेशंस एशिया एण्ड पैसिफिक सेंटर, क्वालालमपुर; नेशनल एसोसिएशन फार एशिया एण्ड पैसिफिक एजुकेशन; यूनाइटिड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन इंडिया, कामनवेल्थ फंड फार टेकनिकल क्वापरेशन, लंडन, तथा स्वेडिश इंटरनेशनल, डेवलपमेंट एजेंसी, स्टाकहोम।

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान इसकी गतिविधियों में दिलचस्पी लेने के लिए और सहयोग करने के लिए संस्थान निम्नांकित देशों की सरकारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

विषय सूची

संस्था के उद्देश्य
आभार ज्ञापन
विहंगावलोकन

भाग एक

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और कार्यक्रम/21

भाग दो

अनुसंधान और अध्ययन/38

भाग तीन

परामर्शदायी, सलाहकारी तथा सहायता सेवाएं/53

भाग चार

अन्य अकादमिक गतिविधियां/61

भाग पांच

अकादमिक एककें/66

भाग छः

अकादमिक आधारिक संरचना/74

भाग सात

प्रशासन और वित्त/87

भाग आठ

छठीं योजना की उपलब्धियां/91

अनुबंध

एक : प्रशिक्षण कार्यक्रम/107
दो : अनुसंधान अध्ययन/126
तीन : संकाय का अकादमिक योग/137
चार : आगंतुक गण/143

परिशिष्ट

एक : परिषद के सदस्यों की सूची/147
दो : कार्यकारिणी समिति के सदस्य/150
तीन : वित्त समिति के सदस्य/151
चार : कार्यालय सलाहकार समिति के सदस्य/152
पांच : प्रकाशन सलाहकार समिति के सदस्य/153
छः संकाय तथा प्रशासनिक स्टाफ/154
सात : वार्षिक लेखा और अंकेक्षण रिपोर्ट/157

विहंगावलोकन

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान की स्थापना भारत सरकार ने 1970 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में की थी। इसके पहले यह संस्थान "शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों का राष्ट्रीय स्टाफ कॉलेज" के नाम से जाना जाता था। 1962 में इसकी स्थापना "शैक्षिक योजना और प्रशासन का एशियाई संस्थान" के नाम से 10 वर्षीय अनुबंध के तहत यूनेस्को द्वारा की गई थी। बाद में भारत सरकार ने इसकी व्यवस्था अपने हाथ में ले ली थी।

इस रिपोर्ट में अप्रैल 1984 से मार्च 1985 तक की संस्थान की मुख्य गतिविधियों का विवरण दिया गया है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएँ नीचे दी गई हैं :

प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष के दौरान संस्थान ने कुल 53 कार्यक्रम आयोजित किए, इसके पूर्ववर्ती वर्ष में जबकि 47 कार्यक्रम संस्थान ने चलाए थे। इसमें कुल 907 भागीदारों ने हिस्सा लिया, जिसमें 709 लोग विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के थे तथा शेष 92 लोग दूसरे देशों से आए थे। भागीदारों में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा भारत सरकार के अधिकारी तथा एन सी ई आर टी, योजना आयोग, विश्वविद्यालय व्यवस्था से संबंधित कई राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के लोग भी शामिल थे।

क्षेत्रवार भागीदारी इस प्रकार थी : उत्तरी क्षेत्र जो सबसे अधिक थी (265), पूर्वी क्षेत्र (193), पश्चिमी क्षेत्र (128) तथा दक्षिणी क्षेत्र (123)। राज्यों मे सबसे अधिक भागीदारी जम्मू तथा कश्मीर की थी। उसके बाद क्रमश: असम, दिल्ली, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश थे।

इस वर्ष के दौरान आयोजित कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को नीचे दिया गया है :

(क) डिप्लोमा पाठ्यक्रम

1. **भारत के जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में डिप्लोमा (12 जुलाई 1984—28 जनवरी 1985)** : इस शृंखला का यह तीसरा कार्यक्रम था। हर भागीदार से कार्य-योजना बनाने का काम शुरू किया गया। उसके क्षेत्र विशेष से संबद्ध सिंडिकेट कार्य का यह एक हिस्सा था। ग्यारह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 24 अधिकारियों ने इस पाठ्यक्रम में हिस्सा लिया।
2. **शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा (14 जनवरी, 1984—13 जुलाई, 1985)** : दक्षिण एशिया तथा तीसरी दुनिया के अन्य देशों के शिक्षाकर्मियों के प्रशिक्षण की मांग को पूरा करने के लिए नीपा ने पहला अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम जनवरी 1985 में शुरू किया। इसमें पांच देशों

के बारह अधिकारी भागीदार बने। ये देश थे, अफगानिस्तान, भूटान, कुवैत, मॉरिशस तथा श्रीलंका।

(ख) प्राथमिकता के क्षेत्र

प्राथमिकता वाले विषयों में, (जैसे प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण, प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा) विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के लोगों के लिए रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान अभिविन्यास कार्यक्रम चलाए गए। दो राष्ट्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं। पहली शिक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर अनौपचारिक शिक्षा के लिए वैकल्पिक माडल के विकास पर थी तथा, दूसरी प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के सहयोग से ऊंचे स्तर के शिक्षा कर्मियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियोजन तथा प्रबंध विषय पर थी। आश्रम स्कूलों के प्रशिक्षण से संबंधित तथा दूसरा शिक्षा में समता पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(ग) नए क्षेत्र

इस सत्र के दौरान व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के प्रबंध ने लोगों का ध्यान अधिक आकर्षित किया। इस वर्ष दो कार्यक्रम इस क्षेत्र में आयोजित किए गए। जम्मू कश्मीर के महिला पोलिटेकनीक प्रशिक्षकों और प्रशासकों के लिए एक कार्यक्रम और इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपलों के लिए दूसरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। 2 स्तर के शिक्षा के व्यवसायीकरण की योजना तथा प्रबंध पर भी कार्यक्रम आयोजित किया गया।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तीन नए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। वे कार्यक्रम इस प्रकार हैं: कश्मीर विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्षों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, कॉलेजों के विज्ञान विभागों के अध्यक्षों के लिए कार्यक्रम तथा कॉलेजों के शिक्षण पद्धतियों पर कार्यशिविर। इन सभी कार्यक्रमों में संपूर्ण संस्था के प्रबंध के बजाए संस्थाओं, विभागों तथा कार्यक्रमों के प्रबंध पर बल दिया गया।

विषय विशेष को केंद्र में रखकर दो कार्यक्रम आयोजित किए गए : पहला था, प्रोजेक्शन एण्ड फोरकास्टिंग तकनीक तथा दूसरा था नेतृत्व तथा निर्णय पर कार्यशिविर।

(घ) कार्यक्रम जो चल रहे हैं

संस्थान ने तीन सप्ताह के तीन कार्यक्रम कॉलेज के प्राचार्यों के लिए, तीन सप्ताह के दो कार्यक्रम वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों के लिए, तीन सप्ताह के दो कार्यक्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्यों के लिए तथा दो सप्ताह की अवधि के दो कार्यक्रम विश्वविद्यालय वित्त के प्रबंध पर आयोजित किए।

(ङ) विशिष्ट कार्यक्रम

राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशों के शिक्षा कर्मियों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सस्थान

ने विशेष प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। इनके लिए आग्रह करने वाले राज्य थे : असम, उत्तर प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय विद्यालय संगठन तथा एयरफोर्स के शिक्षा विभाग के विशेष अनुरोध पर संस्थान ने इनके शिक्षा कर्मियों के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया।

अनुसंधान और अध्ययन

वर्ष 1983-84 के दौरान अनुसंधान और अध्ययन पर सरकारी अनुदान के 3.60 लाख रुपए खर्च हुए थे। उसकी तुलना में वर्तमान सत्र में 4.23 लाख रुपए खर्च हुए। अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थान ने 7.65 लाख रुपए कोश की व्यवस्था की है। इस सत्र के दौरान अनुसंधान तथा अध्ययन पर कुल खर्च 11.88 लाख रुपये तक पहुंच गया। इसमें कुल 21 अध्ययन पूरे किए गए तथा 14 का कार्य प्रगति पर है।

पूरे किए गए अध्ययन

1. भारत में शैक्षिक प्रबंध का निदानात्मक अध्ययन (यूनेस्को द्वारा प्रायोजित)।
2. शैक्षिक विकास में क्षेत्रीय असमानता : भारतीय शिक्षा का मानचित्र।
3. भारत में शिक्षा के लिए संसाधनों से संग्रहण का अध्ययन।
4. गुड़गांव (हरियाणा) में शिक्षा की आपूर्ति लागत।
5. विश्वविद्यालय व्यवस्था के लिए एक आदर्श लेख संहिता के विकास का अध्ययन।
6. भारत में उच्च शिक्षा की ग्रंथ सूची (यूनेस्को द्वारा प्रायोजित)।
7. भारत में उच्च शिक्षा के वित्तीयन का गहन अध्ययन (भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायोजित)।
8. विश्वविद्यालय समुदाय की स्वायतत्ता (भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायोजित)।
9. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति का प्रबंध तथा इस्तेमाल का ढांचा और उसका प्रभाव : एक राष्ट्रीय चित्र (गृह मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)।
10. उच्च शिक्षा में प्राधिकरण, असफलता तथा बीच में छोड़कर चला जाना : अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों का कोहार्ट विश्लेषण : राष्ट्रीय चित्र : 3 (गृह मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)।
11. मैट्रिकोत्तर छात्रवृति पाने वालों की सामाजिक पृष्ठभूमि, रहन सहन की स्थितियां तथा अकादमिक निष्पादन : अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों का राष्ट्रीय अध्ययन (गृह मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)।

राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग के कार्य में आगत (इनपुट) के रूप में हाथ में लिए गए अध्ययनों की सूची नीचे दी गई है :

12. भारत में उच्च शिक्षा : एक सर्वेक्षण
13. आर्थिक स्तर
14. सामाजिक स्तर
15. भर्ती : आधार तथा प्रक्रिया
16. गतिशीलता और अंतप्रजन
17. व्यावसायिक तथा कैरियर विकास
18. कार्य की प्रकृति

19 निर्णय में भागीदारी
20. परेशानियां और उनका उपचार
21. व्यावसायिक मूल्य

अध्ययन जो चल रहे हैं

1. स्कूलों में अध्यापक छात्र के मध्य इष्टतम अनुपात का अध्ययन
2. भारत में समाज विज्ञान संबंधी अनुसंधानों का वित्तीयन (भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायोजित)
3. भारत में अवसर की समानता तथा अवसर के समानीकरण के विशेष संदर्भ में शैक्षिक वित्तीयन का अनुशीलन : केरल तथा उत्तरप्रदेश में स्कूल शिक्षा का अध्ययन (भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायोजित)
4. भारत में शैक्षिक योजना एवं नीति का अध्ययन : योजना आयोग की भूमिका : वर्तमान स्थिति तथा भावी परिप्रेक्ष्य
5. वर्ष 2000 में भारतीय शिक्षा : एक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य
6. केरल में शिक्षा के विकास का अध्ययन
7. (क) इंजीनियरिंग कालेजों में कर्मचारियों का ढांचा
   (ख) इंजीनियरिंग कालेजों में सामग्री सूचियों का प्रबंध
8. विकास के कुछ पहलुओं पर शैक्षिक स्तर का प्रभाव : ग्रामीण परिवारों का अध्ययन
9. शिक्षा और रोजगार के बीच लाभकारी संरचनात्मक संबंध : पृष्ठभूमि
10. कालेजों के प्रधानों की भूमिका निष्पादन का अध्ययन
11. पुनहाना प्रखण्ड, जिला गुड़गांव (हरियाणा) के 20 गांवों के एक समूह में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य से शैक्षिक योजना तथा प्रशासन में परिवर्तनकारी प्रथाओं पर आधारित कार्य अनुसंधान
12. संरक्षणात्मक भेदभाव तथा शैक्षिक अवसरों के समानीकरण की भूमिका
13. शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए 9 राज्यों में 9-14 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण संबंधी अनौपचारिक शिक्षा के लिए प्रयोगात्मक योजना का मूल्यांकन अध्ययन (शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)

आकस्मिक आलेख

1. भारत में उच्च शिक्षा : क्षेत्रीय आयाम
2. शिक्षा में भेदभाव युक्त मूल्य निर्धारण

सलाहकारी, परामर्शकारी तथा समर्थनकारी सेवाएं

केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीय संस्थानों के अनुरोध पर तथा उनके सहयोग से राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान ने कई अनुसंधान अध्ययन और कार्यक्रम हाथ में लिए। संस्थान ने केंद्र तथा राज्य सरकारों को, तथा योजना और प्रशासन में संलग्न संगठनों को संकाय समर्थन, अकादमिक तथा व्यावसायिक सलाह, तथा निर्देशन देना जारी रखा। संस्थान ने शिक्षा मंत्रालय के तथा योजना आयोग के निकट सहयोग से काम किया तथा शैक्षिक योजना और प्रशासन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में गृहमंत्रालय, राज्य शिक्षा विभागों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, भारतीय लोक-प्रशासन संस्थान, केंद्रीय विद्यालय संगठन, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय आदि के साथ मिलकर कार्य किया।

गृह मंत्रालय के अनुरोध पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक विकास पर एक अध्ययन कार्यक्रम संस्थान में चलाया गया, जिसकी चर्चा यहां प्रासंगिक जान पड़ती है। इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि संस्थान ने उच्च शिक्षा के अध्यापकों की वर्तमान अवस्था पर एक अनुसंधान अध्ययन चलवाया। शिक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर एक मूल्यांकन अध्ययन चलाया गया उसका उल्लेख करना आवश्यक है। अध्ययन का नाम था: "9 शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में 9-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए अनौपचारिक शिक्षा पर प्रयोगात्मक परियोजना"।

दूसरे देशों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से कुछ खास कार्यक्रम आयोजित किए। जिन देशों के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किए गए वे देश हैं: श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, फिलीपीन्स, तथा संयुक्त राज्य अमरीका।

अंतर्राज्यीय अध्ययन दौरा

4-9 फरवरी 1985 के बीच एक अंतर्राज्यीय अध्ययन दौरे का आयोजन किया गया, यह दौरा इस शृंखला सें तीसरा था। इसका उद्देश्य मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चालू की गई "पढ़ाई के साथ कमाई योजना" को निकट से देखना था। संस्थान उपर्युक्त सफल प्रयोग के विषय में एक पुस्तक के प्रकाशन की योजना बना रहा है।

नीपा वार्तालाप

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार के विषयों पर वार्तालाप आयोजित किए गए। इनमें शैक्षिक योजना और प्रबंध से लगाकर विकास की दुविधा तथा शिक्षा तथा समाज पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव जैसे विषय शामिल थे।

अकादमिक एककें

राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और पैदा होने वाली आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने अपने क्षेत्रों में इन एककों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए तथा अनुसंधान कार्य करवाए। इन एककों के नाम इस प्रकार हैं: शैक्षिक

योजना, शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक नीति, स्कूल और अनौपचारिक शिक्षा, उच्चशिक्षा प्रादेशिक शिक्षा प्रणाली, तथा अंतर्राष्ट्रीय एकक।

अकादमिक ढांचा

संस्थान के बहुमुखी तथा उत्तरोत्तर बढ़ते हुए कार्यक्रमों, अनुसंधान तथा अन्य अकादमिक गतिविधियों को पुस्तकालय, प्रलेखन केंद्र, प्रकाशन एकक, हिंदी कक्ष, डाटा बैंक, कार्टोग्राफिक कक्ष (आरेखण कक्ष), तथा इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग तथा रिप्रोग्राम यूनिट से लगातार बहुमूल्य समर्थन मिलता रहा।

इस वर्ष के दौरान पुस्तकालय तथा प्रलेखन केंद्र को लगभग 3000 और दस्तावेज प्राप्त हुए तथा "वर्तमान कालिक जागृति सेवा" प्रदान करता रहा, "रिजन इनफार्मेशन रिव्यू" में भाग लिया तथा "ईपा" त्रैमासिक बुलेटिन में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित सूचनाएं प्रकाशित कराईं।

देश के हिंदी भाषी इलाकों से आए, प्रशिक्षण में भाग लेने वाले भागीदारों के लिए हिंदी कक्ष ने हिंदी में प्रशिक्षण सामग्री और रिपोर्ट तैयार करने में मदद की।

प्रकाशन

एक समूल्य पुस्तक का प्रकाशन किया गया, दो पुस्तकें प्रकाशनार्थ प्रेस में थी और चार पाण्डुलिपियां प्रकाशन के लिए ली गईं। प्रकाशन संबंधित विस्तृत सूचना नीचे दी जा रही है :

1. "गवर्नमेण्ट सपोर्ट फार हायर एजुकेशन एण्ड रिसर्च" लेखक डा. जे एल आजाद (प्रकाशित)
2. "एजुकेशनल प्लानिंग : ए लांग टर्म पर्सपेक्टिव" संपादक, प्रो. मूनिस रज़ा (प्रेस में)
3. "ए फाइनेंशियल कोड फार यूनिवर्सिटी सिस्टस" लेखक एम एल सोबती.
4. "कास्ट आफ सप्लाई एट माइक्रो लेवल : ए केस स्टडी आफ टू एजुकेशन क्लस्टर्स इन डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव, हरियाणा, "ले. जेब बी जी तिलक तथा जी के भट्ट
5. "मोबलाइजेशन आफ एडिशनल रिसोर्सेज फार एजुकेशन : ए स्टडी आफ सर्टेन स्टेट्स इन इंडिया" ले. सी बी पद्मनाभन (प्रकाशन के लिए स्वीकृत)
6. "आरगेनाइजेशनल हिस्ट्री आफ दि मिनिस्ट्री आफ एजुकेशनल," लेखक ए मैथ्यू (प्रकाशन के लिए स्वीकृत)
7. "रिसोर्सेज फार एजुकेशन इन इंडिया" लेखक जे बी जी तिलक तथा एन वी वर्गीस (प्रकाशन के लिए स्वीकृत)

स्टाफ की संख्या

31 मार्च 1985 की स्टाफ के कुल सदस्यों की संख्या 161 थी। इसके अतिरिक्त इसी तिथि को परियोजनाओं में कार्यरत सदस्यों की संख्या 40 थी।

मानव संसाधन विकास

अकादमिक तथा स्टाफ के अन्य सदस्यों को, सेवाकालीन प्रशिक्षण को मानव संसाधन विकास का महत्वपूर्ण तत्व मानकर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया । संकाय के तीन सदस्यों ने विदेशों में जाकर विशेषता वाले तथा उच्चतर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया ।

नीपा के नियम तथा विनियम

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के सेवा विनियमों की समीक्षा, तथा इसमें नए प्रावधानों का समावेश करने के लिए कार्य शुरू किया गया तथा इस काम के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित समिति के विचारार्थ प्रारूप तैयार किया गया ।

अनुसंधान प्रस्ताव बनाने के लिए तथा उनकी रिपोर्ट जमा करने के लिए विस्तृत निर्देश बियम भी बनाए तथा जारी किए गए ।

लेखा तथा प्रशासन का आधुनिकीकरण

संगणक के जरिए इनक्रीमेंट का स्वत: लगना और परियोजना स्टाफ तथा कैडर की नियमित समीक्षा का कार्य प्रारंभ किया गया । वित्तीय लेखा तथा इनवेंट्री कंट्रोल प्रणाली के लिए कार्यक्रम भी बनाए गए ।

कार्यक्रम की रिपोर्टिंग

त्रैमासिक रिज्यूमें (टंकित तथा साइक्लोस्टाइल्ड) भी निकाले गए जिसमें संस्थान की विविध गतिविधियों तथा महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा थी ।

कार्यालय उत्पादकता तथा रिपोर्टिंग : एक नवाचारी दृष्टि

कार्यालय के कार्यों की मुख्य चीजों के समेटने के लिए कार्यालय रिपोर्टिंग तथा देखरेख में नवाचारी दृष्टि प्रचलित की गई । इसमें कर्मचारी, वस्तुओं की आपूर्ति तथा उनकी मरम्मत, संपत्ति तथा निर्माण आदि बातें शामिल थीं । यह सब बातें प्राप्तियों की निसन व्यवस्था से पृथक हैं ।

नीपा का परिसर

नीपा परिसर को इस वर्ष और अधिक सुधारा गया । एक ट्यूबवेल और लगाया गया । इसके पूर्व एक ट्यूब-वेल लगाया जा चुका था । निर्देशक के आवास का निर्माण कार्य और साथ में टाइप II तथा टाइप III

आवासों का निर्माण कार्य आरंभ किया गया।

कार्यालय के लिए स्थानाभाव तथा रिहाइश के स्थानाभाव को संस्थान इस सत्र में भी झेलता रहा।

छात्रावास

छात्रावास में रुकने वालों की संख्या काफी अधिक बनी रही। लोगों के रुकने से इस वर्ष की छात्रावास की आय 2.37 लाख रु० तक पहुंच गई।

वित्तीय विवरण

वर्ष 1984-85 के दौरान सरकारी अनुदान में से कुल व्यय 80·31 लाख रुपए हुए (35.18 लाख योजनेतर मदों पर तथा 43.13 लाख योजना वाले मदों पर) इसके विपरीत 1983-84 में कुल व्यय 68.42 लाख रुपए थे (34.43 लाख योजनेतर मदों पर तथा 33.99 योजना वाले मदों पर) इसके अलावा 14.01 लाख रुपए उन कार्यक्रमों तथा अनुसंधान अध्ययनों पर खर्च किए गए जिनके लिए वित्त अन्यत्र से प्राप्त हुआ था।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) की उपलब्धियां

यह छठी पंचवर्षीय योजना का आखिरी साल था। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान संस्थान ने उल्लेखनीय प्रगति की। कार्यक्रमों में विविधता आई। इसकी कुछ मुख्य मुख्य बातों को नीचे दिया जा रहा है :

प्रशिक्षण कार्यक्रम

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 4000 से भी अधिक शिक्षा कर्मियों ने विविध कार्यक्रमों में भाग लिया। ये प्रतिभागी विभिन्न स्तरों के थे, इनमें 400 प्रतिभागी विदेशों के थे।

कार्यक्रमों में बढ़ोत्तरी : 1980-81 में कार्यक्रम दिवसों तथा कार्यक्रम व्यक्ति दिवसों की संख्या 391 तथा 7497 थी। 1984-85 में यह संख्या बढ़कर क्रमश: 1015 और 14852 हो गई। यह बढ़ोत्तरी क्रमश: 153% तथा 98% की थी।

क्षेत्रवार भागीदारी

सभी राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश विभिन्न शिक्षा कर्मियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भेजते रहे हैं। सबसे अधिक भागीदारी उत्तरी क्षेत्र की रही (1272) इसके बाद दक्षिणी क्षेत्र (711), पूर्वी क्षेत्र (704) तथा पश्चिमी क्षेत्र (690)। सबसे अधिक भागीदारी महाराष्ट्र प्रदेश की रही (293) इसके बाद उत्तर प्रदेश (231) तथा दिल्ली (231)। शिक्षा की दृष्टि से नौ पिछड़े हुए राज्यों की भागीदारी (1427) रही जो कुल राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों की भागीदारी का 34% था।

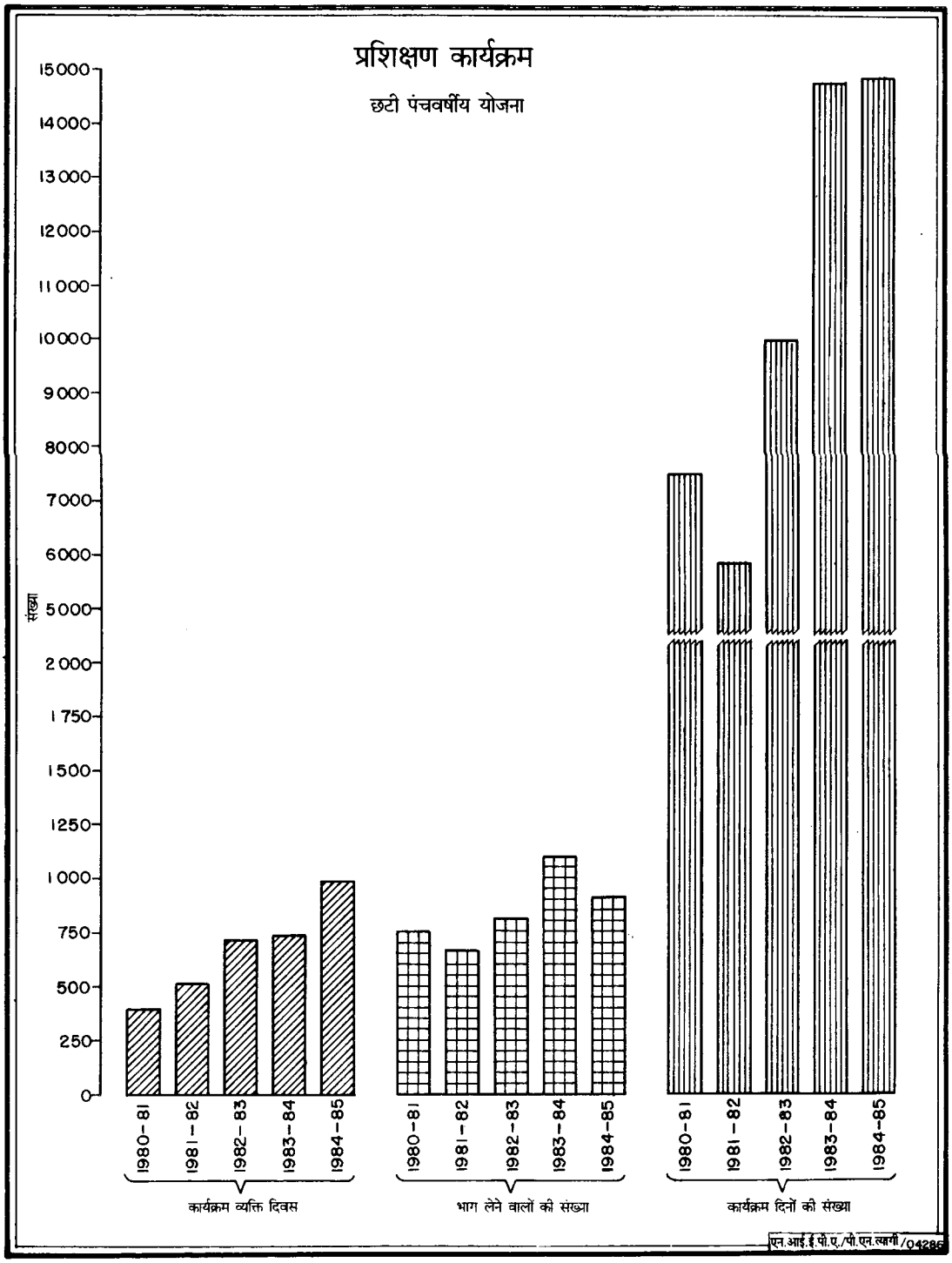
प्रशिक्षण कार्यक्रम
छटी पंचवर्षीय योजना
संख्या
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
कार्यक्रम व्यक्ति दिवस
भाग लेने वालों की संख्या
कार्यक्रम दिनों की संख्या
एन.आई.ई.पी.ए./पी.एन.त्यागी/04286

विदेशी भागीदारों में 31 देशों से आए हुए लोग थे। इन देशों के नाम हैं; अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, बहरीन, बंगला देश, बारबाडोस, भूटान, कनाडा, चीन, साइप्रस, ईथोपिया, फीजी, इण्डोनेशिया, ईरान, जापान, कीनिया, कोरिया, कुवैत, मलेशिया, मारिशस, नेपाल, पाकिस्तान, पापुआ तथा न्यूगिनी, फिलीपाइन्स, सिंगापुर, श्रीलंका, स्विटजरलैंड, तंजानिया, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमरीका।

राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के कार्यक्रम : जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए 1982-83 में एक छमाही डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ किया गया। शिक्षा सत्र 1983-84 और 1984-85 में दूसरा तथा तीसरा पाठ्यक्रम क्रमशः चलाए गए।

कई कार्यक्रम ऐसे चलाए गए जो कैडर पर आधारित थे। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए आवश्यकता पर आधारित विशेष कार्यक्रमों का आयोजन राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए किया गया। विभिन्न विषयों पर तथा शिक्षा प्रबंध के विभिन्न पहलुओं पर कार्यशिविर और संगोष्ठियां आयोजित की गईं।

अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम : एक छमाही अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम 1984-85 के दौरान आरंभ किया गया। श्रीलंका के लोगों के लिए एक छः महीने का शिक्षा प्रबंध का कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभिन्न देशों के अधिकारियों के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, क्षेत्रीय कार्यशिविर/संगोष्ठियों और अध्ययन दौरों का भी आयोजन किया गया है।

अनुसंधान कार्यक्रम

अनुसंधान के क्षेत्र में संस्थान ने विशेष बल दिया और शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के विभिन्न पक्षों पर 45 अनुसंधान अध्ययनों को पूरा किया गया। वर्ष 1980-81 के दौरान सिर्फ एक अनुसंधान अध्ययन पूरा किया गया था इसके विपरीत 1984-85 में 21 अनुसंधान अध्ययन पूरे किए गए। इसके अलावा 31-3-85 को 17 अध्ययन प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में थे।

अनुसंधान पर व्यय : वर्ष 1980-81 में सरकारी अनुदान से अनुसंधान पर 0.22 लाख रुपये खर्च हुए जो 1984-85 में बढ़कर 4.23 लाख हो गए। छठी योजना में मूलतः 5.50 लाख रुपये का प्रावधान संस्थान ने इस मद के लिए निर्धारित किया था लेकिन योजना के अंत तक खर्चे की राशि बढ़कर 10.72 लाख रुपये पहुंच गई। इन सबके अतिरिक्त संस्थान ने 24.08 लाख रुपये की निधि की अलग से व्यवस्था की। यह विभिन्न संस्थाओं के अनुरोध पर लिए गए अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए था। ये संस्थाएं थीं : गृह मंत्रालय, उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, यूनेस्को तथा भारतीय समाजशास्त्र अनुसंधान परिषद।

महत्वपूर्ण अध्ययन : कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के नाम इस प्रकार हैं : राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में शैक्षिक प्रशासन का अखिल भारतीय सर्वेक्षण; शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नौ राज्यों में शैक्षिक प्रशासन का अध्ययन; राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक स्तर पर शैक्षिक नीति, नियोजन और प्रबंध के विभिन्न पक्षों का अध्ययन; मेवात क्षेत्र के पुनहाना प्रखंड में कार्ययोजना। (यह इलाका शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है), शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए नौ राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन।

आकस्मिक तथा अनुसंधान आलेख

शैक्षिक योजना और प्रशासन के विभिन्न पक्षों से संबंधित अनुसंधान को प्रचारित करने के उद्देश्य से संस्थान ने आकस्मिक आलेखों तथा अनुसंधान आलेखों का प्रकाशन आरंभ किया तथा इसको "आकस्मिक तथा अनुसंधान आलेख" नाम दिया गया। छठी योजना अवधि के दौरान इस प्रकार के नौ आलेख प्रकाशित किए गए।

सलाहकारी, परामर्शकारी तथा समर्थनकारी सेवाएं

सलाहकारी, परामर्शकारी तथा समर्थनकारी सेवाओं के कुछ मुख्य विषय छठी पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार थे :

(अ) स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षक आयोग का कार्य;
(ब) राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर टास्कफोर्स, कार्यदल, सलाहकार मंडल तथा आयोग में योगदान;
(स) राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और विश्वविद्यालय शिक्षा विभागों को परामर्शकारी सेवाएं;
(द) विभिन्न राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य निकायों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए संकाय का समर्थन तथा,
(य) अन्य देशों तथा यूनेस्को को परामर्शकारी सेवाएं।

अन्य अकादमिक गतिविधियां

छठी योजना अवधि में अकादमिक गतिविधियों के दूसरे प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं :

(क) नवाचारों का प्रसार : इसके अंतर्गत अध्ययन किए गए कार्यक्रमों में स्कूल सुधार के रैपर्ट आधारित कार्यक्रम (महाराष्ट्र), 2 स्तर पर स्कूल शिक्षा का व्यवसायीकरण, (तमिलनाडु), तथा "पढ़ो और कमाओ" (मध्यप्रदेश) आदि शामिल हैं।
(ख) शैक्षिक योजना तथा प्रशासन में नवाचारी अवधारणाओं तथा प्रयोगों के लिए वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत;
(ग) शैक्षिक मदों पर अनौपचारिक विचार विमर्श, तथा
(घ) नीपा एसोसिएटशिप का दिया जाना

प्रकाशन

संस्थान ने 275 प्रकाशन निकाले जिसमें 47 मुद्रित थे तथा शेष अनुलेखित थे।

अकादमिक ढांचा

अकादमिक कार्यक्रमों में सहायता करने के लिए कुछ नई एककें स्थापित की गईं। इनके नाम हैं : राष्ट्रीय

अनुसंधान और अध्ययन

छटी पंचवर्षीय योजना

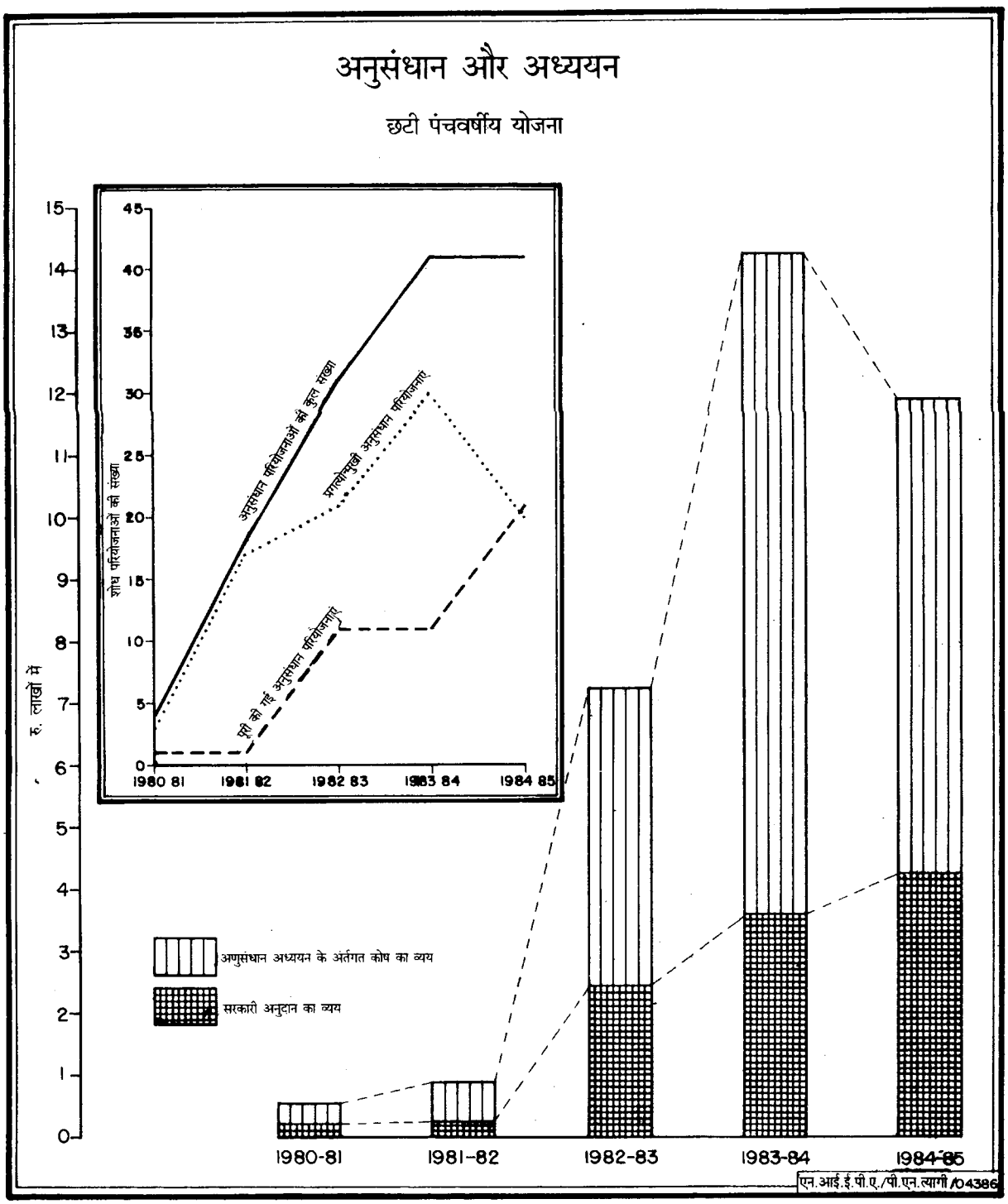

एन.आई.ई.पी.ए./पी.एन.त्यागी/04386

प्रलेखन केंद्र, प्रकाशन एकक, आरेखण कक्ष, डाटा बैंक, हिंदी कक्ष : तथा इलैक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग एकक। फरवरी 1983 से संस्थान का पुस्तकालय पूरे वर्ष रोज खुला रहने लगा। सिर्फ राष्ट्रीय अवकाश के समय बंद रहता हैं।

प्रशासन और वित्त

कैडर नियोजन : संस्थान में 1 अप्रैल 1980 में कुल कैडर संख्या 103 थी लेकिन 31 मार्च 1985 को यह संख्या बढ़कर 161 हो गई। कैडर नियोजन का मकसद संस्थान की व्यावसायिक दक्षता को सुदृढ़ करना तथा प्रशासन को चुस्त बनाना था ताकि कैडर को अधिकतम समर्थन मिल सके।

अनुसंधान अध्ययनों को चलाने के लिए परियोजना कर्मियों की भी नियुक्तियां की गईं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान : 1-4-1982 से संकाय के लोगों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान लागू किए गए। पुस्तकाध्यक्ष तथा प्रलेखन अधिकारी के लिए यह वेतनमान 21-3-1984 से लागू हुए।

प्रबंधकीय कार्य : संस्थान को सशक्त तथा सुदृढ़ बनाने के लिए जो मुख्य कदम उठाए गए, उनमें कुछ इस प्रकार थे : संकाय तथा प्रशासन का पुनर्गठन किया गया जिससे वह पूरी जिम्मेदारी से काम करके उत्पादकता में वृद्धि करे। विभिन्न अकादमिक तथा प्रशासनिक कर्मियों को वित्तीय अधिकार दिए गए जिससे कार्य की गति की तेज किया जा सके, अवरोधों को दूर किया जा सके, सभी श्रेणी के कर्मचारियों का मानव संसाधन विकास, कार्यालय प्रबंध का आधुनिकीकरण, अकादमिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय कार्यों प्रबंधकीय रिपोर्टिंग का आरंभ तथा संगणक का प्रयोग किया जा सके लेकिन इन सबके बावजूद संकाय कर्मियों की कमी, कार्यालय तथा आवासीय स्थान की कमी प्रमुख बाधा बनी रही।

निधि का वितरण : 1980-81 के दौरान कुल खर्चा 43.13 लाख रुपये था (इसमें योजना के अंतर्गत तथा योजनेतर खर्चे शामिल हैं)। यह खर्च 1984-85 में बढ़कर 94.32 लाख हो गया (योजना तथा योजनेतर) इस काल में सरकारी अनुदान से किया गया खर्च 22.61 लाख रुपये (1980-81) से बढ़कर 45.64 लाख रुपये (1984-85) हो गया। यह बढ़ोत्तरी लगभग 100 प्रतिशत की है।

छठी पंचवर्षीय योजना में मूलत: 115 लाख रुपये व्यय (खर्चे) का प्रावधान किया गया था। मध्यावधि पुनरीक्षण के बाद संस्थान का यह व्यय बढ़कर 157.59 लाख रुपये हो गया क्योंकि योजना का खर्चा बढ़ गया था। संस्थान से 42.19 लाख रुपये अतिरिक्त कार्यक्रमों के लिए जुटाए। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान संस्थान का कुल खर्च 341.64 लाख रुपये हो गया (योजना और योजनेतर को मिलाकर) इसमें वह राशि भी शामिल है जो कुछ कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक संस्थानों से प्राप्त हुई थी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में नई बातों पर बल

(अ) शैक्षिक योजना और प्रशासन में राज्य स्तर के केंद्रों की स्थापना

शैक्षिक योजना और प्रशासन में सुधार लाने के लिए राज्य स्तर पर केंद्रों की स्थापना विचाराधीन है। इसका उद्देश्य है केंद्रीकृत योजना पर खास बल देना, जनता की भागीदारी तथा शिक्षा में निचले स्तर पर काम करने वाले शिक्षा कर्मियों को प्रशिक्षित करना।

(ब) शैक्षिक योजना और प्रबंध में पत्राचार पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (नीपा) राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय के लिए शैक्षिक योजना एवं प्रबंध में दूर शिक्षण के लिए संसाधन केंद्र का कार्य करेगा।

(स) शैक्षिक योजना और प्रबंध में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का व्यवहार

शैक्षिक योजना और प्रबंध में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकी के व्यवहार को सुदृढ़ बनाया जाएगा।

(द) कार्य अनुसंधान और विस्तार

राज्यों तथा केंद्र में चल रही शिक्षा योजनाओं में सुधार के लिए और अधिक कार्य अनुसंधान परियोजनाएं चलाना,

क्षेत्राधारित अध्ययन तथा प्रयोगात्मक परियोजनाओं को चलाना, इनसे प्राप्त जानकारियों का इस्तेमाल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किया जाएगा। शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में अनुसंधान के निष्कर्षों को प्रसारित करना।

भाग एक

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रम

देश के तथा विदेशों से आए हुए विभिन्न शिक्षा कर्मियों के लिए संस्थान ने, समीक्षाधीन सत्र के दौरान, बहुत से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, कार्य शिविर तथा संगोष्ठियों का आयोजन किया।

वार्षिक योजना

प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण, प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण, आंकड़ा संसाधन और सूचना प्रणाली का प्रबंध, शिक्षा में निष्पक्षता, शैक्षिक विकास में समुदाय की संलग्नता आदि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर इस सत्र के लिए प्रशिक्षण गतिविधियों की वार्षिक योजना तैयार की गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए, वर्तमान संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने तथा व्यवस्था की आंतरिक क्षमता को ऊपर उठाने के लिए, भागीदारों को जरूरी तकनीक तथा दक्षता प्रदान करने पर अधिक जोर दिया गया। इस बात को स्वीकार करते हुए कि मानवीय संसाधन सबसे अधिक मूल्यवान है तथा व्यक्तियों की क्षमता के ऊपर ही शैक्षिक व्यवस्था की दक्षता निर्भर करती है, अतः शैक्षिक योजनाकारों तथा प्रशासकों की योजना तथा प्रबंध संबंधी क्षमता को सुधारने पर विशेष बल दिया गया।

प्रशिक्षण गतिविधियों की वार्षिक योजना तैयार करते समय, प्रशिक्षण की आवश्यकता, प्रशिक्षित किए जाने वाले लोगों को संबद्ध विभागों तथा अभिकरणों के साथ विचार-विमर्श कर चुना गया। योजना बनाते समय संस्थान की परिप्रेक्ष्य योजना में दी गई प्राथमिकताओं का विशेष ध्यान रखा गया। काफी पहले कार्यक्रम सूची सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, प्रशासकों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य संबद्ध संस्थानों को भेज दी गई थी। इस सूची में विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी तिथि आदि के साथ दी गई थी। कुल मिलाकर 52 कार्यक्रम चलाए गए। इसके पहले वाले वर्षों में कार्यक्रमों की संख्या 47 तथा 44 थी।

वर्तमान सत्र (1984-85) के कार्यक्रम

सत्र 1984-85 के दौरान चलाए गए कार्यक्रमों की सामान्य वर्गीकृत सूची नीचे दी जा रही है :

1. स्कूल शिक्षा की योजना और प्रशासन	9 कार्यक्रम
2. उच्च शिक्षा की योजना और प्रशासन	7 कार्यक्रम
3. शैक्षिक प्रबंध पर कार्यक्रम	5 कार्यक्रम

4. तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध	3 कार्यक्रम
5. प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा की योजना तथा प्रशासन	3 कार्यक्रम
6. शैक्षिक योजना	3 कार्यक्रम
7. शैक्षिक वित्त का प्रबंध	2 कार्यक्रम
8. शैक्षिक नीति	4 कार्यक्रम
9. अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रम	4 कार्यक्रम
10. अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	12 कार्यक्रम
कुल योग	52 कार्यक्रम

ऊपर दी गई सूची से स्पष्ट होता है कि 52 कार्यक्रमों में से 40 कार्यक्रम राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक हैं तथा शेष 12 अंतर्राष्ट्रीय हैं।

सत्र 1984-85 के दौरान संस्थान द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा संलग्नक 1 में दिया गया है। नीचे उन कार्यक्रमों की सूची दी गई हैं, जो इस सत्र में संस्थान में चलाए गए थे :

अ. राष्ट्रीय/प्रादेशिक कार्यक्रम

1 वर्गीकरण	2 तिथि तथा अवधि	3 भागीदारों की संख्या	4 कार्यक्रम व्यक्ति दिवस
स्कूल शिक्षा की योजना और प्रबंध			
1. एयरफोर्स के शिक्षाधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में अभिविन्यास कार्यक्रम	अप्रैल 2-29, 1984 (18 दिन)	36	648
2 जिला शिक्षाधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में तीसरा कार्यक्रम	जुलाई 2, 1984— जनवरी 28, 1985 (184 दिन)	24	4416
3. सीधे भर्ती किए गए उत्तर प्रदेश के शिक्षाधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में अभिविन्यास कार्यक्रम	सितंबर 17—अक्तूबर 1, 1984, (15 दिन)	3	45
4. पोर्टब्लेयर (अण्डमान निकोबार) के शिक्षाधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में अभिविन्यास कार्यक्रम	अक्तूबर 10-20, 1984 (11 दिन)	30	330
5. असम के स्कूल प्राचार्यों का अभिविन्यास कार्यक्रम	नवंबर 5-23, 1984 (17 दिन)	17	323

1	2	3	4
6. वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में अभिविन्यास कार्यक्रम	जनवरी 7-25, 1985 (19 दिन)	10	190
7. असम के स्कूल प्राचार्यों के लिए शैक्षिक प्रबंध में अभिविन्यास कार्यक्रम	जनवरी 21—फरवरी 8, 1985 (19 दिन)	29	512
8. वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में अभिविन्यास कार्यक्रम	फरवरी 11-28, 1985 (18 दिन)	8	144
9. पांडिचेरी के माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के लिए संस्थागत नियोजन पर कार्यशिविर	फरवरी 25—मार्च 2, 1985 (छः दिन)	26	156
उच्च शिक्षा की योजना और प्रशासन			
10. महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में विज्ञान कार्यक्रमों की योजना और प्रबंध की समस्याएं और मुद्दे	14 अगस्त, 1986 (एक दिन)	7	7
11. कालेज प्राचार्यों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में अभिविन्यास कार्यक्रम	सितंबर 4-24, 1984 (सात दिन)	35	735
12. कॉलेजों में शिक्षण पद्धतियों पर राष्ट्रीय कार्यशिविर (यूनेस्को/ यूजीसी)	अक्तूबर 8-14, 1984 (सात दिन)	29	203
13. महिला कॉलेज प्राचार्यों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में अभिविन्यास कार्यक्रम	दिसंबर 31, 1984—जन० 20, 1986 (इक्कीस दिन)	20	420
14. कश्मीर विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्षों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में अभिविन्यास कार्यक्रम	फरवरी 4-22, 1985	9	171
15. कॉलेज प्राचार्यों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में अभिविन्यास कार्यक्रम	फरवरी 4-24, 1985	28	588

1	2	3	4
16. कॉलेजों के विज्ञान विभागाध्यक्षों के लिए विज्ञान शिक्षा की योजना और प्रबंध में अभिविन्यास कार्यक्रम	मार्च 11-16, 1985 (छः दिन)	31	186
शैक्षिक प्रबंध			
17. महिला बहुशिल्प विद्यालयों के सर्वेक्षण साधन विनियोग पर कार्यशिविर	अप्रैल 18-19 1984, (दो दिन)	17	34
18. केंद्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षाधिकारियों के लिए शैक्षिक प्रबंध में अभिविन्यास कार्यक्रम	मई 21-जून 1, 1984 (बारह दिन)	25	300
19. विश्वविद्यालय प्रशासन की नवाचारी दृष्टि पर कार्यशिबिर	मई 28-जून 5, 1984 (नौ दिन)	14	126
20. केंद्रीय विद्यालय संगठन के सहायक आयुक्तों के लिए प्रबंध विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिसंबर 3-14, 1984 (बारह दिन)	24	288
21. निर्णय तथा नेतृत्व पर कार्यशिविर	फरवरी 25-28, 1985 (चार दिन)	22	88
तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध			
22. महिला बहुशिल्प विद्यालयों के शिक्षकों और प्रशसकों के लिए माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण तथा तकनीकी शिक्षा में अभिविन्यास	अप्रैल 9-11, 1984 (तीन दिन)	17	51
23. इंजीनियरिंग कॉलेज स्तर के प्रबंध पर संगोष्ठी	अगस्त 13-18, 1984 (छः दिन)	14	84
24. 2 स्तर पर शिक्षा के व्यवसायीकरण की योजना और प्रबंध में अभिविन्यास कार्यक्रम	जनवरी 28- फरवरी 1, 1985	46	230

1	2	3	4
प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा की योजना तथा प्रशासन			
25. अनौपचारिक शिक्षा के वैकल्पिक प्रशासनिक मॉडलों पर राष्ट्रीय कार्यशिविर	अप्रैल 9-13, 1984 (पांच दिन)	33	165
26. प्रौढ़ शिक्षा के उच्चाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना और प्रबंध पर कार्यशिविर	अगस्त 6-10, 1984 (पांच दिन)	37	185
27. अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के मूल्यांकन अध्ययन पर तकनीकी कार्यशिविर	मार्च 18-20, 1985 (तीन दिन)	14	42
शैक्षिक योजना			
28. पर्यावरण नियोजन और प्रौद्योगिकी केंद्र (स्कूल फार प्लानिंग), अहमदाबाद के लिए ग्रीष्मकालीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम	मई 7-जुलाई 7, 1984 (ल।सठ दिन)	2	124
29. शिक्षा में सातवीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	जून 4-15, 1984 (बारह दिन)	16	192
30. प्रोजेक्शन तथा फोरकास्टिंग तकनीक पर कार्यशिविर	मार्च 18-22, 1985 (पांच दिन)	16	80
शैक्षिक वित्त का प्रबंध			
31. राज्य सरकारों के अधिकारियों के लिए वित्तीय प्रबंध में अभिविन्यास कार्यक्रम	अगस्त 20-31 (बारह दिन)	8	96
32. विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारियों के लिए शैक्षिक वित्तीयन पर अभिविन्यास कार्यक्रम	फरवरी 4-9, 1985 (छः दिन)	32	192

1	2	3	4
शैक्षिक नीति			
33. आश्रम विद्यालयों के प्रशासन पर अभिविन्यास कार्यक्रम	मई 7-11, 1984 (पांच दिन)	25	125
34. "शिक्षा में निष्पक्षता के सूचक" विषय पर अभिविन्यास कार्यक्रम	सितंबर 24-28, 1984 (पांच दिन)	19	95
35 प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की योजना और प्रबंध पर प्रशिक्षण कार्य शिविर	अक्तूबर 15-19, 1984 (पांच दिन)	17	85
36. प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए समुदाय की भागीदारी पर राष्ट्रीय कार्यशिविर	दिसंबर 3-14, 1984 (बारह दिन)	21	252
अन्य कार्यक्रम			
37. "प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण" योजना में काम करने वाले क्षेत्र कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	जुलाई 31, अगस्त 3, 1984 (चार दिन)	3	12
38. धूमरहित चूल्हों के संबंध में गांव की महिलाओं को प्रशिक्षण	अगस्त 30-31, 1984 (दो दिन)	10	20
39. बीस गांवों की महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए कार्यक्रम	मार्च 18-19, 1985 (दो दिन)	18	36
40. मध्यप्रदेश का अंतर्राज्यीय अध्ययन दौरा	फरवरी 4-9, 1985 (छः दिन)	20	120
	ब. अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम		
41. एशियाई प्रशिक्षार्थियों का शैक्षिक योजना और प्रशासन में उन्नत प्रशिक्षण के एक हिस्से के रूप में अध्ययन दौरा	जून 18-22, 1984 (पांच दिन)	13	65
42. संयुक्त राज्य अमरीका के सामाजिक अध्ययन के पर्यवेक्षकों तथा पाठ्यक्रम परामर्शदाताओं के लिए भारतीय इतिहास और संस्कृति पर कार्यशिविर	जुलाई 3—अगस्त 10 1984 (उन्तालीस दिन)	16	624

1	2	3	4
43. फिलीफांइस के शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय ओ पी एस के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	अगस्त 2-सितंबर 9, 1984 (उन्नतालीस दिन)	1	39
44. श्रीलंका, बंगलादेश और भारत के शैक्षिक प्रबंध के प्रशिक्षकों के लिए अंतर्देशीय अध्ययन दौरा	सितंबर 24-28, 1984 (पांच दिन)	3	15
45. श्रीलंका के अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में प्रशिक्षण कार्यक्रम	नवंबर 3, 1984 जनवरी 3, 1985 (तैंतीस दिन)	14	462
46. भूटान के अधिकारियों के लिए कार्यालय प्रबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम	जनवरी 1, मार्च 31 1984 (नब्बे दिन)	1	90
47. बंगला देश के यू पी ई परियोजना अधिकारियों का अध्ययन दौरा	जनवरी 14-21, 1985 (आठ दिन)	8	64
48. शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम	जनवरी 14-जुलाई 13, 1984	11	836
49. अध्यापकों के प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास तथा शैक्षिक योजनाकारों के लिए पर्यावरण शिक्षण के बारे में परामर्शकारी बैठक	फरवरी 11-15, 1985 (पांच दिन)	8	40
50. अफगानिस्तान के अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में प्रशिक्षण कार्यक्रम	मार्च 4-मई 4, 1984 (चौंतीस दिन)	6	204
51. बंगलादेश के अधिकारियों का अध्ययन दौरा	मार्च 8-15, 1985 (आठ दिन)	8	64
52. श्रीलंका के क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों का अभिविन्यास कार्यक्रम	मार्च 20-मई 4, 1984 (चौंतीस दिन)	6	204
53. शिक्षा अधिकारी (थाईलैंड) के लिए दीर्घकालीन शैक्षिक योजना में प्रशिक्षण कार्यक्रम	मार्च 5-अगस्त 31 1985 (27 दिन)	1	27
	378 दिन	96	2734

टिप्पणी : अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने वाले 96 भागीदारों में से चार लोग भारतीय थे।

व्यापक भागीदारी

संस्थान में 1984-85 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में लगभग सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 709 भागीदार थे। क्षेत्रवार भागीदारी का विवरण नीचे दिया गया है :

क्षेत्र	संख्या
उत्तरी क्षेत्र	265
पूर्वी क्षेत्र	193
पश्चिमी क्षेत्र	128
दक्षिणी क्षेत्र	123
योग	709
केंद्र सरकार तथा अन्य राष्ट्रीय संस्थाएं	106
अन्य देश	91
कुल योग	906

राज्यों में अधिकतम भागीदारी जम्मू तथा कश्मीर की थी। उसके बाद क्रमश: असम, दिल्ली, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश की भागीदारी थी। फिर भी गौर करने की बात यह है कि संस्थान के विभिन्न कार्यक्रमों में कई अन्य राज्यों की तुलना में शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों से अधिक लोगों ने भाग लिया। राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के अलावा निम्नांकित दूसरी संस्थाओं से भी 106 लोगों ने इसमें भाग लिया : भारत सरकार के अधिकारी, तथा राष्ट्रीय स्तर की अन्य संस्थाओं के लोग जैसे एन सी ई आर टी, योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ज ने वि, दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, एयरफोर्स का शिक्षा विभाग आदि।

सोलह देशों के 91 लोगों ने कार्यक्रमों में भाग लिया, देश के अनुसार उनका विवरण नीचे दिया गया है :

देश का नाम	भागीदारों की संख्या
अफगानिस्तान	7
बंगलादेश	18
भूटान	4
चीन	2
इंडोनेशिया	1
ईरान	1
जापान	1
कुवैत	1
मलेशिया	2
मारिशस	1
नेपाल	1
पाकिस्तान	1
फिलिपांइस	1
श्रीलंका	29
थाईलैंड	6
संयुक्त राज्य अमरीका	16

कार्यक्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए वर्तमान सत्र के दौरान चलाए गए कार्यक्रमों में भागीदारों की संख्या, कार्यक्रम दिवस, कायंक्रम व्यक्ति दिवस आदि नीचे की सारणी में दिए गए :

वर्गीकरण **राष्ट्रीय/प्रादेशिक**

कार्यक्रम	भागीदारों की संख्या	कार्यक्रम दिवस	कार्यक्रम व्यक्ति दिवस
1	2	3	4
1. स्कूल शिक्षा की योजना और प्रशासन (9 कार्यक्रम)	182	309	6764
2 उच्च शिक्षा की योजना और प्रशासन (7 कार्यक्रम)	159	96	2310
3. शैक्षिक प्रबंध पर कार्यक्रम (5 कार्यक्रम)	102	40	858
4. तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के प्रबंध पर कार्यक्रम (5 कार्यक्रम)	77	14	356
5. शैक्षिक योजना पर कार्यक्रम (3 कार्यक्रम)	84	13	392
6. प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा की योजना और प्रशासन पर कार्यक्रम (3 कार्यक्रम)	34	79	396
7. शैक्षिक वित्त के प्रबंध पर कार्यक्रम (2 कार्यक्रम)	40	18	288
8. शैक्षिक नीति पर प्रशिक्षण कायक्रम (4 कार्यक्रम)	82	27	557
9. अन्य कार्यक्रम 4 कार्यक्रम	55	14	188
	अंतर्राष्ट्रीय		
10. शैक्षिक योजना और प्रशासन में उन्नत कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन दौरे तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान संबंधी कार्यक्रम (13 कार्यक्रम)	96	378	2707
53 कार्यक्रम कुल योग	907	1015	14852

*अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के 96 भागीदारों में से 4 भागीदार भारतीय थे।

डिप्लोमा पाठ्यक्रम

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान निम्नांकित दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाए गए :

(अ) भारत के जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम; और

(ब) अन्य देशों के अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा।

(अ) जिला शिक्षाधिकारियों के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम : नीपा द्वारा आयोजित जिला शिक्षा अधिकारियों का यह तीसरा डिप्लोमा पाठ्यक्रम था। पहला कार्यक्रम 1982-83 तथा दूसरा कार्यक्रम 1983-84 में आयोजित किया गया था। पहले दो कार्यक्रमों में प्रत्येक में 29 व्यक्तियों की भागीदारी थी, तीसरे कार्यक्रम में भागीदारों की संख्या 24 थी। तीसरे कार्यक्रम में भागीदारों का राज्यवार ब्योरा नीचे दिया गया है :

प्रदेश/केंद्रशासित प्रदेश	संख्या
आंध्र प्रदेश	2
मध्यप्रदेश	3
महाराष्ट्र	1
मणिपुर	4
पंजाब	2
राजस्थान	3
सिक्किम	2
तमिलनाडु	1
उत्तर प्रदेश	3
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1
दिल्ली	2
कुल संख्या	24

वर्तमान डिप्लोमा पाठ्यक्रम तीन अलग-अलग चरणों में विभाजित करके चलाया गया था :

(i) संस्थान में रह कर 3 महीने का गहन पाठ्यक्रम अध्ययन (जुलाई 2—सितम्बर 28, 1984)

(ii) प्रशिक्षणार्थी के अपने जिले में 4 महीने का पर्यवेक्षित परियोजना कार्य (अक्तूबर 1, 1984-जनवरी 28, 1985)

(iii) प्रशिक्षार्थियें द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट पर संस्थान में चार दिनों का कार्यशिविर (फरवरी 28-21, 1985)

इस कार्यक्रम में कुल 28 क्रेडिट अंक निर्धारित थे। इनमें 26 क्रेडिट अंक प्रज्ञिक्षार्थी के नीपा पाठ्यक्रम कार्य के लिए निश्चित थे तथा 22 अंक प्रशिक्षार्थी के अपने कार्य-क्षेत्र में किए गए परियोजना कार्य के लिए थे।

प्रथम और द्वितीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रशिक्षार्थियों से प्राप्त समीक्षात्मक टिप्पणियों के आधार पर पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तथा उसके खाकों का पुनरीक्षण किया गया है और उसमें जरूरी सुधार किए गए हैं। तीसरे कार्यक्रम में एक नई बात जोड़ी गई है। इसके तहत हर भागीदार को एक कार्य योजना सिंडीकेट

कार्य के रूप में चलाई गई। है यह कार्य उसके अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित होगा। कार्य योजना में जो विषय शामिल किए गए थे उनमें कुछ इस प्रकार हैं : जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों में संदर्भों का तात्कालिक निपटान; जिला अमरावती के लिए एक कार्य योजना; जिला शिक्षाधिकारी के कार्यालय के कर्मचारियों की वक्त की पाबंदी को सुनिश्चित करना : (पूर्व), गंगटोक; राजस्थान के सीकर जिले में माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अंकेक्षण आपत्तियों से निपटना; महबूब नगर जिले में नगरों की गंदी बस्तियों के प्राइमरी स्कूलों की नामांकन और छात्रों को रोक रखने की समस्याओं से निपटना; कोटा जिले के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रशासन को प्रभावी बनाना; मणिपुर के बिशनपुर जिले के हाईस्कूलों में प्रधानाचार्यों के पर्यवेक्षण को प्रभावी बनाने के लिए योजना आदि। भागीदारों ने विविध विषयों पर संगोष्ठी आलेख भी लिखे जिन पर भागीदारों की संगोष्ठियों में पढ़कर बहस की गई। उन्होंने जिला योजनाएं भी बनाईं। शिक्षा में नवीन विकास के प्रति भागीदारों को संवेदनशील बनाने के अतिरिक्त, उनको पर्यवेक्षण तथा प्रशासन की आधुनिक तकनीकों से भी परिचित कराया गया जिसमें कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना, अंतर कर्मचारी संबंध, निर्णय करना, विवाद प्रबंध, सदाचार आदि भी शामिल थे। कुछ भागीदारों के परियोजना कार्य का स्तर अत्यंत उन्नत था।

कुल 24 भागीदारों में से 21 भागीदारों ने पाठ्यक्रम की अत्यंत सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है तथा उनको डिप्लोमा उपाधि से संस्थान ने सम्मानित भी किया हैं। इनमें से दो लोग कार्यक्रम के तीसरे चरण में अपनी परियोजना रिपोर्ट जमा नहीं कर सके क्योंकि वे कुछ समय के लिए विदेश चले गए तथा परियोजना रिपोर्ट जमा करने के लिए उन्होंने और समय मांगा। उन्होंने बाद में अपना काम पूरा कर दिया तथा चौथे पाठ्यक्रम के भागीदारों के साथ उन्हें भी डिप्लोमा प्रदान किया गया।

(ब) शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा : तीसरी दुनिया के देशों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर जनवरी 1985 से शैक्षिक योजना और प्रशासन में एक अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा (आई डी ई पी ए) शुरू किया गया। यह छः महीने का डिप्लोमा कार्यक्रम है। इसको दो चरणों में बांटा गया है, (i) नीपा में रहकर तीन माह का पाठ्यक्रम संबंधी अध्ययन, (ii) तीन महीने का अपने कार्यक्रम में पर्यवेक्षित परियोजना कार्य।

भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षामंत्री श्री कृष्णचंद्र पंत ने 14 जनवरी, 1985 को इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में मंत्री महोदय ने उन आधारभूत समस्याओं की समानता को रेखांकित किया जिसका सभी तीसरी दुनिया के देश सामना कर रहे हैं तथा इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया कि शिक्षा का निरूपवेक्षीकरण (डीकालोनाइजेशन) किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तीसरी दुनिया की शिक्षा प्रणाली एक भिन्न ऐतिहासिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में निर्मित हुई थी उसमें छोटी-मोटी खामियां अवरोध पैदा कर रही हैं इसलिए वे वर्तमान तथा भविष्य दोनों आवश्यकताओं के लिए निष्क्रिय साबित हो रही हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नीपा द्वारा शुरू किया गया नया अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, जिसमें तीसरी दुनिया की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है, न सिर्फ इन देशों की मैत्री को सुदृढ़ करेगा, बल्कि इन देशों के शिक्षा कर्मियों के कार्यों को व्यावसायिक दृष्टि प्रदान करेगा तथा इस प्रकार उनके विकास की गति को तेज करने में मदद करेगा।

प्रथम अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में निम्नलिखित देशों के निम्नांकित भागीदारों ने भाग लिया था :

देश	भागीदारों की संख्या
अफगानिस्तान	1
श्रीलंका	6
भूटान	3
मारिशस	1
कुवैत	1
कुल	12

काफी सोच-समझ कर इसके पाठ्यक्रम का खाका तैयार किया गया। इसके पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटा गया था : (i) मुख्य कोर्स (ii) विशेषज्ञता का पाठ्यक्रम। मुख्य पाठ्यक्रम में शैक्षिक योजना प्रशासन की आधारभूत संकल्पनाओं और तकनीकों को रखा गया था, विशेषज्ञता वाले हिस्से में भागीदार द्वारा चुने गए किसी खास क्षेत्र में किए जाने वाले कार्य को रखा गया था। इस पाठ्यक्रम में जो विभिन्न विषय लिए गए, वे इस प्रकार थे : शैक्षिक योजना का मात्रात्मक पक्ष, परियोजना का नियोजन, संचारेक्षण तथा मूल्यांकन, संगठनात्मक व्यवहार, कार्मिक प्रबंध, वित्तीय प्रबंध, कार्यालय प्रबंध इत्यादि। पाठ्यक्रम के अकादमिक विषय के पूरक के रूप में विभिन्न दौरों का आयोजन किया गया। इन दौरों में स्कूलों का दौरा, दिल्ली की बड़ी संस्थाओं का दौरा तथा बिहार, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र का दौरा शामिल हैं। इन क्षेत्र भ्रमणों का आयोजन भागीदारों को भारतीय परिस्थितिवों की प्रत्यक्ष जानकारी के लिए किया गया था जिससें वे अपने देश की समस्याओं के समाधान के लिए प्रासंगिक निष्कर्ष प्राप्त कर सके।

भागीदारों की फीस तथा अन्य खर्चे यू एन डी पी, कामनवेल्थ फंड फार टेकनिकल क्वापरेशन, स्विडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एथारिटी तथा कुवैत सरकार ने वहन किए।

प्रथम कार्यक्रम के समापन के समय 12 अप्रैल 1985 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सचिव श्री आनंदस्वरूप ने विदाई भाषण दिया।

प्राथमिकता के क्षेत्र

प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण, प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा, तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की विकास पूरक जरूरतों की पूर्ति के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा कर्मियों के लिए इस वर्ष अभिविन्यास कार्यक्रम चलाए गए।

अक्तूबर 1984 में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की योजना और प्रबंध पर एक प्रशिक्षण कार्य-शिविर आयोजित किया गया। इसमें प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल दिया गया। इसमें भाग लेने वाले लोग देश के विभिन्न भागों के शिक्षा संस्थानों / राज्य शैक्षिक अनुसंधानों और प्रशिक्षण परिषदों के लोग थे। इसमें भागीदारों को प्रशिक्षण की तकनीक बताने के अलावा प्रथम पंचवर्षीय योजना से छटी योजना तक में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण का, उपलब्धियों तथा असफलताओं को ध्यान में रखते हुए, पुनरीक्षण किया गया। भागीदारों को प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के गुणात्मक और मात्रात्मक पक्षों के संचारेक्षण तथा मूल्यांकन की तकनीकों की भी जानकारी कराई गई।

यूनेस्को के सहयोग से दिसबर 1984 में सार्वजनीन प्रारंभिक शिक्षा में समुदाय की भागीदारी पर एक राष्ट्रीय कार्यशिविर आयोजित किया गया। इस कार्यशिविर में राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में निचले

स्तर के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में संलग्न व्यक्तियों को प्रशिक्षण माडल बनाने में लगाया गया। इन प्रशिक्षण माडलों में जिन विषयों को लिया गया था, वे इस प्रकार थे : व्यष्टि स्तर की योजना और प्रबंध, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के विशेष संदर्भ में शिक्षा में समुदाय की भागीदारी में विशेष प्रयोग तथा नवाचार, प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम और प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के बीच संपर्क तथा समन्वय।

ग्रामांचलों को खासतौर से ध्यान में रखकर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की तीव्र उपलब्धि के लिए दो विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें से एक कार्यक्रम अगस्त 1984 में किया गया था। इसमें मेवात (गुडगांव) क्षेत्र के आठ गांवों की महिलाओं ने भाग लिया था। जैसे : ग्राम सेवक, प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा के अधिकारी तथा आंगनबाड़ी के प्रभारी अधिकारी। स्वास्थ्य कर्मचारियों तथा अन्य अभिकरणों को इसमें शामिल करके इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नवाचारी दृष्टियां अपनाई गईं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान स्वास्थ्य शिक्षा के साथ एकीकरण तथा धूमरहित चूल्हों का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम से प्रौढ़ों में क्रियात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद मिली। चूंकि इनमें से एक कार्यक्रम में बहुत सी निरक्षर महिलाओं ने भाग लिया था, प्रशिक्षण की अनौपचारिक विधि का प्रयोग किया गया।

क्रमशः अप्रैल तथा अगस्त 1984 में दो राष्ट्रीय कार्यशिविर आयोजित किए गए : पहला अनौपचारिक शिक्षा के लिए वैकल्पिक प्रशासनिक माडल विकसित करने से संबंधित था और दूसरा प्रौढ़ शिक्षा के उच्च अधिकारियों के लिए योजना और प्रबंध संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित। प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम भारत सरकार के प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के सहयोग से आयोजित किया गया। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की नई विधियों (उपागमों), प्रौढ़ शिक्षा का अन्य विकास विभागों से समन्वय, साक्षरता के बाद की स्थिति के लिए संचार माध्यमों का इस्तेमाल तथा प्रौढ़ शिक्षा में अनुवर्ती कार्य से इसके भागीदारों को परिचित कराया गया। भागीदारों ने अपनी-अपनी स्थितियों के लिए प्रासंगिक कार्य योजनाएं बनाईं। देश के विभिन्न राज्यों में प्रचलित वैकल्पिक संगठनात्मक प्रथा को, अनौपचारिक शिक्षा के प्रशासनिक माडल पर होने वाले कार्यशिविर में तलाशा गया। इसमें पता चला कि जहां कुछ राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अंग के रूप में काम कर रहा है वहीं कुछ अन्य राज्यों में इसको प्रौढ़ शिक्षा के साथ संबद्ध कर दिया गया है। कार्यशिविर में ऐसा महसूस किया गया कि माडल चाहे कोई भी रखा जाए लेकिन भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा प्रौढ़ निरक्षरता के उन्मूलन के लिए, अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में समन्वित दृष्टि अपनाना लाभकारी होगा।

चूंकि उचित शैक्षिक विकास के लिए शिक्षा की बेइंसाफी को समाप्त करना महत्वपूर्ण है, इसलिए मई 1984 में आश्रम स्कूलों के प्रशासन पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। और शिक्षा में न्याय पर एक कार्यक्रम सितंबर 1984 में आयोजित किया गया। इसमें स्त्री-पुरुष, ग्रामीण-नगरीय, अनुसूचित जाति तथा गैर अनुसूचित जाति के बीच असमानताओं को दूर करने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित रखा गया।

कार्य के नए क्षेत्र

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के प्रबंध पर विशेष ध्यान दिया गया। अप्रैल 1984 में कश्मीर की महिला पोलिटेकनीक की शिक्षिकाओं तथा प्रशासकों के लिए एक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। फरवरी, 1985 में +2 स्तर के शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना और प्रबंध पर एक अन्य अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन दोनों ही कार्यक्रमों में न सिर्फ शिक्षा को काम से

जोड़ने के अवधारणात्मक ढांचे पर काम किया गया बल्कि इसकी योजना और प्रबंध पक्षों पर भी कार्य हुआ जैसे रोजगार पर सर्वेक्षण कराना, सार्थक पाठ्यक्रमों की तलाश, विकास के साथ रोजगार पर शिक्षा के संबंध, रोजगार परक संस्थाओं से आने वाले छात्रों की ऊर्ध्वीय गतिशीलता, अवसंरचनात्मक सुविधाओं का प्रबंध, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें आदि। इसका उद्देश्य रोजगार परक शिक्षा को प्रभावी बनाना था।

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, अगस्त 1984 में देश के विभिन्न भागों के इंजीनियरिंग कालेजों के प्राचार्यों के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय तकनीकी शिक्षा संगठन के सहयोग से किया गया था। भागीदारों को जिन विषयों में दक्षता के लिए प्रशिक्षित किया गया वे विषय इस प्रकार हैं : इंजीनियरिंग कालेज का संगणक के विशेष संदर्भ में प्रबंध, प्रशिक्षण तथा नियुक्ति, सतत शिक्षा, कर्मचारी विकास और संसाधनों का प्रबंध आदि। कार्यशाला के उपकरणों के पुराने पड़ने तथा उनकी उपयोगिता पर भी विचार विमर्श किया गया।

उच्च शिक्षा में तीन नए कार्यक्रम चलाए गए वे कार्यक्रम इस प्रकार थे :

(i) कश्मीर विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्षों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में अभिविन्यास कार्यक्रम (फरवरी 1985)

(ii) कॉलेजों के विज्ञान विभागाध्यक्षों के लिए विज्ञान शिक्षा की योजना और प्रबंध विषय में अभिविन्यास कार्यक्रम (मार्च 1985)

(iii) कॉलेजों में शिक्षण पद्धति पर कार्यशिविर : यू जी सी और यूनेस्को द्वारा प्रायोजित (अक्तूबर, 1984)

इन सभी कार्यक्रमों में संपूर्ण संस्थागत प्रबंध की तुलना में कार्यक्रमों तथा विभागों के प्रबंध पर विशेष बल दिया गया था। कश्मीर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों का केस अध्ययन किया गया। ये विभाग थे : क्षेत्रीय विकास और भूगोल विभाग; बायो रसायन विभाग, भौतिकी विभाग, तथा अर्थशास्त्र विभाग। इस अध्ययन का उद्देश्य था योजना तथा प्रबंध की समस्याओं की पहचान करना, पाठ्यक्रमों का विस्तार तथा उनका पुनर्गठन, विभिन्न विभागों की कार्यक्षमता में सुधार करना। विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में इकाई लागत तथा अनुदान के लिए मानदंड विषय पर एक अध्ययन हाथ में लिया गया।

मार्च 1985 में विषय की आधार बनाकर दो कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे प्रोजेक्शन तथा अनुमान तकनीक पर कार्यशिविर तथा नेतृत्व और निर्णय। पहले कार्यशिविर में राज्य शिक्षा विभागों की योजना इकाइयों के लोगों ने भाग लिया। इनको प्रोजेक्शन तथा अनुमान में अभिविन्यास किया गया। इसमें छात्रागमन विश्लेषण, मल्टीपुल रिग्रेशन तथा संगणक का प्रयोग शामिल थे। दूसरे कार्यक्रम में कॉलेजों के प्रधान, पालिटेकनीक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रधानों ने भाग लिया। इन लोगों को निर्णय लेने, कार्मिकों के आपसी संबंध, प्रेरणा, संप्रेषण, संगठनात्मक सुधार संबंधी दक्षता से परिचित कराया गया।

चल रहे कार्यक्रम

जिला शिक्षाधिकारियों के डिप्लोमा कार्यक्रम चलाने के अलावा इस सत्र के दौरान संस्थान ने कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए जो अब भी जारी हैं। उनके विषय में नीचे दिया गया है :

(अ) कालेज प्रचार्यों का अभिविन्यास कार्यक्रम : तीन सप्ताह की अवधि वाले अलग-अलग तीन कार्यक्रम, एक महिला कालेज प्राचार्यों के लिए दूसरा उन कालेजों के प्राचार्यों के लिए जिन कालेजों में अनुसूचित

National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D-9365
Date 5-12-86

जातियों/जनजातियों के छात्रों की संख्या अधिक है तथा तीसरा अन्य कालेजों के प्राचार्यों के लिए।

(ब) वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम : इसमें तीन-तीन सप्ताह की अवधि वाले दो कार्यक्रम हैं।

(स) असम के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए संस्थागत प्रबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक कार्यक्रम तीन सप्ताह अवधि का था।

(द) विश्वविद्यालयों का वित्तीय प्रबंध विषय पर अभिविन्यास कार्यक्रम : दो कार्यक्रम, एक कार्यक्रम एक सप्ताह अवधि का विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारियों के लिए तथा दूसरा दो सप्ताह अवधि का कार्यक्रम राज्य सरकारों के वित्त अधिकारियों के लिए।

(य) केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम (दो कार्यक्रम) एक कार्यक्रम केंद्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षा अधिकारियों के लिए तथा दूसरा केंद्रीय विद्यालय संगठन के सहायक आयुक्तों के लिए (दो सप्ताह अवधि)

(फ) उत्तर प्रदेश में सीधे भर्ती किए गए शिक्षा अधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्य : दो सप्ताह की अवधि का एक कार्यक्रम

अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान, पेरिस, भारत के संयुक्त राज्य अमरीकी शैक्षिक न्यास, नई दिल्ली, यूनेस्को तथा प्रशांत क्षेत्र के तथा तीसरी दुनिया के संगठनों के अनुरोध पर संस्थान कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करता है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान शैक्षिक योजना और प्रशासन में पहला डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित करने के अलावा संयुक्त राज्य अमरीका के समाज विज्ञान शिक्षण के पर्यवेक्षकों तथा पाठ्यक्रम परामर्श-दाताओं के लिए भारतीय इतिहास और संस्कृत पर एक कार्यशिविर चलाया (इस शृंखला में 7 वां)। शैक्षिक योजना और प्रबंध में प्रमुख पदों के प्रशिक्षकों के लिए (एशियाई क्षेत्र के लिए) अंतरदेशीय दौरों का आयोजन किया तथा फिलिपाइन्स के, शिक्षा मंत्रालय के योजना सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

बंगलादेश सरकार के अनुरोध पर संस्थान ने वहां के प्राइमरी स्कूल शिक्षा अधिकारियों के दो अध्ययन दौरों को स्वीकृति प्रदान की। पहली जनवरी तथा दूसरी मार्च 1985 में थी। इन दोनों दौरों की अवधि दस दिनों की थी। प्रत्येक दौरे में 8 यू पी ई शामिल थे। बंगलादेश के शिक्षा अधिकारियों को विभिन्न नवाचारी कार्यों से परिचित कराया गया जिनके द्वारा भारत सार्वजनीन प्राइमरी शिक्षा को प्राप्त करना चाहता है।

यूनेस्को, पेरिस के आमंत्रण पर पाठ्यक्रम विकास तथा शिक्षक प्रशिक्षकों और शैक्षिक योजनाकारों तथा पर्यावरण शिक्षण के प्रशिक्षण विषय पर परामर्शदात्री समिति की एक बैठक हुई। दक्षिण एशिया और प्रशांत क्षेत्र के दस वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

सामग्री की तैयारी

सभी कार्यक्रमों की सामग्री की तैयारी के लिए काफी पहले से कदम उठाए गए थे। इसमें सामग्री थी : सूचना निर्देशिका चुनी हुई टिप्पणी के साथ पाठ्यसामग्री सूची आदि। इन पाठ्यक्रमों में भी तरह-तरह की सामग्री प्राप्त हुई जैसे अध्ययन रिपोर्ट, राज्य/जिला दस्तावेज, केस अध्ययन और कार्य योजनाएं। डिप्लोमा पाठ्यक्रम में भागीदारों द्वारा तैयार की गई अनुसंधान अध्ययनों की रिपोर्टों को टंकित कराकर वितरित किया गया। कुछ में संबंधित पुस्तकों तथा सामग्री की प्रदर्शनी आयोजित की गई। भागीदारों को क्षेत्र दौरों पर उचित स्थानों पर ले जाया गया। ये यात्राएं दिल्ली में तथा दिल्ली के बाहर भी थीं। इन यात्राओं का विभिन्न संस्थाओं, जिनमें स्कूल कॉलेज और अनौपचारिक शिक्षा केंद्र भी शामिल हैं, को दिखाना था। एन सी ई आर टी, योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आदि को दिखाने के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कुछ भागीदारों को देखते हुए हिंदी में भी प्रशिक्षण सामग्री तैयार की गई।

अंतर विषयी उपागम

लगभग हर कार्यक्रम के लिए एक कृतिक बल बनाया गया जिसमें विभिन्न एककों के सदस्य थे जिससे इसके स्वरूप को अंतर विषयी बनाया जा सके। जबकि कार्यक्रम के प्रबंध का दायित्व अकादमिक इकाइयों में से एक इकाई के जिम्मे था, अन्य अकादमिक इकाइयों ने भी सामग्री आदि के द्वारा इसमें काफी योगदान किया। व्याख्यानों के लिए प्राय: संस्थान अपने संकाय सदस्यों पर निर्भर था लेकिन जहां आवश्यकता पड़ी वहां अतिथि संकायों से बहस के लिए, प्रायोगिक कार्यों और सिंडिकेट कार्यों आदि के लिए, मदद ली गई। प्रशिक्षण की प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल भी काफी मात्रा में किया गया। इनमें संगणक, फिल्म, वीडियो तथा ओवर-हेड प्रोजेक्टर का इस्तेमाल शामिल है। काफी हद तक अनुसंधान और प्रशिक्षण में समन्वय कायम किया गया है। विभिन्न कार्यशिविरों, गोष्ठियों तथा कार्यक्रमों में अनुसंधान परिणामों का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया गया है।

संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में लगातार सहयोगी संस्थाओं जैसे एन सी ई आर टी, केंद्रीय विद्यालय संगठन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों, भारतीय शिक्षा संस्थान, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, आई आई एम एस तथा राज्यों के लोक प्रशासन संस्थान ने मदद की है।

भागीदारों द्वारा कार्यक्रम का मूल्यांकन आमतौर पर पाठ्यक्रम बनाने में किया जाता है। बनी बनाई प्रश्नावलियों तथा अन्य विधियों से भागीदारों से प्राप्त उत्तर काफी सकारात्मक रहे हैं। अपने कुछ कार्यक्रमों के प्रभाव मूल्यांकन से संस्थान काफी प्रभावित रहा है क्योंकि इससे क्षेत्र से उसे टिप्पणियां मिली हैं।

भावी दिशाएं

पहले तीन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सफलता को ध्यान में रखकर, जिनका आयोजन गत तीन सत्रों में संस्थान ने जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए किया है, यह तय किया गया है कि 1985-86 से हर साल एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने की जगह संस्थान प्रत्येक वर्ष छ: माह की अवधि के दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाया करेगा।

चूंकि 1985-86 सातवीं योजना का आरंभिक वर्ष है, सातवीं योजना में प्रस्तावित प्राथमिकताओं पर विशेष बल दिए जाने का प्रस्ताव है। निम्नांकित राष्ट्रीय उपलब्धियों से संबंधित विषयों पर विशेष बल दिया जाएगा : प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण, प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा, निष्पादनोन्मुख प्रशासन, व्यवस्था की आंतरिक क्षमता में वृद्धि, आधुनिक प्रौद्योगिकी का व्यवहार, सूचना प्रबंध व्यवस्था, शैक्षिक विकास में असमानताओं की दूर करना आदि।

सारे देश में बिखरे हुए विभिन्न स्तर के शिक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण देने का काम बहुत ही गुरूतर दायित्व वाला कार्य है। एकदम आधारभूत स्तर के शिक्षा कर्मियों तक पहुंचने के लिए राज्य स्तर के केंद्रों की स्थापना की आवश्यकता हो सकती है जिसका संबंध संस्थान से रहे। वैसी स्थिति में संस्थान की प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर खास ध्यान देना पड़ेगा। संस्थान के लिए अनौपचारिक तरीके अपनाना उतना ही आवश्यक हो सकता है जिससे आमने सामने बैठकर प्रशिक्षण देने की जगह उन सेवारत व्यक्तियों के लिए दूर शिक्षण की व्यवस्था करनी पड़े। किसी विशेष कारण से नियमित कक्षा वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने में असमर्थ हैं।

चूंकि इस समय सरकार नई शिक्षा नीति बनाने में व्यस्त है, आगामी वर्षों में इस नई नीति को साकार करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पहले से ही संस्थान नई शिक्षा नीति के निर्माण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को मदद देने में सक्रिय रूप से संलग्न है।

भाग दो

अनुसंधान और अध्ययन

संस्थान की अनुसंधान संबंधी गतिविधियों की मुख्य दिशा शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में समष्टि और व्यष्टि दोनों ही स्तरों पर आनुभाविक स्थितियों की खोज करना है। इनका लक्ष्य ज्ञान प्रदात करना, सार्थक आंकड़े उपलब्ध करना, लोगों की प्रतिक्रिया प्राप्त करना है। जिससे क्षेत्र की समस्याओं और नीतियों के लिए समाधान खोजा जा सके। अनुसंधान अध्ययनों से प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी लगातार खुराक मिलती रहती है। संस्थान की विशेषज्ञ समिति, राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक सरकारें, आई सी एस एस आर जैसे अनुसंधान संस्था तथा अंतराष्ट्रीय संस्थान इन अध्ययनों के लिए विषय वस्तु का निर्धारण करते हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अनुसंधान और अध्ययन पर सरकारी अनुदान का 4.23 लाख रुपए खर्च हुए इसके पूर्ववर्ती साल में यह रकम 3.60 लाख रुपए थी। अनुदान प्रदत्त अनुसंधान कार्यों के लिए संस्थान ने 7.65 लाख रुपए अन्य स्रोतों से एकत्र किए। अनुसंधान तथा अध्ययन पर कुल व्यय इस वर्ष 11.88 लाख रुपए पहुंच गया। इक्कीस अध्ययन समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पूरे किए गए तथा ग्यारह अध्ययनों का काम प्रगति पर है।

इस वर्ष के दौरान पूरे किए गए अध्ययनों में मुख्य हैं: भारत में शैक्षिक प्रबंध का निदानात्मक अध्ययन, शैक्षिक विकास में क्षेत्रीय असमानता, भारत में शिक्षा संशाधनों की व्यवस्था का अध्ययन, हरियाणा के गुड़गांव जिले में शिक्षा की आपूर्ति लागत, उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की असफलता, टिके रहना तथा बीच में छोड़कर जाने का राष्ट्रीय पार्श्व चित्र, मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की सामाजिक पृष्ठभूमि, जीवन की स्थितियों तथा अकादमिक निष्पादन का राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन, तथा अध्यापकों की स्थिति के विविध पक्षों पर 10 अध्ययन (उच्च शिक्षा आयोग के लिए तकनीकी इनपुट के रूप में किया गया अध्ययन) यहां इस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए कि "भारत में सन् 2000 में शिक्षा : एक दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य" पर, भारत सें शैक्षिक नीति का नियोजन) योजना आयोग की भूमिका, और स्कूलों में छात्र-शिक्षक का अनुपात, इस समय चल रहे हैं।

मेवात क्षेत्र के पुनहाना प्रखण्ड में 20 गांवों में एक कार्य अनुसंधान हाथ में लिया गया है। मेवात शैक्षिक दृष्टि सें अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है।

शिक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नौ राज्यों में प्रारंभिक स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा का मूल्यांकन अध्ययन संस्थान ने हाथ में लिया है। वे राज्य हैं: आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, जम्मू तथा कश्मीर, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल। इस अध्ययन के निष्कर्ष, ऐसी आशा की जाती है, योजना को कार्यक्रम देने में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे। इस प्रकार अनौपचारिक शिक्षा की नीति तथा कार्यक्रम पर इसका महत्वपूर्ण असर पड़ेगा।

संस्थान ने दो कालेजों का मार्गदर्शी अध्ययन कराया है, इसमें एक कालेज दिल्ली का है, दूसरा

गुडगांव का। इसका मकसद है : कॉलेजों के विज्ञान विभागाध्यक्षों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्य सामग्री तैयार करना ताकि उनकी आवश्यकताओं की सार्थक तरीके से पूर्ति की जा सके। इस अध्ययन में निम्नांकित बातों का भी ध्यान रखा गया : स्थान, कर्मचारी, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला की सुविधाएं, शिक्षणात्मक प्रक्रियाएं तथा हरियाणा के नए उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए संकाय की संकल्पना। इसका उद्देश्य है हरियाणा के 250 प्राचार्यों के लिए (कालेज तथा स्कूलों के) प्रशिक्षण आगत प्रदान करना जहां 2 स्तर पर उच्चतर माध्यमिक योजना की शुरूआत की जा चुकी है।

पूरे किए गए अध्ययन

1. भारत में शैक्षिक प्रबंध का निदानात्मक अध्ययन (यूनेस्को प्रायोजित)

यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय बैंकाक के अनुरोध पर यह अध्ययन हाथ में लिया गया था। यह यू एन डी पी समर्थित परियोजना का एक हिस्सा था। वह परियोजना थी, "उन्नत प्रबंध और योजना द्वारा शिक्षा में कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय तकनीक सहयोग का कार्यक्रम।" यह अध्ययन अक्तूबर 1983 में आरम्भ किया गया था और मई 1984 में इसको पूरा कर लिया गया था। इसके अध्ययन दल के सदस्यों के नाम इस प्रकार है : श्री एम एम कपूर, श्री वी ए कालपाण्डेय, श्री चन्द्रप्रकाश तिवारी, तथा डा. श्रीमती प्रमिला मेनन।

इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे : भारत में शिक्षा की वर्तमान संगठन तथा प्रबंध प्रणाली का अध्ययन, काम के ढांचे की सीमाओं, अवरोधों और कमियों को पहचानना, तथा विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के प्रबंध में उठने वाली समस्याओं का समाधान सुझाना। पांच राज्यों मध्य प्रदेश (मध्यवर्ती क्षेत्र), जम्मू तथा कश्मीर (पश्चिमोत्तर क्षेत्र), तमिलनाडु (दक्षिणी क्षेत्र), असम (पूर्वोत्तर क्षेत्र), महाराष्ट्र (पश्चिमी क्षेत्र) से सूचनाएं इकट्ठी की गईं। इसके लिए एक विस्तृत प्रश्नावली का इस्तेमाल किया गया जो शिक्षा के हर पहलू को समेटती है।

इस अध्ययन में जो बातें उद्घाटित हुईं, वे इस प्रकार हैं : कुल शिक्षा की तुलना में निदेशन तथा प्रशासन पर खर्च कम हुआ है यानी 1946-47 में यह 3.2% था लेकिन 1981-82 में यह 2.17% रह गया है, निरीक्षण करने वाले कर्मचारियों की गैर-अकादमिक कार्यों की मात्रा अधिक हो गई है अर्थात् उनके समय का 60% से अधिक इस काम में लगता है। राज्य स्तर के नीचे प्रशासन का कोई सुनिर्धारित ढांचा नहीं है, प्रशासन के हर स्तर पर बहुत अव्यवस्था, कार्यों की पुनरावृत्ति तथा आंकड़ों की जानकारी में समय का अंतराल है, अध्यापकों का तबादला अकादमिक अथवा व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जाता है, सभी संस्थाओं में आत्मकेंद्रीयता की प्रवृत्ति दिखाई देती है, उनका अपने आसपास की सहयोगी संस्थाओं से किसी प्रकार का समन्वय या सहयोग नहीं है।

इसमें सुझाव दिया गया है कि कम से कम शैक्षिक व्यय का 5% इसके प्रशासन और प्रशिक्षण पर खर्च होना चाहिए, वर्तमान प्रशासनिक ढांचे का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए तथा इसका कार्य के आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए, विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिशा को निर्देश और प्रशासनिक ढांचे के लिए रखरखाव के विविध नमूने तथा मानदंड निर्धारित किये जाने चाहिए, प्रभावी विकेंद्रीकरण के लिए राज्य स्तर के नीचे की योजना और प्रशासन को साफ शब्दों में परिभाषित किया जाना चाहिए तथा सामान्य

योजना तथा राज्यस्व प्रशासन की इकाइयों के साथ इसका संबंध होना चाहिए; जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को सुदृढ़ किया जाना चाहिए, समन्वित योजना प्रणाली, खासतौर से जिला स्तर पर, अपनाई जानी चाहिए, शिक्षा में प्रशासनिक पद के लिए योजना तथा प्रशासन के प्रशिक्षण को पूर्वशर्त बनाया जाना चाहिए; जहां तक संभव हो अध्यापक की नियुक्ति नीति विद्यालय या क्षेत्राधारित होनी चाहिए; अध्यापकों की स्थानांतरण नीति का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए, सामान्य शाला संगम की जगह ऐसे शाला संगम विकसित किए जाने चाहिए जिसमें कालेज भी शामिल हों।

2. शिक्षा के विकास में क्षेत्रीय असमानता : भारतीय शिक्षा का मानचित्र

यह परियोजना अप्रैल 1982 में आरंभ की गई तथा 1984 में इसको पूरा कर लिया गया। इस परियोजना दल में निम्नांकित लोग थे : प्रो. मूनिस रज़ा (परियोजना निदेशक), प्रो. एज़ाज अहमद, मानद परामर्शदाता; श्री शीलचंद नुना, परियोजना सहायक; श्री पी एन त्यागी, मान चित्रकार तथा श्री पदमसिंह, श्री रामफल, श्री दीन मोहम्मद, संगणक विभाग।

इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक विकास के भौगोलिक आयामों की पहचान तथा क्षेत्रीय विकास की प्रक्रिया के साथ इसके दुहरे (द्विदिशात्मक) संबंध को जानना था। इसके मानचित्र का कार्य पूरा हो चुका है, इसमें द्विचरीय तथा बहुचरीय सांख्यिकीय तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। इसके आंकड़ों के प्रमुख स्रोत चतुर्थ अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण तथा भारतीय जनगणना है।

इस अध्ययन से पता चलता है कि क्षेत्रीय असमानता बहुत अधिक है। जम्मू तथा कश्मीर के पहाड़ी जिलों में, हिमाचल तथा उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में तथा पूर्वोत्तर और मध्यभारत के जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा तक पहुंच बहुत कम है। शैक्षिक विकास में असमानता के विविध स्तर हैं, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति तथा गैर अनुसूचित जातियों के बीच असमानता, ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के बीच असमानता तथा स्त्री-पुरुषों के बीच असमानता। जहां अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों का शिक्षा से वंचित रहना अतुलनीय है, अशिक्षा इन लोगों तक ही सीमित नहीं है। जो क्षेत्र बहुत ही पिछड़े हुए हैं वहां की निचली जातियों की निरक्षरता की बाकी जनता की भयानक निरक्षरता से अलग करना बहुत कठिन है।

इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कि देश के विभिन्न क्षेत्र विशेषता की दृष्टि से इतने भिन्न हैं कि वर्तमान यथास्थिति को व्यष्टि स्तर की समन्वित योजना से ही तोड़ा जा सकता है।

3. भारत में शिक्षा के लिए संसाधनों की व्यवस्था का अध्ययन

केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली के लिए अप्रैल 1982 में एक मार्गदर्शी अध्ययन हाथ में लिया गया। उसके बाद इसको भारत के 9 प्रमुख राज्यों के लिए कर दिया गया जिसमें आंध्रप्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश और केरल शामिल थे। सितंबर 1984 में यह अध्ययन पूरा हो गया। इस परियोजना दल में शामिल लोगों के नाम इस प्रकार हैं : डा. सी बी पद्मनाभन, परियोजना निदेशक; श्रीमती सक्रिया ब्राकर तथा सुश्री कल्पना पंत परियोजना सहायक।

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य थे, शैक्षिक वित्त के लिए संसाधनों का पता लगाना, उनके सापेक्ष महत्व में परिवर्तन करना, तथा उनका प्रभावी उपयोग करना। इसमें जो अध्ययन की पद्धति अपनाई गई उसमें

विभिन्न राज्यों की स्थितियों का प्रश्नावली के जरिए सर्वेक्षण करना तथा कुछ राज्यों का दौरा करना शामिल था। इसमें 1956-57 से 1966-67 की अवधि अध्ययन के लिए ली गई थी।

इस अध्ययन के कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार थे, शिक्षा के ऊपर खर्च में सरकार का हिस्सा सभी राज्यों में इन वर्षों में बढ़ता चला गया है, यह प्रवृत्ति सारे देश की प्रवृत्ति से मेल खाती है, कुछ राज्यों में कुछ योजनाओं में लगाया गया सरकारी वित्तीय हिस्सा इस्तेमाल नहीं किया जा सका है। शिक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए नगर पालिका और जिला परिषद जैसे स्थानीय निकायों का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्कूल बोर्ड खासतौर पर नगरीय स्थानीय निकाय प्राइमरी स्कूल चलाने के लिए कोष एकत्र कर रही है तथा बंबई महानगर परिषद जैसे बड़े नगरीय निकाय नगर क्षेत्रों में सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए अत्यधिक वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं, इसमें शिक्षा भी शामिल हैं।

ऐसा सुझाया गया है कि संसाधनों को जुटाने तथा उनके आबंटन में क्षेत्रीय आयामों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है क्योंकि शिक्षा के खर्च में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में काफी भिन्नताएं हैं।

4. गुड़गांव (हरियाणा) में शिक्षा की आपूर्ति लागत

दिसंबर 1982 में इस अध्ययन को हाथ में लिया गया था। एक मार्गदर्शी अध्ययन करके इसकी रूपरेखा को पूरी तरह सुधारा गया। 1984 में यह अध्ययन पूरा हुआ। इस अनुसंधान दल में जो लोग शामिल थे उनके नाम इस प्रकार हैं : डा. जे बी जी तिलक, परियोजना निदेशक, डा. जे के भट्ट, परियोजना सह अध्येता, तथा श्री पी के राव, परियोजना सहायक। आरंभ में डा. जी डी शर्मा इस परियोजना के निदेशक थे।

इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे : शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की इकाई लागत निकालना; इकाई लागत के अवयवों तथा निर्धारकों की परीक्षा करना, ऐसे उपाय सुझाना जिससे विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की इकाई लागत को कम किया जा सके। वर्तमान उपलब्ध अवसंरचनात्मक सुविधाओं को इस्तेमाल करने के लिए तरीके सुझाना, इसके लिए दो प्रखंड चुने गए : सोहना और पुनहाना, इनमें पहला आर्थिक रूप से संपन्न है और दूसरा पिछड़ा हुआ। गहन अध्ययन के लिए प्रत्येक प्रखंड में एक शैक्षिक संगम पर ध्यान केंद्रित किया गया। गांवों स्कूलों से संबंधित सवालों के स्कूलों तथा क्षेत्रों के संसाधनों को भी ध्यान में रखा गया था।

दो विद्यालय समूह क्षेत्रों में शिक्षा की कुल लागत तथा इकाई लागत के विषय में इस अध्ययन से पर्याप्त जानकारी मिलती है। यह सूचना उसी विषय के व्यष्टि स्तर के विश्लेषण से यह सुझाती है कि शिक्षा की घरेलू लागत देश में कुल लागत के ज्यादा होने का कारण है और राष्ट्रीय लेखा के किसी भी सार्थक अभ्यास में इसको शामिल करना बहुत आवश्यक है। इस सामान्य धारणा के विपरीत कि इकाई लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है, वे प्रति व्यक्ति बहुत कम हुई हैं। स्थाई लागत कुल लागत का, जो शिक्षा में वस्तु संपति निर्मित करती है, एक बहुत ही छोटा हिस्सा है, अध्यापकों के वेतन के अलावा स्थाई लागत का नगण्य भाग अन्य मदों पर खर्च किया जाता है। अधिकांश स्कूलों में मानव संसाधनों का जबर्दस्त अभाव, और भौतिक संसाधनों की कमी रही है। मिडिल तथा माध्यमिक स्तर के स्कूलों में प्राइमरी स्तर की शिक्षा की लागत अपेक्षाकृत ऊंची नहीं रही है, शिक्षा की इकाई लागत को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक छात्राध्यापक संबंध रहा है।

यह सुझाया गया है कि बहु-उद्देश्यीय भवनों के निर्माण से शैक्षिक गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी के स्तर में सुधार होता है। इन भवनों की अन्य कार्यों के लिए भी हम काम में लाते हैं। इसके फलस्वरूप

एक ओर तो शिक्षा की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार होता है तथा दूसरी ओर शिक्षा की लागत कम हो जाती है। शैक्षिक योजना में समूह दृष्टि भी शिक्षा की कुल लागत को कम करती है तथा समुदाय के भौतिक और मानव संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल को संभव बनाती है। इससे शिक्षा की लागत में और कमी होती है, माध्यमिक अथवा मिडिल स्कूल खोलना और अधिक लाभदायक होगा, इसकी तुलना में जहां केवल प्राइमरी कक्षाएं चलती हों, यह न सिर्फ सामान्य शिक्षा लागत के लिहाज से लाभदायक होगा, प्रभावी लागत तथा ड्राप आउट तथा अवरोध की दृष्टि से भी। क्योंकि दोनों स्तरों में मिडिल तथा माध्यमिक स्तरों में लागत काफी कम होती है।

5. विश्वविद्यालयों के लिए लेखा संहिता तैयार करना

श्री एम एल सोबती ने अगस्त 1983 में इस पर काम करना आरंभ किया तथा नवंबर 1984 में यह कार्य पूरा हो गया।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य एक लेखा संहिता बनाना था जो निर्देशिका अथवा मार्गदर्शिका का कार्य कर सके और जिसके आधार पर प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी निजी लेखा संहिता बना सके जिसमें उसकी स्थानीय आवश्यकताएं और विशेष जरूरतें पूरी हो सकें।

लेख संहिता की मोटी रूपरेखा वर्तमान ऐक्ट, स्टेच्यूट, रेग्यूलेशन तथा आर्डिनेंस आदि के अध्ययन के बाद तैयार की गई। कुछ राज्यों तथा केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राज्य तथा केंद्र सरकार की लेखा नियमावलियों से भी इस काम में मदद ली गई। 75 विश्वविद्यालयों और संस्थानों, (राष्ट्रीय स्तर के), 16 राज्यों, शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारतीय विश्वविद्यालय संघ से सुझाव आमंत्रित किए गए।

लेखा संहिता दो खंडों में तैयार की गई है : (1) लेखा संहिता, (2) लेखा फार्मों की पुस्तिका। लेखा संहिता में 24 अध्याय हैं तथा इसमें बहुत सारे विषय शामिल किए गए। यह एकात्मक तथा संबद्ध दोनों प्रकार के विश्वविद्यालयों के लिए बनाई गई हैं। मोटे तौर पर कहें तो यह लेखा नियमों की संकल्पना, भुगतान और रसीदों की देखरेख, संकायों में, कालेजों में तथा शिक्षण संस्थाओं में लेखा रखना; छात्रों की सुविधाओं से संबंधित लेखों का रखरखाव, फेलोशिप तथा छात्रवृत्तियों का हिसाब, छात्रावास तथा खेल इत्यादि का हिसाब; किसी विशेष विभाग अथवा सेवा के ऊपर लागू होने वाली लेखा प्रक्रिया, सहायक एककों और सेवाओं में काम आने वाली लेखा पुस्तिकाएं तैयार करना तथा उनका रखरखाव, बजट तथा वित्तीय नियंत्रण; संगणक पर आधारित लेखा प्रणाली में एकाउंटिंग तथा ट्रेजरी प्रक्रिया; एकाउंट फार्म की पुस्तिका में एकाउंट प्रलेखों के महत्वपूर्ण नमूने दिए गए हैं ताकि विश्वविद्यालय अपना लेनदेन का हिसाब रख सके।

6. भारत में उच्च शिक्षा : पुस्तक सूची (यूनेस्को प्रायोजित)

यह काम अगस्त 1984 में आरंभ हुआ और दिसंबर 1984 में पूरा हुआ। इसके अध्ययन दल में प्रो. मूनिस रज़ा तथा कु. निर्मल मल्होत्रा (पुस्तकाध्यक्ष) थे।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य विद्वानों, योजनाकारों, प्रशासकों, सरकारी अधिकारियों, भारत में उच्च शिक्षा से जुड़े अन्य लोगों के लिए उपयोगी संसाधन मुहैया कराना था।

7. मैट्रिकोतर छात्रवृत्ति का उपयोग तथा प्रबंध : एक राष्ट्रीय अध्ययन (राष्ट्रीय पार्श्व चित्र-2)

8. उच्च शिक्षा में धारण, असफलता, पुनरावृत्ति, तथा मध्य में छोड़ जाना : अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों का कोहार्ट विश्लेषण : एक राष्ट्रीय अध्ययन (राष्ट्रीय पार्श्व चित्र-3)

9. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों की सामाजिक पृष्ठभूमि, जीवन स्थितियां, तथा अकादमिक निष्पादन : अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों का राष्ट्रीय अध्ययन (राष्ट्रीय पार्श्व चित्र-4)

ये अध्ययन, अनुसूचित जाति/जनजाति शैक्षिक विकास एकक द्वारा हाथ में लिया गया था जिसकी स्थापना गृह मंत्रालय के अनुरोध पर संस्थान में की गई थी, और उसी ने इसका वित्तीय भार भी उठाया था : इसमें तीन अध्ययन जनवरी 1984 में आरंभ किए गए थे तथा उसी वर्ष क्रमश: अप्रैल, नवंबर और दिसंबर में इनको पूरा कर लिया गया था। इसके अनुसंधान दल में ये लोग थे : डॉ. एस एम दुबे, परियोजना, निदेशक श्री डी एच श्रीकांत तथा डा. एस क्यू ए नक्वी परियोजना सहअध्येता, डा. राजकुमार शर्मा और श्री जोगेश्वर बोरा, परियोजना सहायक। यह अध्ययन एकक परियोजना के समाप्त होने पर 31-12-84 को बन्द कर दिया गया।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति का उपयोग और प्रबंध : एक राष्ट्रीय अध्ययन (राष्ट्रीय पार्श्व चित्र-2)

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे : मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति में संबंधित विभिन्न विभागों के बीच लंबवत संबंधों तथा समन्वय को समझना, इस छात्रवृत्ति प्रबंध ढांचे को जानना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्थानिक (राज्य, एन एस एस क्षेत्र तथा जिले) और सामाजिक जनांकिकीय (अनुसूचित जाति/जनजाति, स्त्री-पुरुष आदि) कोटियों में रखकर उसका विश्लेषण करना, और विभिन्न कोटियों के अंतर पर प्रकाश डालकर इसकी प्रभाविता को कारगर बनाने के लिए औपचारिक कदम सुझाना तथा इस योजना के सुधार के लिए संस्तुतियां करना।

इसकी रिपोर्ट मूलत: द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। इसके आंकड़ों का आधार 15 राज्यों में इस छात्रवृत्ति की कार्यपद्धति तथा प्रबंध को बनाया गया है। जिसमें केंद्रशासित प्रदेश भी है। इसके अलावा हर तरह की उच्च शिक्षा की 14 संस्थाएं (शैक्षिक) जिनको राज्यों की राजधानियों में चुना गया है। यह अध्ययन 3454 छात्रों के दृष्टिकोण पर आधारित हैं जिनमें 2753 अनुसूचित जाति के हैं और 701 अनुसूचित जनजाति के हैं।

इस अध्ययन से यह उद्घाटित हुआ है कि सामान्य पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति के पुरुषों का हिस्सा कुछ हद तक संतोषजनक रहा है। कुछ राज्यों को छोड़कर व्यावसायिक शिक्षण में पुरुषों की भागीदारी बहुत अच्छी नहीं है, सभी पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों की महिलाओं का हिस्सा बहुत कम है; प्रक्रिया में, स्वीकृति देने में तथा छात्र को छात्रवृत्ति देने में विलंब का मामला हर राज्य में एक जैसा है; कोई ऐसा उपयुक्त तरीका नहीं था जिससे मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रभाव तथा छात्र के कार्य निष्पादन के बीच संबंधों का पता लगाया जा सके।

उच्चशिक्षा में धारण असफलता तथा मध्य में छोड़ जाना (राष्ट्रीय पार्श्व चित्र : 3)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति पानेवालों की सामाजिक पृष्ठभूमि, जीवन स्थितियां तथा अकादमिक निष्पादन : अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों का राष्ट्रीय अध्ययन (राष्ट्रीय पार्श्व चित्र : 4)

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे : जन्म, पारिवारिक पेशे का स्वरूप तथा आकार, जोतें, आय, परिवार के सदस्यों और माता-पिता की शैक्षिक पृष्ठभूमि आदि के परिप्रेक्ष्य में इस योजना से फायदा उठाने वालों का पता लगाना; व्यय के तरीकों, आय के स्रोतों और जीवन शैली तथा आवास के स्वरूप के विशेष संदर्भ में उनकी जीवन स्थितियों को समझना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की पर्याप्तता, प्रभाविता और उपयोगिता की पड़ताल करना, बीच में छोड़ जाने वालों, पुनरावृत्ति करने वालों, कुछ समय के लिए छोड़ने वालों तथा पाठ्यक्रम बदलने वालों को केंद्र में रख कर छात्रवृति पाने वालों के अकादमिक निष्पादन की परीक्षा करना, भावी समाजीकरण (यानी औपचारिक शिक्षण, परामर्श एवं निर्देश, रोजगार सूचना, परीक्षापूर्व शिक्षण, सचिवीय कार्य आदि) की संभावनाओं का पता लगाना तथा उनके वंचित होने का कारण मूलत: वंचित छात्रों की दृष्टि में।

कुछ चुनी हुई संस्थाओं में आंकड़े एकत्र करने के उद्देश्य से सांस्थानिक समय सारणी का प्रचार किया गया जिसमें कैरियर सूची तथा लाभ प्राप्त करने वालों की सूचियां शामिल थीं। इसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को लिया गया था। संस्थागत सूची के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़े में कोहार्ट पद्धति पर बल दिया गया था कि कुल नामांकित छात्रों की संख्या क्या थी तथा अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या था तथा छोड़ने वाले, स्थानांतरित होने वाले और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या था।

दोनों प्रतिवेदन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनका आधार हैं : 18 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों, 34 एन एस एस क्षेत्र, 62 जिलों, 62 संस्थाओं 4033 छात्रों का कैरियर पार्श्व चित्रों तथा 1500 अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों से साक्षात्कारों पर आधारित ये आंकड़े हैं जो स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहे हैं।

राष्ट्रीय पार्श्व चित्र 3 के अध्ययन में देखा गया है कि जहां तक व्यावसायिक छात्रों का ताल्लुक है, सबसे अच्छा कार्य निष्पादन आंध्रप्रदेश के उत्तरी भाग तथा बिहार के दक्षिणी क्षेत्र के छात्रों का रहा है। सबसे खराब निष्पादन तमिलनाडु के उत्तरी तटवर्ती क्षेत्र के विद्यार्थियों का रहा है। जहां तक स्नातक पाठ्यक्रमों का संबंध है, सबसे अच्छा निष्पादन उत्तर मध्य क्षेत्र, बिहार का उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों तथा पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मैदानी इलाकों का रहा है। अपेक्षाकृत खराब निष्पादन हरियाणा के पूर्वी इलाकों का तथा राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र का रहा है।

10. भारत में उच्च शिक्षा के वित्तीयन का गहन अध्ययन (भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायोजित)

डा. जे एल आजाद ने आंध्रप्रदेश, गुजरात, हरियाणा तथा उड़ीसा का केस अध्ययन हाथ में लिया। इसका उद्देश्य एक प्रशस्त नीतिगत ढांचा बनाना था जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय संस्थानों को वित्तीय

मदद उपलब्ध कराई जाती है। इसमें अन्य बातों की भी जानकारी प्राप्त की गई है जैसे राज्य अनुदानों के प्रतिरूप तथा उनकी प्रतिक्रियाएं, यू जी सी, आई सी एस एस आर आई सी ए आर जैसी संघीय संस्थाओं से प्राप्त अनुदानों से राज्य के द्वारा की गई सहायता का संबंध, तथा राज्यों में वित्तीय सहायता के तरीके। इस अध्ययन का आरंभ अप्रैल 1981 में हुआ तथा मार्च 1985 में इसको पूरा कर लिया गया।

राज्य सरकारों तथा संघीय अभिकरणों से सरकारी अनुदानों की प्रक्रियाओं तथा प्रतिरूपों के ढांचों के विषय में नवीनतम सूचनाएं प्राप्त की गईं। आंकड़ों की सारणी के माध्यम से कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों और कालेजों से सूचनाएं एकत्र की गईं। विश्वविद्यालय के कुलपतियों, कुल सचिवों और वित्त अधिकारियों के विचारों को प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र किया गया। संबद्ध अधिकारी से व्यक्तिगत साक्षात्कार भी लिए गए।

शिक्षा और उच्च शिक्षा पर कुल खर्चे के आचरण की परीक्षा करते समय इस अध्ययन से यह पता चला है कि शिक्षा और उच्च शिक्षा पर खर्चे में बढ़ोत्तरी के बावजूद लगातार बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय आगत पर्याप्त है, ऐसा कहना मुश्किल है। जो संस्थाएं उच्च शिक्षा की वित्तीय मदद देती है, उनका व्यवहार संगत नहीं है और किन्हीं अर्थों में वह दोषपूर्ण भी है, अंतर्संस्थागत तथा अंतर्क्षेत्रीय (विषय के अनुसार) संसाधनों का आबंटन कुछ निरुत्साहित करने वाला रहा है, इससे कुछ संस्थानों की तो स्थिति कुछ बेहतर बनी है लेकिन भयंकर स्थिति में चलने वाली ढेरों संस्थाओं का अस्तित्व साथ-साथ बना हुआ है।

यह भी पता चला है कि यह व्यवस्था इस अर्थ में असमतामूलक है कि कुछ संस्थाओं को अन्यों की तुलना में अधिक उदारतापूर्वक अनुदान दिया जाता है। विभिन्न राज्यों ने अनुदान का अलग-अलग ढांचा अपना रखा है, इससे भी कालेज शिक्षा में अंतर्राज्यीय भेदभाव पैदा हुआ है, अनुदान की प्रणाली में एकरूपता तथा निश्चितता नहीं है, कालेज संस्थानों द्वारा वित्तीय संसाधनों की जुटाने के लिए विशेष ध्यान नहीं दिया गया है।

11. विश्वविद्यालय समुदाय की स्वयत्तता (भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायोजित)

डा. जे एन कौल ने यह अध्ययन फरवरी 1982 में हाथ में लिया और मार्च 1985 में उन्होंने इसको पूरा कर लिया।

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: इस बात का पता लगाना कि विश्वविद्यालयों को कितनी स्वायत्तता मिली हुई है और क्या स्वायत्तता विश्वविद्यालय प्रशासन की कोई पद्धति हो सकती है। इस अध्ययन के पीछे यह संकल्पना थी कि अकादमिक समुदाय और विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की अवधारणा विदेशी है और भारतीय विश्वविद्यालय व्यवस्था की दृष्टि से यह दिनोदिन अप्रासंगिक होती जा रही है तथा इससे भारतीय विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने की समस्या में रोड़े अटका रही है। इस अध्ययन से जो कुछ प्रमुख निष्कर्ष निकाले गए वे इस प्रकार हैं: विश्वविद्यालय का स्वायत्तता का ढांचा इस बात पर निर्भर करेगा कि समाज ने विश्वविद्यालय को किस प्रकार का कार्य सौंप रखा है या इन्हें सामाजिक आवश्यकता की संगति के अनुसार चुना जाना चाहिए, उसकी मांग और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। क्रमश: यह अपनी उपयोगिता और चमक खो रही है जैसा कि इस तथ्य से जाहिर होता है कि करदाता और खरीददार

दोनों ही इसके भारी खर्च के प्रति सचेत हैं। और भी, बिना जिम्मेदारी के स्वतंत्रता विश्वविद्यालय के सही और स्थायी हित के विरुद्ध जा सकती है। फिर भी विश्वविद्यालय अपनी स्वायत्तता के दबाव के कारण अपना वर्गगत या जातिगत चरित्र नहीं खो देगा। आगे यह भी पाया गया कि स्वायत्तता नियंत्रण की सक्षम पद्धति नहीं रह गई है। वास्तविक स्वायत्तता से छात्रों, अध्यापकों तथा प्रशासकों को सही विकल्प मिलना चाहिए।

उच्च शिक्षा में अध्यापकों की हैसियत के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन

12. भारत में उच्च शिक्षा : एक सर्वेक्षण
13. आर्थिक हैसियत
14. सामाजिक हैसियत
15. भर्ती : आधार तथा प्रक्रिया
16. गतिशीलता तथा अंत:प्रजनन
17. व्यावसायिक तथा कैरियर का विकास
18. कार्य भावना
19. परेशानियां तथा उनका निराकरण
20. निर्णय में भागीदारी
21. व्यावसायिक मूल्य

"उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय आयोग" की ओर से नीपा के केंद्रीय तकनीकी एकक ने एक अनुसंधान डिजाइन तैयार किया, सर्वेक्षण कराया, तथा उच्च शिक्षा के अध्यापकों की हैसियत पर दस अनुसंधान अध्ययन कराए। यह उच्च शिक्षा आयोग के लिए तकनीकी आगत के रूप में था। ये अध्ययन मई 1983 में आरंभ हुए थे तथा अगस्त 1984 में इनको पूरा कर लिया गया था। अनुसंधान प्रारूप तथा उच्च शिक्षा का सर्वेक्षण इसकी पृष्ठभूमि के रूप में रखे गए थे।

इसके अनुसंधान दल में जो लोग शामिल थे उनके नाम इस प्रकार हैं : प्रो. मूनिस रज़ा, डा. जी डी शर्मा, डा. शक्ति रईस अहमद, डा. वाई पी अग्रवाल, श्री महबूद हसन, डा. डी एन सिन्हा, डा. अमरीक सिंह, डा. के ए नक्वी, डा. के जोपड़ा, सुश्री आशा कपूर, सुश्री मार्जरी फर्नांडीस, डा श्रीमती एस एम लूथरा, डा. श्रीमती अनीता बनर्जी, डा. एम वी पायली, डा. एन पी गुप्त, प्रो. श्यामाचरण दुबे तथा डा. श्रीमती हेमलता स्वरूप।

यह अध्ययन 2144 विश्वविद्यालय के अध्यापकों (7%) तथा 6306 कॉलेज प्राध्यापकों (4%) के प्रश्नोत्तरों पर आधारित है जो सारे देश से प्राप्त किए गए हैं। इनके अतिरिक्त इस अध्ययन में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि के यहां वहां से चुने गए 2214 छात्रों के उत्तर तथा विभिन्न आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों तथा शैक्षिक पृष्ठभूमि के समुदाय के 1658 व्यक्तियों के विचारों को भी लिया गया है। देश के विभिन्न क्षेत्रों के दौरों के दरम्यान शिक्षा आयोग के सदस्यों के समक्ष पेश किए गए अथवा रखे गए 140 अध्यापकों के स्मरण पत्र, 4211 अध्यापकों और 239 प्रसिद्ध शिक्षाविदों के विचारों को भी इसमें लिया गया है।

भारत में उच्च शिक्षा का सर्वेक्षण

इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य थे, स्थानीय भिन्नताओं की आलोचनात्मक परीक्षा करना, महत्वपूर्ण समस्याओं को खोजना तथा उनका संभावित समाधान सुझाना, सर्वेक्षण में 1857 और उसके बाद के उच्च शिक्षा के विकास पर प्रकाश डाला गया है तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्रीय आयामों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इस सर्वेक्षण में शिक्षा व्यवस्था के विक्रियता के विशेष बिंदुओं को रेखांकित किया गया है। उपनिवेशकालीन शिक्षा व्यवस्था की खामियों को भी इसमें दिखाया गया है तथा वर्तमान काल की उच्च शिक्षा के विरोधी प्रतिरोधों को भी दिखाया गया है जैसे संख्या और गुणवत्ता, न्यायता और दक्षता, प्रतिबद्धता और निस्संगता, समग्रता और विभेद आदि।

इस सर्वेक्षण से यह तथ्य उद्घाटित हुआ है कि एक चौथाई (27%) से भी अधिक अध्यापक खेतिहर परिवारों के हैं तथा 12% की पृष्ठभूमि व्यवसाय वाली है, आगे एक चौथाई लोग राजकीय या निजी क्षेत्रों की सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के परिवारों के लोग हैं। सात और आठ प्रतिशत लोग क्रम स्कूल के अध्यापकों और अन्य पेशों में लगे लोगों के परिवारों से आए हैं जैसे डाक्टर, इंजीनियर, आदि। इन अध्यापकों का बहुत छोटा हिस्सा कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय प्राध्यापकों के परिवार का है या दक्ष और तकनीकी कर्मचारियों के परिवार का है। इनमें 77% से 78% अध्यापक युवा हैं तथा इनकी आयु 45 वर्ष से कम है। उसके बाद के 17% प्रतिशत अध्यापक 46-55 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। नमूने के तौर पर लिए गए अध्यापकों में महिलाओं का अनुपात 23% था। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी हुई जातियों को मिलाकर कुल हिस्सेदारी 13% थी।

आर्थिक और सामाजिक स्थिति

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे : अध्यापक की स्थिति का परीक्षण करना जो उनके वेतन, व भत्तों, जीवन स्थितियों और सेवा शर्तों से बनती है तथा उनकी तुलना उसी योग्यता तथा अकादमिक पृष्ठभूमि वाले सरकारी कर्मचारी की स्थितियों से करना, इसी प्रकार के व्यवसाय में लगे तीसरी दुनिया के अन्य देशों के लोगों से इनकी तुलना करना, विकसित तथा विकासशील देशों के लोगों से तुलना करना, अध्यापकों की अपनी दृष्टि में, अपने छात्रों और समुदाय की दृष्टि में उनकी स्थिति, तथा अध्यापकों की स्थिति में सुधार के लिए उपाय सुझाना।

इस अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता हैं कि पिछले एक दशक से अध्यापकों की आर्थिक स्थिति दिनोदिन बिगड़ती गई है। यद्यपि सरकारी नीति के अनुसार अध्यापक का समाज में अत्यंत सम्मानजनक स्थान है और इसी के अनुसार उसकी आर्थिक हैसियत होनी चाहिए लेकिन व्यवहार में उनकी हैसियत अपेक्षाकृत नीची है जब हम उनकी तुलना आई ए एस, आई एफ एस तथा कम योग्यता वाली सेवाओं जैसे बैंक, एल आई सी के कार्मिकों से करते हैं, मुख्य अंतर तीन बातों के कारण होते हैं : गृह तथा स्वास्थ्य भत्ता, बच्चों की शिक्षा तथा वेतनमान। एक लंबी अवधि के दौरान अध्यापक की सामाजिक हैसियत भी गिरी है। राजनीतिज्ञों तथा सरकारी अधिकारियों की नजर में उनकी हैसियत सबसे नीची है। लेकिन छात्रों तथा समुदाय की जनता के बीच उनकी छवि ठीक ठाक है।

अध्यापकों की भर्ती का आधार और उसकी प्रक्रिया

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य थे : अध्यापकों की भर्ती के आधार तथा उसकी प्रक्रिया की परीक्षा करना तथा ऐसे उपयुक्त उपाय सुझाना जिससे इस पेशे में प्रतिभाशाली अध्यापकों को आकृष्ट किया जा सके।

इस अध्ययन में अध्यापकों के भर्ती की प्रक्रिया और आधार संबंधी-असंतोष सामने आए है जैसे नियुक्तियों में पक्षपात, विज्ञापन का स्वरूप तथा उसका उचित प्रसार, चयन समिति का निर्माण, साक्षात्कार का स्वरूप और साथ ही प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने और चयन के बीच अनावश्यक अंतराल। यद्यपि इसमें मात्रा का थोड़ा बहुत अंतर है लेकिन इस प्रकार का असंतोष कॉलेज तथा विश्वविद्यालय दोनों ही अध्यापकों में है। जहां भर्ती की प्रक्रिया की समीक्षा आवश्यक है इस बात को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए जिस तरह लोगों की पहले तदर्थ नियुक्तियां हो जाती हैं और बाद में स्थाई हो जाते हैं।

उच्च शिक्षा संस्थाओं में धारणा, गतिशीलता तथा अंतप्रजनन

इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे : उन स्थितियों का पता लगाना जिनके कारण अध्यापक अपने व्यवसाय में बना रहना चाहता अथवा छोड़कर भाग जाना चाहता है; व्यवसाय के अंतर अध्यापक की गतिशीलता लंबवत तथा समानांतर; अंत:प्रजनन के कारण तथा उनके नतीजे, अंत:प्रजनन रोकने के लिए, प्रतिभाशाली अध्यापकों की व्यवसाय में बनाए रखने के लिए, उनकी गतिशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए उपाय सुझाना।

इस अध्ययन से संकेत मिलता है कि अन्य व्यवसायों से इस व्यवसाय में आने की गति वस्तुत: नगण्य है सिवाए कुछ व्यावसायिक विषयों में थोड़े से लोगों को छोड़कर जैसे इंजीनियरिंग, वाणिज्य, कृषि तथा पशु चिकित्सा विज्ञान। शिक्षा व्यवसाय के लोगों की गतिशीलता बहुत अधिक है जैसा कि इन आंकड़ों से पता चलता है कि 52% विश्वविद्यालय के शिक्षक तथा 42% कॉलेज के शिक्षक एक संस्था से दूसरी संस्था में जाते रहे हैं। लेकिन यह गतिशीलता ऊपर की दिशा में नहीं बल्कि समांतर दिशा में है लोग उसी स्थान पर एक संस्था से दूसरी संस्था में जाते रहे हैं। नीचे से ऊपर की ओर जानेवालों की संख्या नहीं के बराबर है। नीचे से ऊपर चढ़ने का कारण यह है कि ऊपर के पद बहुत होते हैं। अधिकांश अध्यापकों का ऐसा मानना हैं कि अंत:प्रजनन का प्रतिशत 45% के आसपास है। व्यावसायिक संस्थानों में यह अनुपात ज्यादा लगता है। लगभग 49% प्रतिशत अध्यापकों ने विश्वविद्यालयों शिक्षण में अंत:प्रजनन का विरोध किया है।

व्यावसायिक तथा पेशागत विकास

इस अध्ययन के मुख्य अध्ययन इस प्रकार थे : प्रवेश, पेशागत विकास, व्यावसायिक विकास के संदर्भ में अध्यापक की उन्नति के रास्तों की परीक्षा करना तथा अध्यापक के व्यावसायिक और पेशागत विकास के लिए उपाय सुझाना। इस अध्ययन ने इस तथ्य का उद्घाटन किया है कि विश्वविद्यालय के 30% अध्यापक और कॉलेजों के 40% अध्यापक एक ही पद पर 10-15 वर्ष तक काम करते रहते हैं, उनका विकास अवरूद्ध रहता है। इसके विपरीत जो लोग नागरिक सेवाओं तथा प्रशासनिक पदों पर होते हैं उन्हें 15 साल में कम से कम तीन या चार पदोन्नतियां मिलती हैं तथा वे संयुक्त सचिव या अवर सचिव के पद पर पहुंच जाते

है। (जो पद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद से भी बड़ी होती है।) यही बात वित्तीय प्रशासन जैसे बैंक, एल आई सी, आदि संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्तियों के विषय में सच है।

कार्यदिवस, काम का बोझ तथा काम का स्वरूप

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे : संस्थाओं में काम के दिनों की तथा अवकाश के दिनों की संख्या की परीक्षा करना (गत तीन वर्षों के दौरान)। अध्यापक ने अपना समय शिक्षण पर, अनुसंधान तथा परा अकादमिक कार्यों पर, विस्तार कार्य तथा प्रशासनिक कार्यों पर किस तरह खर्च किया है, इसकी परीक्षा करना, अध्यापक के कार्य दिवस में वृद्धि के लिए रास्ते सुझाना और अध्यापक द्वारा हाथ में लिए गए कार्य के स्वरूप तथा मात्रा के लिए नीति बनाने में योगदान करना।

इस अध्ययन से पता चलता है कि यद्यपि अध्यापक की भूमिका काफी व्यापक है तथा उसे समाज की जरूरतों से प्रति संवेदनशील होना चाहिए किंतु व्यवहार में हम यह देखते हैं कि मोटे तौर पर उसकी भूमिका काफी संकीर्ण है तथा कक्षाध्यापन तक सीमित है, अनुसंधान तथा एक्स्टेंशन किसी कॉलेज अध्यापक की गतिविधि का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की स्थिति कॉलेज की तुलना में थोड़ी बेहतर हैं। यहां तक कि लगता है इस सीमित भूमिका का निर्वाह भी वह कुछ कारणों से ठीक से नहीं कर पाता है। यहां तक कि औसतन शिक्षा के बड़े-बड़े संस्थान भी निर्धारित समय के एक चौथाई ही खुलते हैं। अध्यापकों के कक्षा व्याख्यानों का औसत नियत व्याख्यानों का एक तिहाई होता है। यहां तक कि काम के दिन भी आम तौर पर अध्यापक लोग अपनी संस्थाओं में कम समय व्यतीत करते है जो कि शिक्षक छात्र संपर्क के लिए आवश्यक है। अनुसंधान के नतीजे बहुत ही नगण्य हैं, इनको अध्यापकों के प्रकाशित कार्यों में देखा जा सकता है, अनुसंधान निर्देशों में लक्षित किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग इसके अपवाद भी हैं। वे लोग जो अपने काम को गंभीरता से लेते हैं, वे निर्धारित मानदंडों से भी काफी अधिक काम करते हैं।

निर्णय में अध्यापकों की भागीदारी

इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे : संस्था के भीतर अकादमिक, परा-अकादमिक तथा संस्था के प्रशासनिक मामलों में निर्णय लेते समय अध्यापकों की भागीदारी की परीक्षा करना तथा निर्णय लेने में अध्यापकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाना।

इस अध्ययन से यह बात सामने आई है कि सामाजिक निर्णयों में जैसे आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मामले में अध्यापकों की भागीदारी नाममात्र को है। विकास कार्यों के निर्णय में मुश्किल से किसी अध्यापक से परामर्श किया जाता होगा। यद्यपि इस व्यवसाय में निर्णय करने में अध्यापक की भागीदारी अंतर्निहित है फिर भी कभी कभी, किसी किसी मामले में प्रायः निर्णय विधिवत बनाई गई समितियों से बाहर ही कर लिए जाते हैं। जहां सामाजिक मामलों में अध्यापक की निर्णय में भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, व्यवसाय के भीतर की निर्णय की प्रक्रिया की बारीकी से छानबीन की आवश्यकता है।

अध्यापकों की तकलीफें तथा उनका समाधान

इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य अध्यापकों की परेशानियों के सामान्य रूप का पता लगाना तथा उनको दूर करने की प्रक्रियाओं की परीक्षा करना था।

इस अध्ययन से संकेत मिले हैं कि अध्यापकों की मुख्य तकलीफें इस प्रकार हैं : गलत नियुक्तियां तथा पदोन्नतियां, खराब कार्य दशाएं, मकान, वाहन, विभागों में कक्ष, अध्ययन कक्ष तथा प्रयोगशाला की सुविधाओं का आंबटन तथा उसमें पक्षपात, काम का बंटवारा तथा प्रशासकों का गलत व्यवहार आदि। उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए न्यायाधिकरणों का प्रावधान लगता है मात्र एक तिहाई के लिए उपलब्ध है, इसलिए अधिकांश अध्यापकों को अपनी परेशानियों के समाधान के लिए अध्यापक संघों की शरण में जाना पड़ता है। अधिकांश अध्यापकों का मानना था कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तभी अध्यापक को अपनी समस्या का हल न्यायालय के जरिए करना चाहिए।

अध्यापकों का मूल्याभिविन्यास

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य थे : देश की विरासत तथा प्रजातंत्र, समाजवाद, धर्म निरपेक्षता तथा वैज्ञानिक मिजाज जैसे आदर्शों और अकादमिक श्रेष्ठता के आदर्शों के मुताबिक अकादमिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों की परीक्षा करना जिसको इस व्यवसाय में पोषित पल्लवित किया जाता है तथा पोषित पल्लवित करने की जरूरत है, समाज तथा व्यवसाय के प्रति अध्यापक के दायित्व की परीक्षा करना; तथा उपर्युक्त आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाना।

जैसा कि इस अध्ययन से प्रगट होता है कि यह संतोष की बात है कि जैसा कि अध्यापकों के उत्तरों से झलकता है सभी अध्यापकों को व्यवसाय संबंधी मान्यताएं, चाहे वैचारिक स्तर पर ही सही, नहीं बदली हैं। अधिकांश अध्यापकों का अभी भी यह मानना है कि प्राइवेट ट्यूशन से या कुंजी लिखकर पैसे कमाना, पुराने व्याख्यानों के नोट्स से पढ़ाना, कक्षा में पढ़ाने के बदले बोलकर लिखाना, बिना अवकाश लिए कक्षाओं से गायब रहना, अन्य सहयोगी या सहयोगियों के खिलाफ छात्रों को उकसाना, छात्रों को अधिक अंक देकर पक्षपात करना व्यावसायिक नैतिकता के विरुद्ध है। अध्यापक इस बात को भी महसूस करते हैं कि कुछ विशेष मूल्यों में अध्यापकों को अभिविन्यास किया जाना चाहिए जैसे, वैज्ञानिक मिजाज, धर्म निरपेक्ष और लोकतांत्रिक दृष्टि का विकास, सामाजिक न्याय तथा समता, पर्यावरण के प्रति जागरूकता मानव जाति के प्रति प्रेम तथा नागरिक दायित्व।

प्रगत्योन्मुखी अध्ययन

नीचे कुछ अध्ययनों की तालिका दी गई है। इनको संस्थान ने हाथ में लिया था। ये सभी अध्ययन प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं :

(क) जारी अध्ययन

1. इष्टतम छात्राध्यापक अनुपात का अध्ययन (यह अध्ययन जुलाई 1982 में आरंभ हुआ था)
2. भारत में समाज विज्ञान अनुसंधान का वित्तीयन (भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायोजित, यह मार्च 1983 में शुरू किया गया।)
3. भारत में अवसर की समानता तथा शैक्षिक अवसर के समानीकरण के विशेष संदर्भ में शैक्षिक वित्तीयन का अध्ययन : उत्तर प्रदेश तथा केरल में स्कूल शिक्षा का अध्ययन (भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायोजित, मार्च 1983 में आरंभ किया गया।)
4. भारत में शैक्षिक नीति और नियोजन का अध्ययन : योजना आयोग की भूमिका, वर्तमान स्वरूप तथा भावी संभावनाएं, (इसे अप्रैल 1983 में आरंभ किया गया।)
5. वर्ष 2000 में भारतीय शिक्षा : एक दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य (यह अध्ययन मई 1983 में आरंभ किया गया।)
6. केरल में शिक्षा के विकास के इतिहास का अध्ययन (यह अध्ययन फरवरी 1984 में आरंभ किया गया।)
7. तकनीकी शिक्षा का प्रबंध : इन्जीनियरिंग कालेजों में कार्मिक ढांचे तथा सामग्री सूची के नियंत्रण के लिए प्रत्याशंसा (यह अध्ययन मई 1984 में आरंभ किया गया।)
8. विकास के कुछ आयामों पर शैक्षिक स्तर का प्रभाव ग्रामीण परिवारों का अध्ययन (यह परियोजना मई 1984 में आरंभ की गई) ।
9. शिक्षा तथा रोजगार के बीच लाभकारी संरचनात्मक संबंध : एक पृष्ठभूमीय जिल्द (यह कार्य जून 1984 में आरंभ किया गया।)
10. कालेज के प्रधानों द्वारा अपनी भूमिका के निष्पादन का अध्ययन (यह कार्य अगस्त 1983 में आरंभ किया गया।)
11. पुनहाना प्रखंड जिला गुड़गांव (हरियाणा) के बीस गांवों के एक समूह में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य से शैक्षिक योजना और प्रशासन में नवाचारी व्यवहारों पर आधारित कार्यानुसंधान (यह कार्य मार्च 1984 में आरंभ किया गया।)
12. शैक्षिक अवसरों के समानीकरण में संरक्षणात्मक भेदभाव की भूमिका (यह अध्ययन सितंबर 1984 में आरंभ किया गया था।)
13. कॉलेजों के विज्ञान संकाय के विभागाध्यक्षों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पाठ्य सामग्री तैयार करने का मार्गदर्शी अध्ययन (यह कार्य दिसंबर 1984 में हाथ में लिया गया) ।
14. नौ शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा का मूल्यांकन (मार्च 1985 में यह अनुसंधान आरंभ किया गया) ।
15. हरियाणा में 2 स्तर की शिक्षा के क्रियान्वयन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए केस अध्ययनों का विकास (फरवरी 1985 में आरंभ किया गया।)

(ख) स्वीकृत अध्ययन

1. अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जाति की जनसंख्या का जिलावार विश्लेषण
2. शैक्षिक गतिविधियों के लिए स्थानिक प्रावधान

अनुसंधान तथा सामयिक आलेख

1. भारत में उच्च शिक्षा का क्षेत्रीय आयाम

इस सामयिक आलेख को प्रो. मुनीस रजा तथा डॉ. वाई पी अग्रवाल ने मिलकर लिखा था।

क्षेत्रीय भिन्नताओं की समझ का विकास करने के लिए इस आलेख में भारत में उच्च शिक्षा के विकास में क्षेत्रीय असमानताओं के विभिन्न पक्षों की परीक्षा की गई हैं।

शैक्षिक प्रगति का सर्वेक्षण करते समय पता चलता है कि उच्च शिक्षा में काफी असंतुलन विद्यमान है। ऐसा लगता है कि कुछ क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का विकास काफी तेज गति से हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि योजनाबद्ध विकास के पिछले तीस वर्षों के दौरान विकृत परंपरागत ढांचे को तोड़ने के लिए प्रयास किए गए हैं लेकिन अभी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस प्रकार ऐसा लगता है शैक्षिक विकास की समस्याएं मूलत: सामाजिक आर्थिक ढांचे के विविध पहलुओं से जुड़ी हुई हैं, तथा समग्र रूप से देखने पर ये पूरी विकास प्रक्रिया से जुड़ी हैं। शैक्षिक योजना का क्षेत्रीय संकीर्ण दृष्टिकोण से संवृद्धि के साथ समानता का लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जा सकता है।

2. शिक्षा में भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण

यह आलेख डॉ. जे बी जी तिलक और डॉ. एन बी वर्गीज ने मिल कर लिखा था। इस आलेख में शुल्क को अतिरिक्त संसाधन जुटाने के शक्तिशाली औजार के रूप में मोड़ने की संभावनाओं का पता लगाया गया है जिससे लोक सहायता की उल्टी व्यवस्था को रोका जा सके। इसके लिए तर्क दिया गया है, भेदभावपूर्ण शुल्क ढांचा इस दुहरे उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। लेखकों के तर्क का आधार है : (अ) शिक्षा की लागत, (ब) शिक्षा से सीधे फायदा उठाने वालों की शुल्क देने की क्षमता, तथा (स) पुरस्कार का सांचा। एक लंबे अर्से के बाद शिक्षा शुल्क तथा शिक्षा लागत के बीच अंतराल का पैदा होना, लाभकर्त्ताओं की शुल्क अदायगी की क्षमता में समय के साथ वृद्धि तथा शिक्षा के लाभ लोगों के बीच अलग अलग रूपों में पहुंचा है।

अनुभव के आधार पर यह दर्शाया गया है कि यहां तक कि यदि हम अपेक्षाकृत कम आय वाले 50% छात्रों को भी शुल्क मुक्त कर दें तो कुल योगदान, भेदभाव पूर्ण प्रणाली के अंतर्गत, उच्च शिक्षा में गैर भेदभावपूर्ण प्रणाली से कई गुना ज्यादा होगा। भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण के साथ भेदभावपूर्ण प्रोत्साहन की भी इस आलेख में वकालत की गई है जिससे श्रेष्ठता को पुरस्कृत किया जा सके तथा कम सुविधा प्राप्त लोगों को फायदा हो सके। सुझाए गए इस ढांचे की अच्छाई यह है कि यह न केवल शिक्षा के लिए अधिक संसाधनों की व्यवस्था करता है बल्कि अत्यन्त महत्वपूर्ण तरीके से शिक्षा को कम प्रतिगामी बनाता है। यह भी तर्क दिया गया है कि सुझाए गए अन्य विकल्पों से यह काफी अच्छा भी है।

भाग तीन

परामर्शदायी, सलाहकारी तथा समर्थनकारी सेवाएं

शिक्षा के क्षेत्र में परामर्शदायी, सलाहकारी तथा समर्थनकारी सेवाएं प्रदान करना संस्थान के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संस्थान ने केंद्र और राज्य सरकारों को तथा भारत के विश्वविद्यालयों तथा अन्य संगठनों को कई प्रकार की सेवाएं प्रदान की। समस्याभिमुखी अनुसंधानों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों कार्यशिविरों का संयोजन कर तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन और अकादमिक समर्थन देकर संस्थान ने दूसरे देशों की सरकारों, संस्थाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी सेवा की।

इस क्षेत्र की संस्थान की गतिविधियों तथा क्रियाकलापों को मोटे तौर पर नीचे लिखे तीन भागों में बांट सकते हैं :

(अ) केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुरोध पर हाथ में लिए गए अनुसंधान अध्ययन और परियोजनाएं।

(ब) राज्य सरकारों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठनों के अनुरोध पर आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशिविर/अध्ययन दौरे।

(स) संगोष्ठियों, कार्य शिविरों, समितियों तथा कार्यबलों तथा अन्य परामर्शकारी सेवाओं के रूप में संकायों का योगदान।

राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान द्वारा प्रदान की गई परामर्शदायी, सलाहकारी और समर्थकारी सेवाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :

1. राष्ट्रीय स्तर की सेवाएं

(अ) अध्ययन तथा परियोजनाएं

इस वर्ष के दौरान संस्थान ने 16 अध्ययन पूरे किए, इनमें तीन परियोजनाएं गृह मंत्रालय के आग्रह पर, दस योजनाएं राष्ट्रीय शिक्षणक आयोग : द्वितीय (उच्च शिक्षा) के आग्रह पर, भारती समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद के आग्रह पर दो तथा भारत सरकार के नीति नियोजन समिति के आग्रह पर एक परियोजना पूरी की गई। इनके अलावा भारती समाज विज्ञान अनुसंधान द्वारा प्रायोजित भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर तीन अध्ययन प्रगति पर हैं। इनका विस्तृत विवरण इस रिपोर्ट के भाग दो तथा संलग्नक दो में दिया गया हैं।

(ब) प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान ने कुल 11 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, इनमें एयर फोर्स के शिक्षा विभाग के अनुरोध पर एक, पर्यावरण नियोजन और प्रौद्योगिकी केंद्र, स्कूल आफ प्लानिंग एंड टेक्नालोजी, अहमदाबाद के अनुरोध पर एक कार्यक्रम, केंद्रीय विद्यालय संगठन के अनुरोध पर दो, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के कहने पर एक तथा विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग के आग्रह पर दो कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के बारे में भाग एक में विस्तार से बताया गया है।

(स) अखिल भारतीय समितियों, संगोष्ठियों, कार्यशिविरों सम्मेलनों, कार्यबलों तथा अन्य परामर्शदायी सेवाओं में संकाय का योगदान

विभिन्न अखिल भारतीय सम्मेलनों, समितियों तथा संगोष्ठियों में संस्थान ने भाग लिया। इस संबंध में संस्थान ने निम्नलिखित विषयों में महत्वपूर्ण योगदान किया :

(i) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) की तैयारी

शिक्षा के क्षेत्र में सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने में भारत सरकार द्वारा बनाए गए निम्नांकित कार्य-दलों में संस्थान ने अपने प्रतिनिधि भेजे :

1. शिक्षा, संस्कृति और खेल के लिए संचालक दल
2. प्रारंभिक शिक्षा पर बना कार्यदल
3. माध्यमिक शिक्षा के लिए कार्यदल
4. प्रौढ़ शिक्षा के लिए कार्यदल
5. दूर शिक्षण तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर कार्यदल
6. कला और संस्कृति पर कार्यदल
7. सूचना तथा पुस्तकालय के आधुनिकीकरण कर कार्यदल
8. संचारेक्षण तथा मूल्यांकन पर बना कार्यदल
9. शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधन पर बना कार्यदल

शिक्षा के विषय में विभिन्न कार्यदलों की अलग-अलग रिपोर्टें बनाने में संस्थान ने मदद की। साथ ही शिक्षा की एक समग्र एकीकृत रिपोर्ट तैयार करवाने में भी संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंतिम रिपोर्ट बनाने में संस्थान ने अत्यंत सक्रिय भूमिका निभाई।

(ii) वार्षिक योजना संबंधी विचार विमर्श

इस वर्ष के दौरान योजना आयोग में शिक्षा क्षेत्र पर बने सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के कार्यदलों में संस्थान का प्रतिनिधित्व रहा। विशेष कंपोनेंट योजना तथा जनजातीय उपयोजनाओं की बैठकों में भी संस्थान ने भाग लिया।

(iii) नई शिक्षा नीति

नई शिक्षा नीति के विषय में राष्ट्रीय स्तर के विविध विचार विमर्शों में संस्थान का सक्रिय भागीदारी थी।

(iv) प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण संबंधी गतिविधियों से जुड़ाव

देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नौ राज्यों के लिए शिक्षा मंत्रालय ने प्रारंभिक शिक्षा पर एक कृतिकबल का गठन किया है और इसके लिए केंद्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय समिति का भी गठन किया गया है। संस्थान का प्रतिनिधित्व इन सभी कृतिक बलों और समितियों में है। विभिन्न राज्यों में हुई समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सभी बैठकों में संस्थान के वरिष्ठ संकाय सदस्यों ने भाग लिया तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए विभिन्न राज्यों में बनाई जानेवाली व्यष्टिस्तरीय योजनाओं को तैयार करने में मदद की।

शैक्षिक योजना और प्रशासन में नवाचारी व्यवहारों पर आधारित कार्य अनुसंधान योजना के क्षेत्र में भी संस्थान ने काफी प्रगति की। इसका उद्देश्य गुड़गांव के पुनहाना प्रखण्ड के 20 गांवों के एक समूह में शिक्षा का सार्वजनीकरण था। इस क्षेत्र के लिए प्रशिक्षार्थियों के दौरों का आयोजन किया गया जिससे वे इसके क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन कर सकें।

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में तथा निरक्षरता दूर करने के कार्यक्रम में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए पुरस्कार देने के लिए शिक्षा मंत्रालय को एक पद्धति तैयार करने में संस्थान ने मदद की।

(v) शैक्षिक विकास संबंधी सूचना का प्रसार

राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में क्या-क्या नवीनतम विकास हुए, इसकी सूचना प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए, संस्थान ने विभिन्न स्रोतों से इस प्रकार की सूचनाएं एकत्र करने की एक प्रणाली का विकास किया है। ये सूचनाएं अलग-अलग स्रोतों मे एकत्र की जाती हैं जैसे क्षेत्रीय समाचार-पत्रों के संकलन से, राज्यों के संवाददाताओं के पत्रों के जरिए, योजना, शिक्षा तथा वित्त विभाग (राज्यों के), आदि। ये सूचनाएं ई पी ए बुलेटिन में "राज्यों की सूचनाएं" स्तंभ में प्रकाशित की गईं।

(vi) राष्ट्रीय शिक्षक आयोग

संस्थान ने राष्ट्रीय शिक्षक आयोग (उच्च शिक्षा) की विभिन्न बैठकों में तथा राष्ट्रीय शिक्षक आयोग (स्कूल शिक्षा) की विभिन्न बैठकों में भाग लिया और इसके विचार-विमर्श के दौरान महत्वपूर्ण योगदान किया।

(vii) शिक्षा मंत्रियों/सचिवों की बैठकों में भागीदारी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तरों पर आयोजित विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों, शिक्षा सचिवों और शिक्षा निदेशकों की विभिन्न बैठकों में संस्थान ने भाग लिया। इन बैठकों में शैक्षिक योजना और प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए और शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के कैडर को व्यावसायिक दक्षता प्रदान करने के लिए संस्थान ने बहुमूल्य सुझाव दिए।

(viii) शिक्षा मंत्रालय की बैठकें

इस वर्ष के दौरान शिक्षा मंत्रालय के ब्यूरो अध्यक्षों की बैठकों में संस्थान ने नियमित रूप से भाग लिया। संस्थान ने निम्नलिखित विशेष बैठकों में भी भाग लिया :

1. शैक्षिक परामर्शदात्री समिति
2. शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन
3. बीस सूत्री कार्यक्रम के सोलहवें सूत्र की राष्ट्रीय समिति
4. राज्य प्रौढ़ शिक्षा निदेशालयों तथा राज्य संसाधन केंद्रों के निदेशकों की बैठक
5. प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण तथा प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा के लिए पारितोषिक के मानदंड तय करने के लिए बुलाई गई बैठक
6. (i) लड़कियों का नामांकन, (ii) अनौपचारिक शिक्षा, और (iii) प्रौढ़ महिला साक्षरता को प्रोत्साहन पुरस्कार देने के लिए शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति की बैठक
7. मंत्रालय के परामर्शदायी कैडर को पुनः बनाने के लिए बैठक
8. शिक्षा मंत्रालय में केंद्रीय विद्यालय संगठन की बैठक
9. शैक्षिक नीति, नियोजन, प्रबंध और मूल्यांकन के अध्ययन की सहायता योजना के अंतर्गत अनुसंधान प्रस्तावों पर विचार करने के लिए बुलाई गई बैठक
10. शिक्षा मंत्रालय के शैक्षिक कार्यक्रमों के संचारेक्षण के लिए सूचना प्रणाली को संगणकीकृत करने के लिए बैठक
11. शिक्षा मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक

(ix) बैठकें, संगोष्ठियां तथा परिचर्चाएं

निम्नांकित बैठकों, संगोष्ठियों तथा परिचर्चाओं में संस्थान ने भाग लिया :

1. बड़े विश्वविद्यालयों के लिए प्रशासनिक उपकेंद्र स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश सुझाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समिति
2. सहकारी प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद की समिति
3. नए विश्वविद्यालय खोलने तथा स्नातकोतर शिक्षण के लिए नए केंद्र खोलने के लिए बनी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थाई समिति
4. भारत के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को विश्वविद्यालयों की मांगों के लिए सम्मेलन
5. स्कूलों में संगणकों का इस्तेमाल आरंभ करने के लिए समिति
6. समुदाय के कमजोर वर्गों के छात्रों को रखने के लिए कुछ छात्रावास वाले स्कूल चलाने के औचित्य पर विचार करने के लिए समिति
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान द्वारा आयोजित शैक्षिक मूल्यांकन पर कार्य-शिविर
8. पर्यावरण शिक्षण पर अखिल भारतीय संगोष्ठी
9. ब्रिटिश काउंसिल द्वारा आयोजित शिक्षा में नैतिक मूल्यों पर परिचर्चा

10. इंडिया इंटरनेशनल सेंटर द्वारा आयोजित शिक्षा के विशेष संदर्भ में सातवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के उपागम पर पैनल विचार-विमर्श
11. यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग द्वारा आयोजित शिक्षकों की हैसियत पर संगोष्ठी
12. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रौढ़ शिक्षा में विश्वविद्यालयों की भूमिका पर संगोष्ठी
13. विश्वविद्यालयों में प्रौढ़ तथा अनवरत शिक्षा तथा विस्तार कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की परामर्शदात्री समिति
14. विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण तथा दूसरे मामलों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समिति
15. भारतीय विश्वविद्यालय संगठन द्वारा आयोजित संगणक तथा परीक्षा पर आयोजित कार्यशिविर
16. प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के आधारभूत साक्षरता सामग्री के पुनरीक्षण संबंधी निर्देशिका बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति
17. दो स्तर के लिए योजना तैयार करने के लिए खुला विद्यालय समिति
18. योजना आयोग द्वारा आयोजित "ब्रेन ट्रेन" पर परिचर्चा
19. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा आयोजित स्कूल शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी तथा संगणक की सहायता से चलने वाली शिक्षा पर सम्मेलन
20. इंस्टीच्यूट आफ अप्लाएड मैन पावर रिसर्च द्वारा आयोजित रोजगार नीति पर संगोष्ठी ।

(x) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद से सहयोग

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण कार्यक्रम और +2 स्तर पर शिक्षा के व्यवसायीकरण कार्यक्रम के लिए संस्थान ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के साथ सहयोग किया। इसमें कार्यक्रम का खाका तैयार करने में तथा परिषद के अनौपचारिक शिक्षा तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के व्यवसायीकरण क्षेत्र में कार्यरत लोगों को व्याख्यान तथा विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित कर सहयोग प्राप्त किया गया। विभिन्न कार्यक्रमों में पैनल विचार-विमर्श में भी लोगों की भागीदारी थी। संस्थान द्वारा चलाए गए शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए नौ राज्यों में प्रारंभिक स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा के मूल्यांकन परक अध्ययन में, अध्ययन का खाका तैयार करने में परिषद का सक्रिय सहयोग शुरू से ही प्राप्त किया जाता है। अध्ययन परियोजना के एक हिस्से के रूप में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद पाठ्यक्रम की विषयवस्तु तथा शैक्षिक सामग्री और शैक्षिक युक्तियों के मूल्यांकन का कार्य भी हाथ में लेगा।

पाठ्यक्रम के प्रबंध तथा संगणक के उपयोग के मामले में भी संस्थान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के साथ सक्रिय सहयोग कर रहा है। परिषद ने संस्थान के विभिन्न कार्यक्रमों के भागीदारों के लिए इसमें प्रदर्शन का आयोजन किया है।

संस्थान ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की निम्नलिखित विभिन्न बैठकों, संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों में भाग लिया :

1. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण की तकनीकी

समिति

2. शिक्षा के व्यवसायीकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी
3. परिषद का नीति, नियोजन तथा सहयोग पर उपसमूह
4. बहरों के लिए एकीकृत शिक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी
5. एस यू पी यू/कार्यानुभव पर राष्ट्रीय स्तर की परामर्शदायी बैठक
6. माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन से संबंधित संचालन समिति
7. शिक्षा संबंधी "साफ्ट वेयर" पर राष्ट्रीय सम्मेलन
8. शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई अल्पसंख्यक स्कूलों की मार्गदर्शी सेवाओं के संबंध में संगोष्ठी
9. स्कूल शिक्षा में नए निदेशकों पर संगोष्ठी
10. अनौपचारिक शिक्षा पर वार्षिक सम्मेलन

II. प्रादेशिक स्तर

(अ) अध्ययन और परियोजनाएं

1. **दादरा तथा नागर हवेली के शिक्षा विभाग के पुनर्गठन का अध्ययन** : यह अध्ययन केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के अनुरोध पर हाथ में लिया गया था तथा इसे पूरा करके केंद्रशासित प्रदेश को उसी वर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई।

2. **पंजाब में शैक्षिक प्रशासन के आधुनिकीकरण का अध्ययन** : पंजाब के शिक्षा विभाग के अनुरोध पर राज्य में सूचना प्रबंध प्रणाली शुरू करने के विशेष संदर्भ में नीपा ने एक अध्ययन हाथ में लिया। पंजाब में शिक्षा प्रशासन का आधुनिकीकरण नाम से रिपोर्ट उसी वर्ष राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई।

(ब) प्रशिक्षण कार्यक्रम

कुल मिलाकर नौ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। जम्मू तथा कश्मीर सरकार के अनुरोध पर एक कार्यक्रम, उत्तरप्रदेश सरकार के अनुरोध पर दो कार्यक्रम; अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन की ओर से एक कार्यक्रम; असम सरकार के अनुरोध पर दो कार्यक्रम; हरियाणा सरकार के अनुरोध पर एक कार्यक्रम; कश्मीर विश्वविद्यालय के लिए एक, तथा केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी प्रशासन के अनुरोध पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन कार्यक्रमों की सूची इस रिपोर्ट के प्रथम भाग में पहले ही दी गई है।

संस्थान ने शैक्षिक योजना और प्रशासन में आयोजित कार्यक्रमों में संकाय का समर्थन प्रदान किया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन जिन संस्थाओं ने किया था, उनके नाम इस प्रकार हैं :

(i) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़
(ii) एस एन डी टी महिला विश्वविद्यालय, बंबई
(iii) राज्य शिक्षा संस्थान, हरियाणा
(iv) राज्य शिक्षा संस्थान, दिल्ली

(v) राज्य शिक्षा संस्थान, उत्तरप्रदेश

(स) संगोष्ठियों, कार्यशिविरों, समितियों, कृतिक बलों तथा अन्य परामर्शदायी सेवाओं में संकाय का योगदान

1. कोहिमा में आयोजित, उच्च शिक्षा की योजना और उसका प्रशासन पर संगोष्ठी,
2. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में कार्य अध्ययन तथा कैडर समीक्षा समिति
3. पंजाब के शिक्षा सुधार आयोग की बैठक
4. इलाहाबाद विश्वविद्यालय : चुनौतियां और परिप्रेक्ष्य पर संगोष्ठी
5. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्कूल शिक्षा मंडल की बैठक
6. भारतीय शिक्षा संस्थान, पूना द्वारा आयोजित लेखकों के केस अध्ययन पर कार्यशिविर
7. दिल्ली प्रशासन के राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन समिति
8. माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए पुस्तकों की तैयारी तथा प्रकाशन के लिए मार्ग-दर्शिका तथा मानदंड तैयार करने के लिए राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा मंडल की समिति
9. एस एन डी टी महिला विश्वविद्यालय की योजना समिति
10. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एकीकृत ग्रामीण विकास पर कार्यशिविर
11. हरियाणा, समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित बाल विकास पर संगोष्ठी
12. मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यायय, कोदाई कनाल द्वारा आयोजित शिक्षा तथा महिलाओं के लिए रोजगार विषय पर संगोष्ठी
13. राजस्थान में जनजातियों के शिक्षा के विकास पर कार्यशिविर
14. जम्मू तथा कश्मीर में एन सी ई आर टी के स्कूल पाठ्यक्रम पर बैठक
15. दिल्ली विश्वविद्यालय, रसायनशास्त्र शिक्षा का संपादक मंडल
16. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के लिए तमिलनाडु की राज्य परिषद के अनुसंधान और प्रशिक्षण का पैनल
17. उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
18. भोपाल में आयोजित जनजातीय जनांकिकी
19. जम्मू विश्वविद्यालय के प्रौढ़ शिक्षा तथा सतत शिक्षा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक
20. काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्कूलों में 10+2 शिक्षा प्रारंभ करने के विषय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति की बैठक
21. सौराष्ट्र विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उच्च शिक्षा में परीक्षा के सुधार विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी
22. भारतीय शिक्षा संस्थान, पूना द्वारा आयोजित शिक्षा में विकल्प पर संगोष्ठी

अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

संस्थान कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से भी काम करता आ रहा है, ये संस्थाएं हैं : एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के लिए शिक्षा का यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकाक; शैक्षिक योजना का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान पेरिस; तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमंडल कोष; संयुक्त राष्ट्रसंघ का विकास कार्यक्रम; स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय

विकास अभिकरण तथा भारत में संयुक्त राज्य अमरीका का शिक्षा संगठन आदि। इनके साथ शैक्षिक योजना तथा प्रशासन से संबंधित कार्यक्रमों में ही संस्थान ने सहयोग लिया।

8 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, इनमें दो छः मास के अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी शामिल थे। इन कार्यक्रमों में भागीदारों का प्रायोजन उपर्युक्त संस्थान तथा उनकी सरकारों ने क्रमशः किया था। इनके अतिरिक्त 4 अध्ययन दौरों का भी आयोजन किया गया जिनमें से तीन यूनेस्को द्वारा प्रायोजित थे तथा एक अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान पेरिस के अनुरोध पर आयोजित किया गया था।

भाग चार

अन्य अकादमिक गतिविधियां

प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श और सलाहकारी सेवाएं (शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में) संस्थान की प्रमुख गतिविधियों का अंग हैं। इनके अतिरिक्त दूसरी महत्वपूर्ण गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है :

(अ) वरिष्ठ शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के बीच अनुभवों के पारस्परिक आदान-प्रदान के लिए और शैक्षिक योजना और प्रशासन में गहन नवाचारी प्रयोग के लिए अंतर्राज्यीय अध्ययन दौरों का आयोजन करना ताकि एक दूसरे के विचारों की जानकारी को बढ़ावा मिले और विस्तार की संभावना और सफल प्रयोगों तथा नवाचारों को दूसरे राज्यों तक पहुंचाया जा सके,

(ब) विचार-विमर्श के लिए पहल करना जिससे संकाय अपनी अवधारणा शक्ति को तीव्र बना सके, इसके सैद्धांतिक आधार को सुदृढ़ कर सके और देश की शैक्षिक नीति के आधारभूत मुद्दों तथा उद्देश्यों पर अधिक स्पष्ट बुद्धि से योगदान कर सकें,

(स) शैक्षिक योजना तथा प्रशासन में नवाचारी अवधारणाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करना,

(द) अन्य संगठनों की गतिविधियों में तथा अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में संकाय के सदस्यों द्वारा अकादमिक योगदान करना,

(य) प्रतिनिधियों और आगंतुकों के आने पर उनका स्वागत सत्कार करना।

इस प्रकार की अकादमिक गतिविधियों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है जो समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संस्थान ने चलाई थी :

(अ) अंतर्राज्यीय अध्ययन दौरे

विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित होने वाले नवाचारी प्रयोगों को लेखाबद्ध किया गया है। यह कार्य नियमित रूप से अंतर्राज्यीय दौरों के आयोजन के उद्देश्य से किया जाता है।

एक अंतर्राज्यीय दौरे का आयोजन किया गया जो इस शृंखला में तीसरा था फरवरी 4—9, 1985। इसका उद्देश्य, "अध्ययन के दौरान अर्जन" कार्यक्रम को निकट से देखना था। इस कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने की है। पांच राज्यों के वरिष्ठ शिक्षा कर्मियों ने इसमें भाग लिया। ये राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तथा केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़। इनके साथ योजना आयोग, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के प्रतिनिधि भी शामिल थे। भागीदारों को चार समूहों में बांट दिया गया था जिन्होंने

मध्यप्रदेश के चार क्षेत्रों का दौरा किया तथा "अध्ययन के दौरान अर्जन" कार्यक्रमों का निकट से निरीक्षण किया।

मध्य प्रदेश की "अध्ययन के दौरान अर्जन" योजना पर संस्थान एक पुस्तक के प्रकाशन पर विचार कर रहा है। इस पुस्तक का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। यह पुस्तक पूरे देश में इस सफल प्रयोग के संदेश को फैलाने में काफी उपयोगी रहेगी।

(ब) नीपा विचार मंच

शिक्षा और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श तथा विचारों के आदान-प्रदान के लिए नीपा विचार मंच एक प्रोफेशनल मंच है। इसका उद्देश्य सकाय की अवधारणा क्षमता को तीव्र बनाना, इसके सैद्धांतिक आधार को सुदृढ़ बनाना तथा शैक्षिक नीति तथा उद्देश्यों के प्रश्नों पर अधिक स्पष्टता के साथ योगदान करना है। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भागीदार तथा दिलचस्पी लेने वाले लोगों का नीपा विचारमंच स्वागत करता है।

वर्ष 1984-85 के दौरान 26 विचार विमर्श आयोजित किए गए। इन विभिन्न आयोजनों में जिन विषयों में बातचीत की गई, उनमें इस प्रकार के विषय थे : योजना तथा प्रबंध विकास की दुविधा, शिक्षा तथा समाज पर प्रोद्यौगिकी का प्रभाव। इसमें भाग लेने वाले वक्ता विभिन्न संगठनों के कार्यकर्त्ता रहे हैं, जैसे भारत तथा बाहर के विश्वविद्यालयों के लोग, विशेषज्ञता वाले संस्थानों, योजना आयोग, शिक्षा मंत्रालय तथा नीपा। विभिन्न विषयों का विस्तृत विवरण तथा उनके वक्ताओं के नाम नीचे की तालिका में दिए गए हैं :

1 क्रम सं०	2 विषय	3 वक्ता का नाम	4 तिथि
1.	मूल्य शिक्षा	श्री जोस पाल शैक्षिक योजना, नई दिल्ली	अप्रैल 11, 1984
2.	शिक्षा व्यवस्था के प्रबंध के कुछ मुद्दे	डा. वी एस गौतम, प्रोफेसर सी एस एम आई आई टी, नई दिल्ली	अप्रैल 25, 1985
3.	प्रौढ शिक्षा में जनता की भागीदारी	श्री एस के मैत्रा, राज्य संसाधन केंद्र के निदेशक, पश्चिम बंगाल समाज सेवा लीग, कलकत्ता	मई 2, 1984
4.	शैक्षिक प्रभाव के आकलन के लिए वैकल्पिक पद्धतियां	डॉ. एम मुखोपाध्याय वरिष्ठ अध्येता, नीपा	मई 9, 1984
5.	शिक्षा में भेदभाव-पूर्ण मूल्य निर्धारण	डॉ. जे बी जी तिलक, नीपा तथा डॉ. एन वर्गीस, नीपा	मई 16, 1984

1	2	3	4
6.	शिक्षा में निवेश तथा सामाजिक चुनाव	डा. तापस मजुमदार, प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	
7.	संगठनात्मक स्वमूल्यांकन	डा. जे एच वाली, ब्रिटिश कोलंबिया वि वि कनाडा	मई 30, 1984
8.	फिलिपाइन्स में शिक्षा व्यवस्था : आर्थिक आधार और सामाजिक परिणाम	श्री जय भगवान, परियोजना सहायक, नीपा	जून 13, 1984
9.	स्कूल पुस्तकालय का संगठन	श्री एस सत्यनारायण जिला शिक्षाधिकारी कर्नाटक	जून 20, 1984
10.	शैक्षिक विकास के लिए भावी योजना	श्री पी सी सूरी, निवर्तमान प्रतिनिधि पंजाब सरकार	जून 28, 1984
11.	प्रखंड स्तर की योजना	कु. प्रीति तथा कु. इथर स्कूल आफ प्लानिंग, अहमदाबाद	जुलाई 11, 1984
12.	शिक्षा में केंद्र राज्य संबंध	डा. डी सेन गुप्त, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली	जुलाई 11, 1984
13.	विशेष शिक्षा की वर्तमान स्थिति तथा भावी प्रबंधकीय चुनौतियां	श्री ए के मित्तल चेयरमैन, ब्लाइंड रीलीफ एसोसिएशन, नई दिल्ली	जुलाई 18, 1984
14.	सार्वजनीन प्रारंभिक शिक्षा : एक विकल्प	डा. जान कुरियन, अधिगम संसाधन केंद्र, पूना	जुलाई 25, 1984
15.	शैक्षिक प्रोद्यौगिकी का प्रबंध	डा. एस एस कुलकर्णी, सीनियर प्रोफेसर, एन आई बी एम, पूना	अगस्त 2, 1984
16.	शिक्षा में प्रवेश बिंदु के रूप में बाल अनुरक्षण	डा. एस चौधरी प्रोफेसर एमेरिटस बाल स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता	अगस्त 23, 1984
7.	शिक्षा में संगणक	डा. आर सक्सेना एन. सी ई आर टी, नई दिल्ली	सितंबर 19, 1984

1	2	3	4
18.	ग्रामीण दरिद्रता का निवारण	डॉ. डी बेदोपाध्याय, आई ए एस, सलाहकार, 20 सूत्री कार्यक्रम तथा ग्राम विकास, योजना आयोग, नई दिल्ली	नवंबर, 21, 1984
19.	प्रौढ़ शिक्षा में चीन का अनुभव	डॉ. एस के टुटेजा, निदेशक प्रौढ़ शिक्षा, भारत सरकार	दिसंबर, 19,1984
20.	प्रबंध सूचना प्रणाली तथा संगणक	डॉ. एल एस गणेश, नीपा, नई दिल्ली	जनवरी 2, 1985
21.	शिक्षा में नया बल	प्रो. एस शुक्ल, प्रोफेसर शिक्षा, जामिया मिल्लया इस्लामियां, नई दिल्ली	जनवरी 23,1985
22.	कर्म संस्कृति	श्री सतबीर (कमोडोर) आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली	जनवरी 30, 1985
23.	प्रबंध : एक सरकारी अधिकारी का दृष्टिकोण	डॉ. डी एन कौल, आई पी एस, भूतपूर्व महा निदेशक पुलिस जम्मू तथा कश्मीर	फरवरी 6, 1985
24.	भागीदारीमुक्त प्रबंध	एक चलचित्र "टाप टु बॉटम"	फरवरी 27, 1985
25.	विकास की दुविधा	प्रो. आर एल पारेख, कुलपति गुजरात विद्यापीठ	मार्च 21, 1985
26.	प्रौद्योगिकी समाज और शिक्षा	डॉ. एन सी माथुर, प्रबंध निदेशक, एजुकेशन कनसलटेंट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	मार्च 27, 1985

(स) शैक्षिक योजना और प्रशासन में नवाचारी अवधारणाओं तथा व्यवहारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

शैक्षिक योजना और प्रशासन में नवाचारी अवधारणाओं तथा व्यवहारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया। इसकी शुरूआत वर्ष 1982-83 में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई थी :

1. व्यष्टि स्तर पर शैक्षिक योजना और प्रशासन में नवाचारी व्यवहारों को बढ़ावा देना;
2. अपने रचनात्मक सोच तथा नवाचारी प्रयोगों के अनुभवों को सहज तरीके से कहने तथा अर्थपूर्ण ढंग से उसका सार प्राप्त करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को उत्प्रेरित करना;
3. ऐसे साधन उपलब्ध कराना जिसके जरिए ऐसे प्रयोगों, अनुसंधानों तथा रचनात्मक सोच के नतीजों को (जिला शिक्षाधिकारियों के) उनके अन्य सहयोगियों तक पहुंचाया जा सके।

इस कार्यक्रम को खास तौर से इस तरह का बनाया गया है जिससे जिला शिक्षा अधिकारी शक्षिक योजना और प्रशासन में नवाचारी व्यवहारों को (व्यष्टि स्तर पर) बढ़ावा दे सकें तथा एक दूसरे के अनुभव का आदान प्रदान कर सकें। जिला स्तर पर शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित नवाचारी तथा प्रयोगात्मक विषय पर भागीदारों को आलेख लिखने की आवश्यकता होती है। जिन आलेखों को पुरस्कृत किया जाता हैं उनमें से प्रत्येक विजेता को रु. 1000/-देने का प्रावधान है (अधिकतम 10 व्यक्तियों को)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान तीसरी अखिल भारतीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया लेकिन नियुक्त किये गए निर्णायकों ने जितने आलेख जमा किए गए थे, उनमें से एक को भी पुरस्कार के उपयुक्त नहीं माना। व्यापक भागीदारी के लिए प्रस्ताव हैं कि इसमें उप जिला शिक्षा अधिकारियों, वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के प्रधानों, उच्चतर माध्यमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों को भी शामिल किया जाए। यह प्रस्ताव है कि इसको अधिकाधिक प्रचारित करने के लिए शैक्षिक पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में भी भविष्य में विज्ञापित किया जाए।

(द) विशेषज्ञता के क्षेत्रों में संकाय का अकादमिक योगदान

संस्थान के संकाय अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, दूसरे अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थानों को अकादमिक तथा प्रोफेशनल आगत प्रदान करते हैं, अकादमिक तथा अधिकारियों की समितियों में सदस्य के रूप में सेवा करते हैं, शिष्ट मंडलों में जाते हैं तथा विशेषज्ञता के विविध क्षेत्रों में अनुसंधान आलेख तथा पुस्तकें प्रकाशित कराते हैं।

संस्थान ने निम्नांकित संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों संकाय का समर्थन प्रदान किया, भारतीय विश्व विद्यालयों का संस्थान, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़; काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, प्रौढ़ शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली; केंद्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली; भारतीय शिक्षा संस्थान, पूना; राष्ट्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली; एन सी ई आर टी, योजना आयोग, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; पंजाब राज्य लोक प्रशासन संस्थान, तथा संयुक्त स्कूल संगठन।

संकाय की इन गतिविधियों का संक्षिप्त ब्यौरा संलग्नक तीन में दिया गया।

(य) प्रतिनिधि और आगंतुक

देश के विभिन्न भागों से संस्थान में प्रतिनिधि आते हैं, विदेशों से भी संस्थान में प्रतिनिधि आते हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जिन महत्वपूर्ण लोगों ने संस्थान का दौरा किया उनके संस्थानों के नाम इस प्रकार हैं: शैक्षिक योजना का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, पेरिस; राष्ट्रीय प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, मलेशिया; स्टाकहोम शिक्षा संस्थान, स्टाकहोम, स्वीडन; अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान विकास केंद्र, सिंगापुर आदि। आगंतुक व्यक्तियों में मंत्रीगण, कुलपति तथा अन्य विख्यात शिक्षाविद और भारत सरकार के मंत्रालयों के लोग थे। इसके अतिरिक्त योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षासचिव, शिक्षा निदेशालय के व्यक्ति तथा राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारीगण थे। संलग्नक चार में इन आगंतुकों की एक सूची दी गई है।

भाग पांच

अकादमिक एककें

संस्थान के संकाय को निम्नांकित आठ अकादमिक एककों में बांटा गया है :

1. शैक्षिक योजना एकक
2. शैक्षिक प्रशासन एकक
3. शैक्षिक वित्त एकक
4. शैक्षिक नीति एकक
5. स्कूल तथा अनौपचारिक शिक्षा एकक
6. उच्च शिक्षा एकक
7. प्रादेशिक शिक्षा व्यवस्था एकक
8. अंतर्राष्ट्रीय एकक

अकादमिक एककों की भूमिका

अकादमिक एककों से यह उम्मीद की जाती है कि वे विभिन्न प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्यक्रमों के विकास तथा क्रियान्वयन के लिए पूरी जिम्मेदारी से कार्य करेंगी तथा संस्थान की नीति के अनुसार तथा उपलब्ध धनराशि के अंतर्गत अपने-अपने विशेष क्षेत्र में परामर्श तथा सलाहकार सेवाएं प्रदान करेंगी । एककों से उम्मीद की जाती हैं कि :

1. वे विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए समय सारणी बनाएंगें।
2. परामर्श तथा सलाहकार सेवाओं के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करेंगे।
3. उनको अपने अपने अध्ययन क्षेत्र में संस्थान में जो कार्य सौंपा गया है उसमें सहयोग करेंगे।
4. एकक के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तथा अनुसंधान की रूपरेखा पर विचार करेंगे।
5. समय समय पर दिए गए अन्य कार्यों को भी पूरा करेंगे।

एकक के अध्यक्षों से उम्मीद की जाती है कि वे अपनी अपनी एकक का मार्गदर्शन करेगे। उनके कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करेंगे तथा उनके कर्तव्य पालन में उनकी मदद करेंगे तथा एकक में समय समय पर बैठकें आयोजित कर उसमें विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तथा अन्य गतिविधियों पर विचार विमर्श करेंगे। वे अपनी एकक की आवश्यक देखरेख भी करते हैं। वे अन्य संकाय सदस्यों के काम की देखरेख भी करते हैं। इन के ऊपर सामान्य पर्यवेक्षण, निदेशक, कार्यकारी निदेशक तथा डीन प्रशिक्षण का होता है।

अकादमिक एकक दीर्घावधि तथा धारावाहिक आधार पर कार्य करती है। खास कार्यक्रमों के लिए समय समय पर निदेशक विशेष समितियां तथा कृतिक बल का निर्माण करता है। संस्थान द्वारा हाथ में लिए गए विभिन्न अनुसंधान कार्यक्रमों का परामर्श देने, सुझाव देने और उनके संचारेक्षण के लिए विशेषज्ञ लोगों की समितियां बनाई जाती हैं।

संकायों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के मोटे स्वरूप की रूपरेखा नीचे दी जा रही है :

शैक्षिक योजना एकक

शैक्षिक योजना के दो व्यापक आयाम होते हैं। पहला यह कि विकास तथा परिवर्तन के संदर्भ में यह शिक्षा तथा दूसरे सामाजार्थिक क्षेत्रों के दुहरे संबंधों के साथ कार्य करता है। दूसरी बात यह है कि शैक्षिक क्षेत्र के निष्पादन के मूल्यांकन में भी यह मदद करता है तथा लक्ष्यों तक किस प्रकार पहुंचा जा सकता है, इसके लिए उपाय निकालता है। शैक्षिक योजना एकक इन दोनों पक्षों का विस्तार से अध्ययन करता है ताकि समन्वित रूप से नीति के प्रभावों की प्रकाश में लाया जा सके। शिक्षा मंत्रालय, योजना आयोग तथा कुछ राज्य सरकारों के समर्थन में यह व्यावसायिक समूह की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ऐसा करने की क्षमता हासिल करने के मकसद से एककें अपने भीतर विशेषता विकसित करने की कोशिश करती हैं, दोनों ही क्षेत्रों में, परिप्रेक्ष्य निर्माण में तथा प्रतिरूप निर्माण के श्रमसाध्य क्षेत्र तथा पद्धति विश्लेषण के क्षेत्र में भी। यह शिक्षा व्यवस्था को संपूर्ण समाज व्यवस्था का एक हिस्सा मानती है तथा परिवर्तन के क्षेत्र में गति-निर्धारक तत्व।

और अधिक स्पष्ट रूप सें कहें तो कहना चाहेंगे कि शैक्षिक योजना क्षेत्र का प्रशिक्षण तथा अध्ययन शिक्षा और जनांकिकी, शिक्षा तथा रोजगार का विश्लेषण करता है तथा इनके बीच समन्वय कायम करता है साथ ही एक ही क्षेत्र के भीतर समन्वय स्थापित करता है जैसे शैक्षिक योजना में मानवशक्ति का अनुमान तथा शिक्षा में क्षेत्रीय तथा संस्थागत योजना। इस एकक की गतिविधियां योजना के अंतर्गत शिक्षा, बहुस्तरीय योजना, तथा मात्रात्मक प्रारूपों तथा तकनीकों के आधार पर दीर्घावधि भविष्यपरक अध्ययन आदि पर केंद्रित रहती है।

इस वर्ष के दौरान संस्थान ने इस एकक के माध्यम से पांच कार्यक्रम आयोजित किए, उदाहरणार्थ, अफगानिस्तान के अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना में प्रशिक्षण कार्यक्रम (मार्च 4-मई 4, 1984), सेंटर आफ इनवायरनमेंट प्लानिंग एंड टेक्नालोजी, स्कूल आफ प्लानिंग, अहमदाबाद के लिए, स्नातकोत्तर योजना छात्र (मई 7-जुलाई 7, 1984), शिक्षा में सातवीं पंचवर्षीय वोजना तैयार करने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (जून 4-जून 15, 1984) भविष्यवाणी की पद्धतियों तथा अनुमान की तकनीकों पर कार्य शिविर (मार्च 18-22, 1985) और शिक्षा अधिकारी (थाईलैंड) के लिए शैक्षिक योजना में दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (मार्च 5-अगस्त 31, 1985)

इस समय यह एकक एक अनुसंधान परियोजना में व्यस्त है जिसका नाम है, "वर्ष 2000 सें शिक्षा" इसका उद्देश्य देश में दीर्घावधि शैक्षिक योजना को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र राज्य के लिए प्रमुख शैक्षिक चरों के अनुमान पर पहले ही रिपोर्ट का प्रारूप तैयार कर चुकी है। इसी वर्ष के दौरान दो और परियोजनाएं इस एकक ने हाथ में ली थीं जिनका क्रमशः नाम है "शिक्षा तथा रोजगार के बीच लाभकारी संरचनात्मक संबंध : एक पृष्ठभूमि खंड", तथा "शिक्षा और ग्रामीण विकास"। ये दोनों परियोजनाएं अब पूरी होने वाली हैं।

शैक्षिक प्रशासन एकक

वर्तमान दायित्वों की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तथा समय समय पर पैदा होने वाले नए कार्यों के पूरा करने के लिए शिक्षा का आधुनिकीकरण कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। जहां प्रशासनिक व्यवस्था के संरचनात्मक स्वरूप में सुधार की आवश्यकता है, वर्तमान पद्धति के उपयोगी प्रबंध के माध्यम से निकट भविष्य में शीघ्र परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं, विशेष रूप से संस्थानों के नैतिक बल को प्रोत्साहित करके तथा कार्मिक प्रबंध को सुधार कर।

संस्थान के मुख्य सरोकारों में से एक सरोकार शैक्षिक प्रशासकों के व्यावसायिक विकास द्वारा शिक्षा के प्रशासन में सुधार करना है। प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा अन्य गतिविधियों के जरिए शैक्षिक प्रशासन एकक सांस्थानिक स्तरों पर शैक्षिक प्रशासकों की कार्यक्षमता को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करती है। जहां एक ओर यह शैक्षिक प्रशासन तंत्र को आधुनिक बनाने में मदद करती है, वहीं यह इस बात के लिए भी प्रयास करती है कि वे नई चुनौतियों और नई आवश्यकताओं की पूर्ति में भी समर्थ हों, सामाजिक चुनौतियों का सामान्य रूप से तथा शैक्षिक चुनौतियों का विशेष रूप से। कुछ विषयों पर विशेष जोर दिया जाता है, जैसे सांस्थानिक प्रबंध, प्रतिनिधान, नेतृत्व, निर्णय करना, उत्प्रेरणा, संप्रेषण, विवादों का प्रबंध, समय का प्रबंध, मानव संसाधन का विकास, नवाचारों तथा परिवर्तन का प्रबंध, व्यक्तिगत मूल्यांकन, संस्थागत मूल्यांकन आदि यानी जिन विषयों की शिक्षा के क्षेत्र में प्रासंगिकता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एकक ने ग्यारह कार्यक्रम विश्वविद्यालय तथा स्कूलों के प्रबंध से संबंधित आयोजित किए। इसमें तकनीकी शिक्षा भी शामिल थी। इनमें निम्नांकित कार्यक्रम शामिल है, कुलसचिवों के लिए विश्वविद्यालयों के प्रति नवाचारी दृष्टि पर कार्य शिविर (मई 28-जून 5, 1984) केंद्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षा अधिकारियों तथा शिक्षा आयुक्तों के लिए दो प्रशिक्षण कार्यक्रम (मई 21-जून 1, 1984 तथा दिसंबर 3-14, 1984), असम के स्कूल प्राचार्यों के लिए दो कार्यक्रम (फरवरी 5-8 1985 तथा जून 21-23, 1984) जम्मू तथा कश्मीर के पोलिटेकनीक महिला शिक्षिकाओं तथा प्रशासकों के लिए दो कार्यक्रम, विषय तकनीकी शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण (अप्रैल 9-11, 1984, जनवरी 28-फरवरी 7, 1985), प्रथम स्तर के इंजीनियरिंग कालेजों के प्रबंध पर संगोष्ठी, (अगस्त 13-18, 1984) नेतृत्व तथा निर्णय पर विषय केंद्रित कार्यशिविर (फरवरी 25-मार्च 1, 1985) तथा फिलीपाइन्स के शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय योजना सेवा के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (अगस्त 2-सितंबर 9, 1984)।

इस वर्ष इस एकक द्वारा चलाई जा रही दो परियोजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई। ये परियोजनाएं हैं: "कालेजों के प्रधानों का भूमिका निष्पादन" इसका उद्देश्य है इस बात का पता लगाना कि ये अपनी विभिन्न भूमिकाएं किस सीमा तक निभा सकते हैं तथा उन कारकों का पता लगाना जो इनकी भूमिका को प्रभावित करते हैं। दूसरी परियोजना हैं, "इंजीनीयरिंग कालेजों में कर्मचारियों का ढांचा तथा सामग्री सूची प्रबंध।"

शैक्षिक वित्त एकक

भारत जैसे विशाल देश में सभी स्तरों पर शिक्षा का अभूतपूर्व विस्तार तथा जनसंख्या में वृद्धि ने शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था पर काफी दबाव पैदा किया है। इसलिए शैक्षिक वित्त के प्रबंध ने महत्वपूर्ण रूप ग्रहण कर लिया है।

इस नई स्थिति के अनुसार शैक्षिक वित्त एकक राज्य के शिक्षा विभाग तथा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा उनकी वित्त प्रबंध की क्षमता बढ़ाने में संलग्न है। यह शिक्षा में नवीनतम विकास और शिक्षा की नवीनतम प्रवृत्तियों में उनको परिचित कराता है तथा वित्त प्रबंध की आधुनिकतम प्रणालियों और तकनीकों की उन्हें जानकारी देता है। यह निम्नलिखित विषयों में उनकी जानकारी बढ़ाकर उन्हें दक्षता प्रदान करता है जैसे पी पी बी एस, संसाधन का उपयोग, लागत निकालना, व्यय का संचारेक्षण, शैक्षिक विकास के लिए गैर मौद्रिक आगत; आदि। इस वर्ष के दौरान शैक्षिक वित्त एकक ने दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए : विश्वविद्यालय के वित्त प्रबंध पर अभिविन्यास कार्यक्रम (फरवरी 4-9, 1985) तथा राज्य शिक्षा अधिकारियों के लिए वित्त प्रबंध पर अभिविन्यास कार्यक्रम (अगस्त 21-31, 1984)।

इस एकक ने दो अनुसंधान अध्ययनों को अंजाम दिया : गुड़गांव जिला (हरियाणा) में "शिक्षा आपूर्ति की लागत," और "भारत में शिक्षा के लिए संसाधनों की व्यवस्था"। "केरल तथा उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में शिक्षा की समानता" नामक परियोजना प्रगति पर है।

शैक्षिक नीति एकक

शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का एक महत्वपूर्ण कारक मानकर स्वतंत्रता के बाद से ही सरकार की मुख्य चिंता शिक्षा पर अधिकाधिक ध्यान देने की रही है। सभी के लिए शिक्षा सुलभ हो, समाज की आवश्यकताओं से जोड़ने के लिए शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हो और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, सरकार लगातार इसके लिए कोशिश कर रही है। ग्रामीण तथा अन्य पिछड़े इलाकों में शिक्षा सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं तथा जनजातियों, लड़कियों और अपंग लोगों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा को भविष्य के परिप्रेक्ष्य के रूप में भी देखा जा रहा है।

भारत तथा तीसरी दुनिया के शैक्षिक नीति के महत्वपूर्ण मुद्दों को शैक्षिक नीति एकक ने अपना लक्ष्य बनाया है। जिन प्रमुख मुद्दों को लेकर शैक्षिक नीति एकक की चिंता है, वे हैं : शिक्षा और विकास तथा उनका अंत:संबंध, गुणवत्ता तथा मात्रात्मकता, समता और कार्यक्षमता के मुद्दे; शिक्षा तथा परिवर्तन तथा परंपरा और आधुनिकता के सवाल; शिक्षा में केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण तथा समवर्ती सूची में केंद्र राज्य संबंध।

इस एकक की अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां इनमें से ही एकाध विषयों से संबद्ध है।

इस एकक ने आश्रम स्कूलों के प्रधानों व जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया (मई 7-11, 1984) इस एकक ने देश के मध्यवर्ती क्षेत्र के जनजातीय इलाकों के लिए एक अनुसंधान कार्यक्रम चलाया था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सामग्री इसी अनुसंधान से ली गई थी। "शिक्षा में न्यायता" पर राज्य शिक्षा अधिकारियों के लिए (योजना अधिकारी) एक अन्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था (सितंबर 24-28, 1984)। "शैक्षिक विकास में क्षेत्रीय असमानता : भारतीय शिक्षा का मानचित्र" इस वर्ष के दौरान पूरा किया गया तथा "केरल में शिक्षा के विकास का इतिहास" नामक अनुसंधान अध्ययन प्रगति पर है।

स्कूल तथा अनौपचारिक शिक्षा एकक

स्कूल तथा अनौपचारिक शिक्षा एकक ने निम्नांकित को अपना लक्ष्य बनाया है : स्कूल तथा अनौपचारिक शिक्षा से संबद्ध विभिन्न समस्याएं तथा प्रबंध संबंधी मुद्दे, इन समस्याओं को हल करने के लिए वैकल्पिक हल तलाशने की रणनीतियां तय करना, इसके लिए स्कूल प्राचार्यों तथा अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यों को आयोजन करना। यह उनके दक्षता, ज्ञान तथा रुख को विकसित करना चाहती है तथा उनकी व्यावसायिक दक्षता में सुधार लाना चाहती है जिससे व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से वांच्छित परिणाम प्राप्त करने की स्थिति में हो सके।

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण कार्यक्रम को भारत ने अत्यंत उच्च प्राथमिकता दी है। स्वतंत्रता के बाद से सभी के लिए शैक्षिक अवसरों के विस्तार के कारण स्कूल शिक्षा को काफी व्यापक फैलाव प्रदान किया है जिसमें लड़कियों, सुविधा वंचित समुदायों के बच्चों पर अधिक ध्यान दिया गया है। चूंकि औपचारिक स्कूल शिक्षा के पूरक के रूप में अनौपचारिक, अंशकालिक तथा निजकालिक शिक्षा को जारी रखना है उससे शैक्षिक प्रशासन को एक नया आयाम मिला है। प्रौढ़ निरक्षरता निवारण कार्यक्रमों को भी अधिक महत्व दिया जा रहा है।

भारतीय राजव्यवस्था की इकाई के रूप में, जिले का विशेष महत्व है, यह इसके परिस्थितिकीय समरूपता, द्वंद्वात्मक एकरूपता पर जिला शिक्षाधिकारी शैक्षिक योजना और प्रशासन का प्रभारी होता है, वह कई अर्थों में भारतीय शिक्षा व्यवस्था की धुरी होता है। इस बात की ध्यान में रखकर यह एकक शैक्षिक योजना तथा प्रशासन में जिला शिक्षाधिकारियों के लिए छः मास का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है जिसमें तीन माह का संस्थान के भीतर गहन पाठ्यक्रम का कार्यक्रम होता है तथा तीन महीने का पर्यवक्षित परियोजना कार्य होता है जो वह अधिकारी अपनी नियुक्ति वाले जिले में जाकर करता है। इस कार्यक्रम का संक्षिप्त अवधि का एक पूरक कार्यक्रम चलाया जाता है जिसमें शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक/उपनिदेशक तथा अन्य वरिष्ठ शिक्षाधिकारी भाग लेते है। यह कार्यक्रम संगोष्ठी या कार्यशिविर के रूप में होता है। 1985-86 के बाद से दो डिप्लोमा कार्यक्रम हर साल चलाए जाने का प्रस्ताव है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एकक ने जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए तीसरा डिप्लोमा पाठ्यक्रम (जुलाई 2, 1984 जनवरी 28, 1985) आयोजित किया तथा सात कार्यक्रम स्कूल शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले कार्मिकों के लिए आयोजित किए। ये कार्यक्रम इस प्रकार हैं : "प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण पर कार्यशिविर" (अक्तूबर 15-19, 1984), "शिक्षा के सार्वजनीकरण में समुदाय की भागीदारी" पर कार्यशिविर (दिसंबर 3-14, 1984), अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा पर दो अन्य कार्यक्रम (अप्रैल 9-13, तथा अगस्त 6-10, 1984), तथा पांडिचेरी के स्कूल प्रधानों के लिए संस्थागत योजना पर कार्यशिविर (फरवरी 25-मार्च 2, 1985)।

उच्च शिक्षा एकक

स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत में उच्च शिक्षा की आकांक्षा तथा मांग लोगों में कई गुना बढ़ गई है। विश्वविद्यालय, कॉलेज तथा उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों की संख्या काफी बढ़ गई है। ये काफी संख्या में शिक्षित तथा प्रशिक्षित मानव शक्ति पैदा करते हैं लेकिन ज्ञान प्रदान करने तथा ज्ञान के विकास करने के साथ साथ

कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे समुदाय के विकास की गतिविधियों से अपने को जोड़ेंगे और विस्तारपरक गतिविधियों के जरिए उनकी सहायता करेंगे।

उच्च शिक्षा में संलग्न प्रमुख व्यक्तियों की क्षमताओं के विकास पर यह एकक विशेष ध्यान देती है, जैसे कॉलेजों के प्राचार्य, कॉलेज विकास समितियों के निदेश, छात्र कल्याण की संकायाध्यक्ष, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुल सचिव और अन्य अधिकारी। यह कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य संबद्ध संस्थाओं के सहयोग से किया जाता है। बदलती हुई सामाजिक आर्थिक स्थितियों में उच्च शिक्षा के संस्थानों में योजना तथा प्रशासन की आधुनिक तकनीकों पर यह विशेष बल देती है। कार्यक्रमों में जिन बातों पर विशेष बल दिया जाता है वे इस प्रकार हैं : उच्च शिक्षा को राष्ट्रीय विकास से जोड़ना, निर्णय लेना, अंतर्वैयक्तिक संबंध, कार्यालय प्रबंध, वित्तीय प्रबंध, जैसी आधुनिक तकनीकों के जरिए उच्च शिक्षा के संस्थानों की कार्यक्षमता को ऊपर उठाना, पाठ्यक्रमों को सामाजिक रूप से सार्थक बनाकर, नई शिक्षण पद्धतियां चलाकर छात्र सेवाओं को सुधार कर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना आदि। शिक्षण संस्थानों, छात्रों तथा अध्यापकों के मूल्यांकन तकनीकों पर भी विचारविमर्श किया जाता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस एकक ने कुल सात कार्यक्रम आयोजित किए। कॉलेज प्राचार्यों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में तीन अभिविन्यास कार्यक्रमों की श्रृंखला इसमें शामिल है (सितंबर 4-24, 1984, दिसंबर 31, 1984 जनवरी 1985, फरवरी 4-24, 1985), दो कार्यक्रम विभागाध्यक्षों के लिए, इनमें से प्रत्येक कश्मीर विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष तथा वहां के कालेजों के विभागाध्यक्षों के लिए था (फरवरी 4-22 तथा मार्च 11-16, 1985), कालेजों और विश्वविद्यालयों में विज्ञान कार्यक्रमों के आयोजन की समस्याओं तथा मुद्दों पर संगोष्ठी (अगस्त 14, 1984), तथा कालेजों में शिक्षण पद्धति पर राष्ट्रीय स्तर का कार्यशिविर, यू जी सी तथा यूनेस्को द्वारा प्रायोजित (अक्तूबर 8-14, 1984), विज्ञान कालेजों के प्रधानों के लिए दो कालेजों का मार्गदर्शी अध्ययन कार्यक्रम के आगत के रूप में किया गया।

इस एकक के लक्ष्य उच्च शिक्षा योजना तथा प्रशासन के कुछ समवर्ती मुद्दे भी हैं। एकक इनसे संबंधी अनुसंधान भी हाथ में लेती है। इसने राष्ट्रीय शिक्षक आयोग (उच्च शिक्षा) के केंद्रीय तकनीकी एकक के रूप में भी कार्य किया। आयोग की ओर से इस एकक ने 10 अनुसंधान अध्ययन उच्च शिक्षा में अध्यापकों की स्थिति पर प्रकाशित किए। इनका विवरण इस प्रकार है : अनुसंधान का खाका, भारत में उच्च शिक्षा, एक सर्वेक्षण, आर्थिक स्थिति; सामाजिक स्थिति; गतिशीलता तथा अंत:प्रजनन; व्यावसायिक नौकरी का विकास; कार्य की लगन; निर्णय में भागीदारी : परेशानियां तथा उनका निराकरण; व्यावसायिक मूल्य; इसके अनुवर्ती कार्य के रूप में एकक ने 5 वर्षों के लिए उच्च शिक्षा में एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार कर रखा है।

प्रादेशिक शिक्षा व्यवस्था एकक

प्रभावी योजना और प्रशासन के लिए इसके स्थानिक आयाम का अध्ययन आवश्यक है, विशेष रूप से भारत जैसे देश के संदर्भ में जहां विभिन्न क्षेत्रों में संवृद्धि तथा विकास के अंतर काफी महत्वपूर्ण हैं। यहां तक कि एक ही राज्य में कुछ जिले तथा प्रखंड अधिक विकसित हैं तथा कुछ उनकी तुलना में बहुत पीछे हैं तथा उनकी समस्याएं और आवश्यक तथा सामाजिक आर्थिक स्थितियों की बहुरूपता को ध्यान में रखकर तथा इसलिए भी कि योजना तथा विकास को स्थानीय परिवेश के साथ जोड़कर देखना है, राष्ट्रीय लक्ष्य तथा उपायों को ध्यान

में रखकर विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

इसी के मुताबिक प्रादेशिक प्रणाली, जहां तक देश के विभिन्न भागों में शिक्षा के विकास का प्रश्न है, अपनी निगाहें यथार्थ पर टिकाए हुए है तथा उनके मूल्यांकन और उनकी देखरेख में मदद करती है। लगातार यह विशेष क्षेत्र अनुभव का विकास कर रही है। साथ में ज्ञान भी अर्जित कर रही है जहां तक पांच क्षेत्रों की बात है, जैसे उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, तथा भारत का दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र। शैक्षिक योजना में व्यष्टि स्तर पर भी इसने विशेषज्ञता विकसित कर ली है, विशेष रूप से स्कूल मानचित्र आरेखण, संस्थागत योजना और मूल्यांकन, परियोजना, योजना और प्रबंध सूचना प्रणाली।

क्षेत्रीय तथा राज्य स्तर की समस्याओं के विशेष संदर्भ में अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा परामर्श के आयोजन के अलावा यह एकक सफल प्रयोगों तथा विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नवाचारों को (जो शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में है) दूसरे राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों की जानकारी में डालती है। यह विभिन्न राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों को पुनर्गठित करने तथा प्रशासन को सुदृढ़ करने में मदद करती रही है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान राष्ट्रीय, राज्यीय, जिला तथा अन्य स्तरों पर इस एकक ने शैक्षिक योजनाकारों तथा प्रशासकों के लिए 9 कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें निम्नांकित कार्यक्रम शामिल थे: शैक्षिक योजना और प्रशासन में वरिष्ठ शिक्षा योजनाकारों तथा प्रशासकों के लिए दो अभिविन्यास कार्यक्रम जो इस शृंखला में दसवें तथा ग्यारहवें थे (जनवरी 7-25, 1985 तथा फरवरी 11-28, 1985) राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में दो अभिविन्यास कार्यक्रम, एक उत्तर प्रदेश के सीधे भर्ती किए गए बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए, और दूसरा, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए (सितंबर 17-अक्तूबर 1, 1984, तथा अक्तूबर 10-29, 1984); पुनहाना प्रखंड, गुड़गांव (हरियाणा) के दो गांवों की महिलाओं के लिए सजग बनाने के लिए कार्यक्रम (मार्च 18-19, 1985); भारत के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नौ राज्यों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के मूल्यांकन के लिए तकनीकी कार्यशिविर (मार्च 18-20, 1985); मध्यप्रदेश की (सीखो और कमाओ योजना) में शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में सफल नवाचार तथा प्रयोगों को जानने के लिए अंतर्राज्यीय अध्ययन दौरों का आयोजन (फरवरी 4-9, 1985) दो यूनेस्को प्रायोजित कार्यक्रम, एक एशियाई देशों के प्रमुख पदों पर कार्यरत, प्रशिक्षार्थियों के लिए अंतर्राज्यीय अध्ययन दौरों, और दूसरा भूटान के शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक प्रशासन के विशेष संदर्भ में कार्यालय प्रबंध में दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम (सितंबर 24-28, 1984 और जनवरी 1, दिसंबर 31, 1985)।

अपने अधीन होने वाले अनुसंधान में इस एकक ने यूनेस्को द्वारा प्रायोजित "भारत में शैक्षिक प्रबंध का निदानात्मक अध्ययन" की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया, इसको यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय ने प्रकाशित किया। शिक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर इस एकक ने शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए सभी 9 राज्यों में प्रारंभिक स्तर के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम योजना का मूल्यांकन अध्ययन प्रारंभ किया जिसे केंद्र ने प्रायोजित किया था।

परामर्श सेवा के अंग के रूप में पंजाब तथा दादरा और नागर हवेली सरकारों के अनुरोध पर "कार्य के आधार पर उनके शिक्षा विभागों के पुनर्गठन" पर इस एकक ने रिपोर्ट तैयार की।

अंतर्राष्ट्रीय एकक

संस्थान के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है, शैक्षिक योजना और प्रशासन को केंद्र में रखकर क्षेत्रीय सहयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय समझदारी को बढ़ावा देना। इस उद्देश्य के लिए सूचना का आदान-प्रदान, विशेषज्ञता का आदान प्रदान तथा मौजूदा संसाधनों में हिस्सेदारी को सामूहिक आत्मनिर्भरता को विकसित करने के आवश्यक कदम के रूप में देखा जाता है।

यह संस्थान अपने जन्मकाल से ही शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र सें शीर्ष संस्था रही है। तभी से यह संस्था यूनेस्को, यू एन डी पी, यूनीसेफ, सीडा तथा राष्ट्रीय सरकारों के अनुरोध पर एशियाई तथा अफ्रीकी देशों को लगातार सहयोग प्रदान करती रही है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में तथा दृष्टिकोणों के आदान-प्रदान के क्षेत्र में तथा शैक्षिक योजना और प्रशासन के विशेष क्षेत्र में, विशेषकर तीसरी दुनिया के देशों में अंतर्राष्ट्रीय एकक बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करती है।

दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों तथा एशिया और अफ्रीका के देशों को यह एकक प्रशिक्षण सुविधाएं देता है तथा परामर्श सेवाएं मुहैया कराता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य शैक्षिक योजना और प्रशासन में इन देशों की सहायता करना होता है। इस रूप में यह वरिष्ठ शिक्षा कर्मियों की लक्षित करती है जो अपने देश में अन्य शिक्षा कर्मियों के प्रशिक्षकों के रूप में काम कर सकें, और इस प्रकार प्रशिक्षण को फैलाने का कार्य कर सकें।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस एकक ने सात कार्यक्रम चलाए। इसी वर्ष शैक्षिक योजना और प्रशासन में एक अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ किया गया (जनवरी 14-जुलाई, 13, 1985); दूसरे कार्यक्रमों में निम्नांकित कार्यक्रम शामिल हैं: श्रीलंका के अधिकारियों के लिए दो दीर्घावधि पाठ्यक्रम (नवम्बर 3, 1983-मई 3, 1984 तथा मार्च 20-मई 4, 1985), शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकास पर तथा अनौपचारिक शिक्षा में शैक्षिक प्रशासकों के लिए पाठ्यक्रम विकास पर एक बैठक का आयोजन (फरवरी 11-15, 1985); एक यू एस ई एफ आई प्रायोजित यू एस ए के निरीक्षकों तथा सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम परामर्शदाताओं के लिए भारती इतिहास और संस्कृति पर कार्यशिविर (जुलाई 3, अगस्त 10, 1984), तथा एशियाई प्रशिक्षार्थियों के लिए दो अध्ययन दौरे (जून 8-22, 1984) तथा यू पी ई परियोजना अधिकारी बंगलादेश (जनवरी 14-21, 1985)।

तीसरी दुनिया के देशों के पार्श्व चित्रों पर काम करने के अतिरिक्त यह एकक दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया के शैक्षिक विकास पर तुलनात्मक अध्ययन का कार्य भी हाथ में लेती रही है। इसने राष्ट्रकुल देशों में महिलाओं की शिक्षा पर भी एक तुलनात्मक अध्ययन हाथ में लिया है।

भाग छः

अकादमिक आधारिक संरचना

निम्नांकित घटकों को मिलाकर संस्थान की आधारिक संरचना का गठन हुआ है : पुस्तकालय, प्रलेखन केंद्र, प्रकाशन एकक, हिंदी प्रकोष्ठ, आंकड़ा बैंक, आरेक्षण प्रकोष्ठ तथा इलेक्ट्रानिक आंकड़ा संसाधक व रिप्रोग्राफिक एकक। इन एककों तथा प्रकोष्ठों से बहुमुखी वर्धमान कार्यक्रमों, अनुसंधान तथा संस्थान की अन्य गतिविधियों को समर्थ आधार तथा सशक्त समर्थन मिलता है।

एशिया क्षेत्र में शैक्षिक योजना और प्रशासन में सबसे संपन्न पुस्तकालयों में से एक पुस्तकालय होने का यह दावा कर सकती है। सालों के दौरान यह गंभीर अध्ययन तथा शिक्षण के केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। इसमें सारे वर्ष प्रलेखन तथा पुस्तकालय की सेवाएं सुलभ रहती हैं, बेहतर परिवेश तथा भौतिक सुविधाएं इसकी अपनी खासियत है। इस वर्ष 2000 से भी अधिक दस्तावेज इस पुस्तकालय ने एकत्र किए हैं। इसने "वर्तमान जागरूकता सेवा" प्रदान करना बरकरार रखा है तथा "क्षेत्रीय सूचना पुनर्जागरण" में इसने "एजूकेशन इन एशिया एंड पैसिफिक रिव्यू" में टिप्पणी समेत पुस्तक तथा लेख सूची प्रदान कर योगदान किया है। इस पत्रिका का प्रकाशन यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकाक द्वारा किया जाता है। पुस्तकालय ने तीन पुस्तक प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया।

इस बर्ष के दौरान राज्य तथा जिला स्तर पर भी राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र ने शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित लगभग 1000 नए अभिलेखों का संग्रह किया। इसने "ईपा" बुलेटिन में "राज्यों से सूचनाएं" नामक स्तंभ का प्रकाशन जारी रखा और शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में नवाचारी अनुभवों के संबंध में सूचना को फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया।

प्रकाशन एकक ने "ईपा" त्रैमासिक बुलेटिन का प्रकाशन जारी रखा तथा अपने प्रकाशन कार्यक्रम का आगे विस्तार किया। एक समूल्य प्रकाशन लाया गया जिसका शीर्षक था, "गवर्नमेंट सपोर्ट फार हायर एजुकेशन" ले. डा. जे एल आजाद, दो पुस्तकें प्रेस में थीं तथा कुछ नए प्रकाशनों को इस वर्ष हाथ में लिया गया। सात आरेखण पत्र, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण रिपोर्ट तथा सामयिक अनुसंधान आलेख भी निकाले गए।

संस्थान की अकादमिक गतिविधियों को डेटा बैंक, इलेक्ट्रानिक डेटा प्रोसेसिंग, रिप्रोग्राफिक एकक तथा आरेखण कक्ष से लगातार बहुमूल्य समर्थन मिलता रहा। आंकड़ों का आधार बनाने के साथ ही प्रशासन तथा लेखा से संबद्ध विभिन्न विषयों के पैकेज का विकास भी किया गया।

देश के हिंदी भाषी क्षेत्रों के प्रशिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हिंदी में प्रशिक्षण सामग्री तथा रिपोर्ट तैयार कर हिंदी कक्ष ने मूल्यवान योगदान किया। गांव की महिलाओं का एक कार्यक्रम हिंदी में चलाया गया। इस कार्यक्रम की रिपोर्ट भी हिंदी में ही तैयार की गई। प्रशिक्षण के लिए कुछ सामग्री

का भी हिंदी अनुवाद किया गया। इस कक्ष ने संस्थान के प्रशिक्षण तथा अन्य गतिविधियों में हिंदी को बढ़ावा देने में काफी मदद की।

ऊपर के एककों की गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

I. पुस्तकालय

संस्थान की देखरेख में शैक्षिक योजना तथा प्रशासन से संबंधित पुस्तकों का एक अत्यंत सुव्यवस्थित पुस्तकालय है। इसमें संबद्ध विषयों की पुस्तकों का अच्छा भंडार है। इसमें अंतर्विषयी पुस्तकें भी काफी संख्या में हैं। यह सिर्फ संकाय, शोध छात्र तथा भागीदारों की ही सेवा नहीं करता बल्कि अंतर्पुस्तकालयीय विनिमय व्यवस्था के माध्यम से अन्य पुस्तकालयों तथा संगठनों की भी सेवा करता है। पुस्तकालय के अध्ययन कक्ष की सुविधाएं सबके लिए उपलब्ध हैं।

पुस्तकें : समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस पुस्तकालय में 2000 दस्तावेजों की बढ़ोतरी हुई। इस समय पुस्तकालय में 370405 पुस्तकों का संग्रह मौजूद है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे यूनेस्को, यू एन ओ, आई एल ओ, यूनिसेफ आदि की बैठकों, सभाओं तथा गोष्ठियों की कार्यवाहियों तथा आलेख पन्नों का बहुत अच्छा संग्रह पुस्तकालय में विद्यमान है।

पत्र पत्रिकाएं : इस पुस्तकालय में 287 पत्र-पत्रिकाएं आती हैं। इनमें मुख्यत: शैक्षिक योजना तथा प्रशासन प्रबंध तथा अन्य संबद्ध विषयों की पत्रिकाएं होती हैं। इन पत्रिकाओं के सारे महत्वपूर्ण लेखों की सूचीबद्ध किया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कुल 3150 लेखों को सूचीबद्ध किया गया।

पुस्तकालय ने पत्रिकाओं के उपयोग पर एक सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण के आधार पर 8 पत्रिकाओं की बंद किया गया तथा 17 नए नाम इस सूची में जोड़े गए।

पुस्तकों का परिचालन : समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में आए भागीदारों को 30,000 अभिलेख पढ़ने के लिए दिए गए। इसमें संकाय तथा अन्य संस्थाओं के अंतर्पुस्तकालय आदान प्रदान के अभिलेख भी शामिल हैं। पुस्तकालय में 3000 अभिलेखों का इस्तेमाल अनुसंधान करने वाले लोगों ने किया।

समाचार पत्र क्लिपिंग : इन पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं के अलावा शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित पत्रिकाओं और समाचारों की क्लिपिंग रखने की भी इस पुस्तकालय में व्यवस्था है। वर्तमान समय में पुस्तकालय के पास 150 विषयों की फाइलें हैं।

वर्तमान जागरूकता सेवाएं : पाठकों को शिक्षा जगत की वर्तमान हलचलों के प्रति सजग तथा संवेदनशील रखने के लिए पुस्तकालय ने अपना मिमियोग्राफ निकालना जारी रखा जो पाक्षिक होता है और जिसका शीर्षक होता है, "शिक्षा के विषय में पत्र पत्रिकाएं : समीक्षित पुस्तकें तथा उनकी विषय वस्तु।"

मासिक सूची भी तैयार की गई ताकि पाठकों को नवीन पुस्तकों तथा महत्वपूर्ण पुस्तकों की जानकारी दी जाती रहे।

चुनी हुई सूचनाओं का प्रसार : संस्थान के कार्यक्रमों तथा अनुसंधान परियोजना की टीमों के लिए विविध स्त्रोतों से पुस्तकालय ने बहुत सी उपयोगी सूचनाएं एकत्र कीं। ये सूचनाएं उनके लिए काफी उपयोगी थीं।

पाठ्य सामग्री सूची : इस वर्ष के दौरान संस्थान में आयोजित कार्यक्रमों के लिए पुस्तकालय ने पाठ्य सामग्री सूची या पुस्तक सूची बनाई। अन्य संस्थाओं के अनुरोध पर पाठ्य सामग्री सूची निम्नांकित विषयों पर तैयार की गई :

1. अनुसंधान पद्धति
2. खुली शिक्षा
3. पर्यावरण शिक्षा
4. शैक्षिक नीति और नियोजन में अनुसंधान
5. भारत का इतिहास और संस्कृति

क्षेत्रीय सूचना सुधार : पुस्तकालय ने भारतीय दस्तावेजों की एक टिप्पणी के साथ संदर्भ सूची तैयार की थी। इसका शीर्षक था, "एशियाई दष्तावेजों पर टिप्पणी"। यह "एजुकेशन इन एशिया एंड पैसिफिक, रिव्यूज, रिपोर्ट्स एंड नोट्स" पत्रिका के लिए तैयार की गई थी जिसको यूनेस्को का बैंकाक क्षेत्रीय कार्यालय प्रकाशित करता है।

प्रदर्शनियां : इस वर्ष के दौरान पुस्तकालय ने निम्नांकित विषयों से संबंधित पुस्तकों की तीन प्रदर्शनियों का आयोजन किया :

1. शिक्षा तथा राष्ट्रीय एकता
2. गांधीजी तथा शिक्षा
3. शिक्षा तथा संगणक

II. राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र

पुस्तकालय के अंतर्गत एक उप एकक के रूप में प्रलेखन केंद्र अलग से कार्य करता है ताकि संस्थान के कार्यक्रमों की एक प्रभावशाली सूचना आधार प्रदान किया जा सके, विशेष रूप से उन कार्यक्रमों को जो राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आयोजित किए जाते हैं। प्रलेखन केंद्र प्रादेशिक प्रणाली एकक के निकट सहयोग से कार्य करता है ताकि संस्थान सूचना तथा अनुभव के प्रसारक का भी काम कर सके।

प्रलेखन : यह केंद्र शिक्षा तथा संबद्ध विषयों में शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित संदर्भ सामग्री एकत्र करता है। इसमें से अधिकांश सामग्री राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेशों, जिला शिक्षा अधिकारियों और राज्य स्तर के संस्थानों द्वारा प्रकाशित की गई होती है। इस केंद्र का मुख्य काम जिला स्तर तक की सूचनाओं का संकलन, संरक्षण तथा प्रसार है।

इस समय केंद्र में लगभग 5,500 प्रलेख संग्रहीत किए जा चुके हैं। इनमें राज्य के गजेटियर्स, राज्य की जनगणना, हैंडबुक्स, शैक्षिक सर्वेक्षण, राज्य शिक्षा योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं, बजट, स्टेट यूनिवर्सिटी हैंडबुक्स, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक इतिहास, प्रारंभिक स्त्रोत पुस्तकें तथा पुस्तकसूचियां, संदर्भ सूचियां, प्रेस क्लिपिंग्स, टेक्नो-इकनामिक तथा निर्देश सर्वेक्षण, जिला गजेटिर्स, जिला जनगणना पुस्तिकाएं, वार्षिक योजनाएं, शैक्षिक योजनाएं, जिला ऋण योजनाएं, लीड बैंक रिपोर्ट, जिला निदर्श सर्वेक्षण, जिला शिक्षा सर्वेक्षण, जिला सांख्यिकी पुस्तिकाएं, गांव तथा प्रखंड स्तर की योजनाएं तथा अध्ययन, अनुसंधान तथा परियोजना रिपोर्ट, संसाधन सूची अध्ययन, टेक्नो इकानामिक सर्वेक्षण जैसी चीजें शामिल हैं।

राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों से सूचनाएं : विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से सूचनाएं एकत्र करने के लिए प्रलेखन केंद्र 14 क्षेत्रीय अखबारों के लिए चंदा देता है। केंद्र में फाइलें रखी जाती हैं जिनमें शिक्षा संबंधी सूचनाएं अखबारों से एकत्र की जाती है। ये सूचनाएं प्रदेशों तथा केंद्रशासित प्रदेशों की होती हैं। राज्यों से एकत्र की गई सूचनाओं को एकत्र करके ईपा बुलेटिन में 'न्यूज फ्राम स्टेट्स एंड यूनियन-टेरिटोरीज' के अंतर्गत प्रकाशित किया जाता है।

प्रलेखन तथा सूचना सेवाएं : शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में नई प्रगति तथा नवाचारी अनुभव संबंधी सूचनाओं को प्रचारित प्रसारित करने का काम प्रलेखन केंद्र करता है। जिन माध्यमों से वह इस काम को करता है उन्हें नीचे दिया गया है :

1. अनुसंधान कर्त्ताओं तथा संकाय सदस्यों के लिए चुनी हुई सूचनाओं का प्रसारण,
2. अर्द्धवार्षिक प्रलेखन सूत्री,
3. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सटिप्पणी संदर्भ सूची का संकलन।

III. प्रकाशन एकक

संस्थान के मुख्य उद्देश्यों में एक उद्देश्य पत्र-पत्रिकाएं और पुस्तकें तैयार करना तथा उन्हें प्रकाशित करना है तथा संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में पत्रिका का प्रकाशन भी इसका उद्देश्य है।

प्रकाशन एकक ने ई पी ए त्रैमासिक बुलेटिन का प्रकाशन जारी रखा। यह बुलेटिन शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित है। संस्थान ने समूल्य प्रकाशन, बिना मूल्य प्रकाशन, अनुसंधान प्रकाशन तथा सामयिक आलेख पत्रों की श्रृंखला का प्रकाशन किया।

(क) **समूल्य प्रकाशन** : एक पुस्तक प्रकाशित हुई, दो पुस्तकें प्रेस में हैं तथा चार पुस्तकें प्रकाशन के लिए ली गईं। इस सब का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :

1. गवर्नमेंट सपोर्ट फार हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, जे एल आजाद,
2. एजुकेशनल प्लानिंग : ए लांगटर्म पर्सपेक्टिव, सं. प्रो. मूनिस रजा,
3. ए फाइनेंशियल कोड फार यूनिवर्सिटी सिस्टम, एम एल सोबती,
4. कास्ट आफ सप्लाई आफ एजुकेशन ऐट माइक्रो लेबेल : ए केस स्टडी आफ टू एजुकेशनल क्लस्टर्स इन डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव, हरियाणा, जे बी जी तिलक
5. मोबिलाइजेशन आफ एडिशन रिसोर्सेज
6. आरगेनाइजेशनल हिस्ट्री आफ दि मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन, ए मैथ्यू,
7. रिसोर्स फार एजुकेशन इन इंडिया, जे बी जी तिलक और एन वी वर्गीस

इस वर्ष के दौरान समूल्य प्रकाशन के लिए जी गई पांडुलिपियां :

1. ग्रास रूट्स : ए जर्नल आफ माइक्रो लेविल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन; इसे समूल्य प्रकाशन के रूप में लाने का विचार है :

इस वर्ष के बिना मूल्य के प्रकाशनों की सूची इस प्रकार है :

1. वार्षिक रिपोर्ट 1982-83 (हिंदी)

2. वार्षिक रिपोर्ट 1982-83 (अंग्रेजी)
3. ई पी ए क्वार्टर्ली बुलेटिन 2 अंक (संयुक्तांक)

नीचे लिखे प्रकाशनों को मिमियोग्राफ किया गया। संस्थान ने 20 अनुसंधान अध्ययन, 2 आकस्मिक पत्र तथा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की 48 रिपोर्ट निकालीं (1984-85)

IV. डेटा बैंक

डेटा बैंक के प्रमुख कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है :

1. संस्थान में अनुसंधान करने वाले शोधकर्ताओं को आंकड़ा संग्रह तथा उनको संसाधित करने में सहायता करना;
2. नीपा द्वारा लिए गए विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित आंकड़ों के संगणकीकरण को सुकर बनाना;
3. जिला स्तर पर शैक्षिक योजना के लिए जिला स्तर के पर्याप्त आंकड़ा आधार तैयार करना, और
4. ऐसे व्यवस्थित तरीके से संगणीकीकृत आंकड़े संग्रहीत करना जिससे उसको दुबारा भविष्य में उपयोग में लाया जा सके।

नई दिल्ली के राष्ट्रीय सूचना केंद्र में स्थित साइबर प्रणाली के उपयोग करने वालों में नीपा भी एक है। हाल में नीपा ने भी एक माइक्रो-संगणक प्राप्त किया है। यह छोटा सा आंकड़ा आधार बनाने में मदद करेगा जिसका प्रशिक्षण के लिए व्यापक इस्तेमाल किया जा सकेगा, साथ में शैक्षिक योजना और प्रबंध के क्षेत्र में कुछ और कार्य किया जा सकेगा।

1981 की जनगणना तथा साक्षरता की सारणी से संबद्ध (जिनका स्त्री पुरुष तथा ग्रामीण नगरी विभाजन भी किया गया है) के आंकड़ों का जिलावार आधार भी संगणकीकृत किया जा चुका है तथा जो इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें उपलब्ध भी है। अनुसूचित जाति की साक्षरता से संबंधित आंकड़ों की सारणी बन रही है। इसके अलावा विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण के लिए नीपा के अनुसंधान सहायकों को इस एकक ने प्रश्नावली, सारणी तथा योजना बनाने में मदद दी। इस वर्ष के दौरान निम्नांकित परियोजनाओं के आंकड़ों को संसाधित करने का कार्य विशेष रूप से किया गया :

1. राष्ट्रीय शिक्षक आयोग : अध्यापकों का सर्वेक्षण (पूरा हो गया),
2. इष्टतम छात्राध्यापक अनुपात
3. वर्ष 2000 में शिक्षा
4. अनुसूचित जातियों का शैक्षिक विकास
5. शैक्षिक विकास में क्षेत्रीय असमानताएं
6. पुनर्भाषा प्रखंड कार्य-अनुसंधान परियोजना,

V. आरेखण कक्ष

आंकड़ों का मानचित्र तथा रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण करके अनुसंधान तथा प्रशिक्षण में आरेखण कक्ष ने उल्लेखनीय योगदान किया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान गुड़गांव (हरियाणा) के लिए शिक्षा आपूर्ति की लागत के अध्ययन के लिए "भारतीय शिक्षा वर्ष 2000 में : एक दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य," के लिए राष्ट्रीय शिक्षक आयोग (उच्च शिक्षा) के लिए, तथा पुनहाना, प्रखंड में कार्य अनुसंधान परियोजना के लिए इस कक्ष ने 110 नक्शे तथा रेखाचित्र बनाए।

इसके अलावा वार्षिक रिपोर्ट के लिए, ईपा बुलेटिन के लिए तथा विभिन्न कार्यक्रमों तथा सामयिक आलेखों के लिए आरेखण कक्ष ने 125 नक्शे, रेखाचित्र तथा चित्र तैयार किए।

VI. हिंदी कक्ष

नीपा की राज्य भाषा कार्यान्वयन समिति की देखरेख में हिंदी कक्ष काम करता है। संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा अन्य अकादमिक गतिविधियों में हिंदी कक्ष ने पर्याप्त समर्थन दिया है। "ग्राम समुदाय की कामगर महिलाओं संवेदनशीलता कार्यक्रम" में हिंदी विचार-विमर्श की एकमात्र माध्यम थी। यह कार्यक्रम 18-19 मार्च 1985 को संस्थान में चलाया गया था। इस कार्यक्रम की रिपोर्ट भी हिंदी में ही निकाली गई। जनवरी 1985 में प्रशिक्षण के भागीदारों के बीच वितरण के लिए हिंदी कक्ष ने "पुनहाना प्रखंड के माड्यूल" का भी हिंदी रूपांतर तैयार किया था। यह कार्यक्रम भी जनवरी 1985 में चलाया गया था। "नए और पुराने का संश्लेष : तिलोनियां में ग्राम विकास में प्रयोग" का अनुवाद इस कक्ष ने फरवरी 1985 में किया। यहां तक कि जिन कार्यक्रमों में भाषण तथा विचार विनिमय का माध्यम अंग्रेजी होती है, भागीदारों को अपनी रिपोर्ट हिंदी में लिखने की छूट होती है।

कार्यालय में हिंदी में पत्र व्यवहार करने में भी कक्ष ने पर्याप्त मदद की। जो राज्य 'अ' क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उनके साथ हिंदी में पत्र व्यवहार करने में तथा जो 'ब' क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उनसे हिंदी तथा अंग्रेजी में पत्र व्यवहार करने में संस्थान ने मदद की, संस्था में इस्तेमाल किए जाने वाले विविध प्रोफार्माओं का हिंदी में अनुवाद किया गया। अब वे सभी हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं।

पुस्तकालय में कई हिंदी दैनिक तथा साप्ताहिक मंगाए जाते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र सरकारों से कुछ पत्रिकाएं इस पुस्तकालय में आती हैं। हिंदी भाषी राज्यों से प्रलेखन केंद्र में शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित कई दस्तावेज मंगाए जाते हैं।

संस्थान नीपा परिचायिका, प्रशिक्षण कार्यक्रम सूची तथा ईपा क्वार्टरली बुलेटिन को भी हिंदी मे निकालने की योजना बना रहा है।

VII. इलेक्ट्रानिक डेटा प्रोसेसिंग तथा रिप्रोग्राफिक एकक

शैक्षिक योजना और प्रशासन के लिए आंकड़ों का आधार बनाने में और प्रशासन तथा प्रबंध के क्षेत्र में आधुनिक इलेक्ट्रानिक उपकरणों के उपयोग में इलेक्ट्रानिक डेटा प्रोसेसिंग तथा रिप्रोग्राफिक एकक इस समय जुटा हुआ है। विभिन्न कार्यक्रमों के भागीदारों के लिए संस्था संगणक के प्रदर्शन का भी आयोजन कर रहा है ताकि उन्हें शैक्षिक योजना और प्रशासन में संगणक के प्रयोग से परिचित कराया जा सके। ई डी पी आर एकक ने डेटा बेंक के निकट सहयोग से डेटा प्रोसेसिंग की आवश्यकता पूर्ति हेतु काम किया।

(अ) **शब्द संसाधन** : संस्थान में लगाए गए उपकरणों का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है : (i) एच

सी एल सिस्टम 2,64 के बी मेमोरी। एम बी के दो डिस्क, 80 के बी का एक डिस्कड्राइन तथा एक लेटर क्वालिटी प्रिंटर; (2) 64 के बी मेमोरी के साथ एच सी एल वर्क हार्स 200 के बी/80 के बी के दो टुएल डेस्टिनी डिस्क, इनमें से प्रत्येक एच सी एल सिस्टम-2 के साथ मेल खाता हुआ।

शब्द संसाधक पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की रिपोर्ट, नीपा वार्षिक रिपोर्ट तथा अन्य प्रलेख निकाले जा चुके हैं। राष्ट्रीय शिक्षक आयोग की रिपोर्ट, यूनेस्को प्रायोजित विभिन्न परियोजनाओं की रिपोर्ट, बाह्य अभिकरणों की मदद से चलाई गई परियोजनाओं की रिपोर्ट आदि शब्द संसाधक पर निकाली गई। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पाठ्य सामग्री बांटने के लिए कई अनुसंधान आलेख तथा पाठ्य सामग्री को शब्द संसाधक में डिस्क पर रख दिया गया है। इससे बहुत सा अनावश्यक दुहरा श्रम बचाया गया है। संस्थान के अपने काम के अलावा लगभग 0.66 लाख रुपये का कार्य सहयोगी संस्थाओं, परियोजनाओं तथा बाह्याभिकरणों द्वारा दिए गए कोष से चलाए गए कार्यों के लिए किया गया। इसमें उनके बारे में दिए गए निर्देशों के मुताबिक कार्य किया गया।

संगणकीकृत आंकड़ा संसाधन के पैकेजों का जो शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के अलग अलग क्षेत्रों से संबद्ध हैं, विकास किया गया है। संगणकों के इस्तेमाल के जरिए, लेखा के आधुनिकीकरण के लिए वेतन बिलों के भुगतान तथा सालाना वेतन बढ़ोत्तरी का संगणकीकरण किया गया है। माइक्रो संगणक के ऊपर स्वत: सामान सूची संसाधन के लिए पैकेज विकसित किया गया है तथा उसको काम में लाया जा रहा है।

(ब) **रिप्रोग्राफी** : ओलंपिया फोटो कापियर, यूविक्स किलबर्न 1600 एम आर फोटो कॉपियर। इस वर्ष के दौरान बड़ा तथा फोटो करने की व्यवस्था से युक्त एक फोटो कॉपियर खरीदा गया। इनका उपयोग कई कामों के लिए किया गया जैसे तकनीकी रिपोर्टों की कई प्रतियां बनाने के लिए, पाठ्य सामग्री के लिए, आलेखों की कई प्रतियां बनाने के लिए, तथा इसी प्रकार के अन्य कार्यों के लिए।

भाग सात

प्रशासन तथा वित्त

संस्थान भारत सरकार की वित्तीय सहायता से चलाया जाता है। इसका प्रधान या अध्यक्ष भारत द्वारा मनोनीत व्यक्ति होता है। संस्थान का प्रमुख कार्यपालक अधिकारी निदेशक होता है जिसकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

परिषद, कार्यपालिका समिति, तथा वित्त समिति मिलकर संस्थान के नीति निर्माण के अवयव के रूप में कार्य करते हैं। परिषद संस्थान की सर्वोच्च निकाय है, इसमें बड़े-बड़े शिक्षाशास्त्री, प्रांतीय तथा राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों के उच्च अधिकारी विद्यमान हैं। ये गण्यमान व्यक्ति संस्थान की अपने उद्देश्यों की प्राप्त करने में मार्ग दर्शन करते हैं और संस्थान के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण भी करते हैं, कार्यपालिका समिति सस्थान के कार्यों का प्रशासन और प्रबंध सम्हालती है और बजट तथा लेखा की परीक्षा करने तथा अन्य वित्तीय मामले में वित्त समिति कार्यपालिका समिति की मदद करती है। संस्थान का निदेशक पदेन संस्थान का उपाध्यक्ष तथा कार्यपालिका तथा वित्त समिति का अध्यक्ष होता हैं। कुल सचिव परिषद तथा कार्यपालिका समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

कार्यपालिका समिति ने दो समितियां बनाई हैं, कार्यक्रम सलाहकार समिति तथा प्रकाशन सलाहकार समिति। पहली समिति प्रशिक्षण अनुसंधान तथा अन्य अकादमिक गतिविधियों के बारे में अनुसंशा करती हैं तथा दूसरी समिति नीपा द्वारा प्रकाशित की जाने वाली सामग्री के विषय में संस्थान को परामर्श देती है। कुल सचिव तथा प्रकाशन अधिकारी क्रमश: दोनों के सचिव के रूप में कार्य करते है।

निदेशक को उसके कार्यों में मदद करने के लिए कार्यकारी निदेशक होता है जो प्रशासनिक तथा वित्तीय मामलों में उसकी मदद करता है। कुल सचिव तथा वित्त अधिकारी क्रमश: प्रशासन तथा वित्त विभाग के प्रधान होते हैं जो कार्यकारी निदेशक की देखरेख में अपना कार्य करते हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। भूतपूर्व शिक्षा तथा संस्कृति मंत्री शीला कौल के अपने पद से मुक्त होने पर श्री कृष्णचंद्र पंत शिक्षा तथा संस्कृति मंत्री के पद पर आसीन हुए और 30 जनवरी 1985 को उन्होंने नीपा का अध्यक्ष पद भी सम्हाला। प्रो. मूनिस रजा मई 1981 से संस्थान के निदेशक पद पर कार्य कर रहे थे, संस्थान की उल्लेखनीय सेवा के बाद 23 जुलाई 1984 को अपना पद छोड़ दिया तथा संस्थान की बागडोर तत्कालीन कार्यकारी निदेशक प्रो. सत्यभूषण के हाथों में चली गई जिन्हें पहले अस्थाई तौर पर निदेशक बनाया गया उसके बाद 28 नवंबर 1984 को उन्हें स्थाई निदेशक नियुक्त कर दिया गया।

नीति निर्माण के अंग

परिषद

संस्थान की सर्वोच्च निकाय होती है तथा संस्थान का अध्यक्ष इसका भी अध्यक्ष होता है। संस्थान के उद्देश्यों को बढ़ाना परिषद का ही काम होता है। यह संस्थान के सभी कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण भी करती है।

नीपा का निदेशक इस परिषद का उपाध्यक्ष होता है। परिषद के अन्य सदस्य इस प्रकार हैं: अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार के चार सचिव (शिक्षा, वित्त, योजना आयोग तथा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग), निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद, छः शिक्षा सचिव (राज्यों के पांच तथा केंद्रशासित प्रदेश का एक), छः नामी शिक्षाशास्त्री; कार्यकारिणी समिति के सारे सदस्य, नीपा संकाय का एक सदस्य। कुलसचिव नीपा परिषद के सचिव के रूप में काम करते हैं। परिषद की छठी बैठक 24 मार्च 1985 को हुई। 31 मार्च 1985 तक परिषद के सदस्यों की सूची परिशिष्ट एक में दी गई है।

कार्यकारिणी समिति

कार्यकारिणी समिति संस्थान के प्रशासन तथा प्रबंध कार्यों को अंजाम देती है। संस्थान का निदेशक इसका पदेन अध्यक्ष होता है। शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग के सचिवों के द्वारा मनोनीत सदस्य, किसी राज्य का एक शिक्षा सचिव; एक विख्यात शिक्षाशास्त्री, नीपा का कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के कुलसचिव कार्यकारिणी समिति के सचिव के रूप में काम करते हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कार्यकारिणी समिति की बैठक दो बार हुई। पहली बैठक 30 मई 1984 तथा दूसरी 7 दिसंबर 1984 को हुई।

31 मार्च 1985 तक कार्यकारिणी समिति के जो सदस्य थे, उनकी सूची परिशिष्ट दो में दी गई है।

वित्त समिति

संस्थान का अध्यक्ष एक वित्त समिति नियुक्त करता है। संस्थान का निदेशक इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। इसके सदस्यों में वित्तीय सलाहकार तथा इसी तरह के अन्य लोगों को, जिन्हें अध्यक्ष आवश्यक समझता है, सदस्य के रूप में नियुक्त करता है। यह समिति लेखा की समीक्षा करती है, बजट अनुमानों की समीक्षा करती है तथा नए खर्चों तथा अन्य वित्तीय प्रस्तावों पर यह कार्यकारिणी समिति को अपनी अनुशंसा भेजती है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वित्त समिति की दो बार बैठकें हुईं। पहली 30 मई 1984 तथा दूसरी सात दिसंबर 1984 को। 31 मार्च तक जो लोग इसके सदस्य थे उनकी सूची परिशिष्ट तीन में दी गई है।

प्रशासन और वित्त
प्रभागीय ढांचा

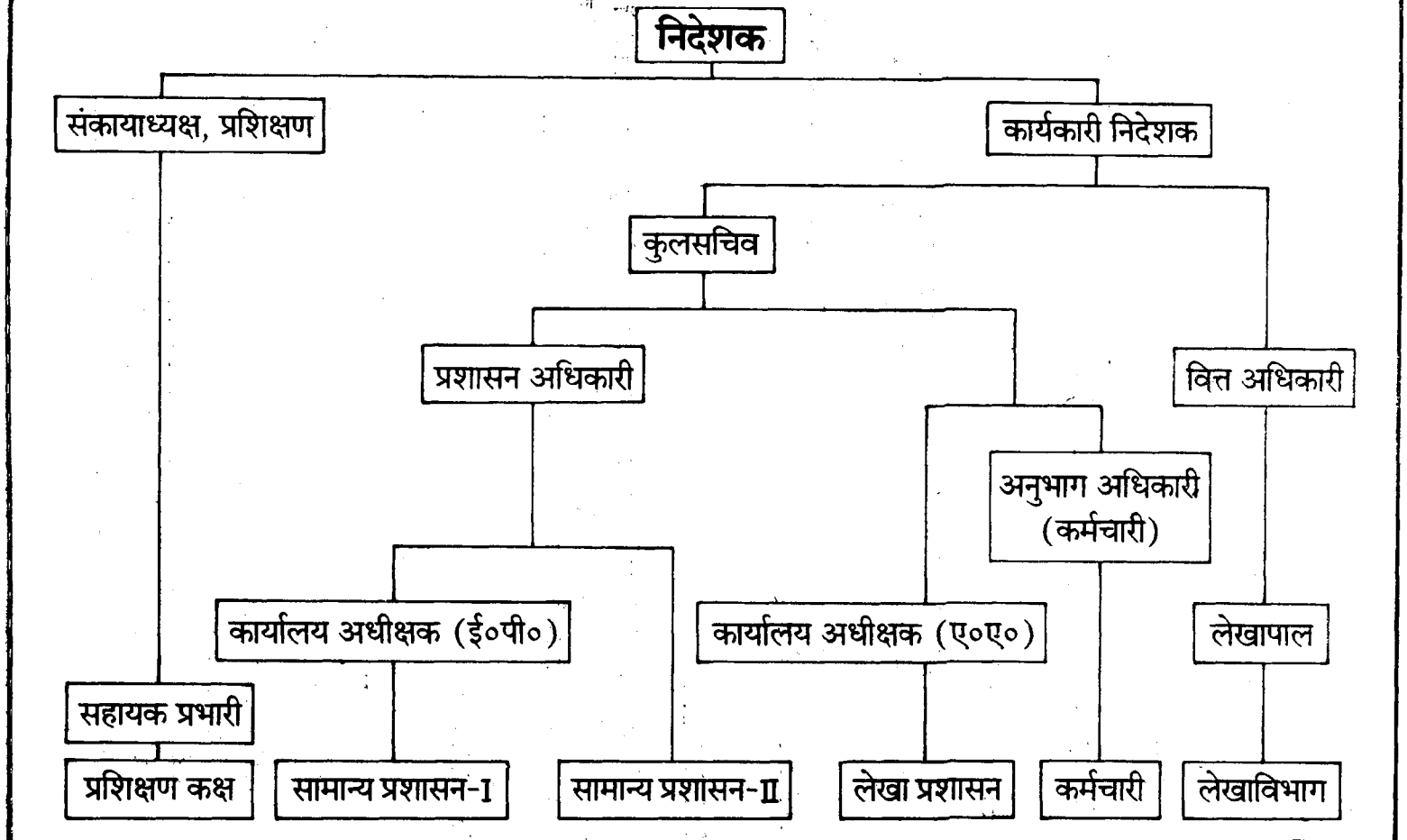

कार्यक्रम सलाहकार समिति

प्रशिक्षण अनुसंधान तथा अन्य कार्यक्रमों के विषय में कार्यक्रम सलाहकार समिति कार्यकारिणी समिति को अपनी सिफारिश प्रस्तुत करती है। यह संस्थान के अकादमिक कार्यों का परीक्षण भी करती है। नीपा के निदेशक इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा इसके सदस्य शिक्षा मंत्रालय के मनोनीत सदस्य, योजना आयोग के मनोनीत सदस्य तथा कार्यकारिणी द्वारा मनोनीत कुछ अन्य सदस्यगण होते हैं। नीपा के कुलसचिव इस समिति के सचिव होते हैं।

कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति की ग्यारहवीं बैठक 30 मई 1984 को हुई। 31 मार्च 1985 को इसके सदस्यों की सूची इस प्रकार थी (देखिए परिशिष्ट चार)

प्रकाशन सलाहकार समिति

संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाने वाली सामग्री के विषय में प्रकाशन सलाहकार समिति कार्यकारिणी समिति को अपनी सिफारिश भेजती है तथा प्रकाशन से संबंधित सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का समायोजन करती हैं। प्रकाशन अधिकारी इसके सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं। प्रकाशन सलाहकार समिति की दूसरी बैठक 31 मई 1984 को हुई। 31 मार्च 1985 को जो लोग प्रकाशन सलाहकार समिति के सदस्य थे उनकी सूची परिशिष्ट पांच में दी गई हैं।

कर्मचारियों को संख्या

नए पदों की रचना तथा भर्ती के ऊपर लगे हुए प्रतिबंध के कारण समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कर्मचारियों को संख्या में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हो सकी तथा 31 मार्च 1985 को संस्थान के कर्मचारियों की संख्या 161 बनी रही। इसी तिथि पर संस्थान में विविध परियोजनाओं में कार्यरत लोगों की संख्या 40 थी।

कर्मचारियों के पदों में परिवर्तन

1. डॉ. शीलचंद्र नुना 7-6-84 को एसोसिएट फैलो बनाए गए।
2. प्रो. मुनिस रज़ा ने 23-7-84 को निदेशक के कार्य से मुक्ति ले ली।
3. डॉ. एस एल गणेशन ने 27-9-84 को एसोसिएट फैलों के रूप में संस्थान में कार्यभार ग्रहण किया।
4. श्री माबुद हसन, परियोजना फेलो, राष्ट्रीय शिक्षक आयोग 30-9-1984 को कार्य समाप्त होने के बाद संस्थान से मुक्त हुए।
5. प्रो. सत्यभूषण, कार्यकारी निदेशक नीपा, ने 28-11-84 को निदेशक का पदभार सम्हाला।
6. डॉ. वाई. पी अग्रवाल, एसोसिएट फेलो नीपा (डेटा बेंक) सहायक प्रोफेसर के रूप में प्रति-नियुक्त होकर तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान चंडीगढ़ में 31-12-84 को छः मास के लिए गए।

7. प्रो. सत्य मित्र दुबे, वरिष्ठ परियोजना अध्येता तथा अध्यक्ष, एस क्यू एस नक्वी, डी एच श्रीकांत, परियोजना सहअध्येता अनुसूचित जाति तथा जनजाति विकास, अध्ययन एकक, एकक का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 31-12-84 को अपने पद से मुक्त हुए।
8. डॉ. आर पी सिंघल, परामर्शदाता, नीपा ने 1-2-95 को कार्यकारी निदेशक के रूप में अपना पदभार सम्हाला।

मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में अकादमिक तथा गैर अकादमिक दोनों ही कर्मचारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण पर ध्यान दिया गया। इस नीति के अनुपालन के अंतर्गत, संकाय तथा संकायेतर कर्मचारियों की सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए देश के भीतर तथा बाहर दोनों जगह प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया जिससे उनकी व्यावसायिक दक्षता को आगे विकसित किया जा सके। इसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :

1. डॉ. आर पी सक्सेना, कुलसचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, ने कागज पत्र प्रबंध व्यवस्था : खराब व्यवस्था के संभावित कारण तथा इसको दूर करने के उपाय, पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इसका आयोजन अप्रैल 3-4, 1984 को प्रोडक्टिविटी सर्किल नई दिल्ली ने किया था।
2. श्री के एल दुआ, प्रशासन अधिकारी ने रेकार्ड प्रबंध पर आयोजित कार्य शिविर में भाग लिया। इसका भी आयोजन प्रोडक्टिविटी सर्किल ने किया था। इसका आयोजन दिनांक अप्रैल 5-7, 1984 को किया गया था। इन्होंने रेकार्ड प्रबंध पर एक दिन का व्याख्यान भी सुना जिसका आयोजन भारतीय अभिलेखागार ने 3-9-84 को किया था।
3. श्री एम ए अंसारी, परियोजना सहायक ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में आयोजित संगणक के प्रथम कार्यक्रम में भाग लिया।
4. श्री इंद्रकुमार गुप्त, तकनीकी सहायक ने हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड द्वारा आयोजित संगणक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कार्यक्रम में भाग लिया। यह कार्यक्रम दिनांक 11-15 जून 1984 के दौरान चलाया गया था।
5. डा. श्रीमती कुसुम प्रेमी तथा कु. के सुजाता ने राजस्थान में आयोजित "अनुसूचित जनजाति की शिक्षा" पर आयोजित कार्यशिविर में 7-8 जुलाई 1984 को भाग लिया।
6. कु. नीलम बाला, हिंदी टाइपिस्ट ने हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित आशुलिपि पाठ्यक्रम प्रशिक्षण में भाग लिया। इसका आयोजत भारत सरकार के राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) नई दिल्ली ने किया था (16.8.84-31.7.85)।
7. श्री टी आर ध्यानी, कार्यालय अधीक्षक तथा श्री एम एल शर्मा, कार्यालय अधीक्षक ने कार्यालय प्रशासन सुधार संबंधी एक कार्यक्रम में भाग लिया। इसका आयोजन अक्तूबर 8-11, 1984 में प्रोडक्टिविटी सर्किल, नई दिल्ली ने किया था।
8. डा. रामस्वरूप शर्मा, एसोसिएट फेलो और श्री अरुण सी मेहता, तकनीकी सहायक ने इफेक्टिव फार्म डिजाइन एंड कंट्रोल पर आयोजित कार्य शिविर में भाग लिया। इस कार्य शिविर का आयोजन

प्रोडक्टिविटी सर्किल, नई दिल्ली ने अक्तूबर 12-15 के मध्य किया था।

9. डा. श्रीमती उषा नायर, फेलो ने "एशिया में सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रशासन" तथा प्रशांत क्षेत्र पर आयोजित प्रशिक्षण कार्य शिविर में भाग लिया। इसका आयोजन सांस्कृतिक स्रोत तथा प्रशिक्षण नई दिल्ली ने नवंबर 26-30, 1984 के दौरान किया था।
10. डा. श्री एल एस गणेश, एसोसिएट फेलो ने "संरचनात्मक पद्धति विश्लेषण तथा संरचनात्मक डिजाइन" पर आयोजित एक पाठ्यक्रम में भाग लिया। इसका आयोजन टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज, नई दिल्ली ने दिसंबर 3-6 के दौरान दिल्ली में किया था।
11. डा. वाई पी अग्रवाल तथा डा. वी मुरलीधर ने हिन्दुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, नेहरू प्लेस में डी-बेस II (डेटा बेस पैकेज) के इस्तेमाल पर एक दिन की संगोष्ठी में भाग लिया। इसका आयोजन दिसंबर 15, 1984 को नई दिल्ली में किया गया था।
12. श्री चेरियन थानस, लेखापाल ने माइक्रोसाफ्ट में बेसिक लैंग्वेज—जिसमें प्रस्तावना, तथा संगणक प्रणाली की अवधारणा और उसका संचालन शामिल थे—पर माइक्रोसाफ्ट वोकेशनल ट्रेनिंग डिवीजन में एक पाठ्यक्रम में भाग लिया जो छः मास का था तथा 15 दिसंबर 1984 से आरंभ हुआ।
13. डा. कु. के सुजाता तथा श्रीमती जयश्री जलाली, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, ने रोम (इटली) में इतालवी सरकार की छात्रवृत्ति पर विकासात्मक प्रशासन पर विशेषज्ञता के पाठ्यक्रम में भाग लिया (22.11.84.—9.5.85)।
14. डा. एन बी वर्गीस, एसोसिएट फेलो, नीपा ने शैक्षिक योजना और प्रशासन में उच्चतर पाठ्यक्रम के 20वें चरण में भाग लिया। इसका आयोजन आई आई पी पेरिस ने 26.12.84 से 19.7.85 के बीच किया था।

नीपा के नियम तथा विनियम

जून 1984 में नीपा के कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने कराया। इसमें शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कार्मिक विभाग के प्रतिनिधि शामिल किए गए थे इसका उद्देश्य नीपा के नियमों तथा विनियमों का पुनरीक्षण करना, उसमें सुधार सुझाना तथा उसे व्यवस्थित रूप देना था।

इस समिति के गठन के तत्काल बाद, सहयोगी संगठनों की नियमावलियों को एकत्र किया गया तथा इस पर गंभीरता से काम आरंभ किया गया। वर्तमान नियमों तथा विनियमों के सुधारने, अद्यतन बनाने तथा संयोजित करने के अलावा सेवा विनियमों के प्रारूप में परियोजना में काम करने वालों के पदों से संबंधित नियुक्तियों की प्रक्रियाओं की व्यापक व्यवस्था की गई है। इसके अलावा उसमें कई और बातें भी हैं जैसे एमेरिटस प्रोफेसर्स, विजिटिंग फेलो, योग्यता आधारित पदोन्नति, अकादमिक अवकाश के लिए शर्तें, अध्ययन अवकाश, सबाटिकल अवकाश तथा नए प्रकार के बहुत से पदों के लिए भर्ती नियम आदि। सेवा विनियमों के प्रथम प्रारूप की समीक्षा एक आंतरिक समिति ने की थी जिसमें निम्नांकित लोग शामिल थे, कुलसचिव, विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी, श्री एम एल सोबती भूतपूर्व परियोजना अध्येता तथा वित्त अधिकारी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। इसकी समीक्षा के लिए लगातार कई बैठकें की गईं। इसके बाद इस प्रारूप को विभिन्न एककों को टिप्पणी के लिए दिया गया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाई गई समिति की बैठक बुलाने

के पहले विभिन्न एककों से टिप्पणी मिलने के बाद सेवा विनियमों के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस बीच लेखा तथा बजट से संबंधित विनियमों की समीक्षा की जा रही है।

अनुसंधान के लिए मार्ग दर्शन

संस्थान में अनुसंधान की गतिविधियों के उचित विकास के लिए नवंबर 1984 में अनुसंधान प्रस्ताव बनाने तथा संस्थान से वित्त प्राप्त करने और रिपोर्ट जमा करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शिकाएं जारी की गईं। इस आशय के भी निर्देश जारी किए गए कि सबसे पहले अनुसंधान प्रस्ताव को उस विषय के विशेषज्ञ व्यक्ति के पास विभिन्न पहलुओं से उसकी परीक्षा के लिए भेजा जाएगा ताकि वह उसके बारे में अपना रचनात्मक सुझाव पेश कर सके। इसका उद्देश्य अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार तथा अनुसधान के ढांचे को दोष मुक्त रखना था। सभी अनुसंधान परियोजनाओं की परियोजना सलाहकार समितियां होगी जिसकी बैठक नियमित रूप से हुआ करेगी। प्रत्येक तिमाही के अन्त में परियोजना निदेशक एक प्रगति रिपोर्ट पेश किया करेंगे।

अधिकारों का प्रत्यायोजन

विकेंद्रीकरण के तथा क्रियात्मक आधार पर काफी व्यापक स्तर पर अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया है। इस नई व्यवस्था में निदेशक, कार्यकारी निदेशक, डीन प्रशिक्षण तथा एककों के अध्यक्ष और कुलसचिव, प्रशासन अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, तथा कार्यालय अधीक्षकों को अधिकार दिए गए हैं। इससे काम की गति तेज हुई है और गत्यावरोध टूटे हैं। पहले इसके अभाव में निर्णय के स्तर पर काफी विलंब होता था।

मितव्ययिता

लिखने पढ़ने की सामग्री में बहुत बचत की गई है। यह मद संस्थान के खर्चे का अत्यन्त महत्वपूण मद है। यह इसलिए हुआ है क्योंकि इसके लिए नए मानदण्ड लागू किए गए हैं जिसमें निम्नांकित क्षेत्रों में पुनरावृत्ति को रोकने के उपाय किए गए हैं जैसे पाठ्य सामग्री, पृष्ठभूमि सामग्री, रिपोर्ट, व्यक्तिगत स्तर पर चलने वाले आलेख पत्र, कवर की छपाई, तथा कार्यक्रमों में भागीदारों में वितरित की जाने वाली लेखन सामग्री। इसमें संगोष्ठी, कार्यक्रम, कार्यशिविर, सभाओं तथा अन्य गतिविधियों को ध्यान में रखा गया।

प्रशासन और लेखा विभाग का आधुनिकीकरण

इस बात के लिए व्यवस्थित प्रयास किए जा रहे हैं कि जहां तक संभव हो प्रशासन का अधिकांश संगणकीकृत कर दिया जाए। योग्यता अवरोध के मामलों को छोड़कर 1-1-85 से इस आशय के आदेश जारी किए गए जिसमें संगणकों के माध्यम से स्वत: वेतन बढ़ोत्तरी की व्यवस्था की गई थी। संगणकीकरण के जरिए वार्षिक बढ़ोत्तरी प्राप्त करने के प्रचलन के कारण, वार्षिक बढ़ोत्तरी स्लिप जारी करने के झंझट से मुक्ति मिल गई है तथा किसी भी कारण से जो विलंब हुआ करता था, उसकी संभावना समाप्त हो गई है।

संगणकीकरण के द्वारा योजना और योजनेतर पदों के कार्यभार तथा रिक्त पदों आदि से संबंधित विस्तृत विवरण सहित काउट तथा परियोजना के कर्मचारियों की संख्या का पृथक मासिक ब्योरा तैयार किया जाता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वित्तीय लेखा तथा सामग्री सूची के नियंत्रण संबंधी कार्यक्रम तैयार किए गए।

कार्यक्रम की सूचना

संस्थान की महत्वपूर्ण गतिविधियों तथा विकास कार्यों की एक त्रैमासिक विवरणिका निकली है। (मिमियोग्राफ द्वारा)। इसमें उस तिमाही में संस्थान में चलाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्योरा होता है, संस्थान द्वारा हाथ में ली गई परियोजना की प्रगति सूचना तथा स्थिति की जानकारी होती है तथा अन्य गतिविधियों जैसे नीपा कोलोक्यम सलाहकारी, परामर्शकारी तथा समर्थनकारी सेवाओं की जानकारी, प्रकाशन अभिलेखन, पुस्तकालय, कर्मचारियों का आना जाना, सेवाकालीन प्रशिक्षण, विभिन्न निर्णयकारी निकायों की बैठकें तथा कृतिक बलों की बैठकों की सूचनाएं होती हैं। इसकी एक प्रति नीपा परिषद के अध्यक्ष को भेजी जाती है, एक एक प्रति शिक्षा सचिव तथा परिषद के अन्य सदस्यों की भेजी जाती है। वित्त कार्यकारिणी तथा सलाहकार समितियों के सदस्यों और शिक्षा मन्त्रालय के अन्य संबद्ध अधिकारियों के पास भी इसकी प्रतियां भेजी जाती हैं।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों के तहत मासिक एवं त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी जाती है।

कार्यालय उत्पादकता तथा सूचना को नवाचारी दृष्टि

कार्यालय की उत्पादकता बढ़ाने तथा काम के जल्दी-जल्दी निपटान को सुनिश्चित करने के लिए जून 1984 से एक नवाचारी दृष्टि अपनाई गई हैं। इसका मकसद है, संस्थान में कार्यालय सूचना की एक प्रभावी पद्धति लागू करना जिसका आधार व्यापक हो और जो कार्यालय के मुख्य कार्यों को निपटा सके, साथ में उनका संचारेक्षण भी कर सके। संस्थान में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए निम्नांकित बातें निर्धारित की गई हैं :

(अ) बचे हुए कार्य का साप्ताहिक विवरण

(ब) कार्मिक

(i) मासिक कार्मिक सूचना जिसमें इन बातों का समावेश होता है जैसे प्रोबेशन अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करना, वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप देना, निष्पादन मूल्यांकन तथा स्थाई करने के विषय में मूल्यांकन आदि।

(ii) विलम्ब से आने के विषय में मासिक सूचना तथा संकाय की संस्थान के बाहर तथा भीतर अकादमिक कार्यों में संलग्नता।

(स) आपूर्ति तथा सेवाएं

(i) अवशिष्ट मांग पत्रों की सूचना

(ii) अत्यन्त कम हुए स्टाक की सूचना तथा इससे संबंधित की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन।

(द) परिसम्पत्ति तथा निर्माण

(i) परिसर की देखरेख करने वाले, सफाई कर्मचारी तथा बिजली कर्मचारी की दैनिक डायरी, उचित रख-रखाव और सफाई की व्यवस्थित देखरेख की जा सके।

(ii) प्रत्येक महीने में एक निश्चित तारीख के दिन निर्माण तथा रखरखाव के काम के लिए एक माहवारी अंतर्विभागीय बैठक की पद्धति आरंभ की गई है। इन बैठकों में वास्तुकार, अभियंता तथा संस्थान के संबद्ध अधिकारी लोग भाग लेते हैं। इस नई व्यवस्था से निर्माण की प्रगति की नियमित देखरेख, रख-रखाव की समस्याओं को सुलझाने, अंतर्विभागीय मामलों की हल करने तथा तत्काल निर्णय लेने में मदद मिली है।

(य) बचे हुए लेखा विषयक आपत्तियों पर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट।

(फ) फाइल की रिकार्डिंग की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट।

(व) निर्णयकारी निकायों द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की रिपोर्ट।

लेकिन अभी भी इन उपर्युक्त कार्यालय रिपोर्टिंग की पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। लेकिन इन पद्धतियों के सीमित रूप में क्रियान्वयन के परिणाम दिखाई पड़ने लगे हैं। जो पावतियां 7 दिनों से बिना कार्य-वाही के रह जाती थी उनकी संख्या काफी कम हो गई हैं। बहुत से कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची काफी दिनों से बन नहीं सकी थी, उन्हें अब अंतिम रूप दिया जा चुका है। इसके साथ ही अन्य कार्मिक मामलों पर कार्यवाही में काफी प्रगति हुई है। अधिकांश थोक खरीदों के आदेश वर्ष के आरंभ में ही दे दिये गए थे। इस प्रकार मार्च की भीड़भाड़ से बचा गया। अब कम मदें ऐसी हैं जो गोदाम में नहीं, आपातकालीन खरीदों की संख्या कम हो गई है। अधिक सफाई, स्वस्थ वातावरण, अधिकारों का विकेंद्रीकरण, कार्यों का वितरण, स्पष्ट दिखाई पड़ता है, अब कार्य के प्रति लगाव बढ़ा है तथा कार्यालय के कामों में प्रगति नजर आने लगी है।

नीपा का परिसर

जल की आपूर्ति : बागवानी के लिए जल की आपूर्ति की संस्थान के पास कोई अपनी अलग से व्यवस्था नहीं थी। पानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद से लिया जा रहा था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बागवानी के लिए जलापूर्ति की पाइपलाईन डाली गई तथा एक और नलकूप लगाया गया। पीने के पानी के लिए नलकूप पहले से ही (1983-84 में) लगाया जा चुका था। इस प्रकार संस्थान ने पीने के पानी की तथा सिंचाई के लिए पानी समस्या को हल कर लिया गया, यह संस्थान की एक प्रमुख समस्या थी।

आवासीय इकाइयां : संस्थान के निदेशक की पृथक आवासीय व्यवस्था नहीं थी। निदेशक टाइप V के एक भवन में रह रहे हैं जो संकाय तथा प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बनाया गया है। लेकिन यह संतोषजनक व्यवस्था नहीं है। संस्थान आवासीय इकाइयों की भयंकर कमी का सामना कर रहा है। सिर्फ इसके निचले पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए टाइप I के आवास पहले बनाए गए हैं लेकिन इसके मध्यवर्ती स्तर के तथा कनिष्ठ स्तर के संकाय सदस्यों, सचिवीय तथा तकनीकी कर्मचारियों के लिए आवास की कोई व्यवस्था नहीं है। वर्ष के अंत में निदेशक के आवास तथा 8 टाइप II तथा 8 टाइप III आवासों का निर्माण आरंभ हुआ। अगले साल इनके पूरा होने पर निदेशक के पास एक उपयुक्त आवास होगा और आंशिक रूप से आवासीय समस्या से संस्थान की राहत मिलेगी। संस्थान के पास अभी भी संकाय सदस्यों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए टाइप आवासों का अभाव होगा। इस प्रकार संस्थान अभी भी आवास की कमी की समस्या से जूझता रहेगा।

कार्यालय तथा भौतिक अकादमिक ढांचा : इस वर्ष के दौरान दूसरे तल पर स्थित व्याख्यान कक्ष को नए सिरे से संवारा गया और इसमें 40 लोगों के स्थान पर 70 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई। इससे भागीदारों वाले राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को सरलता हो गई है। लेकिन संस्थान अभी भी कार्यालय के स्थान, व्याख्यान कक्षों, गोष्ठी कक्षों आदि की जबर्दस्त कमी का सामना कर रहा हैं। संस्थान में स्थानाभाव को देखते हुए तथा इसकी दीर्घकालीन ज़रूरतों को ध्यान में रखकर, शिक्षा मंत्रालय से 15-20 एकड़ भूमि सांस्थानिक क्षेत्र में मुहैया कराने का अनुरोध किया गया है जो यहां से काफी निकट है।

छात्रावास : दिल्ली में जितने भी कार्यक्रम संस्थान द्वारा आयोजित किए जाते हैं वे सभी के सभी पूर्णत: आवासीय होते हैं। भागीदारों को सातमंजिला छात्रावास में ठहराया जाता है जो 48 कमरों वाला है। वे कमरे पूर्णत: सज्जित हैं तथा स्नानघर संलग्न हैं। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले भागीदारों के लिए प्रथम तल के 8 कमरों को विशेष सुविधाओं, जैसे वातानुकूलन, गीजर तथा कनवेक्टर हीटरों से लैस किया गया है। प्रत्येक कमरे में दो-दो बिस्तरे हैं। अतिरिक्त सुविधाओं वाले कमरों का शुल्क 100/-प्रतिदिन प्रति व्यक्ति यदि एक व्यक्ति रुकता है तो और 75/प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, यदि दो लोग एक साथ रुकते हैं तो। अन्य कमरों का शुल्क रु. 6/प्रति भागीदार तथा गैर भागीदारों के लिए रु. 15/प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है। छात्रावास की समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अपने पूर्ववर्ती वर्ष की आय की तुलना में कम आय हुई। पूर्ववर्ती वर्ष में आय 3.40 लाख थी जब कि इस वर्ष 2.37 लाख। इसका कारण इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों की कम संख्या है तथा देश में 1984 के अंत में खराब स्थिति के कारण नवंबर तथा दिसंबर में छात्रावास लगभग खाली रहा।

यह निर्णय लिया गया है कि वार्डेन का आवास बनाया जाएगा, संकाय अतिथि कक्षों का निर्माण किया जाएगा तथा भंडार गृह बनाया जाएगा एवं छात्रावास के भोजन कक्ष और रसोई में और उन्नत सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। इनके नक्शों को डी डी ए की स्वीकृति का इंतजार है।

वित्तीय स्थिति : 1983-84 में संस्थान को 62.31 लाख रुपए (26.84 गैर योजना इतर तथा 35.47 लाख योजना के अंतर्गत) अनुदान मिले थे। इसकी तुलना में 1984-85 में 74.39 लाख रुपए (योजनेतर 31.44 लाख तथा 42.25 योजना के अंतर्गत) प्राप्त हुए थे। 3.85 रु. के पूर्ववर्ती खाते के सहित कुल प्राप्ति 82.87 लाख रुपए थी तथा छात्रावास तथा अन्य स्रोतों से प्राप्तियां 4.3 लाख थी। इस वर्ष सरकारी अनुदान में से कुल खर्चे 80.31 लाख रुपए थे। इसके अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय, भारतीय समाजविज्ञान अनुसंधान परिषद, सूनेस्को आदि से कार्यक्रम तथा अनुसंधान कार्यों के लिए संस्थान को 13.71 लाख रुपए मिले। प्रायोजित कार्यक्रमों तथा अध्ययनों के लिए 19.53 लाख रुपए मिले। इसमें 5.32 लाख पूर्ववर्ती खातों से था और इस वर्ष इस पर कुल खर्च 1984-85 के दौरान 14 01 लाख रुपए हुआ।

भाग आठ

छठीं योजना की उपलब्धियां

इस वर्ष की खासियत यह रही कि यह छठी पंचवर्षीय योजना का आखिरी वर्ष था। छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान संस्थान का अभूतपूर्व विकास हुआ तथा इसकी अनुसंधान अकादमिक तथा अन्य गतिविधियों को बहुमुखी दिशाएं मिली। इसने अकादमिक तथा अन्य प्रकार की आधारिक संरचना का निर्माण भी किया और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसने आधुनिक प्रबंधकीय प्रणाली को अमली जामा पहनाया। नीचे छठीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संस्थान की कुछ प्रमुख गतिविधियों का जिक्र किया गया हैं :

प्रशिक्षण कार्यक्रम

छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत लगभग 4000 शिक्षा कर्मी, जिनमें 400 विदेशी शिक्षा कर्मी भी शामिल हैं, विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रशिक्षण की गतिविधियों में पर्याप्त वृद्धि हुई है, यह नीचे की तालिका से स्पष्ट हो जाएगा :

	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	योग
1. कार्यक्रमों की संख्या	34	29	44	47	53	207
2. कार्यक्रम दिनों की संख्या	391	512	711	737	1015	3366
3. भागीदारों की संख्या	751	664	809	1099	927	4230
4. भागीदार कार्य	7497	5830	9987	14769	14852	52485

विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सभी राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश विभिन्न शिक्षा कर्मियों को प्रतिनियुक्त करते रहे हैं। भागीदारों में निम्नांकित लोग शामिल हैं : विभिन्न स्तर के अधिकारी, शिक्षा सचिवों तथा कुलपतियों से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी तथा संस्थाओं के प्रधान तक जैसे कालेजों के प्रिंसिपल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रिंसिपल।

क्षेत्रवार भागीदारी

सबसे अधिक भागीदारी उत्तरी क्षेत्र की (1272) रही, इसके बाद दक्षिणी क्षेत्र (711) थी, उसके बाद

पूर्वी क्षेत्र (704) और पश्चिमी क्षेत्र (690) थी। सर्वोच्च भागीदारी महाराष्ट्र (293) की पश्चिमी क्षेत्र से तथा इसके बाद उत्तरी क्षेत्र के उत्तरप्रदेश (231) और दिल्ली 231) की थी। नौ शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों के भागीदारों की संख्या 1427 थी। यह कुल राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या का 34% था।

राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, भारत सरकार तथा विदेशों से छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भागीदारों का विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है :

क्रम संख्या	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	भागीदारों की संख्या 1984-85
1.	आंध्रप्रदेश	200
2	असम	189
3.	बिहार	135
4.	गुजरात	117
5.	हरियाणा	212
6.	हिमाचल प्रदेश	36
7.	जम्मू तथा कश्मीर	180
8.	कर्नाटक	115
9.	केरल	68
10.	मध्यप्रदेश	157
11.	महाराष्ट्र	293
12.	मणिपुर	32
13.	मेघालय	31
14.	नागालैंड	40
15.	उड़ीसा	59
16.	पंजाब	130
17.	राजस्थान	185
18.	सिक्किम	16
19.	तमिलनाडु	211
20.	त्रिपुरा	25
21.	उत्तरप्रदेश	231
22.	पश्चिम बंगाल	91
23.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	49
24.	अरुणाचल प्रदेश	23
25.	चंडीगढ़	67
26.	दिल्ली	231
27.	गोवा दमन तथा दिउ	113
28.	लक्ष द्वीप	1
29.	दादरा तथा नागर हवेली	9

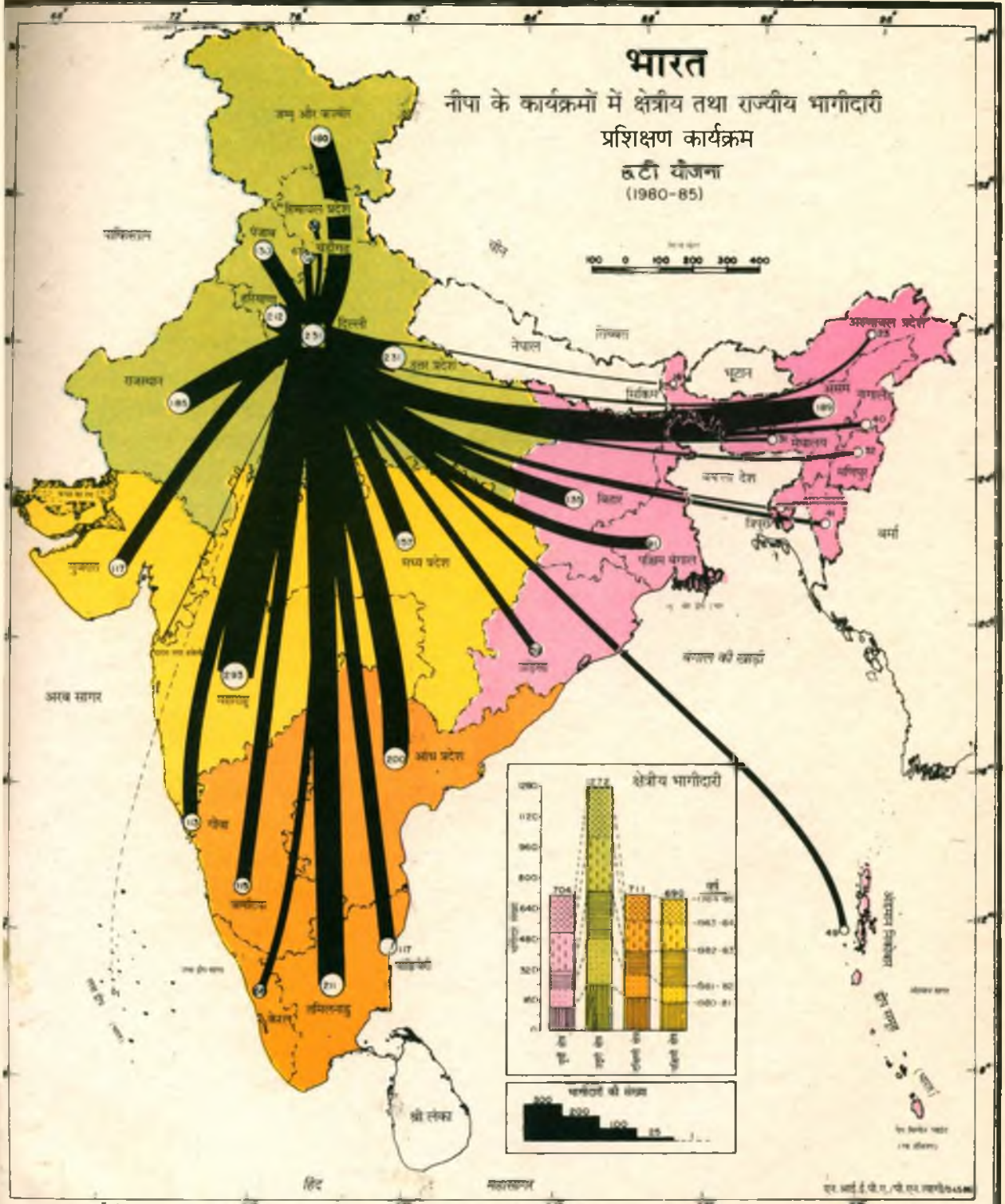

भारत
नीपा के कार्यक्रमों में क्षेत्रीय तथा राज्यीय भागीदारी
प्रशिक्षण कार्यक्रम
छटी योजना
(1980-85)
100 0 100 200 300 400
जम्मू और कश्मीर
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
दिल्ली
राजस्थान
उत्तर प्रदेश
नेपाल
भूटान
गुजरात
मध्य प्रदेश
बिहार
पश्चिम बंगाल
अरुणाचल प्रदेश
असम
मेघालय
मणिपुर
बांग्ला देश
बर्मा
महाराष्ट्र
आंध्र प्रदेश
गोवा
कर्नाटक
तमिलनाडु
केरल
पांडिचेरी
अरब सागर
बंगाल की खाड़ी
श्री लंका
क्षेत्रीय भागीदारी
1272
704
711
690
भागीदारों की संख्या
300
200
100
25
हिंद महासागर

क्रम संख्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	भागीदारों की स० 1984-85
30. मिजोरम	41
31. पांडिचेरी	117
योग	3394
भारत सरकार	432
अन्य देश	413
कुल योग	4239

31 देशों से विदेशी भागीदारों ने हिस्सा लिया था। ये देश हैं : अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, बहरीन, बंगलादेश, बरबाडोस, भूटान, कनाडा, चीन, साइप्रस, इथोपिया, फिजी, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, केनिया, कोरिया, कुवैत, मलेशिया, मालद्वीप, मारिशस, नेपाल, पाकिस्तान, पापुआ तथा न्यू गिनी, फिलीपाइंस, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, थाइलैंड, यूनाइटिड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमरीका।

मुख्य केंद्र

इन सभी कार्यक्रमों का मुख्य जोर आधुनिक प्रबंध तथा मात्रात्मक तकनीकों से भागीदारों को लैस करके तथा उनको विकास के कठिन क्षेत्रों से परिचित कराकर मानव संसाधन के विकास पर रहा है। योजना और प्रशासन में शिक्षा कर्मियों की दक्षता बढ़ाने पर जोर दिया जाता है, उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग तथा नवाचारी दृष्टिकोण अपनाने और निष्पादनोन्मुख प्रशासन पर भी बल दिया जाता है।

कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम

(अ) जिला शिक्षा अधिकारियों का छः माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम

जिला शिक्षा अधिकारियों का छः माह का डिप्लोमा पाठ्यक्रम 1982-83 में आरंभ किया गया। दूसरे तथा तीसरे पाठ्यक्रम क्रमशः 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान चलाए गए।

(ब) कैडर पर आधारित अन्य कार्यक्रम

1. वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों का कार्यक्रम (तीन सप्ताह के कार्यक्रमों की शृंखला,)
2. जिला शिक्षा अधिकारी तथा अनौपचारिक शिक्षा के प्रभारी अधिकारी (दो-तीन सप्ताह के कार्यक्रमों की शृंखला)
3. केंद्रीय विद्यालय के संगठन के सहायक आयुक्त, शिक्षा अधिकारी और प्राचार्य।
4. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य
5. पर्यवेक्षक अधिकारी तथा आश्रम स्कूलों के अध्यक्ष
6. अंध विद्यालयों के प्राचार्य
7. सुरक्षा सेवाओं के शिक्षा निदेशालयों के पर्यवेक्षक अधिकारी

8. लोक पुस्तकालय सेवाओं के वरिष्ठ प्रशासक
9. विश्वविद्यालय प्रशासन की नवाचारी दृष्टि में विश्वविद्यालय के कुलसचिवों का प्रशिक्षण
10. राज्य शिक्षा विभागों तथा विश्वविद्यालयों के वित्त अधिकारी
11. कृषि विश्वविद्यालय के नियंत्रक
12. कॉलेजों के प्राचार्य (तीन सप्ताह के कार्यक्रमों की शृंखला प्रतिवर्ष एक, जिनमें एक महिला विद्यालयों तथा दूसरा ऐसे कालेजों का जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की संख्या अधिक हो)।
13. इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्राचार्य तथा पोलिटेकनीक के प्राचार्य

(स) प्राथमिकता क्षेत्रों के विशेष कार्यक्रम

1. शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नौ राज्यों के संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण
2. जनसंख्या शिक्षा का प्रबंध
3. शिक्षा में न्याय
4. शिक्षा के व्यवसायीकरण की योजना और प्रबंध
5. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना का प्रबंध (राष्ट्रीय मेरिट छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति, तथा ग्रामीण प्रतिभा खोज योजना)
6. शिक्षा और ग्रामीण विकास

(द) संगोष्ठियां और कार्यशिविर

1. दीर्घावधि शैक्षिक योजना
2. गर मौद्रिक आगतों पर विशेष जोर के साथ शैक्षिक विकास के लिए संसाधनों का विवेक संगत इस्तेमाल
3. शिक्षा तथा रोजगार में समन्वय
4. स्कूल शिक्षा शिक्षामंडलों के प्रबंधकीय पक्ष पर स्कूल शिक्षा मंडलों के अध्यक्ष और सचिव
5. विभिन्न शैक्षिक सुधार तथा उनके क्रियान्वयन पर शिक्षा सचिव एवं शिक्षा निदेशक
6. शिक्षा की योजना : सातवीं पंचवर्षीय योजना
7. शैक्षिक योजना और प्रबंध में संगणक का प्रयोग
8. शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रबंध
9. राष्ट्रीय प्रतिभा परीक्षा
10. शैक्षिक प्रबंध में व्यष्टिपरक (केस स्टडीज) अध्ययनों का विकास

(ब) अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

(अ) अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा

1. शैक्षिक योजना और प्रशासन में छः मास का अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम
2. दक्षिणपूर्व एशिया तथा तीसरी दुनिया के अन्य देशों के शिक्षा कर्मियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए जनवरी 1984 में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान ने प्रथम डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ किया ।
3. श्रीलंका के शिक्षा कार्मिकों के लिए शैक्षिक प्रबंध में विशेष डिप्लोमा पाठ्यक्रम । इस संस्थान से विभिन्न स्तर के 52 अधिकारी अब तक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं ।
4. विकास मंत्रालय, भूटान के शिक्षा विभाग के एक शिक्षा अधिकारी के लिए, शैक्षिक प्रशासन के विशेष संदर्भ में कार्यालय प्रबंध में एक वर्ष का उच्चतर प्रशिक्षण कार्य ।

(ब) अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. भूटान, बंगला देश, थाईलैंड, मालदीव तथा फिलीपाइंस के शिक्षा विभागों के वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों का विभिन्न अवधियों का संबंध कार्यक्रम
2. अफगानिस्तान के यूनेस्को अध्येताओं के लिए दो प्रशिक्षण कार्यक्रम
3. बैंकाक स्थित थाईलैंड के शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों के रेक्टरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
4. पापुआ न्यू गिनी के शिक्षा अधिकारियों के लिए तीन महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम

(स) कार्यशिविर तथा संगोष्ठियां

दक्षिण पूर्व एशिया तथा तीसरी दुनिया के देशों के लिए शैक्षिक योजना, शैक्षिक प्रशासन, पर्यावरण शिक्षा की योजना, व्यष्टिस्तरीय शैक्षिक योजना जैसे विषयों पर क्षेत्रीय कार्यशिविर तथा विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया । ये कार्यक्रम यूनेस्को तथा अन्य अभिकरणों के सहयोग से आयोजित किए गए थे ।

(द) अध्ययन भ्रमण

विभिन्न अवधियों के लिए विभिन्न देशों के वरिष्ठ अधिकारीगण अध्ययन भ्रमण के लिए आए जिसका आयोजन यूनेस्को तथा अन्य अभिकरणों के सहयोग से किया गया था । शैक्षिक योजना के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से एशियाई प्रशिक्षार्थी भी नीपा आते रहे हैं । यह अध्ययन दौरा उनके उच्चतर प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक हिस्सा रहा है ।

अनुसंधान कार्यक्रम

संस्थान 1981-82 से ही शैक्षिक योजना और प्रशासन में महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य चलाता रहा है तथा इसमें इसकी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं, जैसा कि नीचे अनुसंधान के खर्चों में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी से संकेत मिलता हैं।

वर्ष	सरकारी अनुदान से किया गया व्यय	अन्य कोशीय सहायता से किया गया खर्च	कुल योग (रु. लाखों में)
1980-81	0.22	0.32	0.54
1981-82	0.24	0.64	0.88
1982-83	2.43	4.81	7.24
1983-84	3.60	10 66	14.26
1984-85	4.23	7.65	11.88
	10.72	24.08	34.80

योजना में 5.50 लाख रुपये व्यय का प्रावधान अनुसंधान अध्ययन के लिए किया गया था लेकिन संस्थान ने योजना अवधि में 34.80 लाख रुपये खर्च किए। मूल योजना का खर्च 5.50 लाख रुपये था लेकिन इससे ऊंची लागत 10.72 लाख रुपये खर्च हुए। संस्थान को 24.08 लाख रुपये की राशि और मिली। यह राशि वित्तीय सहायता से चलने वाले अनुसंधानों के लिए थी जिसे भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अनुरोध पर हाथ में लिया गया था या उच्च शिक्षा संबंधी शिक्षक आयोग, या यूनेस्को तथा आई सी एस एस या शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के अनुरोध पर हाथ में लिया गया था।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान ने कुल 45 अनुसंधान अध्ययन पूरे किए जिनका विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है :

वर्ष	पूरे किए गए अनुसधानों की संख्या
1980-81	1
1981-82	1
1982-83	11
1983-84	11
1984-85	21
योग	45

विभिन्न स्तरों पर 31-3-1985 को 17 अनुसंधान अध्ययन विकास के विभिन्न सोपानों पर थे।

कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजनाएं

1. राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में शैक्षिक प्रशासन का अखिल भारतीय सर्वेक्षण
2. शैक्षिक रूप मे पिछड़े हुए नौ राज्यों मे प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासन का अध्ययन

3. राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक स्तर पर शैक्षिक नीति, योजना तथा प्रबंध के विभिन्न पक्षों का अध्ययन इनमें से कुछ अध्ययनों के नाम इस प्रकार हैं : भारत में शैक्षिक प्रबंध का निदानात्मक अध्ययन, स्कूल स्तर पर शैक्षिक सुविधाओं के लिए मानदंडों का विकास; शैक्षिक विकास के विभिन्न पहलुओं के राष्ट्रीय स्तर पर संचारेक्षण के लिए सरल तथा सुकर प्रबंध पद्धति तैयार करना, विश्वविद्यालयों के लिए वित्तीय विनियम का प्रारूप तैयार करना, शैक्षिक विकास में क्षेत्रीय असमानता; अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के शैक्षिक विकास के आंकड़ों का आधार तैयार करना (उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों का बना रहना, पुनरावृत्ति तथा बीच में छोड़ना : एक राष्ट्रीय पार्श्व चित्र), सामाजिक पृष्ठभूमि, जीवन स्थितियों तथा मैट्रिकोतर छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों के अकादमिक निष्पादन के संदर्भ में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों का राष्ट्रीय अध्ययन; जिला गुड़गांव, हरियाणा में शिक्षा आपूर्ति की लागत; भारत में शिक्षा के लिए संसाधनों की व्यवस्था तथा अध्यापकों की स्थिति पर ग्यारह अध्ययन, इसे राष्ट्रीय शिक्षक आयोग (उच्च शिक्षा) के आगत के रूप में लिया गया था। कुछ चल रहे अध्ययनों का जिक्र भी आवश्यक है जैसे वर्ष 2000 में शिक्षा एक दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य, भारत में शैक्षिक नीति की योजना : योजना आयोग की भूमिका तथा स्कूलों में शिक्षक छात्र संबंध।

(iv) कार्य अनुसंधान

मेवात क्षेत्र के पुनहाना प्रखंड के 20 गांवों में एक कार्य अनुसंधान हाथ में लिया गया है। शिक्षा की दृष्टि से यह सर्वाधिक पिछड़े हुए इलाकों में से हैं। इस परियोजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए तिहरी रणनीति अपनाई गई है, इसमें जिन बातों को शामिल किया गया है, वे इस प्रकार हैं : समुदाय की भागीदारी, विकास से संबंधित अन्य विभागों से संपर्क तथा राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान की समीक्षात्मक मार्गदर्शी भूमिका। दिसंबर 1984 की वर्ष के मध्य की रिपोर्ट से यह बात उद्घाटित होती है कि लड़कों का नामांकन का प्रतिशत 44.22 से बढ़कर 90.55 ही गया है और लड़कियों का 12.48 से 38.66 हो गया है। राहिरा नामक गांव में तो लड़के और लड़कियों दोनों का ही नामांकन 100% हो चुका है। अन्य चार गांवों में यादी पामाखेड़ा रायपुर, राहिरा और टुंडल्का में लड़कों का नामांकन 100% है।

(v) अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन

शिक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नौ राज्यों में प्रारंभिक स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के मूल्यांकन अध्ययन का काम संस्थान ने हाथ में लिया है। इसका उद्देश्य इन राज्यों में खराब नामांकन के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाना है। यह मूल्यांकन कार्यक्रम में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवश्यक परिवर्तन की पहचान करेगा।

(vi) केस अध्ययन

संस्थान ने दो कॉलेजों का पाइलट अध्ययन तथा 6 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का केस अध्ययन किया है। इसको संस्थान अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आगत (इनपुट) के रूप में इस्तेमाल करेगा।

(vii) प्रशिक्षण अनुसंधान संबंध

अनुसंधान में प्राप्त निष्कर्षों को लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम में इस्तेमाल किया जाता है।

(viii) सामयिक और अनुसंधान आलेख

संस्थान ने आलेखों के एक शृंखला के प्रकाशन का आयोजन आरंभ किया है। इस शृंखला का नाम हैं, "सामयिक तथा अनुसंधान आलेख" इसका उद्देश्य शैक्षिक योजना और प्रशासन के विविध पक्षों से संबंधित निष्कर्षों का प्रसार करना है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रकार के नौ पत्र प्रकाशित किए गए।

परामर्शकारी, सलाहकारी तथा समर्थनकारी सेवाएं

(अ) शिक्षकों के राष्ट्रीय आयोग के लिए कार्य

दो राष्ट्रीय शिक्षक आयोगों के कार्य में—एक स्कूल शिक्षा और दूसरा उच्च शिक्षा—संस्थान ने तकनीकी आगत (इनपुट) मुहैया कराया।

(ब) राज्य तथा केंद्र स्तर पर कृतिक बलों, कार्यदलों, सलाहकार मंडलों तथा आयोगों में योगदान

विभिन्न बैठकों में हिस्सा लेकर संस्थान ने योगदान किया। ये बैठकें हैं : शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों के लिए प्रारंभिक शिक्षा पर कृतिक बल तथा केंद्र स्तर पर, वार्षिक योजना पर बहस, सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए शिक्षा पर कार्यदल (1985-90), केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल केंद्रशासित प्रदेशों व राज्यों के शिक्षा सचिवों तथा निदेशकों के सम्मेलन, विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर एन सी ई आर टी तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ, योजनेतर क्षेत्र में शिक्षा के लिए पर्याप्त धन आबंटित करने के लिए वित्त आयोग को एक स्मरण पत्र देना।

(स) राज्य केंद्रशासित प्रदेश तथा विश्वविद्यालय शिक्षा विभागों का परामर्श

संस्थान ने 1982, 1983, 1985 के दौरान सिक्किम, जम्मू तथा कश्मीर, दादरा और नागर हवेली तथा हरियाणा के शिक्षा विभागों को परामर्शकारी सेवाएं उपलब्ध कराईं। स्कूलों के लिए निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने में केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप की मदद की तथा वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली और विद्या-भवन, उदयपुर को दी गई स्वायत्तता के पुनरीक्षण में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा मंडल की सहायता की।

(द) संकाय का समर्थन

विभिन्न राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य निकायों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में संस्थान के संकायों का समर्थन उपलब्ध कराया गया।

(य) यूनेस्को तथा दूसरे देशों को परामर्शकारी सेवाएं

यूनेस्को के अनुरोध पर संस्थान ने कई अनुसंधान अध्ययन तथा दूसरे कार्यक्रम हाथ में लिए। यूनेस्को तथा अन्य देशों ने समय समय पर संकाय के सदस्यों को भी परामर्श के लिए आमंत्रित किया है।

अन्य अकादमिक गतिविधियां

(अ) नवाचारों का प्रसार

शैक्षिक योजना और प्रशासन में सफल प्रयोगों तथा नवाचारों से प्राप्त अनुभवों के आदान प्रदान के लिए संस्थान ने वरिष्ठ शैक्षिक योजनाकारों तथा प्रशासकों के अंतर्राज्यीय दौरों के आयोजन किए। महाराष्ट्र के "रैपोर्ट बेस्ड प्रोग्राम आफ स्कूल इंप्रूवमेंट" के अध्ययनार्थ छठी योजना अवधि के दौरान इस प्रकार के तीन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसीके साथ "तमिलनाडु में 2 स्तर पर शिक्षा का रोजगारीकरण, तथा "मध्यप्रदेश में सीखो और कमाओ" कार्यक्रम भी शामिल हैं।

(ब) शैक्षिक योजना और प्रशासन में नवाचारी अवधारणाओं और व्यवहारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

शिक्षा में नवाचारी अवधारणाओं और व्यवहारों के लिए जिला स्तर पर काम करने वाले शिक्षा अधिकारियों की पहली अखिल भारतीय प्रतियोगिता 1982-83 में आयोजित की गई। उसके बाद से यह प्रतियोगिता हर साल आयोजित की जाती है।

(स) शिक्षा पर अनौपचारिक विचार विमर्श

1982-83 में विचार विमर्श की एक श्रृंखला की शुरुआत की गई। इसमें संकाय के सदस्य, शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में बाहर के विशेषज्ञ, विख्यात शिक्षाशास्त्रियों और बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। इन विचार विमर्शों को नियत कालिक रूप से आयोजित किया जाता है तथा शिक्षा और विकास के क्षेत्र में विचार विमर्श के लिए यह एक व्यावसायिक मंच का काम देता है।

(द) नीपा की उपसदस्यता

शैक्षिक योजना और प्रशासन तथा नवाचार के क्षेत्र में, "राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन की उपसदस्यता" का कार्यक्रम 1982-83 में चलाया गया।

प्रकाशन

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान संस्थान ने 275 प्रकाशन निकाले, इनमें से 47 मुद्रित रूप में थे तथा अन्यो की मिमियोग्राफ रूप में प्रस्तुत किया गया। कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशनों में निम्नांकित शामिल हैं :

1. शैक्षिक योजना और प्रशासन की त्रैमासिक बुलेटिन,
2. विभिन्न राज्यों की शैक्षिक प्रशासन संबंधी सर्वेक्षण रिपोर्ट,
3. शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों की प्रारंभिक शिक्षा के विषय में सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये राज्य हैं : आंध्र-प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू तथा काश्मीर, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान तथा पश्चिमी बंगाल,
4. जिला शिक्षाधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना की मार्गदर्शन पुस्तिका, (मिमियोग्राफ),
5. शैक्षिक विकास के चुने हुए सांख्यिकीय सूचक,
6. शिक्षा तथा नई अंतर्राष्ट्रीय, व्यवस्था (समूल्य),
7. भारत में संगमशाला को पुनरुज्जीवन (समूल्य),
8. शैक्षिक विकास में क्षेत्रीय असमानता : शिक्षा का मानचित्र (मिमियोग्राफ),
9. भारत में शिक्षा के प्रबंध का निदानात्मक अध्ययन (मिमियोग्राफ)

अकादमिक आधारिक संरचना

संस्थान के पुस्तकालय का चतुर्दिक विकास तथा उन्नति हुई है। एशियाई क्षेत्र में शैक्षिक योजना और प्रशासन की पुस्तकों के संग्रह की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालयों में इसकी गणना की जा सकती है। राष्ट्रीय अवकाश की छोड़कर फरवरी 1983 से पुस्तकालय प्रतिदिन खुला रहता है।

जिला और राज्य स्तर के दस्तावेज एकत्र करने के लिए 1982-83 में एक प्रलेखन केंद्र स्थापित किया गया।

संस्थान में 1981-82 के दौरान प्रकाशन एकक की स्थापना की गई ताकि प्रकाशन का कार्य प्रभावी ढंग से चलाया जा सके।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अकादमिक कार्यक्रमों को समर्थन प्रदान करने के लिए संस्थान में आरेखण कक्ष आंकड़ा बैंक, हिंदी प्रकोष्ठ, इलेक्ट्रानिक आंकड़ा सेंसाधन तथा फोटो कार्पिंग एककें स्थापित की गईं।

प्रशासन तथा वित्त

कॉडर योजना : संस्थान में विभिन्न कॉडर के कर्मचारियों की संख्या 1-4-80 तथा 31-3-85 की नीचे तुलना के लिए दी गई है :

क्रम संख्या	कॉडर पद	1-4-1980	31-3-1985	अतिरिक्त बने पद
1.	संकाय	25 (24.3%)	45 (28.0%)	+20
2.	संकाय समर्थन	3 (2.9%)	10 (6.2%)	+ 7
3.	प्रशासनिक तथा सचिवीय स्टाफ	26 (25.3%)	38 (32.6%)	+12
4.	तकनीकी स्टाफ	21 (20.4%)	29 (18.0%)	+ 8
5.	चतुर्थ श्रेणी	28 (27.2%)	39 (24.2%)	+11
	योग	103	161	+58

इस समय संस्थान का ढांचा अधिक संतुलित और संगठित है जिसमें संकाय का कॉडर सर्वोच्च स्थान पर है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान : संकाय के सदस्यों के लिए 1-4-1982 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान लागू किए गए तथा पुस्तकाध्यक्ष और प्रलेखन अधिकारी के लिए यही वेतनमान 21-3-1984 से लागू हुए।

प्रबंधकीय तकनीकों का उपयोग : संस्थान में प्रबंध की आधुनिक तकनीकों के उपयोग के कारण इसकी उत्पादकता तथा कुशलता में वृद्धि हुई। प्रबंध की जिन महत्वपूर्ण आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल इस अवधि में किया गया उनमें से कुछ का उल्लेख यहां किया गया है : अधिकारों का बड़ी सीमा तक हस्तांतरण, प्रतिमानों का निर्धारण, कार्यक्रम की रिपोर्टिंग, कार्य के मुख्य क्षेत्रों को समेटने के लिए कार्यालय रिपोर्टिंग के प्रति नवाचारी दृष्टिकोण, जैसे कार्मिक, आपूर्ति और सेवाएं, संपत्ति तथा निर्माण (प्राप्तियों के व्ययन के अतिरिक्त)। संस्थान की मानव संसाधन विकास नीति के अंतर्गत अकादमिक तथा अन्य कर्मचारियों को सेवा-कालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई।

प्रशासन तथा लेखा का आधुनिकीकरण : मासिक वेतन बिल, बढ़ोतरी तथा कॉडर एवं परियोजना कर्मचारियों का पुनरीक्षण आदि का संगणकीकरण किया जा चुका है। सामग्री सूची नियंत्रण तथा वित्तीय लेखा का संगणकीकरण करने का प्रोग्राम तैयार किया गया है।

नीपा परिसर

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान में निर्माण की गतिविधियां काफी तीव्र गति से चलीं तथा नीपा का अपना परिसर विकसित किया गया। अगस्त 1983 में दो रिहायशी इकाइयां बनकर तैयार हो गईं। इनमें 16 टाइप I के तथा 8 टाइप V के आवास थे। निदेशक के आवास का

निर्माण तथा टाइप II व टाइप III के आठ आठ आवासों की दो इकाइयों का निर्माण चल रहा है और 1985-86 के दौरान इसके बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है।

कार्यालय की वर्तमान आवश्यकता तथा भौतिक अकादमिक आधारिक संरचना तथा भावी विकास को देखते हुए नीपा का वर्तमान 3.75 एकड़ परिसर काफी अपर्याप्त है।

धन का वितरण

छठी पंचवर्षीय योजना के आरंभ से ही संस्थान लगातार संवृद्धि की ओर अग्रसर होता चला गया है। इसको नीचे दिए गए व्यय की प्रवृत्तियों में लक्षित किया जा सकता है :

(रुपए लाखों में)

वर्ष	योजनेतर	योजनांतर्गत	योग
1	2	3	4
1980-81			
(अ) सरकारी अनुदान से	19.72	22.61	42.33
(ब) प्राप्त कोष से	—	0.80	0.80
योग	19.72	23.41	43.13
1981-82			
(अ) सरकारी अनुदान से	23.58	25.88	49.46
(ब) प्राप्त कोष से	—	2.67	2.67
योग	23.58	28.55	52.13
1982-83			
(अ) सरकारी अनुदान से	29.46	29.46	58.93
(ब) प्राप्त कोष से	—	8.70	8.70
योग	29.46	38.17	67.63
1983-84			
(अ) सरकारी अनुदान से	34.43	33.99	68.42
(ब) प्राप्त कोष से	—	16.01	16.01
योग	34.43	50.00	84.43
1984-85			
(अ) सरकारी अनुदान से	34.67	45.64	80.31
(ब) प्राप्त कोष से	—	14.01	14.01
योग	34.67	59.65	94.32

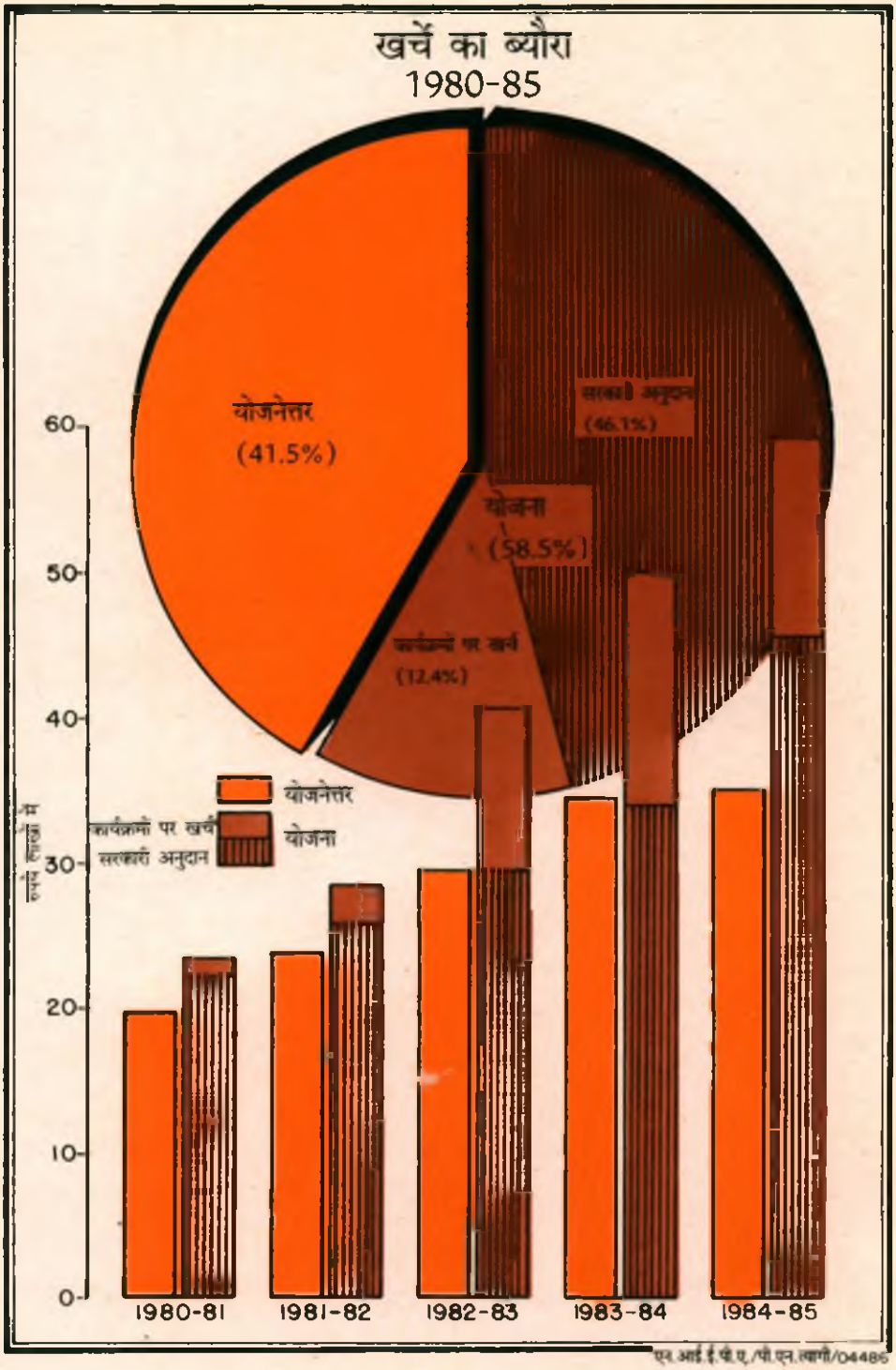
खर्चे का ब्यौरा
1980-85
योजनेत्तर
(41.5%)
सरकारी अनुदान
(46.1%)
योजना
(58.5%)
कार्यक्रमों पर खर्च
(12.4%)
60
50
40
30
20
10
0
योजनेत्तर
कार्यक्रमों पर खर्च
सरकारी अनुदान
योजना
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85

1	2	3	4
कुल योग			
(अ) सरकारी अनुदान	141.86	157.59	299.35
(ब) प्राप्त कोष से	—	42.19	42.19
बृहत योग	141.86	199.78	341.64

छठी पंचवर्षीय योजना के मूल प्रारूप में 115.00 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था लेकिन संस्थान ने बीच में पुनरीक्षण के बाद अधिक धनराशि का प्रावधान किया तथा कुल खर्च 157.59 लाख रुपए व्यय किए गए और प्राप्त कोषों से 42.19 लाख रुपए जुटाए गए।

अनुबध

अनुबंध एक

प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. एयर फोर्स के शिक्षा अधिकारियों का शैक्षिक योजना और प्रशासन में अभिविन्यास कार्यक्रम (अप्रैल 2-19, 1984)

नई दिल्ली के एयर मुख्यालय के शिक्षा निदेशालय के अनुरोध पर संस्थान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य थे : स्वतंत्रता के बाद भारत में विकसित शैक्षिक विकास की प्रवृत्तियों से भागीदारों को परिचित कराना, पर्यवेक्षक तथा प्रशासनिक वक्षता में सुधार करना, तथा वर्तमान समय में एयर फोर्स स्कूलों में प्रचलित निरीक्षण तालिका के मानकीकरण का प्रयास करना। इस कार्यक्रम में छत्तीस वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रबंध समिति में निम्नांकित लोग थे : डा. सी एल सपरा, कार्यक्रम निदेशक, श्री शब्बीर अहमद, श्री टी के डी नायर क्रार्यक्रम संयोजक, श्रीमती रश्मि दीवान कार्यक्रम सहायिका।

2. जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में तीसरा डिप्लोमा पाठ्यक्रम (जुलाई 2, 1984 से जनवरी 28, 1985)

इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे : भागीदारों को शैक्षिक योजना प्रशासन और प्रबंध की मूलभूत अवधारणाओं से परिचित कराना, उनके कार्यों के लिए आवश्यक दक्षताओं तथा तकनीकों के प्रति उनमें अंत-दृष्टि विकसित करना, शैक्षिक निर्णय की क्षमता का विकास करना और राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा के योगदान की प्रत्याशाओं से पैदा होनेवाली समस्याओं के निदान खोजने की क्षमता प्रदान करना, शैक्षिक प्रयोगों तथा अनुसंधानों तथा प्रयोगों की मूलभूत तकनीकों से भागीदारों का परिचय कराना। यह कार्यक्रम इस प्रकार बनाया गया था कि इसमें प्रत्येक तीन माह संस्थान में प्रशिक्षण व गहन पाठ्यक्रम का कार्य तथा तीन माह प्रशिक्षार्थी के नियुक्ति क्षेत्र में पर्यवेक्षित कार्य और चार दिनों की संस्थान में मौलिक परीक्षा की व्यवस्था की गई थी। विभिन्न प्रांतों तथा केंद्रशासित प्रदेशों से चौबीस भागीदारों ने इसमें हिस्सा लिया।

कार्यक्रम की व्यवस्था में डा. सी एल सपरा ने कार्यक्रम निदेशक के रूप में कार्य किया तथा श्री शब्बीर अहमद कार्यक्रम संयोजक थे। श्रीमती जुबेदा हबीब कार्यक्रम सहायिका थीं।

3. उत्तरप्रदेश के सीधे भर्ती किए गए बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन पर अभिविन्यास कार्यक्रम (सितंबर 17 से अक्तूबर 1, 1984

उत्तरप्रदेश सरकार के शिक्षा निदेशालय के अनुरोध पर वहां के सीधे भर्ती किए गए शिक्षा अधिकारियों के लिए 15 दिनों का अभिविन्यास कार्यक्रम का संस्थान ने आयोजन किया था। इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे : शैक्षिक योजना की महत्वपूर्ण तकनीकों में नए भर्ती किए गए अधिकारियों को अभिविन्यस्त करना, विभिन्न स्तरों पर वित्तीयन एवं प्रशासन में अभिविन्यस्त करना, इस प्रकार उन्हें शैक्षिक प्रशासक तथा पर्यवेक्षक के रूप में व्यावसायिक क्षमता और प्रभाविता प्राप्त करने की योग्यता प्रदान करना। इस संगोष्ठी में तीन अधिकारियों ने भाग लिया।

इस कार्यक्रम की प्रबंध व्यवस्था श्री मनमोहन कपूर ने की जो इसके निदेशक भी थे। संयोजन का कार्य डा. रामस्वरूप शर्मा तथा श्री वी ए कालपांडेय ने किया और श्री ए सी मेहता कार्यक्रम सहायक के रूप में सक्रिय रहे।

4. अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन विषय में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (अक्तूबर 10-20, 1984)

केंद्रशासित प्रदेश अंडमान निकोबार के अनुरोध पर अंडमान तथा निकोबार में संस्थान ने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। निम्नांकित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया गया था : शैक्षिक योजना और प्रशासन की नवीनतम अवधारणाओं, तकनीकों, प्रवृत्तियों और समस्याओं से भागीदारों की परिचित कराना, शिक्षा के विकास और खास तौर पर अंडमान और निकोबार की शैक्षिक स्थितियों के संदर्भ में, राष्ट्रीय नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को भागीदारों की जानकारी देना, तथा उनकी व्यावसायिक क्षमता तथा प्रभाविता (शैक्षिक प्रशासक के रूप में) को बढ़ाने में उनकी मदद करना। इस कार्यक्रम में तीस भागीदार उपस्थित थे।

इनके प्रबंध दल में श्री एम एम कपूर कार्यक्रम निदेशक थे और श्री चंद्रप्रकाश तिवारी और रामस्वरूप शर्मा उसके संयोजक थे।

5. असम के स्कूल प्राचार्यों के लिए शैक्षिक प्रबंध विषय पर तीसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम (नवंबर 5 से 23, 1984)

असम सरकार के लोक शिक्षा निदेशालय के अनुरोध पर असम के स्कूल प्राचार्यों के लिए संस्थान ने शैक्षिक प्रबंध विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम कुछ विशेष उद्देश्यों को ध्यान में रखकर आयोजित किया गया। ये उद्देश्य इस प्रकार हैं : संस्था के एक प्रभावशाली नेता के रूप में एक प्राचार्य को जिन दक्षताओं, ज्ञान और जिस भूमिका की आवश्यकता होती है, उससे इनको परिचित कराना, कार्मिक/वित्तीय प्रबंध तथा अकादमिक संचारेक्षण और मूल्यांकन सहित शैक्षिक प्रबंध की प्रमुख अवधारणाओं से भागीदारों को परिचित करना तथा सुधरे हुए स्कूल प्रबंध के लिए कार्य योजना बनाना। प्राचार्यों का यह कार्यक्रम इस शृंखला का तीसरा कार्यक्रम था। इसमें सत्रह स्कूल प्राचार्य उपस्थित थे।

इसके प्रबंध दल में निम्नांकित लोग थे : डा. के जी विरमानी, कार्यक्रम निदेशक तथा श्रीमती नलिनी जुनेजा कार्यक्रम सहयोगी थी।

6. वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन पर अभिविन्यास कार्यक्रम (जनवरी 7-25, 1985, विस्तृत ब्यौरा कार्यक्रम सं. 8 में देखें)

7. असम के स्कूल प्राचार्यों का शैक्षिक प्रबंध में अभिविन्यास कार्यक्रम (जनवरी 21 से फरवरी 8, 1985)

असम के लोक शिक्षा निदेशालय के अनुरोध पर असम के स्कल प्राचार्यों के लिए संस्थान ने एक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया। इस शृंखला में यह चौथा कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के सामान्य उद्देश्य इस प्रकार थे : शैक्षिक प्रबंध तथा अकादमिक संचारेक्षण और मूल्यांकन की मुख्य-मुख्य अवधारणाओं से भागीदारों को परिचित कराना, एक प्रभावशाली संस्थागत नेता के रूप में उचित भूमिका, दक्षता और ज्ञान की संकल्पना करना जो किसी प्राचार्य से अपेक्षित होती है, कार्य योजना बनाना। अट्ठाईस स्कूल प्राचार्यों ने इस अभिविन्यास कार्यक्रम में भाग लिया।

इसके प्रबंध दल में डा. के जी विरमानी कार्यक्रम निदेशक थे तथा श्रीमती नलिनी जुनेजा कार्यक्रम सहयोगी।

8. वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन विषय पर अभिविन्यास कार्यक्रम, फरवरी 21, 28, 1985)

उपर्युक्त छठे तथा आठवें दोनों ही कार्यक्रम इस शृंखला के दसवें तथा ग्यारहवें कार्यक्रम थे। यह कार्यक्रम संस्थान द्वारा वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों के लिए आयोजित किए गए थे। इन कार्यक्रमों के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे : शैक्षिक योजना और प्रशासन की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं और तकनीकों से भागीदारों को परिचित कराना, स्कूल शिक्षा के प्रमुख मुद्दों तथा समस्याओं से भागीदारों को परिचित कराना तथा शैक्षिक प्रशासक तथा पर्यवेक्षक के रूप में व्यावसायिक क्षमता और दक्षता प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना। इन दोनों कार्यक्रमों में से पहले कार्यक्रम में दस वरिष्ठ प्रशासकों ने भाग लिया था तथा दूसरे कार्यक्रम में आठ वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों ने भाग लिया था।

इसके प्रबंध दल में निम्नांकित लोग थे : श्री मनमोहन कपूर कार्यक्रम निदेशक, श्री ए वी कालपांडेय, डा. रामस्वरूप शर्मा कार्यक्रम संयोजक, श्री अरुण मेहता कार्यक्रम सहायक।

9. पांडिचेरी के माध्यमिक स्कूलों के लिए संस्थागत योजना पर कार्यशिविर (फरवरी 25 से मार्च 2, 1985)

पांडिचेरी में माध्यमिक स्कूल के प्रधानों के लिए संस्थागत योजना विषय पर संस्थान ने छः दिनों का एक कार्यशिविर आयोजित किया। इस कार्यक्रम के उद्देश्य थे : उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संस्थागत योजना की अवधारणा तथा व्यवहार के प्रति भागीदारों को सजग बनाना जिसमें गुणात्मक सुधार पर विशेष आग्रह हो,

उनको अपने अपने स्कूलों के लिए कार्य योजना बनाने की क्षमता प्रदान करना ताकि उसे अपने अपने स्कूलों में क्रियान्वित कर सकें। छब्बीस विद्यालय प्रमुखों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

इस कार्यक्रम के निदेशक श्री टी के डी नायर थे तथा उन्होंने ही इसकी व्यवस्था भी की थी। श्री शब्बीर अहमद इस कार्यक्रम के संयोजक थे।

10. विज्ञान के कार्यक्रमों की योजना और प्रबंध विषय पर कॉलेजों के विज्ञान संकाय के अध्यक्षों का अभिविन्यास कार्यक्रम (अगस्त 14, 1984)

राष्ट्रीय शैक्षिक याजना और प्रशासन संस्थान ने कॉलेजों के विज्ञान विभाग के प्रधानों का एक दिन का अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे : विज्ञान के क्षेत्र में नए विकास तथा उसकी क्षमता से, विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में, कॉलेज के अध्यापकों को परिचित कराना, विज्ञान की योजना और प्रबंध में कालेज अध्यापक को अभिविन्यास करना जिससे विज्ञानाभिमुख पाठ्येतर गतिविधियों को आरंभ किया जा सके। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसी संभावनाएं तलाशी गईं जो नई मूल्यांकन पद्धति का विकास थी जिससे परियोजना तथा विस्तार कार्य को भी ध्यान में रखा जा सके, नए विज्ञान शिक्षण में अध्यापकों का अभिविन्यास तथा अध्यापकों के मूल्यांकन में अभिविन्यास जिससे नई पद्धति के विकास की (शिक्षण की) ध्यान में रखा जा सके तथा अभिविन्यास को भी। इसमें सात लोगों ने भाग लिया।

इस कार्यक्रम का प्रबंध डा. शक्ति रईस अहमद ने किया जो इस कार्यक्रम की निदेशिका भी थीं। डा. जी डी शर्मा इस कार्यक्रम के संयोजक थे तथा श्री एम एम रहमान कार्यक्रम सहायक।

11. कॉलेज प्राचार्यों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में अभिविन्यास कार्यक्रम (सितंबर 4-24 1984)

कालेजों के प्राचार्यों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर तीन सप्ताह के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में तीन कार्यक्रमों की एक शृंखला का आयोजन किया (देखें, कार्यक्रम संख्या 13 व 15)। प्रथम कार्यक्रम एक सामान्य कार्यक्रम था तथा इसमें पैंतीस लोगों ने भाग लिया। दूसरा कार्यक्रम खासतौर पर महिला प्राचार्यों के लिए आयोजित किया गया था। इसमें बीस कालेजों के प्राचार्यों की भागीदारी थी। तीसरा कार्यक्रम विशेष प्रकार का था और उन प्राचार्यों के कालेजों के लिए आयोजित किया गया था जिन कालेजों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों का संकेंद्रण है। इसमें अट्ठाईस कालेजों के प्राचार्यों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे : राष्ट्रीय विकास में उच्च शिक्षा की भूमिका के विषय में प्राचार्यों से विचार-विमर्श करना, इसके अतिरिक्त इस प्रकार के मुद्दे जैसे संख्या, गुणवत्ता तथा समानता, कालेजों और समुदाय का संबंध, उच्च शिक्षा का भावी परिप्रेक्ष्य आदि। उनको योजना, प्रबंध की आधुनिक तकनीकों, पद्धतियों, स्तर में सुधार, कालेज तथा समाज के मध्य क्रिया प्रतिक्रिया और मूल्यांकन आदि से परिचित करना।

इन कार्यक्रमों की प्रबंध व्यवस्था डा. जी डी शर्मा ने की थी जो इस कार्यक्रम के निदेशक भी थे।

डा. श्रीमती शक्ति रईस अहमद कार्यक्रम संयोजिका थी। श्री एम एम रहमान, सुश्री मंजु नरूला ने कार्यक्रम सहायक के रूप में कार्य किया।

12. कालेजों में शिक्षण पद्धतियां विषय पर राष्ट्रीय कार्यशिविर (यूनेस्को तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित, अक्तूबर 8 से 18, 1984)

यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकाक तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दिल्ली के अनुरोध पर कालेजों में शिक्षण पद्धतियां विषय पर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान ने एक राष्ट्रीय कार्यशिविर आयोजित किया गया। मोटे तौर पर इस कार्यशिविर के उद्देश्य इस प्रकार थे : कालेज प्राध्यापकों द्वारा चलाये जाने वाले वर्तमान कार्यक्रमों तथा व्यवहारों की समीक्षा करना, शिक्षण पद्धतियों के विषय में प्रशिक्षण माड्यूल बनाना जो बाद में अध्यापकों की क्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए आयोजित कार्यशिविरों में इस्तेमाल की जा सकें। देश के विभिन्न भागों से ओर विभिन्न विषयों से संबद्ध उन्नतीस लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

इस कार्यक्रम का प्रबंध डा. जी डी शर्मा ने किया जो इस कार्यक्रम के निदेशक भी थे। डा. शक्ति रईस अहमद इस कार्यक्रम की संयोजिका थी तथा श्री एम एम रहमान तथा सुश्री मंजु नरूला ने इस कार्यक्रम में सहायकों की भूमिका निभाई।

13. कॉलेज प्राचार्यों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में अभिविन्यास कार्यक्रम :
(दिसंबर 31, 1984, से जनवरी 20, 1985, इसका विस्तृत विवरण कार्यक्रम सं. 11 में देखें)

14. कश्मीर विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्षों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन विषय पर अभिविन्यास कार्यक्रम (फरवरी 4 से 22, 1985)

शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में कश्मीर विश्वविद्यालय के विज्ञान विभागों के अध्यक्षों के लिए संस्थान ने एक अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार थे : विभागों के प्रबंध के आधुनिकतम विकास से लोगों को परिचित कराना, विभागों की योजना और प्रबंध की आधुनिक तकनीकों से परिचित कराना, तथा कुछ अन्य विश्वविद्यालयों तथा व्यावसायिक कालेजों के अध्यक्षों से संपर्क का अवसर प्रदान करना, साथ ही अनुसंधान के लिए कोष की व्यवस्था करने वाली एजेंसियों के प्रधानों के साथ विचारविमर्श का अवसर प्रदान करना जैसे विश्वविद्यालय अनुसंधान परिषद तथा डी एस टी आदि। कश्मीर विश्वविद्यालय के नौ विज्ञान विभागों के अध्यक्षों ने भाग लिया।

इस कार्यक्रम का प्रबंध डा. जी डी शर्मा ने किया था जो इस कार्यक्रम के निदेशक भी थे। डा. शक्ति रईस अहमद इस कार्यक्रम की संयोजिका थी तथा श्री एम एम रहमान कार्यक्रम सहायक थे।

15. कालेज प्राचार्यों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में अभिविन्यास कार्यक्रम, (फरवरी 4-24, 1985, विस्तृत विवरण के लिए कार्यक्रम संख्या 11 देखें ।

16. कालेजों के विज्ञान विभाग के अध्यक्षों के लिए विज्ञान शिक्षण की योजना और प्रबंध विषय पर अभिविन्यास कार्यक्रम (मार्च 11-16, 1985)

विभिन्न राज्यों के कालेजों के विज्ञान विभाग के अध्यक्षों के लिए विज्ञान शिक्षा की योजना तथा प्रबंध विषय पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान ने राष्ट्रीय स्तर का एक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया । इस कार्यक्रम के उद्देश्य मौटे तौर पर निम्नलिखित थे : कालेज के अध्यापकों को विज्ञान के क्षेत्र में हुए विकास और उसकी शक्तियों से परिचित करना, विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में जिसमे विज्ञान के कार्यक्रमों को पुनर्गठित करने की संभावनाओं को तलाशा जा सके ताकि समुदाय की विकास आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें ढाला जा सके, विज्ञान शिक्षण की नई पद्धतियों, उसकी योजना तथा प्रबंध में अभिविन्यस्त किया जा सके, लागत प्रभावी प्रयोगशाला के व्यवहारों से उनको परिचित कराना, प्रयोगशालाओं में सुरक्षा के उपायों से उन्हें परिचित कराना । विभिन्न राज्यों के कालेजों के इकतीस विज्ञान विभागाध्यक्षों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया ।

इस कार्यक्रम का प्रबंध संचालन डा. शक्ति रईस अहमद ने किया जो इस कार्यक्रम की निदेशिका भी थी । डा. जी डी शर्मा इस कार्यक्रम के संयोजक थे और सुश्री कौशल विजारत ने इस कार्यक्रम में सूचना लेखन का काम किया ।

17. महिला पोलिटेकनीकों के लिए सर्वेक्षण साधन विनियोग पर कार्यशिविर (अप्रैल 18-19, 1984)

यह कार्यक्रम जम्मू तथा कश्मीर सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था । इस कार्यशिविर में महिला पोलिटेकनीक श्रीनगर तथा संकायों से 16 लोगों ने भाग लिया । इसका प्रमुख उद्देश्य सर्वेक्षण साधन विनियोग के विकास का विश्लेषण करना था ।

इस कार्यक्रम की व्यवस्था डा. मरमर मुखोपाध्याय ने की थी । वे ही इस कार्यक्रम के निदेशक भी थे । सुश्री नलिनी जुनेजा इस कार्यक्रम में कार्यक्रम सहायिका थीं ।

18. केंद्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक प्रबंध में अभिविन्यास कार्यक्रम (मई 21, जून 1, 1984)

केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली के अनुरोध पर केंद्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षा अधिकारियों के लिए संस्थान ने एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया । इस कार्यक्रम के उद्देश्य थे : शैक्षिक प्रबंध की प्रमुख अवधारणाओं से भागीदारों को अवगत कराना, अपनी भूमिका की ठीक ढंग से संकल्पना करना, सुधरे हुए स्कूल निरीक्षण के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के एक शिक्षा अधिकारी को प्रभावशाली नेतृत्व के लिए उपयुक्त ज्ञान प्रदान करना जिससे वह अपनी योजनो बना सके । इस कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय संगठन के 25 शिक्षा अधिकारियों ने भाग लिया ।

इस कार्यक्रम के प्रबंध दल में जो लोग शामिल थे उनके नाम इस प्रकार हैं : डा .के जी विरमानी, कार्यक्रम निदेशक, श्री शब्बीर अहमद, कार्यक्रम संयोजक तथा श्रीमती प्रमिला यादव, कार्यक्रम सहायिका ।

19. विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रति नवाचारी दृष्टिकोण (मई 28—जून 5,1984)

यह कार्यशिविर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित किया गया था। विश्वविद्यालय प्रशासन की बढ़ती हुई जटिलताओं और उसकी चुनौतियों का विचार कर, प्रासंगिक नवाचारी प्रशासन के प्रकाश में कुछ प्रमुख समस्याओं की छानबीन करना आवश्यक हो गया था। इस कार्यशिविर के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे : अपनी अपनी कार्य स्थितियों में समस्याओं को जानने की भागीदारों को क्षमता प्रदान करना, तथा फार्मों डिजाइनों और नियंत्रण तथा उन पद्धतियों से भागीदारों को परिचित करना जो नवाचारी प्रयोगों से पैदा होती है। कार्यक्रम के दौरान कार्यालय प्रबंध के विशेष संदर्भ में तथा संगणक के इस्तेमाल, फार्मों के डिजाइन तथा नियंत्रण के विशेष संदर्भ में नवाचारी प्रयोगों के लिए प्रयास किए गए। विश्वविद्यालयों के चौदह कुल-सचिवों ने इस कार्यशिविर में भाग लिया।

इसके प्रबंध दल में निम्नांकित लोग थे : डॉ. मरमर मुखोपाध्याय इस कार्यक्रम के निदेशक थे और श्री सी आर के मूर्ती इस कार्यक्रम के सहयोगी।

20. केंद्रीय विद्यालय संगठन के सहायक आयुक्तों के लिए शैक्षिक प्रबंध विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (दिसंबर 3—14,1984)

केंद्रीय विद्यालय संगठन के अनुरोध पर केंद्रीय विद्यालय संगठन के सहायक आयुक्तों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान ने शैक्षिक योजना और प्रबंध विषय पर दो सप्ताह का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम की योजता निम्नांकित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी : शिक्षा में प्रबंध की मुख्य धारणाओं से भागीदारों को परिचित कराना; कम लागत के नवाचारों से नमूना पेश करने वाले शैक्षिक संगठनों के प्रबंध के लिए उनमें उच्चकोटि की व्यावसायिकता विकसित करना, तथा संगठन में उच्चकोटि की कार्यशैली की क्रियान्वित करने की संकल्पना की योग्यता प्रदान करना। केंद्रीय विद्यालय संगठन के 24 आयुक्तों ने इसमें भाग लिया।

इस कार्यक्रम की प्रबंध व्यवस्था दल में डॉ. के जी विरमानी इस कार्यक्रम के निदेशक थे तथा इस कार्य में उनकी सहायिका थीं श्रीमती नलिनी जुनेजा।

21. नेतृत्व तथा निर्णय करने पर कार्यशिविर (फरवरी 25—28, 1985)

शैक्षिक प्रशासकों के लिए संस्थान ने नेतृत्व और निर्णय पर एक कार्यशिविर आयोजित किया। इस कार्य-शिविर आयोजन का प्रयोजन दक्षता का विकास और नेतृत्व की क्षमता का विकास करना था। इस कार्य-शिविर के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे : शैक्षिक संस्थान में स्थिति के विश्लेषण की दक्षता विकसित करना, शैक्षिक परिवेश में नेतृत्व की प्रतिभा के विकास के लिए 'स्व' की समझ का विकास करना; शैक्षिक संस्थानों में निर्णय क्षमता के लिए मामले बनाने का कार्य करना। इस कार्यशिविर में 22 लोगों ने भाग लिया।

इस कार्यक्रम का प्रबंध इसके निदेशक श्री एन एम भागिया ने किया तथा सुश्री नलिनी जुनेजा ने इस कार्य में उनकी सहायिका के रूप में कार्य किया।

22 महिला पोलिटेकनीक शिक्षिकाओं और प्रशासकों के लिए माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण तथा तकनीकी शिक्षा में अभिविन्यास कार्यक्रम (अप्रैल 9—11,1984)

श्रीनगर में महिलाओं का पोलिटेकनीक खोलने के उद्देश्य से जम्मू तथा कश्मीर सरकार के अनुरोध पर जम्मू तथा कश्मीर के अनुभवी माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों के लिए संस्थान ने एक अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण तथा तकनीकी शिक्षा के व्यापक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर इस कार्यक्रम का प्रारूप बनाया गया था। कार्यक्रम में निम्नलिखित निर्देश दिए गए थे: राष्ट्रीय विकास के आर्थिक प्रारूप में परिचय कराना; महिला पोलिटेकनीक के विशेष प्रसंग में भारत की तकनीकी शिक्षा से उन्हें परिचित कराना; तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पोलिटेकनीक संस्थाओं की भूमिका। इस कार्यक्रम में सत्रह लोगों ने भाग लिया।

इस कार्यक्रम के निदेशक डॉ. मरमर मुखोपाध्याय ने इसका प्रबंध सम्हाला। डॉ. सुश्री के सुधाराव ने इसमें संयोजक की भूमिका निभाई तथा सुश्री मीना श्रीवास्तव ने कार्यक्रम सहयोगी के रूप में कार्य किया।

23. इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रबंध पर संगोष्ठी (अगस्त 13—18,1984)

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान ने आई एस टी ई के अनुरोध पर इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रबंध विषय पर पांच दिनों कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे: समस्याओं को जानने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों का पद्धति विश्लेषण करना जिससे संगठन के निदान में विविध दृष्टिकोणों उपकरणों से भागीदारों को परिचित कराया जा सके, विद्यार्थी तथा संस्था के प्रबंध संबंधी विभिन्न मुद्दों और दृष्टिकोणों से उनको परिचित कराना, संस्थान के विकास की कार्य योजना बनाना। कार्यक्रम के दौरान सिद्धांत और व्यवहार के बीच संतुलन खोजने के प्रयास किए गए। उपकरण, पद्धति तथा तकनीक चुनने में प्रशिक्षण माड्यूल को अंतर्वस्तु के हिसाब से बनाया गया। इसमे भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के विशेष उद्देश्यों को तथा प्रशिक्षण के सामान्य उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया। इस पाठ्यक्रम में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया वह इस प्रकार थी: व्याख्यान तथा विचारविमर्श का समवेत रूप अपनाया गया। इसके अलावा समूह गतिविधियाँ, केस विश्लेषण, भागीदारों की संगोष्ठी तथा कार्य योजना। इस कार्यक्रम में चौदह प्राचार्यों ने भाग लिया।

इस कार्यक्रम की व्यवस्था डॉ. मरमर मुखोपाध्याय ने की जो इस कार्यक्रम के निदेशक भी थे। सुश्री के सुधाराव ने इस कार्यक्रम का संयोजन किया तथा श्री सी आर के मूर्ती इस कार्यक्रम के सहायक थे।

24. +2 स्तर पर शिक्षा के व्यवसायीकरण की योजना और प्रबंध में अभिविन्यास कार्यक्रम (जनवरी 28—फरवरी 1, 1985)

सातवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के व्यवसायीकरण को उच्च प्राथमिकता दिए जाने को विशेष रूप से ध्यान में रखकर इस संस्थान ने यह कार्यक्रम आयोजित किया था। विभिन्न राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों तथा कनिष्ठ स्तर के कॉलेजों के प्राचार्यों के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम को चलाने के निम्नांकित उद्देश्य थे: 2 स्तर पर व्यवसायीकरण के

आधारभूत नियोजन तथा प्रबंध की अवधारणा से भागीदारों को परिचित करना, शिक्षा के व्यवसायीकरण की योजना और प्रबंध के नवाचारी व्यवहारों से भागीदारों को परिचित कराना, निचले स्तर पर भागीदारों की क्रियान्वयन क्षमता को बढ़ाना, तथा योजना को यथार्थ रूप प्रदान के लिए कार्य योजनाएं तैयार करना। स्कूलों और कॉलेजों के 45 प्राचार्य (इसमें तकनीकी हाई स्कूल भी शामिल हैं) तथा एक संयुक्त निदेशक ने इसमें भाग लिया।

इस कार्यक्रम का प्रबंध डॉ. मरमर मुखोपाध्याय ने किया, जो इस कार्यक्रम के निदेशक भी थे। डॉ. सुश्री के सुधाराव ने इसका संयोजन किया तथा सी आर के मूर्ति इसके सहायक थे।

25. अनौपचारिक शिक्षा के लिए वैकल्पिक प्रशासनिक माडल पर राष्ट्रीय कार्यशिविर (अप्रैल 9—13,1984)

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के अनुरोध पर संस्थान ने इस कार्यशिविर का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे : अनौपचारिक शिक्षा के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रशासन की मौजूद व्यवस्था से भागीदारों को परिचित कराना तथा उन समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराना जिनका सामना कार्यकर्ताओं को करना पड़ता है तथा प्रस्तावित प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत अनौपचारिक शिक्षा के लिए प्रशासनिक मानदंड बनाने के लिए सुझाव देना। इसमें आगत तथा निर्गत दोनों ही था जिसमें विशेष बल निर्गत पर दिया गया था जिसमें अनौपचारिक शिक्षा के प्रशासनिक माडल के विकास पर समूह कार्य भी शामिल था।

इसके प्रबंध दल में डॉ. सी एल सपरा कार्यक्रम निदेशक थे, श्री शब्बीर अहमद कार्यक्रम संयोजक तथा सुश्री रश्मि दीवान कार्यक्रम सहायिका।

26. बड़े स्तर के अधिकारियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा के प्रशिक्षण कार्यों की योजना तथा प्रबंध पर राष्ट्रीय कार्यशिविर (अगस्त 6—10,1984)

प्रशिक्षण कार्य में संलग्न उच्च स्तर के अधिकारियों के प्रौढ़ शिक्षा में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना तथा प्रबंध विषय पर प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के सहयोग से नीपा ने एक पांच दिन का राष्ट्रीय कार्यशिविर आयोजित किया। इसमें साक्षरता के बाद का अनुवर्ती कार्यक्रम का प्रबंध भी शामिल था। इस कार्यशिविर के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे : प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के नए बलाबल के विषय में एक समझ विकसित करना, साथ ही इसकी कार्यान्वयन संबंधी रणनीतियों को समझना, प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों के लिए आवश्यक ज्ञान, दक्षता तथा भूमिका के विषय में विचारविमर्श करना। इस कार्य में प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित 37 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

इस कार्यक्रम का प्रबंध इसके निदेशक श्री सी एल सपरा ने किया और संयोजन श्रीमती सुषमा भागिया ने। इसमें कार्यक्रम सहयोगी थी श्रीमती जुबेदा हबीब।

27. अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के मूल्यांकन अध्ययन विषय पर तकनीकी कार्यशिविर (मार्च 18—20,1985)

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अनुरोध पर संस्थान ने अनौपचारिक शिक्षा के व्यापक मूल्यांकन अध्ययन का काम हाथ में लिया जिसे 1979 में केंद्र की मदद से शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नौ राज्यों में शुरू किया गया। इसका मकसद था 9-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को, जो स्कूल में दाखिला नहीं ले सके हैं, शिक्षा की परिधि में समेटना। इस कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार थे : सफलता तथा असफलता के क्षेत्रों को समझने के लिए इसकी सामर्थ्य तथा उद्देश्यों का तुलनात्मक मूल्यांकन करना और वांच्छित उद्देश्यों को बनाए रखने तथा कार्यक्रम की रूप रेखा के ढांचे में सुधार के लिए नई दृष्टि सुझाना। शिक्षा जगत के लगभग चौदह विशेषज्ञ इस कार्यशिविर में शामिल हुए।

इस कार्यक्रम की प्रबंध व्यवस्था श्री मनमोहन कपूर ने की जो इस कार्यक्रम के निदेशक थे। श्री बी ए कालपांडेय इसके संयोजक तथा श्री अरूण मेहता की भूमिका सहायक की थी।

28. स्कूल आफ प्लानिंग, अहमदाबाद पर्यावरण योजना और प्रौद्योगिकी केंद्र के लिए ग्रीष्मकालीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम (मई 7—जुलाई 7,1984)

स्कूल आफ प्लानिंग, अहमदाबाद के अनुरोध पर यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया गया। इस पाठ्यक्रस के चलाने का उद्देश्य उनके स्नातकोतर डिप्लोमा पाठ्यक्रम को आंशिक रूप से पूरा करना भी था। स्कूल आफ प्लानिंग के दो स्नातकोतर छात्रों में इस पाठ्यक्रम में भाग लिया। इस पाठ्यक्रम के उद्देश्य थे : विभिन्न स्तरों पर तथा क्षेत्र स्तरीय व्याख्याओं में संबंधित बातों में प्रशिक्षार्थियों को अभिविन्यस्त करना; शैक्षिक अनुसंधान परियोजनाओं का प्रतिरूप तैयार करना, आंकडों का विश्लेषण करना तथा उनकी व्याख्या करना आदि तथा अपनी रुचि की संस्थाओं तक पहुंचने के लिए उनको सक्षम बनाना और उनकी इच्छा वाले संस्थानों में उनके रोजगार के अवसरों का पता लगाना।

इन प्रशिक्षार्थियों की डॉ. ब्रह्म प्रकाश तथा डॉ. जे बी जी तिलक के साथ संबद्ध किया गया था।

29. शिक्षा की पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (जून 4—15,1984)

शिक्षा की योजना (सातवीं पंचवर्षीय योजना) की कार्यक्रम की श्रृंखला में यह तीसरा कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम का मुख्य जोर शैक्षिक योजना की प्रणाली तथा तकनीक पर था। इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे : सातवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के विभिन्न मुद्दों का परीक्षण करना; विभिन्न राज्यों में शैक्षिक योजना की विभिन्न प्रथाओं की वर्तमान अवस्था का पुनरीक्षण करना, प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण तकनीकों की उपयुक्तता की समीक्षात्मक परख करना, तथा भविष्य में योजना निर्माण के लिए राज्य स्तर के सार्थक आंकड़ों का आधार तैयार करने में उनकी मदद करना, इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता यह थी। इसमें इस्तेमाल किए सभी आंकड़े वास्तविक स्थितियों से उठाए गए थे यानी महाराष्ट्री राज्य से लिए गए थे। इस कार्यक्रम में सोलह लोगों ने भाग लिया।

इसके प्रबंध दल में डॉ. ब्रह्म प्रकाश निदेशक के रूप में थे तथा डॉ. एन वी वर्गीस कार्यक्रम संयोजक थे।

30. परियोजना तथा पूर्वानुमान तकनीकों पर कार्यशिविर (मार्च-18-22, 1985)

संस्थान ने परियोजना तथा पूर्वानुमान तकनीकों पर एक-एक कार्यशिविर आयोजित किया। इस कार्यक्रम की रूपरेखा अधिकारियों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई जिसमें परियोजना के लिए अभ्यास के पर्याप्त अवसर दिए गए थे। इस कार्यशिविर के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे : प्रमुख शैक्षिक चरों की योजना तथा पूर्वानुमान के परीक्षण, मूल्यांकन को हाथ में लेने के लिए शिक्षा अधिकारियों में विशेषज्ञता पैदा करना; शिक्षा का एक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य विकसित करना, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रमुख शैक्षिक चरों की प्रवृत्तियों की पहचानने में मदद करना। इसमें 15 लोगों ने भाग लिया।

इस कार्यशिविर का प्रबंध इसके निदेशक डॉ. ब्रह्मप्रकाश ने किया। श्री वाई पी अग्रवाल इस कार्यक्रम के संयोजक थे। डॉ. एन वी वर्गीस तथा श्री ए. अंसारी का इसमें महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त था।

31. राज्य सरकारों के अधिकारियों के लिए वित्त प्रबंध में अभिविन्यास कार्यक्रम (अगस्त 20-31 1984)

संस्थान ने विभिन्न राज्य सरकारों के वित्त अधिकारियों का बारह दिन का एक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया जिससे वित्तीय प्रबंध की वर्तमान व्यवस्था की उनमें बेहतर समझ विकसित की जा सके तथा विभिन्न राज्यों के वित्त अधिकारी आपस में अनुभवों का आदान-प्रदान कर सकें और अपने-अपने राज्यों के वित्त प्रबंध में सुधार कर सकें। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे : आर्थिक विकास तथा शैक्षिक गतिविधियों के आर्थिक पहलू की भूमिका को समझने की भागीदारों में क्षमता प्रदान करना; संबंध अधिकारियों की उनकी नई भूमिका को समझने और पहचानने में उनकी मदद करना तथा नीति निर्माण और कार्यान्वयन में उनकी भूमिका का मूल्यांकन करना; सामान्य रूप से आधुनिक प्रबंध की तकनीकों के प्रति सजगता को बढ़ावा देना तथा एकांउटिंग, बजटिंग आदि को दृष्टि में रखकर आधुनिक तकनीक की विशेष रूप से समझ विकसित करना। इस कार्यक्रम में आठ वित्त अधिकारियों ने भाग लिया।

इसकी प्रबंध समिति में निम्नांकित लोग शामिल थे : डॉ. सी वी पद्मनामन, कार्यक्रम निदेशक, डॉ. जे बी जी तिलक कार्यक्रम संयोजक तथा सुश्री वाई जोसेफिन, कार्यक्रम सहायक।

32. विश्वविद्यालय के वित्त प्रबंध पर अभिविन्यास कार्यक्रम (फरवरी 4-9, 1984)

भारतीय विश्वविद्यालयों के वित्त अधिकारियों के लिए संस्थान ने वित्त प्रबंध पर एक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे : भारत में उच्च शिक्षा के विकास में विश्वविद्यालयों में वित्तीय प्रशासन के महत्व को समझने में भागीदारों की सक्षम बनाना, खास तौर पर प्रबंध तकनीक के प्रति सजगता को बढ़ावा देना, तथा सामान्य तथा आधुनिक वित्तीय प्रबंध के प्रति सजगता लाना। विभिन्न राज्यों से 32 लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

इस कार्यक्रम की प्रबंध व्यवस्था डॉ. सी बी पद्मनामन ने सम्हाली थी और वे ही इसके निदेशक भी थे : डॉ. जे बी श्री तिलक कार्यक्रम संयोजक थे और सुश्री वाई जोसेफिन कार्यक्रम सहायक।

33. आश्रम स्कूलों के प्रशासन पर अभिविन्यास कार्यक्रम (सितंबर 24-28, 1984)

मध्यवर्तीय जनजातीय क्षेत्र के आश्रम स्कूलों का संस्थान ने एक गहन अध्ययन कार्यक्रम चला ा। जहां तक विद्यालयों की कार्यविधि में जनजातीय पक्ष पर कुछ दिलचस्प रोशनी पड़ती है : इसके अतिरिक्त इन बातों की भी जानकारी मिली है जैसे, आश्रम स्कूलों के छात्रों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, इन स्कूलों की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, सामान्य स्कूलों की तुलना में इन स्कूलों की लागत प्रभाविता; इस कार्यक्रम को आयोजित करने के उद्देश्य इस प्रकार थे : अध्ययन के निष्कर्षों का प्रचार-प्रसार करना, स्कूलों के विशेष स्वरूप को ध्यान में रखकर शैक्षिक योजना और प्रबंध की कुछ नई तकनीकों भागीदारों को परिचित कराना। इस कार्यक्रम में कुल 25 लोगों ने भाग लिया।

डॉ. श्रीमती कुसुम प्रेमी इस कार्यक्रम की निदेशका तथा प्रबंधकर्ती थी। डॉ. के सुजाता, श्री ए मैथ्यू इसके संयोजक थे तथा श्री एस एम आई ए जैदी इसमें सहायक के रूप में कार्यरत थे।

34. शिक्षा में निष्पक्षता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (सितंबर 24-28, 1984)

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान ने शैक्षिक विकास के विभिन्न आयामों की खोज का काम हाथ में लिया है, इसमें पक्षपात के विविध पहलू और शैक्षिक लाभों का वितरण भी शामिल है। इस कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में 'शिक्षा में निष्पक्षता के सूचक' विषय पर पांच दिनों का कार्यशिविर आयोजित किया गया। शिक्षा में निष्पक्षता के विभिन्न मुद्दों से संबंधित समस्याओं को स्पष्ट करने में इस कार्यशिविर के व्याख्यानों से काफी हद तक मदद मिली। योजना की प्रक्रिया में इस कार्यशिविर के निष्कर्षों की इस्तेमाल करना इसका प्रथम चरण था। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे : शिक्षा में निष्पक्षता के प्रति भागीदारों की संवेदनशील बनाना, वंचितों के शैक्षिक विकास के लिए किए गए प्रावधानों के वस्तुगत मूल्यांकन में भागीदारों की मदद करना, कमजोर वर्ग में शिक्षा के विकास के लिए रणनीतियों से उन्हें लैस करना तथा पक्षपात की माप को मापने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरणों तथा पद्धतियों से भागीदारों को परिचित कराना। इसमें तीस लोगों ने भाग लिया।

इस कार्यक्रम की व्यवस्था इसकी निदेशिका डॉ. श्रीमती कुसुम प्रेमी ने की थी। डॉ. के सुजाता, डॉ. शीलचंद नुना, और श्री ए मैथ्यू कार्यक्रम संयोजक थे और श्री एस एम आई ए जैदी इस कार्यक्रम में सहयोगी थे।

35. प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की योजना और प्रबंध पर प्रशिक्षण कार्य शिविर (अक्तूबर 25-19 1984)

सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण को दी गई उच्च प्राथमिकता को ध्यान में

रखकर संस्थान ने एक प्रशिक्षण कार्यशिविर आयोजित किया। यह संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दिए गए उद्देश्यों की पूरा करने की दिशा में एक कदम था। यह कार्यक्रम राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के एस सी ई आर टी/एस आई ई एस, शिक्षा निदेशकों के लिए आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार थे : व्यष्टि स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की योंजना और प्रबंध की पद्धति और तकनीक से भागीदारों को परिचित कराना; प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की समस्याओं को हल करने के लिए व्यष्टिस्तरीय योजना तथा प्रबंध तकनीक को कार्यरूप देने में दक्षता हासिल करना; प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण कार्यक्रमों के प्रबंध तथा योजना में नवाचारी व्यवहारों से परिचित कराना, खास तौर पर समुदाय की भागीदारी, प्रासंगिक पाठ्यक्रम, शाला संगम, निचले स्तर के शिक्षा कर्मियों के लिए प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के योजना संदर्भ में संचारेक्षण आदि। इस कार्यक्रम में 18 लोगों ने भाग लिया।

इस कार्यशिविर की प्रबंध व्यवस्था इस कार्यक्रम के निदेशक डॉ. सी एल सपरा ने की। श्री शब्बीर अहमद इस कार्यक्रम के संयोजक थे। श्रीमती रश्मि दीवान तथा श्री बी के पाण्डा इसमें कार्यक्रम सहयोगी थे।

36. प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में समुदाय की भागीदारी पर कार्यक्रम (दिसंबर 3-14, 1984)

एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के यूनेस्को शिक्षा कार्यालय बैंकाक के विशेष अनुरोध पर इस कार्यशिविर का आयोजन किया गया था। यह ढाका में आयोजित प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की योजना तथा प्रबंध पर होने वाले क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशिविर का अनुवर्ती कार्यक्रम था। निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर यह कार्यशिविर चलाया गया था। प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम तथा प्रारंभिक शिक्षा सार्वजनीकरण के विशेष संदर्भ में शैक्षिक विकास की योजना प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी की अवधारणा तथा आवश्यकता से भागीदारों को परिचित कराना, संपर्क तथा समन्वय के प्रति सजगता पैदा करना, सामुदायिक भागीदारी के उपागमों और तकनीकों से भागीदारों को परिचित कराना (प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के प्रबंध तथा उसकी योजना के विषय में तथा प्रौढ़ साक्षरता और यू ए ई के बीच समन्वय कार्यक्रम के विषय में भी) इस कार्यक्रम में इक्कीस व्यक्तियों ने भाग लिया।

इस कार्यक्रम के निदेशक डॉ. सी एल सपरा, ने इसकी प्रबंध व्यवस्था सम्हाली। श्री टी के डी नायर इस कार्यक्रम के संयोजक थे तथा सुश्री रश्मि दिवान और बी के पांडा इसके सहयोगी थें।

37. गुड़गांव के मेवात क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण परियोजना में काम करने वाले क्षेत्र कार्यकर्त्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (जुलाई 31, अगस्त 3, 1984)

एकदम आधारिक स्तर पर अन्य विकास संस्थानों से संपर्क कायम करना तथा समुदाय का समर्थन जुटाना प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में सबसे बड़ी अड़चन जान पड़ती है। इस कार्यक्रम को इसी दृष्टि से आयोजित किया गया था कि क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की सामुदायिक भागीदारों की तकनीकों में तथा स्वयंसेवक तैयार करने में अभिविन्यस्त किया जाए। इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे : प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में गांव समुदाय को लामबंद करने की युक्तियों को समझने में भागीदारों

को मदद करना तथा सहभागितावाली तकनीकें विकसित करना; धूमरहित चूल्हा बनाने में उनकी सहायता करना, उस क्षेत्र की स्वयंसेवी संस्थाओं के मूल्यांकन में उनकी मदद करना तथा उनके कार्यक्षेत्र में सक्रिय अभिकरणों से उनका परिचय कराना। इस कार्यक्रम में सहभागिता की पद्धति का अनुसरण किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली का एक दौरा आयोजित किया गया तथा क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को ग्राम प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित किया गया। साथ ही उसी जगह तत्काल धूमरहित चूल्हा बनाने में लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

इस कार्यक्रम के निदेशक प्रो. सत्यभूषण थे जिन्होंने इस कार्यक्रम की प्रबंध व्यवस्था का भार भी सम्हाला था। डॉ. प्रमिला मेनन तथा डॉ. अब्दुल अज़ीज ने इसमें सहयोगियों की भूमिका निभाई।

38. मेवात क्षेत्र जिला गुड़गांव के आठ महिलाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम (अगस्त 30-31, 1984)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रौढ़ निरक्षरता उन्मूलन और प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली ने मेवात क्षेत्र के आठ गांवों की महिलाओं के लिए दो दिनों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे : एक ऐसा मंच प्रदान करना जहां गांव की महिलाएं तथा विकास कार्यों में लगे हुए परियोजना के लोग आपस में मिल सकें, रणनीति निर्धारित करने के लिए उस क्षेत्र की वास्तविक स्थिति को समझना और महिलाओं की भावनाओं को जानना, बातचीत के दौरान इस बात का पता लगाना कि किस बिंदु से इस स्थिति को तोड़ने की शुरूआत की जा सकती है। व्यावहारिक प्रदर्शन के जरिए उनको धूमरहित चूल्हा बनाने का प्रशिक्षण देना, तथा उनमें साक्षरता से होने वाले फायदों के प्रति चेतना जगाना।

इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक और निदेशक प्रो. सत्यभूषण थे। इस कार्य में उनके सहयोगी थे डॉ. प्रमिला मेनन तथा डॉ. अब्दुल अजीज।

39. बीस गांवों की महिलाओं को सतर्क बनाने का कार्यक्रम (मार्च 18-19, 1985)

गुड़गांव (हरियाणा) के एक गांव में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की एक कार्ययोजना बनाने के लिए संस्थाव ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। गुड़गांव जिला के पुनहाना प्रखंड के गांव की महिला कार्यकर्ताओं के लिए बीस गांवों में साक्षरता को बढ़ावा देने तथा प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था। एक खास समुदाय की विशेष आवश्यकताओं, संसाधनों तथा अवरोधों की ध्यान में रखकर वहां की स्थितियों को समझने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार थे : गांव की सांस्कृतिक सीमाओं में संभावित हल खोजने के लिए समस्याओं का पता लगाना तथा प्रारंभिक स्वास्थ्य की देखरेख तथा स्वास्थ्य विज्ञान के महत्व के बारे में महिलाओं को प्रशिक्षित करना तथा साक्षरता विकास का आधार है, इस बात के प्रति उनमें जागरूकता लाना। इस कार्यक्रम में गांव की अठारह महिलाओं ने भाग लिया।

इस कार्यक्रम के प्रबंध दल में निम्नांकित लोग शामिल थे : प्रो. सत्यभूषण, कार्यक्रम निदेशक तथा प्रबंधक, डा. प्रमिला मेनन तथा अब्दुल अज़ीज कार्यक्रम सहयोगी।

40. मध्यप्रदेश का अंतर्राज्यीय अध्ययन दौरा (फरवरी 4-9, 1985)

'पढ़ने के समय अर्जन करो' कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थान ने एक अंतर्राज्यीय अध्ययन दौरे का आयोजन किया। अध्ययन दौरे के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे : उस अलगाव की स्थिति को तोड़ना जिसमें राज्यों के शिक्षा योजनाकार प्राय: काम करते हैं, यह देखने के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना कि कोई नवाचारी विचार कैसे जन्म लेता है, पल्लवित किया जाता है तथा फलदायक बनता है, अन्य राज्यों के लिए विचारों के विनिमय, सफल प्रयोगों के संचालन तथा नवाचारों को प्रोत्साहित करना, प्रशिक्षण और अनुसंधान को एक दूसरे से जोड़ना और शैक्षिक योजना तथा प्रबंध के लिए स्थानीय सिद्धांत बनाना। इस अध्ययन दौरे में बीस विशेषज्ञों और शिक्षाशास्त्रियों ने भाग लिया।

इस कार्यक्रम की प्रबंध व्यवस्था का कार्यभार श्री मनमोहन कपूर ने सम्हाला जो इस कार्यक्रम के निदेशक भी थे। श्री वी ए कालपांडेय कार्यक्रम संयोजन थे तथा डा. श्रीमती के सुधाराव कार्यक्रम सहायिका।

41. शैक्षिक योजना और प्रशासन में उच्चतर प्रशिक्षण के अंग के रूप में एशियाई प्रशिक्षार्थियों का अध्ययन दौरा (जून 18-22, 1984)

अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, पेरिस के अनुरोध पर संस्थान ने अपने एशियाई प्रशिक्षार्थियों के लिए अध्ययन दौरे का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान द्वारा वर्ष 1983-84 के लिए आयोजित शैक्षिक योजना और प्रशासन में उन्नत प्रशिक्षण कार्य के अंग के रूप इस अध्ययन दौरे का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे : भारत में केंद्र राज्य तथा संस्था के स्तर पर शैक्षिक योजना और प्रशासन की प्रक्रिया तथा उसके ढांचे से एशिया क्षेत्र के प्रशिक्षार्थियों को परिचित कराना, भारत में विभिन्न स्तरों पर हाल में हुए शैक्षिक विकास, जिसमें शैक्षिक सुधार और नवाचार भी शामिल है से प्रशिक्षार्थियों को परिचित कराना तथा क्षेत्रीय सहयोग और शैक्षिक अनुभवों के आदान-प्रदान से क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत बनाना, सात एशियाई देशों (कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, बंगला देश, फिलिपाइन्स तथा चीन) के लोगों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

इसके प्रबंध दल का गठन इस प्रकार किया गया था : श्रीमती डा. उषा नायर, कार्यक्रम निदेशक; सुश्री अंजना मंगला गिरि, संयोजक; सुश्री जयश्री जलाली तथा सुश्री सुनीता चुघ, कार्यक्रम सहयोगी।

42. संयुक्त राज्य अमरीका के सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम परामर्शदाताओं तथा पर्यवेक्षकों के लिए भारतीय इतिहास और संस्कृति पर कार्यशिविर (जुलाई 3-अगस्त 10, 1984)

भारत के संयुक्त राज्य अमरीका के शिक्षा न्यास के अनुरोध पर उपयुक्त शिक्षा कर्मियों के लिए संस्थान में भारतीय इतिहास और संस्कृति पर पांच दिनों का एक कार्यशिविर आयोजित किया। इस कार्यशिविर के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे : भागीदारों को भारतीय इतिहास का विहंगावलोकन कराना; इसकी जनता, संस्कृति तथा कला से उनका परिचय कराना; बदलती हुई सामाजिक आर्थिक स्थितियों के साथ कृषि, उद्योग, प्रौद्योगिकी और शिक्षा में हुए विकास की उनके समक्ष झांकी प्रस्तुत करना; गुट निरपेक्ष आंदोलन

के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय समझदारी और शांति को बढ़ावा देने की दिशा में भारत की भूमिका के प्रति उनमें जागरूकता पैदा करना तथा संयुक्त राज्य अमरीका के स्कूलों के लिए भारतीय इतिहास और संस्कृति में पाठ्यक्रम विकसित करने में भागीदारों की सहायता करना। इसमें सोलह पाठ्यक्रम पर्यवेक्षकों तथा परामर्श-दाताओं ने भाग लिया।

इसके प्रबंध दल में निम्नांकित लोग शामिल थे : प्रो. मूनिस रजा इसके निदेशक थे तथा डा. श्रीमती उषा नायर कार्यक्रम संयोजिका, श्रीमती जयश्री जलाली सहायक संयोजिका और सुश्री अंजना मंगलागिरि तथा सुनिता चुघ कार्यक्रम सहायिका।

43. फिलीपाइन्स के शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के ओ पी एस के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (अगस्त 2—सितंबर 9, 1984)

फिलीपाइन्स के शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के अनुरोध पर तथा भारत सरकार के शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय की स्वीकृति से नीपा ने योजना सेवा के एक अधिकारी के लिए शैक्षिक प्रबंध मे एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे : तीसरी दुनिया के देशों की शैक्षिक समस्याओं को सहानुभूतिपूर्ण तरीके से देखने की समझदारी विकसित करना; शैक्षिकयोजना की प्रक्रियाओं, उपकरणों और तकनीकों की परीक्षा करना तथा योजना और सांख्यिकीय सर्वेक्षण में दक्षता प्राप्त करना; शैक्षिक परियोजना के विकास में दक्षता हासिल करना, फिलीपाइन्स के सामाजिक सदर्भ को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की योजना और प्रबंध के विषय में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि विकसित करना।

इस कार्यक्रम की प्रबंध व्यवस्था डा. मरमर मुखोपाध्याय ने की जो उसके निदेशक भी थे। श्री जय भगवान ने उस कार्यक्रम में उनके सहयोगी के रूप में कार्य किया।

44. शैक्षिक प्रबंध में श्रीलंका, बंगलादेश और भारत के मुख्य प्रशिक्षकों के लिए अंतर्देशीय दौरे का आयोजन (यूनेस्को प्रयोजित, सितवर 24-28, 1984)

बैंकाक स्थित यूनेस्को के एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के शैक्षिक कार्यालय के अनुरोध पर नीपा ने एशियाई देशों के प्रशिक्षकों के लिए एक अंतर्देशीय अध्ययन दौरे का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में तीन भागीदारों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे : शैक्षिक प्रबंध में प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को जानने, प्रशिक्षण की युक्तियों को बनाने, प्रशिक्षण के लिए बिषय वस्तु तथा मूल्यांकन पद्धति के विकास के विशेष संदर्भ में भागीदारों को अनुभव के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान करना।

इस कार्यक्रम का प्रबंध श्री मनमोहन कपूर ने किया जो इस कार्यक्रम के निदेशक भी थे। श्री वी ए कालपांडेय ने कार्यक्रम संयोजक का कार्य किया और श्री अरुण मेहता तथा जयभगवान कार्यक्रम सहायक थे।

45. श्रीलंका के शिक्षा कर्मियों के लिए शैक्षिक प्रबंध में डिप्लोमा पाठ्यक्रम (नवंबर 3, 1983—मई 3,1984)

श्रीलंका सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर तथा भारत सरकार के शिक्षा और संस्कृति मंत्रा-

लय के अनुरोध पर श्रीलंका के शिक्षा कर्मियों के लिए नीपा ने शैक्षिक प्रबंध विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के कुछ मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे : शैक्षिक नीति, योजना और श्रीलंका प्रशासन के विशेष संदर्भ में तीसरी दुनिया के स्कूलों के सामाजिक संदर्भ से प्रशिक्षार्थियों को परिचित कराना; विद्यालय संगठन तथा विद्यालय प्रबंध के सिद्धांत और व्यवहार से भागीदारों को परिचित कराना; स्कूलों के वित्त प्रबंध और योजना में आधारभूत दक्षता प्रदान करना, शैक्षिक प्रबंध में परामर्शदायी तकनीकें और पद्धतियां इस्तेमाल करने तथा प्रशिक्षण प्रणाली तैयार करने में भागीदारों को विशेषज्ञता प्रदान करना। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम छः महीने की अवधि का था जिसमें तीन महीने नीपा में रहकर पाठ्यक्रम पूरा करना तथा तीन महीने श्रीलंका में जाकर क्षेत्र कार्य करना शामिल था। इस कार्यक्रम में श्रीलंका के 15 भागीदारों ने भाग लिया।

इस कार्यक्रम की प्रबंध व्यवस्था श्रीमती उषा नायर ने की, जो इसकी निदेशक भी थी। श्रीमती जयश्री जलाली तथा श्रीमती सुनीता चुघ ने इस कार्यक्रम में सहायकों की भूमिका निभाई।

46. भूटान के अधिकारियों के लिए कार्यालय प्रबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम (जनवरी 1-दिसंबर 31, 1985)

यूनेस्को तथा यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के अनुरोध पर "एजुकेशन कनसल्टेंट इंडिया लि." ने नीपा को उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए चुना, यह कार्यक्रम भूटान के शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के लिए शैक्षिक प्रशासन के विशेष संदर्भ में कार्यालय प्रबंध में चलाया जाना था। इस कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार थे : भागीदार को कार्यालय प्रबंध की महत्वपूर्ण अवधारणाओं तथा तकनीकों से परिचित कराना, कार्यालय प्रबंध की प्रचलित प्रवृत्तियों की भागीदार को जानकारी देना तथा शैक्षिक प्रशासन के विशेष परिप्रेक्ष्य में कार्यालय प्रबंध के क्षेत्र में दक्षता हासिल करने में उसकी सहायता करना।

इसके प्रबंध दल में शामिल व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं : श्री मनमोहन कपूर, कार्यक्रम निदेशक, श्री वी ए कालपाण्डेय तथा डा. आर एस शर्मा कार्यक्रम संयोजक; श्री चमनसिंह, श्री ओ डी त्यागी तथा श्री डी एच श्रीकांत ने कार्यक्रम सहयोगियों का कार्य किया।

47. बंगला देश के यू पी ई परियोजना अधिकारियों का अध्ययन दौरा (जनवरी 14-21, 1985)

यूनेस्को के अनुरोध पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से संस्थान ने यह कार्यक्रम आयोजित किया था। इस दौरे के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे : भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण कार्यक्रम की प्रगति तथा समस्याओं से अधिकारियों को परिचित कराना, भारत में चलने वाली क्षेत्र स्तर की योजना तकनीकों और पद्धतियों से अधिकारियों को परिचित करना, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के संदर्भ में क्षेत्र स्तरीय स्कूल पर्यवेक्षण की विभिन्न नवाचारी पद्धतियों और तकनीकों का निरीक्षण और विश्लेषण करना। इस अध्ययन दौरे में बंगलादेश देश के आठ अधिकारियों ने भाग लिया।

इसके प्रबंध दल में शामिल लोगों के नाम इस प्रकार हैं : श्रीमती डॉ. उषा नायर, कार्यक्रम निदेशक; श्रीमती जय श्री जलाली, और सुश्री सुनीता चुघ ने इस कार्यक्रम में सहयोग दिया।

48. शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम (जनवरी 14,—जुलाई 13,1985)

तीसरी दुनिया के देशों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रशासन में केंद्रीय पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए संस्थान ने पहला डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार थे : भागीदारों में अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में तीसरी दुनिया के शैक्षिक विकास की समझ पैदा करना; विशेष राष्ट्रीय संदर्भ में लागू करने के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन के मूलभूत सिद्धांत, अवधारणाएं और तकनीकों को समझना तथा सांख्यिकीय आंकड़ों तथा अनुमानों आदि के विश्लेषण की क्षमता पैदा करना, निम्नांकित बातों से उनका परिचय कराना : योजना, प्रबंध, मूल्यांकन तथा संचारेक्षण के विभिन्न माडलों से वित्तीय प्रबंध तथा प्रगति नियंत्रण तकनीकों से; जनाधारित शिक्षा की डिजाइन पद्धतियों से परिचय कराना; प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण, तकनीकी और रोजगार परक शिक्षा आदि, विविध राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्राप्त अनुभवों के जरिए क्षेत्रीय सहयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय समझदारी की भावना को पल्लवित करना। इस कार्यक्रम में भूटान, अफगानिस्तान, कुवैत और मारिशस तथा श्रीलंका से 12 लोगों ने भाग लिया।

इस कार्यक्रम के प्रबंध दल में निम्नांकित लोग शामिल थे : डॉ. श्रीमती उषा नायर, कार्यक्रम निदेशिका; सुश्री अंजना मंगलागिरि, कार्यक्रम संयोजक; सुश्री जयश्री जलाली और सुश्री सुनीता चुघ कार्यक्रम सहयोगी।

49. अध्यापकों के प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास तथा पर्यावरण विकास के शैक्षिक योजनाकारों की परामर्शकारी बैठक (फरवरी 11-15, 1985)

यूनेस्को के अनुरोध पर संस्थान ने एक परामर्शकारी बैठक बुलाई। इस बैठक की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थीं : शैक्षिक योजनाकारों के प्रशिक्षण में पर्यावरण शिक्षा को शामिल करने की रणनीति निर्धारित करने के लिए पहली बार शैक्षिक योजनाकार, प्रशासक तथा शिक्षक प्रशिक्षक एक मंच पर एकत्र हुए। इस बैठक के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे, सेवापूर्व तथा सेवाकाली शिक्षक प्रशिक्षण में पर्यावरण शिक्षा पाठ्यक्रम के व्यापक तथा व्यावहारिक रूप से शामिल करने के लिए तरीके तलाशना, पर्यावरण शिक्षा के विकास से संबंधित अनुभवों का आदान-प्रदान करना। नौ देश के लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

इसके प्रबंध दल में निम्नांकित लोग शामिल थे। डा. श्रीमती उषा नायर, निदेशक; सुश्री अंजना मंगलागिरि, संयोजक; सुश्री जयश्री जलाली और सुश्री सुनीता चुघ, कार्यक्रम सहयोगी।

50. अफगानिस्तान के अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रबंध विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (मार्च 4—मई 4,1984)

शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक योजना तथा शैक्षिक बजट के लिए अफगानिस्तान सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने अपने शिक्षा निदेशकों की एक शैक्षिक योजना एकक स्थापित की है। इस उद्देश्य के लिए अफगान शिक्षा मंत्रालय ने छः अधिकारियों की नीपा में शैक्षिक योजना और प्रबंध में प्रशिक्षण देने के लिए चुना। इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे : शैक्षिक आंकड़ों को समझने तथा विश्लेषित करने की समझ प्रदान

करने में उनकी मदद करना, ताकि वे शैक्षिक योजना तथा पद्धतियों के व्यवहार के विषय में आधारभूत दक्षता विकसित कर सकें, स्कूलों के वित्त प्रबंध तथा संस्थागत योजना में दक्षता प्रदान करना तथा परियोजना अभ्यासों को हाथ में लेने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता विकसित करना। इस पाठ्यक्रम में अपनाई गई पद्धति का स्वरूप इस प्रकार था : व्याख्या तथा विचारविमर्श का मिश्र रूप, समूह कार्य, क्षेत्रीय अनुसंधान पर आधारित परियोजना कार्य, कार्य शिविर, व्यावहारिक अभ्यास, केस अध्ययन तथा क्षेत्र भ्रमण।

इस कार्यक्रम की प्रबंध व्यवस्था सम्हालने का दायित्व इस कार्यक्रम के निदेशक श्री ब्रह्मप्रकाश ने सम्हाला था। इसमें उनके सहयोगी थे डा. वाई पी अग्रवाल।

51. बंगला देश के अधिकारियों का अध्ययन दौरा (मार्च 8-25, 1985)

यूनेस्को के अनुरोध पर बंगला देश के शिक्षा मंत्रालय के दौरा करने वाले शिक्षा अधिकारियों के लिए संस्थान ने यह कार्यक्रम चलाया। इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार के : भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए अपनाई गई विभिन्न नवाचारी व्यवहारों तथा तकनीकी का परीक्षण तथा विश्लेषण करना; भारत में क्षेत्र स्तर की पद्धतियों और तकनीकों का अध्ययन करना; प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के संदर्भ में स्कूल स्तर के क्षेत्रीय पर्यवेक्षण पद्धति की नवाचारता का विवेचन करना। बंगला देश के आठ शिक्षा अधिकारियों ने संस्थान का दौरा किया।

इसके प्रबंध दल में श्री शब्बीर अहमद कार्यक्रम निदेशक थे। श्री टी के डी नायर कार्यक्रम संयोजक तथा श्रीमती जुबैदा हबीब कार्यक्रम सहायक थे।

52. श्रीलंका के शिक्षा निदेशकों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में अभिविन्यास कार्यक्रम (मार्च 20—मई 4, 1984)

राष्ट्रकुल तकनीकी न्यास सहयोग के अनुरोध पर श्रीलका के शिक्षा निदेशकों के लिए संस्थान ने शैक्षिक योजना और प्रशासन में एक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे : पद्धतियों और तकनीकों की जानकारी प्रदान करना; जिला स्तर पर शैक्षिक प्रबंध की समस्याओं का विकास करना, अध्यापकों की नवोदित भूमिकाएं और उनके कामों का पार्श्व चित्र, स्कूल प्रधानों तथा प्रशासकों की सेवाओं का पार्श्व चित्र तथा व्यक्तियों और संस्थाओं के मूल्यांकन की नई दृष्टियों के प्रति सजगता का विकास करना, जो संस्थाएं प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की खोज तथा बेहतर प्रोत्साहन के लिए अधिक अनुकूल हैं। इस कार्यक्रम में छः लोगों ने भाग लिया।

इस कार्यक्रम के प्रबंध दल में निम्नांकित लोग शामिल थे : डा. (श्रीमती) उषा नायर, कार्यक्रम निदेशक; सुश्री अंजना मंगलागिरि; कार्यक्रम संयोजक तथा सुश्री जयश्री जलाली और सुश्री सुनीता चुघ कार्यक्रम सहयोगी।

अनुबंध दो

अनुसंधान अध्ययन

(जिन पर कार्य चल रहा है और जिनकी स्वीकृति मिल चुकी है)

चल रहे अध्ययन

1. स्कूलों के लिए छात्रों और अध्यापकों के इष्टतम अनुपात का अध्ययन

यह अनुसंधान अध्ययन डा. आर पी सिंघल ने अपने हाथ में लिया है जिसमें विजय कुमार पांडा और सुश्री रश्मि दिवान ने परियोजना सहायक के रूप में सहयोग दिया। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :

(1) राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत छात्र-अध्ययन के प्रतिमानों का पता लगाना और यह देखना कि वास्तविक स्थितियों में इसका कितना पालन होता है; (2) शिक्षण और गैर शिक्षण अध्यापकीय गतिविधियों के संदर्भ में उनके कार्यभार का मूल्यांकन करना; (3) छात्र-अध्यापक अनुपात का नामांकन, छात्रों के स्कूल से रुकने तथा उनकी वार्षिक परीक्षा की उपलब्धियों पर पड़ने वाले प्रभाव को आंकना, (4) लागत सहित उनके समाध्यता पक्ष के ख्याल से विभिन्न परिस्थितियों में छात्र-अध्यापक इष्टतम अनुपात का निर्धारण करना है।

स्तरीयकृत यादृच्छिक निदर्श तकनीक का इस्तेमाल करके 58 राष्ट्रीय निदर्श सर्वेक्षण, प्राथमिक/मिडिल/माध्यमिक, जनजातीय/गैर जनजातीय, एक कक्षा/बहुकक्षा वाले स्कूल तथा लड़को के /लड़कियों के/सहशिक्षा वाले स्कूल हैं।

एन नियामक सर्वेक्षण पद्धति का इस्तेमाल किया गया है जिनमें प्रश्नावली अनुसंधानकर्ता तकनीकों का प्रयोग होता है। इनकी पूरक सामग्री के रूप में उपलब्ध साहित्य का सर्वेक्षण, शिक्षा कोडो, अधिनियमों नियमों तथा सरकारी आदेशों तथा और बहुत से प्रलेखन जैसे कि विद्यालय का नामांकन खाता, उपस्थिति खाता, उपस्थिति आदि का परीक्षण करके इसको पूरा किया गया।

कंप्यूटर में आंकड़ों के विश्लेषण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और जिन सारणियों को अंतिम रूप दिया गया है वे प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया में है। संबंधित साहित्य विभिन्न पुस्तकालयों से एकत्रित किया गया है और कुछ राज्यों के शिक्षा विभागों से प्राप्त हुआ है। उसकी समीक्षा के आधार पर अध्यायों को एक अस्थाई रूप-रेखा तैयार की जा चुकी है। आंकड़ों के सांख्यिकीय अध्ययन के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

2. भारत में समाजविज्ञान के अनुसंधान का वित्तीयन (आई सी एस एस आर द्वारा आयोजित)

इस अध्ययन को डा. ब्रह्मप्रकाश, वरिष्ठ अध्येता ने अपने हाथ में लिया है। इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य है, विभिन्न सरकारी/अर्ध सरकारी या निजी संस्थाओं द्वारा भारत में समाजविज्ञान अनुसंधान के लिए दी गई वित्तीय सहायता का विश्लेषण करना।

इस परियोजना के लिए आंकड़ों का आधार बनाया गया है। डा. जे एल आजाद द्वारा इस अध्ययन को छः खण्डों में तैयार किया गया है। इन खंडों में शोध संस्थान, अनुसंधान संगठन, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अभिकरण, अनुसंधान प्रायोजित करने वाली स्वायत्त निकाएं, विभिन्न बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के संबंध में सूचना दी गई है।

3. भारत में शिक्षा के अवसर की समानता और शैक्षिक अवसर के समकरण के विशेष संदर्भ में शैक्षिक वित्त का अध्ययन :

केरल तथा उत्तरप्रदेश के स्कूल शिक्षा का केस अध्ययन। इस परियोजना के लिए डा. सी बी पद्मनाभन, परियोजना निदेशक और श्री बी शिवरेड्डी सहित अनुसंधान दल का गठन किया गया है।

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं : (1) समता और समानता के लक्ष्यों के प्रकाश में शैक्षिक वित्त के स्रोतों में हुए परिवर्तन का अध्ययन; (2) शिक्षा के वित्तीय तंत्र का विश्लेषण जिनमें अनुदान सहायता प्रणाली तथा शैक्षिक अवसरों के वितरण पर इसके प्रभाव भी शामिल हैं; (3) स्कूल शिक्षा में आमतौर से शिक्षा के खर्च का वास्तविक लाभकर्ताओं का पता लगाना।

इस अध्ययन का स्वरूप अनुभवाश्रित और विश्लेषणात्मक है और केवल दो राज्यों, केरल और उत्तरप्रदेश तक सीमित है। सीमित अर्थों में यह भारत में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र तथा शैक्षिक दृष्टि से उन्नत क्षेत्रों का शैक्षिक अवसर की समानता के विशेष संदर्भ में शैक्षिक वित्त का तुलनात्मक अध्ययन है क्योंकि अधिकांश शैक्षिक विकास के सूचकों को देखते हुए केरल शिक्षा में सबसे ऊपर है और उत्तरप्रदेश सबसे पीछे है। आंकड़ों का मुख्य स्रोत केंद्रीय तथा राज्य दोनों ही सरकारों की प्रकाशित और अप्रकाशित सामग्री है। सूचना प्राप्त करने के लिए योजना अभिलेख, बजट रिपोर्ट तथा संबंधित राज्यों के सांख्यिकीय एब्स्ट्रेक्ट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

स्कूल स्तर पर 1956-57 और 1980-81 के बीच के शैक्षिक विकास संबंधी आंकड़े एकत्र किए जा चुके हैं ताकि इस बात की परीक्षा की जा सके कि क्या इन वर्षों के दौरान शैक्षिक सुविधा के बीच की असमानता दोनों राज्यों में कम हुई है अथवा नहीं। संकलित आंकड़ों में जिन बातों को शामिल किया गया है, वे बातें हैं : संस्थाओं की संख्या नामांकन, नामांकन अनुपात आदि। इसका उद्देश्य है आबादी के विभिन्न हिस्सों में शैक्षिक सुविधाओं के आबंटन की परीक्षा करना।

यह अध्ययन अब पूरा होने वाला है तथा अंतिम अध्याय लिखे जा रहे हैं।

4. भारत में शैक्षिक नीति और योजना का अध्ययन : योजना आयोग की भूमिका, वर्तमान स्थिति तथा परिप्रेक्ष्य

इस अध्ययन के लिए अनुसंधान दल डा. एस एन सराफ, परियोजना निदेशक, और सुश्री अनीता टपलू

परियोजना सहायक, द्वारा गठित किया गया है। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं: (1) इस बात की समीक्षा करना कि भारत में शैक्षिक नीति नियोजन के क्रमिक विकास के सम्पूर्ण राष्ट्रीय विकास ने स्वतंत्रता से पूर्व और उसके बाद किस तरह से प्रभावित किया; (2) अनेक आयोग और समितियों द्वारा शिक्षा तथा अन्य विकासात्मक क्षेत्रों में दिए गए योगदान का विस्तार करना; (3) विभिन्न स्तर पर शैक्षिक योजना के निरूपण से संबद्ध प्रक्रिया एवं तकनीक का पता लगाना; (4) नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए योजना आयोग, शिक्षा मंत्रालय और राज्य सरकारों की भूमिका; (5) पूरी की गई योजना और कार्यक्रमों का पुनरीक्षण और मूल्यांकन करना; (6) वर्ष 1951-85 के दौरान बनाई गई शैक्षिक रूपरेखा के गुणात्मक विस्तार पर दिए गए निदान एवं सुझाव देना कि इन्हें किस तरह से प्रतिपादित किया जाए; (7) इसके साथ ही अगले 15 वर्षों के दौरान यानी 1985-2001 में सम्पूर्ण राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा योजना का मूल्यांकन एवं संचारेण करना है।

प्रकाशित और अप्रकाशित सामग्री और प्रतिवेदन के रूप में विभिन्न पंचवर्षीय योजना के प्रारूपों की अध्ययन सामग्री, सांख्यिकीय सूचना, वक्तव्यों, सांख्यिकियों, अनुसूचियों तथा विभिन्न समितियों की रिपोर्टों का अध्ययन, वर्गीकरण, विश्लेषण और उसे क्रमबद्ध किया जाएगा।

इस अध्ययन परियोजना की एक एक प्रति 120 प्रमुख लोगों को दी गई थी। इसमें कई तरह के लोग थे जैसे प्रमुख शिक्षा शास्त्री, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, कुछ खास कुलपति, विकास योजनाकार, जनांकिकी विशेषज्ञ, वैज्ञानिक प्रशासक, भूतपूर्व शिक्षामंत्री तथा योजना आयोग के शिक्षा सदस्य तथा उन्हें भी दी गई जो योजना नीति से संबद्ध थे। इन सभी लोगों से बहुत ही महत्वपूर्ण आकलन और सुझाव प्राप्त किए जा चुके हैं और प्राप्त की गई लगभग सभी सामग्री का विश्लेषण किया जा चुका है।

प्रस्तावित अध्ययन के प्रथम अध्याय में प्रथम छः योजनाओं के दौरान शिक्षा नीति और कार्यक्रम के प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों के संश्लेषण को प्रस्तुत करने का भी विचार है और शिक्षा योजना के कतिपय महत्वपूर्ण अवयवों की प्रगति के आलोचनात्मक परीक्षण का भी विचार है। प्राइमरी, पूर्व प्राइमरी, प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर, तकनीकी और प्रौढ़ शिक्षा संबंधी इस अध्याय के हिस्सों का प्रारूप तैयार हो चुका है।

संसद तथा शैक्षिक नीति और कार्यक्रमों की समीक्षा के आरंभिक प्रारूप के अध्याय पर कार्य शुरू किया जा चुका है। शिक्षा के अतिरिक्त विभागों की भूमिका, भारतीय संविधान में शिक्षा और स्वतंत्रता से पूर्व की अपनाई गई नीति ओजना के विशेष संदर्भ सहित शैक्षिक रूप रेखा को कुछ अध्यायों में समीक्षा की गई। सरकार द्वारा स्थापित कुछ वित्त आयोग और समितियों द्वारा दी गई सिफारिशों पर की गई समीक्षा पर कार्य, पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा संबंधी नीतियों और योजनाओं की विशेष चर्चा के अनुसार शैक्षिक, विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों की समीक्षा पूर्वक मूल्यांकन करना, अनेक राजनीतिक दलों द्वारा घोषित चुनाव घोषणा पत्रों का अध्ययन और प्रथम छः पंचवर्षीय योजनाओं में चर्चित समस्त सामाजिक आर्थिक अभिप्राय की समस्त सामग्री को भी विशिष्ट प्रकाश में लाने का कार्य आरंभ किया जा चुका है।

छठी पंचवर्षीय योजना तक के आद्योपांत शिक्षा के बहुत से प्रगति क्षेत्रों से संबद्ध सांख्यिकी आंकड़ों को संकलित कर उनका विश्लेषण किया जा रहा है। इन सबको इस अध्ययन में उचित स्थान पर संगृहित कर दिया जाएगा।

5. वर्ष 2000 में भारतीय शिक्षा एक दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य

इस अध्ययन के लिए डॉ. ब्रह्म प्रकाश, परियोजना निदेशक; श्री एम एम अंसारी, परियोजना सह अध्येता; श्री मनोज शर्मा, परियोजना सहायक और श्री इफ़्तिखार अहमद, परियोजना सहायक सहित अनुसंधान दल का गठन किया गया है।

इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से हैं : (1) शिक्षा में भूतकाल के विकास पर आधारित नामांकन परियोजनाओं की प्रवृतियों का पता लगाना। शिक्षा के हर चरण के लिए एक अभ्यास किया जाएगा यानी प्राइमरी, माध्यमिक, तकनीकी उच्च शिक्षा गैर तकनीकी उच्च शिक्षा। यह कार्य राज्यों तथा अखिल भारतीय दोनों स्तरों पर किया जाएगा, (2) शिक्षा का एक व्यवहारवादी प्रारूप सामने लाना : संस्थाओं के आकार तथा महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक जनांकिकीय चरों के साथ शिक्षा पर होने वाले खर्चों को जोड़ना।

अध्ययन पद्धति, आधार सामग्री तथा अध्वयन क्षेत्र का विस्तृत ब्यौरा देने वाली अनुसंधान की संशोधित रूपरेखा बनाई जा चुकी है। शृंखला आंकड़े अखिल भारत के लिए तथा महाराष्ट्र राज्य के लिए संग्रहित किए गए। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान जिन क्षेत्रों के लिए काम हुआ, वे हैं, 1960-61 से 1982-83 वर्ष के लिए प्राइमरी, मिडिल, तथा माध्यमिक शिक्षा के नामांकन का लेखा-जोखा, 1960-61 से लगातार 1991 तक के खास उम्रवार जनसंख्या का अनुमान, इन दोनों के संबंध में लिंगवार आंकड़े तैयार किए गए; संस्थाओं से संबंधित तथा शिक्षा पर व्यय संबंधी आंकड़ों को एकत्र करने का कार्य किया गया।

महाराष्ट्र राज्य के लिए विभिन्न स्तर पर नामांकन के प्रक्षेपण पर विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, और शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर (वर्ष 2000 तक) अध्यापक मांग, व इसी राज्य के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों वित्तीय संसाधनों की मांग की पूर्ति के लिए खोज का कार्य आरंभ कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त इस राज्य की वर्ष 2000 ई. में शिक्षा का अध्ययन पूरा हो चुका था। इस अध्ययन रिपोर्ट में अध्यापक मांग के नामांकन प्रक्षेपण और शिक्षा के व्यय पर चर्चा की विस्तृत समीक्षा की गई है।

6. केरल में शैक्षिक विकास के इतिहास का अध्ययन

इस अध्ययन के लिए प्रो. के एम पाणिकर, अवैतनिक परामर्शदाता और श्री ए मैथ्यु, परियोजना सहअध्येता सहित इस अनुसंधान दल का गठन किया गया है। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं : (1) माला-बार त्रावणकोर कोचीन के भूतपूर्व रजवाड़ों (केरल) में जिस रूप में शिक्षा का विकास हुआ उसका विश्लेषण करना, (2) केरल राज्य बनाने के बाद 1950 से शिक्षा के प्रसार के स्वरूप का अध्ययन, (3) विभिन्न स्तरों पर निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले घटकों और शक्तियों को पहचानना, (4) उन अड़चनों की रूपरेखा तैयार करना जो निर्णय में बाधा पैदा करती है और जिनकी जानकारी से दूसरे राज्यों को इस पर काबू पाने में मदद मिल सके।

पहले भाग में 1956 से पहले का इतिहास होगा। ऐतिहासिक अभिलेखों पर यह आधारित होगा जैसे, मैनुअल्स, प्रशासनिक रिपोर्ट, शैक्षिक प्रलेख, सांख्यिकीय सूचियां, सरकारी रिकार्डस, तथा स्थानीय कांउसिलों की कार्यवाहियां। दूसरा भाग भी इसी तरह की प्रकाशित सामग्री को ध्यान में रख कर लिया जाएगा। इसके अलावा उन सरकारी कागजातों का अवलोकन किया जाएगा जो सार्वजनिक उपयोग के लिए

प्रतिबंधित नहीं रह गए हैं, साथ साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों और शिक्षा शास्त्रियों के साक्षात्कार (भेंट-वार्ता) से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग भी किया जाएगा।

मद्रास प्रेसिडेंसी का मालाबार प्रांत और इसी प्रकार त्रावणकोर कोचीन की देशी रियासतों से 1820-1947 की अवधि की शैक्षिक विकास से संबंधित सामग्री को प्राप्त किया जा चुका है। यह सामग्री जनगणना, गजेटियरस, प्रशासनिक रिपोर्ट, शिक्षा विभाग की रिपोर्ट और जर्नलस तथा ईसाई मिशनों के अभिलेखों से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है।

संस्थाओं, प्रत्येक राज्य के नामांकन, शैक्षिक नीति संबंधी पहलुओं एवं समस्याओं के हल के लिए 1956 के बाद की अवधि के आंकड़े एकत्रित किए गए हैं।

7. तकनीकी शिक्षा प्रबंध : इंजीनियरिंग कॉलेजों में व्यक्तिगत ढांचे तथा सामग्री नियंत्रण के अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम

इस अध्ययन के लिए डा. एम मुखोपाध्याय, परियोजना निदेशक; और श्री सी आर के मूर्ति, परियोजना सहायक सहित अध्ययन दल का गठन किया गया है। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है : (1) विभिन्न स्तरों पर काम करने के लिए रखे गए लोगों के वर्तमान ढांचे की जानना, विशेष रूप से हर अकादमिक विभाग, प्रशासन तथा लेखा विभाग को (2) इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए अधिकतम रूप से सक्षम कर्मचारियों का प्रस्ताव रखना, (3) विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रचलित वर्तमान सामग्री नियंत्रण प्रबंध व्यवस्था को जानना तथा प्रबंध के दौरान आने वाली समस्याओं का निदान करना, (4) सामग्री प्रबंध के सफल मामलों को पहचानना तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों में सामग्री प्रबंध की एक व्यवस्थित पद्धति का प्रस्ताव रखना।

भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों के सभी विभागों के वर्तमान कर्मचारियों के ढांचे के (कुछ उपकरणों के) आधार पर सर्वेक्षण किया जाएगा। बाद के स्तर पर चल कर 30 इंजीनियरिंग कॉलेजों का अलग अलग विस्तार से अध्ययन किया जाएगा।

इस परियोजना में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, राज्य इंजीनियरिंग कालेज और विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग संकाय का प्रतिनिधित्व करने वाली 30 इंजीनियरिंग कालेजों की समस्याओं पर केस अध्ययन पूरा किया जाएगा। उत्तरी क्षेत्र की 10 संस्थाओं का केस अध्ययन पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी और पश्चिमी भारत की अन्य 12 संस्थाओं के केस अध्ययन को संचालित करने के लिए परियोजना सहायक क्षेत्र दौरे पर गए हुए है।

8. विकास के कुछ पहलुओं पर शैक्षिक स्तर का प्रभाव : ग्रामीण परिवार का अध्ययन

यह अध्ययन डा. एच रामचंद्रन परियोजना अध्येता और सुश्री शारदा मांविकर, परियोजना सह-अध्येता सहित अनुसंधान दल का गठन किया गया है। इस अध्ययन के अंतर्गत निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाना है : (1) क्या नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में शैक्षिक स्तर का प्रभाव पड़ता है ? यदि हां, तो क्या शिक्षा का कोई क्रांतिक स्तर है जो अपनाने को प्रभावित करता है, (2) क्या शैक्षिक स्तर आर्थिक

गतिविधियों के बहुविधिकरण को प्रभावित करते हैं ? (3) बाजार, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों के संदर्भ में शैक्षिक स्तरों तथा परिवारों से संपर्कों के बीच संबंधों का स्वरूप क्या है ? (4) क्या दूसरे विकासात्मक प्रयासों को इस्तेमाल और आत्मसात करने की क्षमता को शिक्षा का स्तर प्रभावित करता है ? (5) क्या शिक्षा का स्तर आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करता है ?

इस प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इस बात का प्रस्ताव रखा गया कि परिवारों के स्तर वाले आंकड़े को इस्तेमाल किया जाएगा। इस आंकड़े को संस्थान ने एक परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से संकलित किया था जो टुमकुर जिला कर्नाटक में चल रही समस्त ग्राम विकास योजना के लिए एकत्र किया गया था जिसमें सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाना था। 245 गांवों की यहां वहां से चुना गया था। इन गांवों से ही लगभग 30,000 परिवारों के आंकड़े एकत्र किए। शैक्षिक स्तर का अनुप्रस्थ सारणीयन किया गया है जिससे कि इनसे उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर खोजे जा सके।

आंकड़ों का कार्य प्रगति पर है। रिपोर्ट का मसौदा तैयार करना आरंभ कर दिया गया है।

9. शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और विकास में लाभदायक संबंध

इस अध्ययन के लिए डॉ. ब्रह्म प्रकाश, परियोजना निदेशक, श्री जे एस चौधरी, परियोजना सहायक और श्री आर के शर्मा, परियोजना सहायक से अनुसंधान दल का गठन किया गया है।

योजना आयोग ने जून 1984 में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और विकास में लाभदायक संबंध पर विशेषज्ञ दल पर मसौदा रिपोर्ट को संशोधित करने के लिए अनुरोध किया था। संबंधित मसौदा रिपोर्ट को संशोधित करके श्री पार्थसार्थी को प्रस्तुत कर दी गई थी।

नीपा से यह भी अनुरोध किया था 'शैक्षिक रोजगार संबंध' विषय पर विशेषज्ञ दल के अधार पत्र पर समरूप जिल्द तैयार करे। इसी तरह का समरूप जिल्द तैयार करना आरंभ कर दिया है।

10. कालेजों के प्राचार्यों की भूमिका का अध्ययन

इस अध्ययन के लिए डॉ. एन एम भागिया, परियोजना निदेशक; और सुश्री प्रमिला यादव, परियोजना सहायक सहित अध्ययन दल का गठन किया गया है। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं : (1) कॉलिजों के प्राचार्यों की भूमिका की प्रत्याशाओं का पता लगाना, (2) प्राचार्यों द्वारा विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं के निष्पादन का मूल्यांकन करना, (3) उनकी भूमिका निष्पादन को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों का पता लगाना।

इस अध्ययन से संबंधित प्रासंगिक साहित्य की समीक्षा करने के बाद चुनी हुई पुस्तकों की सूची विवरण सहित तैयार की गई। प्राचार्यों की भूमिका से जैसा कि अध्यापक छात्र, गैर शिक्षक समुदाय तथा शासी निकास निकाय के सदस्य उसे मानते हैं, एक प्रश्नावली तैयार की गई ताकि उन प्रत्याशाओं का पता लगाया जा सके। एक अलग प्रश्नावली 24 प्राचार्यों को दी गई ताकि यह जाना जा सके कि वे किस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न रहते हैं।

प्रश्नावली को समीक्षा के पश्चात फिर से संशोधित किया जा चुका हैं। और कॉलिज के प्राध्यापकों

के साथ ही अन्य प्रश्नावली स. स्वा प्र (संघटनात्मक स्वास्थ्य प्रश्नावली) जिसमें 40 मदें हैं, तैयार की जा रही है। प्रश्नावली के द्वारा कॉलेजों प्राचार्यों और प्राचार्यों और प्राध्यापकों दोनों के आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। कॉलेज प्राचार्यों को दो प्रश्नावली भेजी जा रही हैं जिनमें से एक "कैटलस 16 पी ए है जो कि 16 तथ्यों के आधार पर व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना है और दूसरी प्रश्नावली द्वारा संक्षिप्त रूप में जीवनी-संबंधी सूचना एकत्र करना है। कॉलेज प्राचार्यों और कॉलेज प्राध्यापकों से संबंधित आंकड़े एकत्र करने का कार्य प्रगति पर है। चुने गए विभिन्न 32 कॉलेज अध्यापकों को प्रश्नावली भेजी जा चुकी है। सब मिलाकर लगभग 390 प्रश्नावली कॉलेज प्राचार्यों को भेजी गई थी जिनमें से 75 प्रश्नावली वापिस प्राप्त हो चुकी हैं। और प्राप्त प्रश्नावलियों के आधार पर आंकड़े विश्लेषण के लिए प्राप्त अंकों को सारणीबद्ध किया जा रहा है।

दिल्ली के कॉलेजों का दौरा प्रगति पर हैं। दिल्ली के कॉलेजों का दौरा पूर्ण होने के पश्चात 19 कॉलेजों का क्षेत्र कार्य पूरा हो जाएगा।

11. जिला गुड़गांव, हरियाणा के पुनहाना प्रखण्ड के 20 गांवों के समूह में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य से अभिनव कार्यान्वियन के आधार पर कार्यानुसंधान

इस अध्ययन के लिए प्रो. सत्यभूषण, परियोजना निदेशक, डॉ. आर एस शर्मा, सहअध्येता, डॉ. अब्दुल अज़ीज, परियोजना सहअध्येता, डॉ. पी मेनन, परियोजना सहायक, श्री उस्मान खान, कनिष्ठ परियोजना सहायक सहित अनुसंधान दल का गठन किया गया है।

इस परियोजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं: (1) व्यापक संघटित कार्यक्रम को परीक्षण के द्वारा विकसित करना; (2) लोगों की भागीदारी से साक्षरता को बढ़ाना, (3) भागीदारी युक्त खोज, समस्याओं को पहचान, योजना का निर्माण तथा उसके कार्यान्वयन, मूल्यांकन और संचारेक्षण में समुदाय की साथ लेना, (4) अन्य शैक्षिक अभिकरणों के शैक्षिक कार्यक्रमों की पहचान प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनीकरण से संबद्ध करके उनके सहयोग तथा संपर्क स्थापित करना।

जिला गुड़गांव का पुनहाना प्रखण्ड शैक्षिक रूप से पूरे हरियाणा राज्य में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र हैं। वर्तमान प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत सहयोगी रचनातंत्र द्वारा समुदाय की भागीदारी से उन संभावनाओं का पता लगाना है जिनके द्वारा प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण किया जाना है। इस पूरे क्षेत्र की जनसंख्या 19.23% है जिसमें 8.30% अनुसूचित जाति की है। यहां की साक्षरता दर कुल जनसंख्या का 20% है जब कि दो तिहाई से अधिक पुरुष जनसंख्या निरक्षर है। महिलाओं में निरक्षरता की दर 95% है जो कि बहुत अधिक है।

इस क्षेत्र में लड़कियों के नामांकन की प्रमुख समस्या थी इसलिए इस कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी को आवश्यक माना गया था। अत: इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए नीपा ने अगस्त 1984 में आठ गांवों की महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य था कि भागीदारों से परस्पर संबंध बनाकर उनकी समस्याओं को समझा जाए ताकि उनकी आवश्यकताओं की पूरी जानकारी मिल सके। साथ हो स्वास्थ्य विज्ञान के साथ साथ उन्हें साक्षरता और शिक्षा के लाभों के प्रति जागरूक भी बनाना है। ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए उपाय बताना ताकि वे पोषण और अच्छा स्वस्थ्य बनाए रखें और इसके द्वारा श्रम की बचत कर सके। इस परियोचना के कार्या-

न्वयन को सुनिश्चित करने के लिए चार स्तरीय युक्ति अपनाई जाएगी। इसमें ये बातें शामिल है : समुदाय की भागीदारी, स्कूल कांप्लेक्स की सहायक भूमिका, विकास के अन्य विभागों के साथ संपर्क, कार्य को सुकर बनाने के साथ नीपा की समीक्षात्मक व हस्तक्षेपकारी भूमिका।

गांव के स्तर पर स्कूल कांप्लेक्स तथा परियोजना के स्तर पर यह संगठन कार्य करेगा। इनको गांव शिक्षा समिति, स्कूल कांप्लेक्स समिति के नाम से पुकारा जाएगा तथा समूह के स्तर पर इसे परामर्शदात्री समिति नाम से पुकारा जाएगा।

12. महिलाओं के विशेष संदर्भ में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में शैक्षिक अवसरों को समान बनाने में रक्षात्मक भेदभाव की भूमिका

इस अनुसंधान अध्ययन को—डॉ. (श्रीमती) ऊषा नय्यर, अध्येता ने अपने हाथ में लिया है।

इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में रक्षात्मक भेदभाव की नीतियों और कार्यक्रमों का तुलनात्मक विश्लेषण करना ताकि उन आलोचनात्मक घटकों को पहचाना जा सके जो जनसंख्या के विभिन्न समूहों के अंतर को कम करने में मदद कर सकें, विशेष रूप से महिलाओं के बीच के अंतर को।

दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में यह अध्ययन किया जाएगा जिनमें उल्लेखनीय नाम हैं : अफगानिस्तान, बर्मा, बंगलादेश, भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालद्वीप, इंडोनेशिया, और थाईलैंड।

शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त वर्तमान असमानताओं को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित किया जाएगा। नीति संबंधी उपलब्ध अभिलेखों, विशेष कार्यक्रमों/प्रावधानों और योजनाओं के गुणात्मक विश्लेषण का प्रयास किया जाएगा। संरक्षणात्मक भेदभाव में लगाई गई सामग्री और संसाधन संबंधी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के अध्ययन के लिए दो समय बिंदुओं के सांख्यिकीय आंकड़ों का भौतिक विश्लेषण किया जाएगा। दो से तीन सप्ताहों का क्षेत्र भ्रमण आवश्यक होगा ताकि संस्थाओं के कर्मचारियों के साक्षात्कार तथा भेंटवार्ता द्वारा प्रारंभिक साक्ष्य एकत्र किए जा सकें।

इस अध्ययन में प्रमुख आधार सामग्री होगी : संरक्षणात्मक भेदभाव : संसाधनों से संबंधित कानूनो और सरकारी दस्तावेज; वर्तमान सामाजिक साक्ष्य, तथा साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त आंकड़े।

कार्य की तैयारी के लिए यथेष्ठ धनराशि का प्रबंध हो चुका है परंतु अध्ययन में कुछ संशोधन किया गया है ताकि प्रथम बार में 11 देशों के स्थान पर कुछ देशों को अध्ययन कार्य हाथ में लिया जा सके। अत: यह अध्ययन इंडोनेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका तक ही सीमित रहेगा।

13. कालेजों के विज्ञान विभागाध्यक्षों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पाठ्य सामग्री तैयार करने के लिए दो कालेजों का मार्गदर्शी अध्ययन

इस परियोजना के लिए डा. जी डी शर्मा, वरिष्ठ अध्येता; डा. (श्रीमती) शक्ति आर अहमद, परियोजना निदेशक; सुश्री कैशर विजारत, परियोजना सहायक; सुश्री रूपरेखा दलवानी और डा. शशी सेठ, परियोजना सहा-

यक के द्वारा अध्ययन दल का गठन किया गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य निम्नांकित की समीक्षा करना है : कालेज की योजना और प्रबंध में विज्ञान कार्यक्रमों को किस तरह से प्रभावी बनाया जाए, कालेजों में शिक्षण की कौन सी पद्धति अपनाई जाए; अभिविन्यास के लिए पाठ्यक्रम को किस तरह से पुनर्गठित किया जाए, प्रयोगशालाओं में व्यय प्रभाव और अभिनव व्यवहार को किस तरह प्रयोग में लाया जाए, और मूल्यांकन का सुझाव देना है : विज्ञान शिक्षा के योजना और प्रबंध में सुधार लाना, अभिविन्यास विकास और रोजगार के लिए पाठ्यक्रम का पुनर्गठन करना, शिक्षण/अधिगम के सुधार को ध्यान में रखते हुए शिक्षण को नई पद्धति से अवगत कराना है।

गुणात्मक और मात्रात्मक सूचकों के आधार पर कालेजों में विज्ञान शिक्षा की योजना और प्रबंध के विश्लेषण का प्रयत्न किया जाएगा।

उपर्युक्त सूचकों के आधार पर सूचना एकत्र करने के लिए दो कालेजों (अर्थात गार्गी कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली से संबद्ध और राजकीय कालेज, गुडगांव, महर्षि दयानन्द से संबद्ध (का चयन किया गया था।) गार्गी कालेज और गुडगांव कालेज से समुचित आंकड़े एकत्रित किए जा चुके हैं। इन दो कालेजों में विज्ञान शिक्षा के स्तर को आंकने के लिए प्राप्त आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण किया जाएगा। यह सामग्री कालेजों के विज्ञान विभाग अध्यक्षों के अभिविन्यास कार्यक्रम के लिए आधार सामग्री की तैयार करने में सहायक होगी।

14. नौ पिछड़े राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा का मूल्यांकन

इस परियोजना के लिए अभी अनुसंधान दल का गठन किया जाना है। इस मूल्यांकन अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं : सफल और असफल क्षेत्रों को जानना, प्रशासनिक ढांचे की पर्याप्तता और अपनाई गई पद्धति की क्षमता का मूल्यांकन करना, वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों का पुनर्गठन करना तथा संभावित अधिगम प्राप्ति के लिए सुझाव देना।

अध्ययन एक साधारण प्रणाली अध्ययन न होकर अभिविन्यास अनुसंधान कार्य होगा। इस अध्ययन में नौ राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के विस्तार में आने वाली कठिनाइयों एवं समस्याओं का दिग्दर्शन करना और इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की उपलब्धियों व प्रगति को समझने का प्रस्ताव है। इस अध्ययन में अकादमिक, भौतिक, प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं का मूल्यांकन का भी सुझाव देना है।

विकास के प्रस्तावित उपचार के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों से आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। अनौपचारिक शिक्षा केंद्र अनुसूची (केंद्रों का कार्य अध्यापक, विद्यार्थी और केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं को सम्मिलित किया गया है), सामाजिक-आर्थिक आधार पर बीच में छोड़ने वाले विद्यार्थियों की अनुसूची (चयन किए गए माता पिता/बालक जो स्कूल/केंद्र में नहीं गए अथवा, बीच में ही छोड़ गए, इन कारणों का पता लगाना एवं उनके सुझाव प्राप्त करने के लिए); अभिमत सर्वेक्षण अनुसूची (अध्यापकों, माता पिताओं जानकार व्यक्तियों, औपचारिक स्कूलों के अध्यापकों, केंद्रों के विद्यार्थियों, पर्यवेक्षकों और खंड शिक्षा अधिकारियों से अभिमत सर्वेक्षण पूरा करने के लिए); गांव/शहरी क्षेत्रों की सूचना अनुसूची (शैक्षिक,

सुविधा, सामाजिक-आर्थिक जनांकिकी ढांचा और विकास कार्यक्रम क्षेत्रों से आंकड़े एकत्र करने के लिए), खंड सूचना से लिए अनुसूची (निरीक्षण, पर्यवेक्षण और अनौपचारिक पर्यवेक्षकों की पद्धति में शैक्षिक सुविधा, सामाजिक जनांकिकी ढांचा और विकास संबंधी सूचना के लिए), स्वयंसेवी संगठनों की सूचना के लिए अनुसूची (अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम से जुड़ी स्वयंसेवी संगठनों से संबंधित सूचना एकत्र करने के लिए) जिला सूचना अनुसूची (जिला स्तर पर सभी आवश्यक सूचना के लिए) और राज्य सूचना अनुसूची (राज्य स्तर पर सभी आवश्यक सूचना के लिए)।

इसके अतिरिक्त अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन से संबंधित आधार सूचना साधन एकत्रित करने के लिए प्रारूप तैयार किया जाएगा। इसका विकास राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद करेगी। पाठ्यक्रम की विषयवस्तु, संस्थागत सामग्री और शिक्षण रणनीति के मूल्यांकन कार्य भी पूरा करने का प्रस्ताव है। आंकड़ों की सारणी तैयार करने के लिए और प्रारूपों और समेकित सूची निरीक्षण हेतु मार्गदर्शिका तैयार की जाएगी और उसे इस अध्ययन से सम्बद्ध राज्यों को भेजा जाएगा।

स्वीकृत अध्ययन

15. भारत में अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जनसंख्या के बीच साक्षरता स्तर की असमानता का जिलेवार विश्लेषण

इस परियोजना के लिए प्रो. मूनिस रज़ा, निदेशक; डॉ. वाई पी अग्रवाल, परियोजना सहायक निदेशक; और ओ. डी. त्यागी, परियोजना मानचित्रकार द्वारा अनुसंधान दल का गठन किया गया है। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं : अनुसूचित जाति के विभिन्न घटकों में साक्षरता के प्रसार के लिए स्थानिक प्रतिमान का पता लगाना, अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जनसंख्या के बीच साक्षरता स्तर की समानता, और असमानता की समीक्षा करना, साक्षरता के स्तर में दूरी को आंकने के लिए उपयुक्त प्रणाली का विकास करना; अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जनसंख्या के बीच साक्षरता दर की असमानता के स्थानिक प्रतिमान का निरीक्षण करना, अनुसूचित जातियों के घटकों के बीच और अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जनसंख्या के बीच तुलनात्मक प्रकृति और शैक्षिक प्रणाली में असमानताओं को कम करने के लिए क्षेत्रीय आधार पर विशेष नीतियों को विकसित करना। आंकड़े एकत्रित करने का कार्य व संबंधित संसाधनों की पहचान और सारणी संकलन का प्रथम कार्य पूरा किया जा चुका था। परन्तु इस परियोजना के निदेशक और सह निदेशक अन्य कार्यभार संभालने के कारण संस्थान छोड़ चुके हैं इसलिए इस परियोजना का कार्य जनवरी 1985 से रुका हुआ है।

16. 250 कॉलेज और वे स्कूल जिनमें +2 माध्यमिक स्तर आरम्भ किया जा रहा है के प्राचार्यों के लिए मार्गदर्शी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए केस अध्ययन का विकास

इस अध्ययन के लिए डॉ. एम सुखोपाध्याय, वरिष्ठ अध्येता, श्री. एम कंदन और सुश्री सुभ्रा त्रिपाठी, परियोजना सहायक से इस अनुसंधान दल का गठन किया गया है। संस्थान ने इस अध्ययन को हरियाणा

सरकार के अनुरोध पर अपने हाथ में लिया है। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं : स्थान, स्टाफ पुस्तकालय और प्रयोगशाला सुविधाओं के महत्व पर बल देते हुए हरियाणा में तीन केस अध्ययन का विकास करना, नई हायर सेकेंडरी योजना का संकाय बोध और प्रशिक्षण प्रक्रिया; प्रत्येक हाई स्कूल से बढ़ाकर हायर सेकेंडरी स्कूल, 11वर्षीय हायर सेकेंडरी स्कूल से बढ़ाकर 12 वर्षीय हायर सेकेंडरी स्कूल और वे कॉलेज जहां पर 12 वर्षीय हायर सेकेंडरी योजना आरंभ की जाएगी। केंद्रीय विद्यालय, सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालय जहां पर 12 वर्षीय योजना आरंभ की जानी है, विज्ञान शिक्षा, प्रयोगशाला प्रतिमान और पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन पर विशेष बल देते हुए केस अध्ययन का विकास किया जाएगा। हरियाणा के 250 कॉलेज प्राचार्यों और स्कूल प्रधानाचार्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को आधार मानकर केस अध्ययन का विकास किया जाएगा। स्कूल पुस्तकालय, समय सारणी, विज्ञान प्रयोगशाला, मार्गदर्शन और परामर्श पर केस अध्ययन के आंकड़े पहले ही एकत्रित किए जा चुके हैं और इस कार्यक्रम के लिए पाठ्य सामग्री तैयार की जा चुकी है।

17. शैक्षिक गतिविधियों के लिए किए गए स्थानिक प्रावधान का अध्ययन

इस परियोजना के लिए अभी अध्ययन दल का गठन और अध्ययन आरंभ करना है विभिन्न नगर प्राधिकारिणों द्वारा शैक्षिक गतिविधियों के लिए किए जाने वाले स्थान संबंधी प्रावधानों में अपनाई गई वर्तमान नीतियों तथा परंपराओं का तुलनात्मक अध्ययन करना, विभिन्न शैक्षिक स्तर वाले संस्थाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नगरों तथा आवासीय क्षेत्रों की विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों की भावी आवश्यकताओं की विस्तृत स्तरों के शिक्षण संस्थानों के लिए तथा तरह तरह की शैक्षिक गतिविधियों के लिए भवन संबंधी मानदण्ड सुझाना, शैक्षिक गतिविधियों की अनुमानित आवश्यकताओं के आधार और सुझाए गए भवन तथा स्थान के मानदण्डों के आधार पर भविष्य के कुल स्थान और भवन की आवश्यकता का आकलन, स्थान संबंधी आवश्यकता के संदर्भ में शैक्षिक गतिविधियों के विभिन्न चरणों और स्तरों पर नई शैक्षिक प्रोद्योगिकी के प्रभाव का अध्ययन करना, स्थानीय समुदाय की आसपास की सुविधाओं को शैक्षिक सुविधाओं के साथ जोड़ने की पद्धति और तकनीक सुझाना। अनुसंधान के ढांचे की जरूरत के मुताबिक इस अध्ययन के लिए काफी यात्राएं करके वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण करना होगा और इसके दौरान इसके लिए आंकड़े एकत्र करने होंगे।

अनुबंध तीन

संकाय का अकादमिक योग

पुस्तकें

डा. सी बी पद्मनाभन

फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन इंडियन एजुकेशन, सेलेक्ट पब्लिशर्स नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1984

पुस्तकों में लेख के रूप में

डा. सी एल सपरा

दि एजुकेशनल रिफार्मस कमीशन, पंजाब, के लिए "इनवोल्वमेंट आफ कम्यूनिटि इन एजुकेशन" 1984

डा. ब्रह्मप्रकाश

फाइनेन्सिस एंड दि सेवेथं प्लान : डा. मैलकम एस एडिसेसिहा "सेवेंथ प्यान पर्सपेक्टिव", लांसर इंटरनेशनल, नई दिल्ली अध्याय 3, पृ. 78-83 में प्रकाशित।

प्रो. एस एम दुबे

सेंटर फार रिसर्च इन रूरल इंडस्ट्रियल डेवलोपमेंट चंडीगढ़ के लिए "नार्थ इस्ट इंडिया : प्राब्लम्स एंड प्रोस्पेक्टस आफ डेवलोपमेंट" नामक पुस्तक में "दि सोशियो-कल्चर्स प्लुरेलिटि वसर्स नेशनेलिटि : रेलेवेंट एंड एबजर्ड इन दि इंडियन कांटेक्स्ट" एक लेख

श्री एम एम कपूर

एजुकेशनल मैनेजमेंट इनफारमेशन सिस्टम इन इंडिया (इयर बुक इनफारमेशन सिस्टमस इन इंडिया में प्रकाशन के लिए स्वीकृत)

डा. उषा नयर

"कल्चरल रूट्स आफ अप्रेशन पेटर्नस आफ वुमनस एजुकेशन इन इडिया" इन वुमनस प्रॉप्रेशन : पैटर्नस एंड पर्सपेक्टिवस, नई दिल्ली-1985

सुश्री अंजना मंगलागिरि और बी नंदा

"पैटरिआरकल आइडिआलाजि एंड वुमनस अप्रेशन" इन वुमनस अप्रेशन : पैटर्नस एंड पर्सपेक्टिवस, सुशीला कौशिक द्वारा संपादित, शक्ति बुक्स, नई दिल्ली, 1985

अनुसंधान पत्र/आलेख पत्र

डा. आर पी सिंघल "रिमोविंग एडल्ट इलट्रेसी इन इंडिया : प्रोब्लेम्स एंड स्ट्रेटिजिस' ई पी ए बुलेटिन, वाल्युम 6 नं. 3 एंड 4, 1984 में प्रकाशित

"लिंकिंग फार्मल एंड नान-फार्मल एजुकेशन" भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय की एजुकेशनल क्वार्टलि, शरत 1984 में प्रकाशित।

ट्रेनिंग आफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशनस एट ग्रास रूट्स" श्री ए पी सक्सेना द्वारा संपादित "ट्रेनिंग इन गर्वनमेंट : ऑब्जेक्टिवस एंड आपर्च्यूनिटिज, आई आई पी ए 1985, नामक पुस्तक में प्रकाशित।

डा. सी बी पद्मनाभन

"फंक्शन अनैलेसिस आफ दि बजिट आफ बनारस यूनिवर्सिटि" जॅर्नल आफ यूनिवर्सिटि न्यूज में प्रकाशित। फंक्शनल अनैलेसिस आफ एजुकेशनल एक्सपेंडिचर हाउ फ्री इज फ्री एजुकेशन इन नार्थ-ईस्टर्न स्टेटस; युधाना।

"टुअर्डस फंक्शनल फाइनेन्शियल मैनेजमेंट इन इंडियन एजुकेशनल रिव्यू, अक्तूबर, 1985 में प्रकाशित। "अल्टर्नेटिवज इन फाइनेन्सिग आफ एजुकेशनल" फ्रंटिअर्स इन एजुकेशनल में प्रकाशित।

"फाइनेंसिग एंड इक्वलिटि आफ आपर्च्यूनिटि इन एजुकेशन" (शीघ्र प्रकाशित) जर्नल परसपेक्टिवज—एम बी बुच, बड़ोदा में प्रकाशित।

डा. सी एल सपरा

"ह्यूमनाइनिंग एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन" आई ए ई पी ए बुलेटिन, वाल्युम, नं. 2. जनवरी 1985 में प्रकाशित।

डा. ब्रह्मप्रकाश

"वाट एलस यूनिवर्सलाइजेशन आफ एलिमेंटरि एजुकेशन 9" आई ए ई पी ए की बुलेटिन वाल्युम 1 नं. 2, जनवरी 1985 में प्रकाशित।

डा. एस एम भागिया

"इंटेग्रेशन आफ एजुकेशन विद डेवलपमेंट" एजुकेशनल क्वार्टलि, वाल्युम 36 नं. 1, 1984 में प्रकाशित।

"रेलिवेंस आफ चाइनिज एजुकेशन एक्सपीरिएंस टु इंडिया' एजुकेशन एशिया, वाल्युम 4, नं. 3, जुलाई-अगस्त, सितंबर, 1984 में प्रकाशित

डा. एम मुखोपाध्याय

"आर्गेनाइजेशनल इवैल्यूएशन आन डाइअगनैसिस इन एजुकेशन सम मेथडालेजिकल अल्टेर्नेटिवज" "अभिज्ञान" शरत, 1984 में प्रकाशित।

डा. के जी विरमानी

"इंटेलिजेंस टु यूज इंटेलिजेंस-मैनेजरियल ट्रेड थीअरि रिविजिटिड" फाउंडेशनस फार आर्गेनाइजेशनल रिसर्च, जून, 1984 की पत्रिका "अभिज्ञान" में प्रकाशित।

डा. (श्रीमती) कुसुम प्रेमी

"एजुकेशन आफ दि वीक : स्ट्रेटिजिस फार दि सेवेंथ प्लान" योजना वाल्युम 28, नं. 17, सितंबर 16-30, 1984

"एजुकेशनल इक्वलिटि एंड इकोनोमिक आपर्च्यूनिटिज" जर्नेल आफ हायर एजुकेशन में प्रकाशित।

डा. जे बी जी तिलक

"ब्लाक लेवल प्लानिंग इन एजुकेशन", इंडियन जर्नेल आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वाल्युम 17 नं. 1 (अक्तूबर, 1984) (प्रेस में)

"एजुकेशन एड ऐग्रिकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया", इंडियन इकानोमिक अलमैनाक, नं. 9 (अक्तूबर-दिसंबर, 1984) (प्रेस में)

"एजुकेशनल डेवलपमेंट इन हरियाणा : ऐन इंटर-डिस्ट्रिक्ट अनैलेसिस, जर्नेल आफ पंजाब स्कूल आफ इकोनामिक्स, (शीघ्र प्रकाशित)

"पालिटिकल इकोनामी आफ इनवेस्टमेंट इन एजुकेशन इन साउथ एशिया" इंटरनेशनल जर्नेल आफ एजुकेशनल डेवलपमेंट, वाल्युम 4, नवम्बर 2, 1984 में प्रकाशित।

"इक्वलिटि एंड इनइक्वलिटि" कीक्लोस, वाल्युम 37, नं. 2, 1984 (बुक रिव्यू) में प्रकाशित।

"हायर एजुकेशन एंड इंटरनेशनल आर्डर" विकल्प, शीघ्र प्रकाशित (बुक रिव्यू)

डा सुषमा भागिया

फोर्सेस कालिंग फार इनोवेशनस इन दि प्रजेंट इंडियन एजुकेशन" दि उड़ीसा एजुकेशन मैगजीन" वाल्युम 24, नं. 3 और 4, सितंबर और दिसंबर 1982, जानौर 1985 में प्रकाशित।

"सम प्राब्लमस आफ नान-फार्मल लरनिंग, दि हिंदू, वाल्युम 107 नं. 239, अक्तूबर 9, 1984 में प्रकाशित।
"एजुकेशनल इंनोवेशनस एंड देयर मैनेजमेंट इन स्कूल्स दि राजस्थान बोर्ड्स जर्नेल आफ एजुकेशन वाल्युम 20, नं. 1, जून 1984 में प्रकाशित

डा. उषा नाय्यर

"दि एजुकेशन आफ वुमन-ए मेजर पोजर फार दि कामनवेल्थ" सी सी ई ए न्यूजलेटर वाल्युम 6, सितंबर 1984 में प्रकाशित और "भारत में लड़कियों के लिए माध्यमिक स्तर पर शिक्षा-परिप्रेक्ष्य और मूल्यांकन" इंडियन रिव्यू आफ मैनेजमेंट एंड फ्यूचर, वाल्यूम 3,4 1985 में प्रकाशित।

डा. आर एस शर्मा

यूनिवर्सलाइजेशन आफ एलिमेंटरी एजुकेशन एंड दि डिजेबल्ड" हरियाणा जर्नेल आफ एजुकेशन वाल्युम 19, नं. 7, जनवरी-अप्रैल, 1984 में प्रकाशित।

डा. एस सी नुना

स्पेशल पैटर्नस इन ट्राइबल लिटरेसि इन इंडिया" अशिष बोस द्वारा सम्पादित रीडिंग्स इन ट्राइबल डेमोग्राफी एंड डेवलपमेंट में प्रकाशित (प्रेस में)

श्रीमती अंजना मंगला गिरि

"पेट्रिआकल आइडियालाजी एंड वूमनस अप्रेशिएनं" नामक आलेख दिल्ली विश्वविद्यालय की टीचिंग पालि-टिक्स" राजनीतिकविज्ञान एसोसिएशन की दिसंबर 1985 में प्रकाशित।

अकादमिक संस्थाओं में दिए गए व्याख्यान

प्रो. मूनिस रजा

जनसंचार संस्थान में एजूकेशन एंड कालोनियलिज्म पर व्याख्यान दिया।

प्रो. सत्यभूषण

'एजुकेशन फार आल-मिथ एंड रिऐल्टि पर फैकलटि आफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली में व्याख्यान दिया। प्रोग्रेसिव स्कूल्स सेमिनार के समापन अवसर पर भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में विदाई व्याख्यान दिया।

डा. आर पी सिंघल

दिल्ली विश्वविद्यालय में जून 13, 1984 को 'मैनेजमेंट आफ इगेजेमिनेशस" पर व्याख्यान दिया।

"न्यू टेकनालोजिस इन एजुकेशन" पर स्टाफ सेमिनार आफ दिल्ली पब्लिक स्कूल, आर के पुरम नई दिल्ली में व्याख्यान दिया।

कुलाची हंसराज माडेल स्कूल, नई दिल्ली में अखिल भारतीय डी ए वी स्कूल प्रधानाचार्यों के सेमिनार में "प्यूपिल इवैल्यूएशन इन स्कूल' पर व्याख्यान दिया।

दि नेशनल वर्कशाप आन न्यूज आफ कम्प्यूटर इन इगेजेमिनेशन एसोसिएशन आफ इंडियन यूनिवर्सिटिज में मार्च 21, 1985 को "प्रोब्लेम्ज फेस्ड इन मास कंडक्टिड इगेजामस पर व्याख्यान दिया।

डा. सी एल सपरा

उत्तर प्रदेश इंटर्मीडिएट कालेज प्रधानाचार्यों के लिए आयोजित इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग कार्यशिविर, लखनऊ में दिनांक फरवरी 4, 1985 को मुख्य व्याख्यान दिया।

वायुसेवा के स्कूल एकर्कों के अध्यापकों के लिए "न्यू ट्रेंडस इन प्राइमरी एजुकेशन' पर आयोजित कार्यशिविर में दिनांक फरवरी 11, 1985 को मुख्य व्याख्यान दिया।

सहशिक्षा राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडी स्कूल, रिंगरोड, में दिनांक 19 फरवरी, 1984 को सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली के प्रधानाचार्यों के लिए आयोजित "इंस्ट्रीट्यूशनल प्लानिंग इन ए ट्रेनिंग प्रोग्राम" पर व्याख्यान दिया और राजकीय गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नं. 3 सरोजनी नगर, नई दिल्ली में दिनांक फरवरी 2', 1984 को सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली के प्रधानाचार्यों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी व्याख्यान दिया।

डा. एन एम भागिया

स्वास्थ्य शिक्षा के प्रशिक्षकों के लिए "केस स्टॅडि मेथड" पर दिनांक जून 8, 1984 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान में व्याख्यान दिया।

एजुकेशनल इवैल्यूएशन कार्यशिविर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान में दिनांक जुलाई 24, 1984 को "इटर्पिरिटिंग एंड रिपोर्टिंग टेक्स्ट" द्वारा व्याख्यान दिया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान में दिनांक जुलाई 29, 1984 को शिक्षा पर आयोजित कार्यशिविर में "प्रिंसिपलस एंड टेकनीकस आफ आइटम अनैलिसिस" पर व्याख्यान दिया।

"केस मेथड आफ टीचिंग" पर दिनांक सितंबर 18,1984 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान में व्याख्यान दिया।

विश्व युवक केंद्र द्वारा आयोजित अखिल भारतीय इनवाइरनमेंटल एजुकेशन" पर कार्यशिविर में भागीदारों के लिए "इनवाइरनमेंटल एजुकेशन" पर व्याख्यान दिया।

डा. ब्रह्म प्रकाश

पंजाब राज्य लोक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़ द्वारा आयोजित "पावर्टी अलीविएशन प्रोजेक्टस इन 20 पांइट प्रोग्राम, 1984" सेमिनार में व्याख्यान दिया।

विश्व युवक केंद्र में "इकानामिक सिस्टम, प्रोग्रेस एंड फ्यूचर लाइन एंड डेवलपमेंट" पर दिनांक नवंबर 15, 1984 को व्याख्यान दिया।

डा. जी डी शर्मा

द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय, गुड़गांव में दिनांक मार्च 9, 1985 को दीक्षांत समारोह में व्याख्यान दिया।

डा. एम मुखोपध्याय

पंजाब राज्य लोक प्रशासन संस्थान में दिनांक सितंबर 20-21, 1984 को "रोल्स इन आर्गेनाइजेशन" पर व्याख्यान दिया।

पंजाब राज्य लोक प्रशासन संस्थान में दिनांक अक्तूबर 11, दिसंबर 17, और 18, 1984 को "आर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट" पर व्याख्यान दिया।

श्री सी पी तिवारी

नार्थ-ईस्टर्न हिल युनिवर्सिटि, शिलांग और कोहिमा परिसर में "प्रोफेशनलाइजेशनल आफ एजुकेशनल मैनेजमेंट" और "ट्रेनिंग आफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स" पर दो व्याख्यान दिए।

डा (श्रीमती) उषा नय्यर

मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, काडेकनल में दिनांक अक्तूबर, 1985 में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में "भारत में महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार पत्र" प्रस्तुत किया और भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में दिनांक मार्च, 17, 1985 को "ब्रेनड्रेन दि फेनोमेना एंड इट्ज काजिस पत्र सेमिनार में प्रस्तुत किया।

प्रो एस एम दुबे

संघटित ग्रामीण विकास अध्ययन केंद्र बनारस हिंदूविश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा आयोजित संघटित ग्रामीण विकास राष्ट्रीय कार्यशिविर में दिनांक सितंबर 28, 1984 को 4 मोनिटॉरिंग एंड एवैल्यूएशन आफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स" पर व्याख्यान दिया।

डा. (श्रीमती) के सुधाराव

ब्रिटिश कांउसिल द्वारा आयोजित एथिकल वैल्यूज इन एजुकेशन डोमिनिक चर्च संगोष्ठी में दिनांक 16, 1984, के "एथिकल वैल्यूज इन एजुकेशन प्रोस्पेक्टस एंड फ्यूचर परसपेक्टिवज" पर एक व्याख्यान दिया।

श्रीमती जयश्री जलाली

इंस्टिच्यूट पर ला कोआपरेजीन यूनिवर्सिटरिया, रोम में मार्च 1985 में अतर्राष्ट्रीय संगठनों पर आयोजित सेमिनार में भारत में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और भारतीय कृषि व्यवस्था तथा ढांचागत परिवर्तन पर दो व्याख्यान दिए।

दूरदर्शन/रेडियो पर वार्ता

डा. आर पी सिंघल

आकाशवाणी, राजकोट, में दिनांक फरवरी 10, 1984 को "इगजेमिनेशनस रिफोर्मस इन इंडिया : ए प्रपोजल फार डिसेंटरलाईजिंग इग्जोमिनेशन सिस्टम" पर रेडियो वार्ता।

अकादमिक उपलब्धियां

डा सी एल सपरा

अल्बेरटा विश्वविद्यालय, शिक्षा, कनाडा के शैक्षिक प्रशासन विभाग में डॉ. सी एल सपरा ने विख्यात आंगतुक प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय से श्रीमती उषा नायर ने 1984 में पी एच डी की उपाधि प्राप्त की थी।

अनुबंध चार

आगंतुक गण

विदेशों से

डॉ. सेलवेराटनाम, अध्यक्ष, उच्च शिक्षा एककक, राष्ट्रकूल सचिवालय लंदन।
डॉ. ओले आस्टलिग, उप-कुलपति, स्टाकहोम इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन, स्टाकहोम, स्वीडन।
डॉ. डी नीलसन, क्षेत्रीय कार्यक्रम अधिकारी, सामाजिक विज्ञान प्रभाग, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान विकास केंद्र, सिंगापुर।
डॉ. वारेन एल मेलर, शिक्षा संकाय, मोनस, विश्वविद्यालय क्लेटान, आस्ट्रेलिया।
श्री सिल्वेन लायरी, निदेशक और डॉ. बी सी सान्याल, अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना, संस्थान पेरिस।
श्री एस. बिसूनदयाल, निदेशक, इग्रेनेमिनेशन सिंडीकेट, मारिशस
श्री ए बी इडिगटन, अध्यक्ष, मिडिया ग्रुप, साइंस, टेकनालाजि एंड एजुकेशनल डिविजन ब्रिटिश कांउसिल लंदन।
श्री हा-जुंग किम, सभासद, कोरिया गणतंत्र का दूतावास
प्रो. ए. राबर्ट, शिक्षा विभाग, शा विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका।
श्रीमती चाई इआल, गॉन, अध्यक्ष, एन आई ई आर टी, साउथ कोरिया।
डॉ. फिलिप एच. कुमब्स, लंदन विश्वविद्यालय लंदन।
श्री हरी मोहन माथुर, परामर्शदाता, संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान, संस्थान मलेशिया।
श्री कार्लस मैलपिका, कार्यक्रम विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान, पेरिस।

राज्य शिक्षा विभागों से

श्री पासोंग नंगयाल, शिक्षा सचिव, सिक्किम।
श्री पी राय, विद्यालय शिक्षा निदेशक, पश्चिम बंगाल सरकार।
श्री जे ए रियन, विद्यालय शिक्षा निदेशक, तमिलनाडु सरकार
श्रीमती उषा वोहरा, शिक्षा सचिव, पंजाब।
श्री अशोक वाजपेयी, शिक्षा सचिव, मध्यप्रदेश।

डॉ. आत्म प्रकाश, शिक्षा निदेशक, उत्तरप्रदेश ।
श्री आर सी त्रिपाठी, शिक्षा सचिव, उत्तरप्रदेश ।
श्री जे एस मेहता, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान ।
श्री वी वी चिपलकुर, शिक्षा निदेशक, महाराष्ट्र, पुणे ।
श्री जे पी सिंह, शिक्षा सचिव, मेघालय ।
डॉ. एस मारली, जन शिक्षा निदेशक, असम ।
श्री एम ए लहरवाल, शिक्षा सचिव, जम्मू कश्मीर सरकार
श्री एल एम जैन, शिक्षा आयुक्त, हरियाणा ।
प्रो. सुकुमरन, आयुक्त, शिक्षा विभाग, केरल सरकार, त्रिवेंद्रम ।
श्री एम सी वर्मा, शिक्षा सचिव, दिल्ली ।

विश्वविद्यालयों से

प्रो. के एम बहाउद्दीन, उप कुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ ।
मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ ।
डॉ. (श्रीमती) माधुरी शाह, अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ।
प्रो. मूनिस रज़ा, प्रोफेसर आफ जियोग्राफी, जवाहर लाल विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ।
प्रो. रईस अहमद, उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ।
डॉ. एस एन मेहरोत्रा, उप कुलपति, जोधपुर, विश्वविद्यालय ।
प्रो. मंजूर आलम, उप कुलपति, कश्मीर विश्वविद्यालय ।
प्रो. रामलाल पारिख, उपकुलपति, गुजरात विद्यापीठ ।
प्रो. इकबाल नारायण, उप कुलपति, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ।

अन्य

वायु कमांडर, ओ पी दुग्गल, निदेशक (शिक्षा) वायुसेना, नई दिल्ली ।
श्री कांति विश्वास, शिक्षा मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार ।
डॉ. अमरीक सिंह, पूर्व सचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संस्था ।
श्री के सोनावने, निदेशक, राज्य शिक्षा संस्थान, पुणे ।
श्री एन कमिली, निदेशक, प्रबंध और लोक प्रशासन संस्थान, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर ।
श्री एस के मित्तल, निदेशक अनुसंधान विकास और प्रशिक्षण संस्थात, कानपुर ।
प्रो. एस एस कुलकर्णी, वरिष्ठ प्रोफ़ेसर, राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान, बंबई ।
कमान्डर सतबीर, आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली ।
डॉ. विनीत कुमार, निदेशक, क्षेत्रीय अध्ययन और विकास केंद्र, मुरादाबाद ।
श्री अनील बोदियां, अतिरिक्त सचिव श्रम मंत्रालय ।
डॉ. वी एस अरुणाचलम, रक्षा मंत्री के सलाहकार और महानिदेशक ।
डी एफ डी आर्गेनाइजेशन, भारत ।
प्रो. एम सी माथुर, निदेशक, एजुकेशनल कंसलटेंटस इंडिया लिमिटेड ।
प्रो. एम वी माथुर, सदस्य, चतुर्थ वेतन आयोग ।

परिशिष्ट

परिशिष्ट एक

परिषद के सदस्य (31. 3. 1985)

अध्यक्ष

श्री के सी पंत

केंद्रीय शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

उपाध्यक्ष

प्रोफेसर सत्यभूषण

रा शै यो और प्र सं

पदेन सदस्य

डॉ (श्रीमती) माधुरी शाह	अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह मार्ग, नई दिल्ली
श्री आनंद स्वरूप	सचिव, भारत सरकार, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली
श्री एल एस नारायनन,	वित्तीय सलाहकार, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली
श्री आर परमेश्वर	अतिरिक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, नई दिल्ली
श्री जे वीरराघवन	सलाहकार (शिक्षा), योजना आयोग, नई दिल्ली
प्रोफेसर पी एल मल्होत्रा	निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली

शिक्षा सचिव

श्री जे पी सिंह	शिक्षा सचिव, मेघालय सरकार, शिलांग
श्री एस एम पटनायक,	आयुक्त और सचिव, शिक्षा और युवक विभाग उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर

श्री एल एम जैन	आयुक्त और सचिव, शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़
श्री अशोक वाजपेयी	शिक्षा सचिव, मध्यप्रदेश, सरकार, भोपाल
श्री जे ललितंबिका	शिक्षा आयुक्त, विशेष सचिव (सामान्य शिक्षा विभाग) केरल सरकार, त्रिवेंद्रम
श्री एम सी वर्मा	सचिव, शिक्षा विभाग, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली,

शिक्षा निदेशक/जन शिक्षा निदेशक

श्री के पेशया	शिक्षा निदेशक, नागालैंड सरकार, कोहिमा
	शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, नया सचिवालय, गंगटोक-737101
श्री आत्म प्रकाश	शिक्षा निदेशक, उत्तरप्रदेश सरकार, लखनऊ
श्री वी वी चिपलुणकर	शिक्षा निदेशक (प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा) महाराष्ट्र सरकार, पुणे
श्री दिलीप चौधरी	जन शिक्षा आयुक्त, कर्नाटक सरकार, बंगलौर
श्री एल खियांगटे	शिक्षा निदेशक, गोआ, दमण व दिव सरकार, पणजी (गोआ) 40300

प्रतिष्ठित शिक्षाविद

डॉ. मेलकाम एस आरिसेशैया	अध्यक्ष, मद्रास विकास अध्ययन संस्थान, 79, सैकेंड मेन रोड, अह्यार मद्रास-600006
श्री डी जी कुलकर्णी	टाटा इंस्टीच्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च, होमी भाभा रोड, बंबई
श्रीमती ज्योति त्रिवेदी	उपकुलपति, एस एन डी टी विश्वविद्यालय, बंबई
प्रोफेसर सैयद अनवरूल हक्क हक्वी	प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
डॉ. बाई नायुंदम्मा	प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, केंद्रीय चर्म अनुसंधान मुस्लिम विश्व-विद्यालय, अलीगढ़
डॉ. बाई, नायुंदम्मा	प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, अड्यार, मद्रास-600020
डॉ. (श्रीमती) विमला अग्रवाल	अध्यक्षा, मनोविज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

कार्यकारी समिति के सदस्य

श्री पी के पटनायक	संयुक्त सचिव (योजना) शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली
डॉ. आर पी सिंघल	कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

संकाय सदस्य

डॉ. सी बी पद्मनाभन	वरिष्ठ अध्येता, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

सचिव

श्री आर पी सक्सेना	कुलसचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

परिशिष्ट दो

कार्यकारिणी समिति के सदस्य (31. 3. 85)

सभापति

प्रोफेसर सत्यभूषण,

निदेशक,

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

सदस्य

श्री एल एस नारायणन	वित्तीय सलाहकार, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली
श्री पी के पटनायक	संयुक्त सचिव (योजना) शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली
डॉ. वाई नायुंदम्भा	प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान अड्यार, मद्रास-600020
श्री एस एम पटनायक	आयुक्त और सचिव शिक्षा व युवक सेवा विभाग, उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर
श्री जे वीरराघवन	सलाहकार (शिक्षा) योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली
डॉ. आर पी सिंघल	कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

सचिव

श्री आर पी सक्सेना	कुलसचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान नई दिल्ली

परिशिष्ट तीन

वित्त समिति के सदस्य (31. 3. 1985 को)

सभापति

प्रो. सत्यभूषण

निदेशक

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

सदस्य

श्री एल एस नारायणन	वित्तीय सलाहकार, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली
श्री पी के पटनायक	संयुक्त सचिव (योजना) शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली
श्री जे पी सिंह	शिक्षा सचिव, मेघालय सरकार, शिलांग
डॉ. आर पी सिंघल	कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन, नई दिल्ली
	श्री आर पी सक्सेना कुलसचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

परिशिष्ट चार

कार्यालय सलाहकार समिति के सदस्य (31. 3. 1985 को)

सभापति

प्रो. सत्यभूषण

निदेशक

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

सदस्य

श्री वाई एन चतुर्वेदी	संयुक्त सचिब (स्कूल शिक्षा) शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली
श्री पी के पटनायक	संयुक्त सचिव (योजना), शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली
श्री जे वीरराघवन	सलाहकार (शिक्षा) योजना आयोग, नई दिल्ली
श्री एम एस श्री निवासन	संयुक्त शैक्षिक सलाहकार (टी) शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली
प्रो. रईस अहमद	उपाध्याय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली
श्री बी बरुआ	सचिव, शिक्षा विभाग, असम सरकार, दिसपुर, गुहाटी
श्री के के चक्रवर्ती	जन शिक्षा निदेशक, मध्यप्रदेश सरकार, भोपाल
डॉ. इंद्रपाल सिंह	निदेशक, पंजाब राज्य शिक्षा बोर्ड, मुहाली रोपड़ (पंजाब)
प्रो. नितीश डे	निदेशक, पंजाब राज्य लोक प्रशासन संस्थान, 36, सेक्टर 5 ए, चंडीगढ़
प्रो. सुरेश शुक्ला	डीन, शिक्षा संकाय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्व-विद्यालय, नई दिल्ली
डॉ. एस एन मेहरोत्रा	उप कुलपति जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान,
डा. डी डी नरूला	सदस्य सचिव, राष्ट्रीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
डॉ. आर पी सिंघल	कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
डॉ. सी बी पदमनाभन	वरिष्ठ अध्येता, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान,

सचिव

श्री आर पी सक्सेना	कुल सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

परिशिष्ट पांच

प्रकाशन सलाहकार समिति के सदस्य (31. 3.1985 **को**)

सभापति

प्रो. सत्यभूषण

निदेशक

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

सदस्य

डा. आर पी सिंघल	कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
डा. (श्रीमती) एस सरस्वती	उप निदेशक (प्रकाशन) आई सी एस एस आर, 35 फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110001
श्री सेम्युअल इजराइल	प्रकाशन परामर्शदाता, बुक सेल्फ, 29,सुंदर नगर मार्किट, नई दिल्ली 110003
डा. एम मुखोपाध्याय	वरिष्ठ अध्येता, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
डा. (श्रीमती) कुसुम प्रेमी	अध्येयता, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
श्री एम एम कपूर	अध्येयता राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

दो सहयोजित सदस्य होंगे ।

सदस्य-सचिव

श्री बी. सेल्वराज,	प्रकाशन अधिकारी, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशानसन संस्थान नई दिल्ली

परिशिष्ट छः

संकाय और प्रशासनिक स्टाफ (31. 3. 1985 को)

सत्यभूषण,	निदेशक
आर पी सिंघल	कार्यकारी निदेशक
शैक्षिक प्रशासन एकक	
एन एम भागिया	वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
सी मेहता,	सहअध्येता
एम मुखोपाध्याय,	वरिष्ठ अध्येता
के सुधाराव,	सहअध्येता
के जी विरमानी,	वरिष्ठ अध्येता
शैक्षिक वित्त एकक	
वान जोसफीव,	वरिष्ठ तकनीकी सहायक
सी बी पदमनाभन,	वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
जे बी जी तिलक,	अध्येता
शैक्षिक योजना एकक	
वाई पी अग्रवाल,	सहअध्येता (डाटा बैंक)
एल एस गणेश,	सहअध्येता
ब्रह्म प्रकाश,	वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
एन बी वर्गीस,	सहअध्येता
शैक्षिक नीति एकक	
एस सी नुना,	सहअध्येता
कुसुम प्रेमी,	अध्येता और अध्यक्ष
के सुजाता,	सहअध्येता
इज़लाल अचीस जैदी,	वरिष्ठ तकनीकी सहायक

उच्चतर शिक्षा एकक

एस अहमद,	वरिष्ठ अध्येता
एम एम रहमान,	वरिष्ठ तकनीकी सहायक
जी डी शर्मा,	वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष

अंतर्राष्ट्रीय एकक

जे जलाली,	वरिष्ठ तकनीकी सहायक
अंजना, मंगलागिरि,	सहअध्येता
उषा नायर,	अध्येता और अध्यक्ष

विद्यालय तथा अनौपचारिक शिक्षा एकक

शब्बीर अहमद,	अध्येता
सुषमा भागिया,	अध्येता
एस एस दुदाणी,	अध्येता
रश्मि दिवान,	वरिष्ठ तकनीकी सहायक
जेड हबीब,	वरिष्ठ तकनीकी सहायक
टी के डी नायर,	अध्येता
सी एल सपरा,	वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष

प्रादेशिक पद्धति और प्रलेखन एकक

वी ए कालपांडे,	अध्येता
एन डी कांडपाल,	प्रलेखन अधिकारी
एम एम कपूर,	अध्येता और अध्यक्ष
अरुण सी मेहता,	वरिष्ठ तकनीकी सहायक
आर एस शर्मा,	सहअध्येता
सी पी तिवारी,	अध्येता

मानचित्र कक्ष

पी एन त्यागी,	वरिष्ठ तकनीकी सहायक

समन्वय

मीना श्रीवास्तव,	वरिष्ठ तकनीकी सहायक

अनुसंधान परियोजना स्टाफ

इफतिखार अहमद,	परियोजना सहायक
अब्दुल अजीज,	परियोजना सहअध्येता
सुनीता चुग,	परियोजना सहायक
ए मैथ्यु,	परियोजना सहअध्येता

प्रोमिला मेनन,	परियोजना सहायक
सी आर के मूर्ति,	परियोजना सहायक
मंजू नरूला,	परियोजना सहायक
एस क्यू ए नक्वी,	परियोजना सहअध्येता
एस एन सराफ,	वरिष्ठ परियोजना अध्येता
अनीता टपलू,	परियोजना सहायक
ओ डी त्यागी,	परियोजना सहायक
प्रमिला यादव,	परियोजना सहायक

इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग एंड रिप्रोग्राफिक यूनिट

वी मुरलीधर,	कंप्यूटर प्रोग्रामर

प्रकाशन एकक

बी, सेल्वराज,	प्रकाशन अधिकारी
एम एम अजवानी,	वरिष्ठ प्रकाशन सहायक

हिंदी कक्ष

श्यामबिहारी राय,	हिंदी संपादक
रामकिशन,	हिंदी अनुवादक

पुस्तकालय

निर्मल मल्होत्रा,	पुस्तकाध्यक्ष
दीपक मकोल,	कनिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष

कार्यालय प्रशासन

आर पी सक्सेना,	कुलसचिव
एस सुंदरराजन,	वित्त अधिकारी
के एल दुआ,	प्रशासनिक अधिकारी
जी एस भारद्वाज,	अनुभाग अधिकारी
टी आर घ्यानी,	कार्यालय अधीक्षक
एम एल शर्मा,	कार्यालय अधीक्षक
चेरियन थामस,	लेखापाल

वार्षिक लेखा और अंकेक्षण रिपोर्ट

1-4-84 से 31-3-85 की अवधि का प्राप्ति लेखा

प्राप्ति

अर्थ शेष		
हस्तगत रोकड़	8, 865.35	
अग्रदाय	2,250.00	
बैंक में रोकड़	9,73,121.91	9,84,237.26
भारत सरकार से प्राप्त		
सहायता अनुदान		
योजनेतर	31,44,000.00	
योजनागत	42,95,000.00	74,39,000.00
कार्यालय प्राप्तियां		
लाइसेंस शुल्क	47,248.80	
पानी-बिजली प्रभार	4,168.50	
के स स्वा योजना की वसूलियां	168.00	
ई डी पी आर प्राप्तियां	43,880.00	1,09510.85
अन्य प्राप्तियां	14,045.55	
छात्रावास		
छात्रावास किराया		2,37,339.50
ब्याज		
निवेश पर ब्याज	48,703.84	
ब्याज वाली पेशगियों		
पर ब्याज	185.15	
अल्पकालीन जमा राशि पर ब्याज	10,339.69	59,228.68
अनुसंधान अध्ययन		
भारत में शिक्षा के लिए संसाधन जुटाने		
का अध्ययन		
यात्रा भत्ते की वसूली		1,417.00

1-4-84 से 31-3-85 की अवधि का भुगतान लेखा

	भुगतान		
संस्थागत व्यय			
वेतन			
योजनेतर	18,76,491.95		
योजनागत	10,58,261.10		29,34,753.05
पेंशन और उपदान			16,626.00
भविष्य निधि (अ. भ. नि का			
नियोक्ता अंश तथा स. भ. (मि.)			
पर ब्याज तथा प्रोत्साहन बोनस	1,20,495.00		
अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान			
योजनेतर	33,224.55		
योजनागत	13,813.00	47,037.55	
यात्रा व्यय		10,350.00	31,29,261.60
कार्यालय व्यय (अन्य खर्चे)			
योजनेतर	9,00,0000.00		
योजनागत	2,25,717.60		11,25,717.60
छात्रावास (योजनेतर)			
छात्रावास व्यय			1,31,016.30
अनुसंधान तथा प्रशिक्षण			
कार्यक्रम व्यय			
योजनेतर	2,20,00.000		
योजनागत	4,13,921.15		6.33,921.15
अनुसंधान अध्ययन (योजनागत)			
गुड़गांव जिले में शिक्षा की लागत			
का अध्ययन			
अध्ययन व्यय	41,567.00		
भारत में शिक्षा के लिए संसाधन			
जुटाने का अध्ययन			
अध्ययन व्यय	4,530.00		

	प्राप्ति	
प्रायोजित कार्यक्रम और अध्ययन		
नमूना अध्ययन : शैक्षिक रूप से पिछड़े और उन्नत राज्यों में निरीक्षण पद्धति और व्यवहार		
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार		5,000.00
शिक्षा और रोजगार के बीच लाभकारी संबंधों का अध्ययन		27,600.00
राष्ट्रीय शिक्षक आयोग II (केंद्रीय तकनीकी एकक)		
अध्ययन अनुदान	2,67,000.00	
पेशगी वसूली	1,03,331,51	3,70,331.51
इंजीनियरिंग कालेजों के प्रबंध का कार्यक्रम		20,000.00
भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद		
वरिष्ठ शिवावृत्ति (डॉ. जे एन कौल)		10,450.00
अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम		
श्रीलंका के क्षेत्रीय योजनाकार और प्रशासकों के लिए शैक्षिक प्रबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम (सी एफ टी सी		
कार्यक्रम प्राप्ति	15,529.60	
फिलिपिंसनियों के ओ पी एस स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम		
कार्यक्रम प्राप्ति	23,837.90	
शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय उपाधि पत्र		
कार्यक्रम प्राप्ति	4,89,434.69	
एशिया और पैसिफिक में उपक्षेत्रीय संगोष्ठी		
कार्यक्रम प्राप्ति	38,512.50	
एशिया और पैसिफिक के शैक्षिक योजनाकार और प्रशासकों की प्रथम		
क्षेत्रीय संगोष्ठी	57,306.60	
ग्रामीण विकास परियोजना पर शैक्षिक अवयव पर राष्ट्रीय बहुअनुशासनिक कार्यशाला		

	भुगतान
भारत में शैक्षिक विकास की क्षेत्रीय असमानताओं का अध्ययन : भारतीय शिक्षा का मानचित्र	
अध्ययन व्यय	29,927.05
शिक्षा मंत्रालय के संगठनात्मक इतिहास का अध्ययन	
अध्ययन व्यय	331.50
स्कूलों के लिए इष्टतम शिक्षक छात्र अनुपात का अध्ययन	
अध्ययन व्यय	25,886.85
माइल वित्तीय संहिता का अध्ययन	
अध्ययन व्यय	22,385.45
भारत में शैक्षिक नीति और योजना का अध्ययन-योजना आयोग की भूमिका-चालू स्थिति और भावी परिप्रेक्ष्य	
अध्ययन व्यय	45,034.15
केरल राज्य में शैक्षिक विकास के इतिहास का अध्ययन	
अध्ययन व्यय	28,500.05
2000 वर्ष में भारतीय शिक्षा : एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य	
अध्ययन व्यय	65,071.40
कालेज प्राचार्यों की भूमिका का अध्ययन	
अध्ययन व्यय	21,607.30
शैक्षिक स्तर और विकास के कुछ आयाम का अध्ययन	
अध्ययन व्यय	20,000 00
शैक्षिक योजना और प्रशासन कार्यान्वयन की रणनीति पर अनुसंधान कार्य अध्ययन	
अध्ययन व्यय	83,012.97
तकनीकी शिक्षा के प्रबंध पर अध्ययन	
अध्ययन व्यय	26,050.65

	प्राप्ति	
कार्यक्रम प्राप्ति	36,516.65	
शैक्षिक प्रबंध में अंतर्राज्यीय अध्ययन दौरे		
कार्यक्रम प्राप्ति	8,050.00	
पर्यावरणीय शिक्षा पर परामर्शी बैठक		
कार्यक्रम प्राप्ति	1,26,543.56	
उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय सहकारी कार्यक्रम (प्रणाली-विज्ञान शिक्षा)		
कार्यक्रम प्राप्ति	35,550.00	
भूटान के एक अधिकारी के लिए कार्यालय प्रबंध में उच्चतर प्रशिक्षण कार्यक्रम		
कार्यक्रम प्राप्ति	62,750.00	
योजना और यू पी ई प्रबंध पर राष्ट्रीय कार्यशाला		
कार्यक्रम प्राप्ति	15,793.03	9,09,824.53
यूनेस्को की वित्तीय सहायता से अनुसंधान अध्ययन		
भारत में शैक्षिक प्रबंध में नैदानिक अध्ययन पर राष्ट्रीय कार्यबल		
अध्ययन प्राप्ति		27,948.57

	भुगतान	
अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जातियों के लोगों के बीच में साक्षरता की असमानताओं का अध्ययन		
अध्ययन व्यय	9,193.00	4,23,048.17
अन्य शैक्षिक गतिविधियां (योजना)		
शिक्षावृति अवार्ड	3,445.15	
डेटा बैंक	22,661.90	
अंतर्राज्यीय दौरे	10,314.65	
परामर्श	2,562.00	
सांस्कृतिक विनिमय	4,348.00	
पाठ्य शुल्क	9,330.00	
प्रकाशन व्यय	27,605.15	80,266.85
प्रायोजित कार्यक्रम और अध्ययन		
अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास का अध्ययन एकक (गृह मंत्रालय भारत सरकार)		
अध्ययन व्यय	1,85,786.20	
नमूना अध्ययन : शैक्षिक रूप से पिछड़े और उन्नत राज्यों में निरीक्षण पद्धति और व्यवहार (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)	4,000.00	
शिक्षा और रोजगार के बीच लाभकारी संबंधों का अध्ययन (योजना आयोग)		
अध्ययन व्यय	11,341.00	
अनौपचारिक शिक्षा के लिए प्रयोगात्मक परियोजता—एक मूल्यांकन अध्ययन (शिक्षा मंत्रालय)		
अध्ययन व्यय	884.50	
राष्ट्रीय शिक्षा आयोग II (केंद्रीय तकनीकी एकक)		
अध्ययन व्यय 4,23,629.55		
क्षेत्र दौरे खर्च 84,973.61	5,08,603.16	

	भुगतान	
राजा राम मोहन राय पुस्तकालय स्थापना, कलकत्ता के सहयोग से सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा के वरिष्ठ प्रशासकों के लिए योजना और प्रबंध पर अभिविन्यास कार्यक्रम वापस किया गया अनुदान	638.50	
इंजीनियरिंग कालेजों के प्रबंध का कार्यक्रम		
कार्यक्रम व्यय	17,793.30	7,29,047.46
भारतीय समाज बिज्ञान अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय शिक्षावृति (प्रो. एस सी दुबे) आकस्मिक व्यय	87.10	
वरिष्ठ अध्येतावृति (डा. जे एल आजाद) आकस्मिक व्यय	3,923.95	
वरिष्ठ अध्येतावृति (डा. जे एन कौल) आकस्मिक व्यय	2,728.50	
भारत में समान शिक्षा और समान अवसर के आधार पर समानता के विशेष संदर्भ के साथ वित्त प्रबंध की शिक्षा पर अध्ययन केरल और उत्तर प्रदेश की स्कूल शिक्षा से संबंधित मामलों पर एक अध्ययन		
अध्ययन व्यय	13,690.95	20,430.50
अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम		
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना में उपाधि-पत्र जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए 6 मास का पूर्ण-आगमन कार्यक्रम पाठ्य-क्रम (1983)		
श्रीलंका के प्रतिभागी 8,932.00		
भूटान के प्रतिभागी 3,241.50		
मारीशस के प्रतिभागी 1,848.00	14,021.50	
श्रीलंका के शैक्षिक कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (1983-84)		
कार्यक्रम व्यय	1,701.95	

	भुगतान
श्रीलंका के क्षेत्रीय योजनाकार और प्रशासकों के लिए शैक्षिक प्रबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम (सी एफ टी सी)	
कार्यक्रम व्यय	92,915.85
अफगानिस्तान के अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम	79,989.75
कार्यक्रम व्यय	
फिलिपिंस के ओ पी एस स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	
कार्यक्रम व्यय	13,182.90
शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय उपाधि-पत्र	
कार्यक्रम	2,07,938.85
दीर्घकालीन शैक्षिक योजना कार्यक्रम	
व्यय	131.00
एशिया और पैसिफिक में उप-क्षेत्रीय संगोष्ठी	
कार्यक्रम व्यय	38,436.10
एशिया और पैसिफिक के शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों का प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलन	
कार्यक्रम व्यय	248.00
बंगलादेश के शिक्षा अधिकारियों का अध्ययन दौरा	
कार्यक्रम व्यय	15,089.80
ग्रामीण विकास परियोजना पर शैक्षिक अवयव पर राष्ट्रीय बहु-अनुशासनिक कार्यशाला	
कार्यक्रम व्यय	13,044.35
शैक्षिक प्रबंध में अंतर्राज्यीय अध्ययन दौरे	
कार्यक्रम व्यय	9.021.55

भुगतान		
पर्यावरणीय शिक्षा पर परामर्शी बैठक		
कार्यक्रम व्यय	86,335.80	
उच्च शिक्षा प्रणाली विज्ञान के लिए क्षेत्रीय सहकारी कार्यक्रम		
कार्यक्रम व्यय	29,092.50	
भूटान के एक अधिकारी के लिए कार्यालय प्रबंध में उच्चतर प्रशिक्षण कार्यक्रम		
कार्यक्रम व्यय	20,224.90	
योजना और यू पी ई के प्रबंध पर राष्ट्रीय कार्यशाला		
कार्यक्रम व्यय	11,846.50	6,33,221.30
उच्च शिक्षा की ग्रंथ सूची के विकास के लिए उच्च शिक्षा में ए पी ई आई डी क्षेत्रीय सहकारी कार्यक्रम		
अध्ययन व्यय	3,105.00	
ग्रामीण विकास के लिए शिक्षा के अवयव और संबंधों के प्रयोग पर अध्ययन		
अध्ययन व्यय	1,567.50	
भारत में शैक्षिक प्रबंध में नैदानिक अध्ययन पर राष्ट्रीय कार्य बल		
अध्ययन व्यय	13,737.60	18,410.10
पूंजीगत व्यय		
टाइपराइटर	26,404.10	
फर्नीचर और जुड़नार	1,43,667.40	
अन्य कार्यालय उपस्कर	1,19,053.75	
पुस्तकालय की पुस्तकें	1,49,832.57	
		4,38,957.82
जमा (योजनागत)		19,39,043.00
के लो नि वि के पास जमा		
उचंत लेख		21,800.85
वसूली योग्य पेशगियां (योजनेतर)		
साइकिल पेशगी	2,775.00	

प्राप्ति			
जमा			
उचंत लेखा			41,061.66
वसूली योग्य पेशगियां			
साइकिल पेशगी	1,730.00		
त्योहार पेशगी	10,500.00		
स्कूटर पेशगी	500.00		
मकान निर्माण पेशगी	42.648.00		55,378.00
प्रेषण			
प्रतिनियुक्तियों का अंशदायी अ भ नि			2,700.00
		कुल योग	10,301,027.56

हस्ताक्षर

(एस सुंदरराजन
वित्त अधिकारी

	भुगतान	
त्यौहार पेशगी	8,200.00	
मकान निर्माण पेशगी	1,11,900.00	
विविध पेशगियां	6,639.75	1,29,514.75
प्रेषण		
मकान किराया/नगर प्रतिकर भत्ता/ अतिरिक्त महंगाई भत्ता		0.42
अंतशेष		
हस्तगत रोकड़	25,258.46	
अग्रदाय	2,127.50	
यूनेस्को के कूपन	54.00	
बैंक के रोकड़	8,19,929.73	8,47,369.69
	कुल योग	10,301,027.56

हस्ताक्षर
(आर पी सिंघल)
कार्यकारी निदेशक

हस्ताक्षर
(सत्य भूषण)
निदेशक

31 मार्च, 1985 को अंतशेष का विवरण

क्रम सं. व्यय का शीर्ष	अर्थ शेष	वर्ष की अवधि में प्राप्ति	कुल योग
1. योजनेतर			
अनुदान	1,12,796.34	31,44,000.00	
कार्यालय प्राप्तियां	2,477.09	4,61,457.03	37,20,730.46
2. योजनागत			
अनुदान	2,70,029 43	42,95,000.00	
कार्यालय प्राप्तियां		1,417.00	45,66,446.43
3. प्रायोजित कार्यक्रम और अध्ययन	2,93,268.17	4,22,931.51	7,16,199.68
4. भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद	3,157.74	10,450.00	13,607.74
5. अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	2,70,054.35	9,09,824.53	11,79,878.88
6. यूनेस्को की वित्तीय सहायता से अनुसंधान कार्यक्रम	15,734.17	27,948.57	43,682.74
7. उचंत लेखा	13,831.25	41,061.66	54,892.91
8. प्रेषण	2,888.72	2,700.00	5,588.72
	9,84,237.26	9,316,790.30	10,301,027 56

हस्ताक्षर
(एस सुंदरराजन)
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्था, नई दिल्ली,

भुगतान	शेष
34,67,082.95	2,53,647.51
45,63,664.29	2,782.14
7,29,047.46	(—) 12,847.78
20,430.50	(—) 6,822.76
6,33,221.30	5,46,657.58
18,410.10	25,272.64
21,800.85	33,092.06
0.42	5,588.30
94,53,657.87	8,47,369.69

हस्ताक्षर
(आर पी सिंघल)
कार्यकारी निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

हस्ताक्षर
(सत्यभूषण)
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

वर्ष 1984-85 के लिए

व्यय

स्थापना व्यय		31,29,261.60
कार्यालय व्यय		11,25,717.60
छात्रावास व्यय		1,31,016.30
अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यय	6,33,921.15	10,56,969.32
अनुसंधान अध्ययन	4,23,048.17	
अन्य अकादमिक गतिविधियां		80,266.85
व्यय से अधिक आय		18,84,306.54
	कुल योग	74,07,538.21

हस्ताक्षर
(एस सुंदरराजन)
वित्त अधिकारी

आय व्यय का लेखा

आय

सहायता अनुदान	74,39,000.00	
घटाएं : पूंजीकृत अनुदान	4,38,957.82	70,00,042.18
कार्यालय प्राप्तियां		1,09,510.85
छात्रावास प्राप्तियां		2,37,339.50
ब्याज		59,228.68
अनुसंधान अध्ययन		1,417.00
यात्रा भते की वापिसी		
		कुल योग 74,07,538 21

हस्ताक्षर
(आर पी सिंघल)
कार्यकारी निदेशक

हस्ताक्षर
(सत्यभूषण)
निदेशक

31 मार्च, 1985 को तुलना पत्र

देयताएं		
पूंजीकृत अनुदान		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	97,53,516.81	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	4,38,957.82	
घटाएं: पूंजीनिवेश बट्टे खाते में कुल हानि	76,935.13	10,115,539.50
व्यय से अधिक आय		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	38,83,303.35	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	18,84,306.54	57,67,609.89
निर्धारित कार्यक्रम और अध्ययन		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	8,77,582.53	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	12,67,823.10	
घटाएं : वर्ष के दौरान व्यय	14,01,109.36	7,44,296.27
भविष्य निधि		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	7,36,827.00	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	4,83,363.02	
घटाएं : वर्ष के दौरान निकाली गई राशि	2,82,371.00	9,37,819.02
उचंत लेखा		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	13,831.25	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	41.061.66	
घटाएं : वर्ष के दौरान समाशोधन	21,800.85	33,092.06
उपहार और दान		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	910.52	910.52
जमा		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	2,500.00	2,500.00
प्रेषण		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	2,888.72	

परिसंपत्तियां		
भूमि व भवन		
उपस्कर और मशीनें, फर्नीचर और जुड़नार स्टाफ कार सहित गाड़ियां, टाइपराइटर आदि		55,88,382.51
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	30,08,643.10	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,89,125.25	
घटाएं : परिसंपतियों के मूल्य की हानि	7०,003.61	32,21,764.74
पुस्तकालय की पुस्तकें		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	11,50,656.89	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,49,832.57	
घटाएं : मूल्य की हानि	931.52	12,99,557.94
भविष्य निधि का निवेश		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	6,38,822.50	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	60,000.00	6,98,822.00
जमा		
प्रतिभूति जमा		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	41,540.00	41,540.50
के लो नि वि के पास जमा		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	31,58,036.57	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	19,39,043.00	50,97,079.57
वसूली योग्य पेशगियां		
त्यौहार पेशगी	5,500.00	
साइकिल पेशगी	2,090.00	
मकान निर्माण पेशगी	3,35,104.05	
विविध		
नीपा	30,625.75	
एन सी टी II	1,92,036.59	5,65,356.39
विविध कर्जदार		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	8,485.70	8,485.70

वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,700.00	
घटाएं : वर्ष के दौरान निकाली गई राशि	0.42	5,588.30
		17,607,335.56

टिप्पणी : यूनेस्को द्वारा उपहार स्वरूप दी गई उन पुरानी गाड़ियों को अभी बट्टे खाते में नहीं डाला गया है, 1981.82 व 1982-83 में बेच दिया गया, शिक्षा मंत्रालय से भारतीय रुपयों में इनकी कीमत प्राप्त होने पर ऐसा किया जाएगा।

हस्ताक्षर
(एस सुंदरराजन)
वित्त अधिकारी

रोकड़ शेष

हस्तगत	25,258.46	
अग्रदाय	2,127.50	
यूनेस्को कूपन	54.00	
चालू खाता	8,19,929.73	
सा भ नि/अ भ नि खाता	2,38,996.52	10,86,366.21
		17,607,355.56

हस्ताक्षर
(आर पी सिंघल)
कार्यकारी निदेशक

हस्ताक्षर
(सत्य भूषण)
निदेशक

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

निर्धारित कार्यक्रम के लिए लेखा

क्र. सं.	कार्यक्रमों/अध्ययन का नाम	अर्थशेष	वर्ष की अवधि में प्राप्ति
1	2	3	4
	गृह मंत्रालय (भारत सरकार)		
1.	अनुसंधान परियोजनाएं :		
	(i) आश्रम स्कूलों का गहन अध्ययन, और	(—) 21,869.45	—
	(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण से साक्षात्कार		
2.	अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास का अध्ययन एकक	90,681.00	
3.	शिक्षा मंत्रालय (भारत सरकार) नमूना अध्ययन : शैक्षिक रूप से पिछड़े और उन्नत राज्यों में निरीक्षण पद्धति और व्यवहार का प्रारूप	322.05	5,000.00
4.	जनसंख्या शिक्षा परियोजना (एन सी ई आर टी)	12,362.45	
5.	राष्ट्रीय अध्यापक आयोग II		
	(i) केंद्रीय तकनीकी एकक		2,67,000.00
	(ii) आयोग की यात्राओं का आयोजन	5,06,501.72	
6.	अनौपचारिक शिक्षा के एक मूल्यांकन अध्ययन के लिए प्रायोगिक परियोजना (शिक्षा मंत्रालय)		
7.	योजना आयोग भारत सरकार शिक्षा और रोजगार के लाभकारी संबंधों पर अध्ययन	—	27,600.00

प्रोफार्मा/वर्ष 1984-85 के लिए अध्ययन

जोड़	व्यय		अंतशेष
5	6		7
(—)21,869.45	—		(—)21,869.45
90,681.00	1,85,786.20		(—)95,105.20
5,322.05	4,000.00		1,322.05
12.362.45	—		12,362.45
	4,23,629.55		
7,73,501.72	84,973.61		2,64,898.56
	884.50		884.50
27,600.00	11,341,80		16,258.20
638.50	638.50		
20,000.00	17,793.30		2,206.70
(—)13,914.06	87.10		(—) 14,001.16
5,356.85	3,923.95		1,432.90
11,905.35	2,728.50		9,176.85
9,269.60			9,269.60
990.00	13,690.95		(—) 11,700.95
4,549.90	—		4,549.90
(—)46.41	—		(—) 46.41
555.42	—		555.42
1,567.50	1,567.50		—
21,308.27	13,737.60		7,570.67
3,640.55	—		3,640.55
—	15,089.80		(—) 15,089.80
8,050.00	9,021.55		(—) 971.55
12,107.51	—		12,107.51
40,566.37	33,044.35		27,522.02
7,111.17	—		7,111.17
39,860.47	1,701.95		38,158.52
1,25,314.05	92,915.85	32,398.20	
14,506.42	8,932.00	5,574.42	

1	2		3	3
8.	राजाराम मोहनराय पुस्तकालय स्थापना कलकत्ते के सहयोग से सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा के वरिष्ठ प्रशासकों के लिए योजना और प्रबंध पर अभिविन्यास कार्यक्रम		638.50	
9.	इंजीनियरिंग कालेजों के प्रबंध का कार्यक्रम (आई एस टी ई) आई सी एस एस आर नई दिल्ली			20,000.00
10.	प्रो एस सी दुबे		13,914.06	
11.	वरिष्ठ अध्येतावृति डॉ. जे एल आजाद		5,356.85	
12.	वरिष्ठ अध्येतावृति डॉ. जे एन कौल		1,455.35	10,450.00
13.	भारत में समाज विज्ञान अनुसंधान के लिए अनुसंधान परियोजना की वित्त व्यवस्था के अधीन किए गए आंकड़ों के आधार पर विश्लेषणात्मक मोनोग्राम को तैयार करना		9,269.60	
14.	भारत में समानशिक्षा और समान अवसर के आधार पर समानता के विशेष संदर्भ के साथ वित्त प्रबंध की शिक्षा पर अध्ययन। केरल और उत्तर प्रदेश को स्कूल शिक्षा से संबंधित मामलों पर एक अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और अध्ययन		990.00	
अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और अध्ययन				
15.	शिक्षा के लिए स्थानीय सहयोग का प्रबंध		454990	
16.	दो राज्यों में शैक्षिक वित्त व्यवस्था तथा क्षमता पर अध्ययन	(—)	46.41	—
17.	वैकल्पिक भविष्य और शिक्षा पर अध्ययन		555.42	—
18.	ग्रामीण विकास के लिए शिक्षा के अवयव और संबंधों के प्रयोग पर अध्ययन		1 67·50	
19.	भारत में शैक्षिक प्रबंध में नैदानिक अध्ययन पर राष्ट्रीय कार्य बल	(—)	6,640.30	97,948.57

5	6		7
12,069.25	3,241.50		8,827.75
5,769.92	1,848.00		3,921.92
78,531.85	79,989.75	(—)	1,457.90
22,949.65	13,282-90		9,766.75
56,565.96	248.00		56,317.95
4,89,434.69	2,07,938.85		2,81,495.84
—	131.00	(—)	131.00
38,512.50	38,436.10		86.40
—	3,105.00	(|)	3,105.00

1	2	3	4
20. जीवन स्तर को बेह तर बनानेके लिए कार्य अभिलाषा पर अध्ययन		3,640.55	—
21. बंगलादेश शिक्षा अधिकारियों का अध्ययन दौरे	—		
22. शक्षिक प्रबंध में अंतर्राज्यीय अध्ययन दौरे	—		8,050.00
23. स्कूल नामांकन परियोजना के लिए पद्धति पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण सेमिनार		12,107.51	—
24. ग्रामीण विकास परियोजना पर शैक्षिक अवयव पर राष्ट्रीय बहु-अनुशासनिक कार्यशाला		4,049.72	36,516.65
25. श्री लंका के शिक्षा कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (1982-83)		7.111.47	—
26. श्री लंका के शिक्षा कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (1983-84)		39,860.47	—
27. श्री लंका के क्षेत्रीय योजनाकार और प्रशासकों के लिए शैक्षिक प्रबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम		109,784.45	15,529.60
28. राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन में उपाधि पत्र-जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए 6 मास का पूर्व आगमन कार्यक्रम			
पाठ्यक्रम का व्यय			
I. श्रीलंका		14,506.42	—
II. भूटान		12,069.25	—
III. मारिशस		5,769.92	—
29. अफगानिस्तान के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम		78,531.85	—
30. फिलिपिंस के ओ पी एस स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	(---)	888.28	23,837.90
31. एशिया और पैसिफिक के शैक्षिक योजनाकार और प्रशासकों के लिए प्रथम क्षेत्रीय संगोष्ठी	(---)	740.65	57,306.90

1	2	3	4
32.	शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय उपाधि-पत्र		
33.	दीर्घकालीन शैक्षिक योजना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	—	—
34.	एशिया और पैसिफिक में उपक्षेत्रीय संगोष्ठी	—	38,512.50
35.	उच्च शिक्षा की ग्रंथ सूची के विकास के लिए उच्च शिक्षा में ए पी ई आई डी क्षेत्रीय सहकारी कार्यक्रम	—	—
36.	उच्च शिक्षा में प्रणाली विज्ञान के लिए क्षेत्रीय सहकारी कार्यक्रम	—	35,550.00
37.	यू. पी. ई. के योजना और प्रबंध पर राष्ट्रीय कार्यशील	—	15,793.03
38.	पर्यावरणीय शिक्षा पर परामर्शी बैठक	—	1,26,543.56
39.	भूटान के एक अधिकारी के लिए कार्यालय प्रबंध पर उच्चतर प्रशिक्षण कार्यक्रम	—	62,750.00
	कुल योग	8,77,582.53	12,67,823.10

हस्ताक्षर
(एस सुंदरराजन)
वित अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

5	6	7
35,550.00	29,092.50	6.457.50
15,793.03	11,846 50	3,946.53
1,26,543.56	86,335.80	40,207.76
62,750.00	20,224.90	42,525.10
21,45,405,63	14,01,109.36	7,44,296.27

हस्ताक्षर
(आर. पी. सिंघल)
कार्यकारी निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

हस्ताक्षर
(सत्यभूषण)
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अर्थ शेष		98,004.50
अंशदायी पेशगियों की वसूली		3,62,868.02
ब्याज का स्थानान्तरण, कर्मचारियों	1,20,000.00	
का अंशदान, आई, बी इत्यादि	495.00	1,20,945.00
	योग	5,81,367.52

हस्ताक्षर
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

पेशगीयां और निकासी	2,82,375.00
दिनांक 2-4-85 को विशेष जमा	60.0000.00
अंत शेष	2,38,996.52
योग	5,81,367.52

हस्ताक्षर
(आर. पी. सिंघल)
कार्यकारी निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

हस्ताक्षर
(सत्यभूषण)
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना ओर
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र

मैंने राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रकाशसन संस्थान नई दिल्ली के 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखे और तुलन-पत्र की जांच कर ली है। थने सभी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर दिए हैं तथा संलग्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अधीन रहते हुए अपनी लेखापरीक्षा के ररिणामस्वरूप में प्रमाणित कपता हूँ कि मेरी राय में तथा मेरी सर्वोतम जातकारी तथा मुझे दिए गए स्पष्टींकरण तथा संस्थान की बहियों में दर्शाए गए जल्लेखों के अनुसार ये लेखे और तुलन-पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं तथा संस्थान के कार्यकलापों का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

हस्ताक्षर
निदेशक लेखापरीक्षा
केंद्रीय राजस्व-I

नई दिल्ली
दिनांक 23 अक्तूबर 1985

अंकेक्षण रिपोर्ट

(वर्ष 1984-85 के लिए)

1. सामान्य : राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन का प्रमुख वित्तीय स्रोत भारत सरकार है। वर्ष 1984-85 के दौरान इसको प्राप्त कुल अनुदान की राशि 74.39 लाख रुपए थी जिसमें 31.44 लाख योजनेतर और 42.95 लाख योजना के अंतर्गत था।

2. लेखा संबंधी टिप्पणियां

2.1 परिसंपत्तियां : बैलेंस शीट के लायबिलिटी पक्ष में दिखाया गया पूंजीगत अनुदान 101.19 लाख रुपए मार्च 31, 1985 में था तथा स्थाई परिसपत्तियां 101.10 लाख थी जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है।

	(रु. लाख में)
(i) भूमि तथा भवन	55.88
(ii) उपकरण, मशीनें, फर्निचर तथा वाहन आदि	32.22
(iii) पुस्तकें	13.00
योग	101.10

0.06 लाख के अंतर का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। भूमि तथा भवन का संस्थान में ब्योरेवार विवरण नहीं रखा गया है फलस्वरूप खाते में भूमि तथा भवन के 31.3.85 तक के 55.88 लाख मूल्य को सत्यापित नहीं किया जा सका। प्रशासनिक खंड, छात्रावास तथा आवासीय खंडों के पूर्णता प्रमाण पत्र भी संस्थान ने संबद्ध अधिकारियों से नहीं प्राप्त किया है। संस्थान ने दिसंबर 1985 में बताया कि विस्तृत ब्योरों को खोज लिया गया है तथा 1985-86 के लेखा में आवश्यक सुधार कर लिए जाएंगे।

2.2 भौतिक सत्यापन 1979-80 के बाद से स्टोर तथा स्टाक आदि का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका है (इसमें छात्रावास का 84-85 किया गया है) यद्यपि पहले की अंकेक्षण रिपोर्ट में इसकी आवश्यकता की ओर इशारा किया जा चुका है। पुस्तकालय की पुस्तकों का अंतिम सत्यापन 1978-79 में किया गया था। 1984-85 में खरीदी गई पुस्तकों का सत्यापन भी अभी पूरा होना है (अक्टूबर 1985)। संस्थाने ने कहा कि सभी चीजों का सत्यापन शीघ्र पूरा हो जाएगा (दिसंबर 1985) तथा अगले निरीक्षण के समय इसे आडिट को दिखा दिया जाएगा।

2.3 सी पी डब्ल्यू डी से खर्च के ब्योरों का न प्राप्त होना

25 03 लाख रुपए की राशि (विवरण नीचे) अग्रिम के रूप में टाइप I तथा V आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए सी पी डब्ल्यू डी को दी गई :

वर्ष	राशि लाखों में
1979-80	4.17
1980-81	15.45
1982-83	5.41
योग	25.03

जिन आवासों के लिए 1982-83 में राशि जमा की गई थी उसे सी पी डब्ल्यू डी ने जुलाई 1982 तक पूरा कर लिया था तथा अगस्त 1982 में संस्थान ने उसे ले लिया और सितंबर 1982 में उन्हें आबंटित कर दिया गया लेकिन तीन वर्ष बीतने के बाद भी सी पी डब्ल्यू डी से खर्च का विवरण नहीं प्राप्त किया जा सका। इसके फलस्वरूप भवन पर किए गए खर्च को अब भी भूमि तथा भवन के खाते में दिखाने के बजाए सी पी डब्ल्यू डी के खाते में जमा दिखाया जा रहा है।

नई दिल्ली
दिनांक 23 दिसंबर 1985

हस्ताक्षर
लेखा परीक्षा निदेशक
केंद्रीय राजस्व -I

नीपा की अंकेक्षण रिपोर्ट पर अनुच्छेदवार टिप्पणियां : वर्ष 1984-85

अनुच्छेद 1 :कोई टिप्पणी नहीं !

अनुच्छेद 2.1: पूंजीकृत अनुदानों तथा स्थिर परिसंपत्तियों का मूल्य रु. 58.34 है इसका स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है :

जिन परिसंपत्तियों को बट्टे-खाते डाल दिया जाता है उसको खाते में दर्शाने की प्रक्रिया वित्त मंत्रालय के जी ओ आई (व्यय विभाग) ओ एम न. एफ 14 (6) -सी-II (ए) / 80 दिनांक 30. 9. 80 में दी गई है। इन आदेशों में ऐसा माना गया है कि जब कभी कोई परिसंपत्ति बट्टे खाते डाली जाती है बिक्री को अनुदानी संस्थान के रूप में लिया जाएगा तथा उसे आय व्यय के खाते में ही दिखाया जाएगा। जिसे बट्टे खाते

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D 9365
Date 5.12.96

डाला गया है उसे बट्टे खाते के रूप में दिखाया जाएगा और इसे परिसंपत्ति के कुल मूल्य के नीचे परिसंपत्तियों की ओर ही रखा जाएगा तथा उसी को पुन: पूंजीगत व्यय के रूप में बट्टेखाते में दिखाया जाएगा। इस प्रकार इसको आय-व्यय लेखा के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा (यानी व्यय की ओर)। संस्थान ने कुछ परिसंपत्तियों को बेचा जिसकी कीमत रु 6742.55 थी (1977-78)। चूंकि 1977-78 में इस विषय पर कोई आदेश नहीं थे, इन परिसंपत्तियों के मूल्य को आय व्यय के खाते में दर्ज किया गया (व्यय खाते में)। इसके मूल्य को "पूंजीगत अनुदान" से घटाया नहीं गया।

वर्ष 1980-81 के दौरान रु 2.28 जो पहले पूंजीकृत किया गया था परिसंपत्ति से घटा दिया गया लेकिन लाइबिलिटी की ओर से इसे "एक्सेस आफ इनकम ओवर एक्सपेंडीचर" में ले लिया गया।

रु 910.52 की राशि की पुस्तकें दान अथवा उपहार के रूप में प्राप्त हुई थी तथा इनको परिसंपत्ति में शामिल कर लिया गया है लेकिन अब भी उसे दान तथा उपहार के खाते में ही दर्शाया गया है।

इस प्रकार पूंजीगत अनुदानों तथा परिसंपत्ति के बीच युद्ध रु 5834.34 के अंतर को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है :

(i) 1977-78 में बट्टेखाते डाली गई परिसंपत्ति का मूल्य पूंजीगत अनुदान से घटाया नहीं गया रु. 6,742.55

(ii) एक्सेस आफ इनकम ओवर एक्सपेंडीचर से घटी परिसंपत्तियों का मूल्य (1980-81) रु 2.28
6744.83

घटाए गए : उपहार के रूप में प्राप्त परिसम्पत्ति
जिसे भुगतान पत्र में उपहार तथा
दान के रूप में दर्शाया गया है रु० 910.52
रु० 5,834.31

खाते में आइट (I) तथा (II) के विषय में 31.3.86 तक आवश्यक सुधार कर लिए जाएंगे।

पैराग्राफ 2.3 संस्थान ने चीजों के सत्यापन के लिए पहले ही दलों का गठन कर लिया है। जैसे (1)स्टेशनरी, (2) फर्नीचर आदि (3) कार्यालय उपकरण (4) छात्रावास आइटम। नं. 1, 2, तथा तीन का सत्यापन पूरा किया जा चुका है। कार्यालय उपकरणों का सत्यापन प्रगति पर है तथा शीघ्र पूरा हो जाएगा।

पुस्तकालय की पुस्तकों का सत्यापन भी प्रगति पर है। इसमें दिक्कत सिर्फ यह है कि तीन राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर पुस्तकालय हर रोज खुला रहता है। फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि इस काम को यथाशीघ्र पूरा किया जा सके।

पैराग्राफ 2.3 सी पी डब्ल्यू डी से खर्चे के विवरण का न प्राप्त होना

मई 1981 में निर्माण लागत का अनुमान 25.03 लाख रुपए टाइप I तथा II के आवासों के लिए लगाया गया था। इसके लिए सी पी डब्ल्यू डी को 34.28 लाख रुपए 1979-80 तथा 1984-85 में दिए गए। यह भुगतान किश्तों में किया गया। इसके बाद 1984 में 34.28 लाख रुपए का संशोधित अनुमान संस्थान को दिया गया। अंतिम किश्त का भुगतान मार्च 1985 में किया गया। संस्थान ने सी पी डब्ल्यू डी से खर्चे का विस्तृत ब्यौरा देने के लिए अनुरोध किया है। इस मामले पर अंतर्विभागीय समिति की बैठक में भी विचार किया गया। यह बैठक मार्च 1985 में हुई थी जिसमें सी पी डब्ल्यू डी के वरिष्ठ इंजीनियर मौजूद थे। इंजीनियरों ने सूचित किया कि चूंकि अंतिम किश्त का भुगतान मार्च 1985 में किया गया था, इसलिए संभव है कि ठेकेदारों के साथ भुगतान को अंतिम रूप देने में कुछ समय लगे तथा उनके खातों में खर्चे देर से दर्ज किए जाएं। इस मामले को गंभीरता और तत्परता से सी पी डब्ल्यू डी के साथ लिया जा रहा है तथा उम्मीद है कि उनसे लेखा का विवरण शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा।